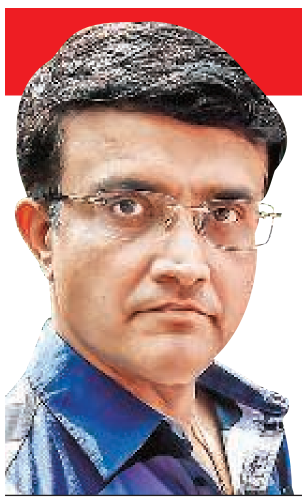

बिखरी बीसीसीआइ को समेटना मेरी प्राथमिकता : गांगुली

>>14

राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

वर्ष 3 अंक 127

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 15 अक्टूबर 2019

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 16

भारत में पले-बढ़े अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

स्टॉकहोम, प्रेट्र : जिस आदमी के पास पेट भरने को भोजन नहीं है, वह टीवी क्यों खरीदेगा? क्या ज्यादा बच्चे होना ज्यादा गरीब बना देता है? अर्थव्यवस्था से जुड़े ऐसे ही कई सवाल उठाने वाले और दो दशक से वैश्विक स्तर पर गरीबी से लड़ने की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी फ्रांसीसी पत्नी एस्थर डुफ्लो को इस साल अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया है। उनके साथ अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर भी विजेता चुने गए हैं। इस एलान के साथ इस साल के नोबेल विजेताओं के नामों के एलान का क्रम भी पूरा हो गया। विजेताओं को 10 दिसंबर को पुरस्कार दिए जाएंगे।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा, 'इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल विजेताओं ने जो शोध किया है, उससे वैश्विक गरीबी से निपटने की हमारी क्षमता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। मात्र दो दशक में उनके प्रयोग आधारित नए तरीके ने विकास की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव किया है, जो व्यापक शोध का विषय है।' उन्होंने गरीबी के खिलाफ जवाब खोजने का नया तरीका दिया है। उनकी खोज और इन पर काम करने वाले अन्य अर्थशास्त्रियों ने गरीबी से लड़ने की क्षमता को निखारा है। उन्होंने मुद्दे को छोटे व आसानी से समझे जा सकने वाले सवालों में बांटा है।

- अर्थव्यवस्था को गरीबी और गरीब पर केंद्रित करने की दिशा में दिया है अहम योगदान
- बनर्जी के साथ उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को भी नोबेल

बोस्टन शहर स्थित घर पर पत्नी एस्थर डुफ्लो के साथ अभिजीत बनर्जी। एएफपी

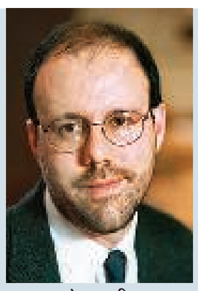

माइकल क्रेमर की फाइल फोटो। एपी

> अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने पर बधाई। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को भी नोबेल जीतने की बधाई देता हूं।
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

> नोबेल जीतने का पता चलते ही मैं अवाक रह गया। कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे नोबेल मिल जाएगा। मुझे कम से कम 10 साल बाद इसकी उम्मीद थी।
> **- अभिजीत बनर्जी**

58 वर्षीय बनर्जी की शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुई है। वह फिलहाल एमआइटी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स के तौर पर जुड़े हैं। 1972 में जन्मी डुफ्लो एमआइटी के इकोनॉमिक्स विभाग में में अब्दुल लतीफ जमील प्रोफेसर ऑफ पॉवर्टी एलीविएशन एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के रूप में जुड़ी हैं। 54 वर्षीय क्रेमर एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गेट्स प्रोफेसर ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज के तौर पर कार्यरत हैं। पुरस्कार के तौर पर मिलने वाली 90 लाख स्वीडिश क्रोनर (करीब 6.46 करोड़ रुपये) की राशि को तीनों विजेताओं में बराबर बांटा जाएगा।

शोध का भारत में दिखा है असर

एकेडमी ने कहा, बनर्जी के अध्ययन का सीधा असर भारत में देखा जा सकता है, जहां स्कूलों में रेमेडियल ट्यूटरिंग कार्यक्रम के जरिये 50 लाख से ज्यादा बच्चों को फायदा मिला है। इसके तहत स्कूलों में कमजोर बच्चों की पहचान करते हुए उनकी खामी का पता लगाया जाता है और उसे निखारने पर मेहनत की जाती है। कई देशों में प्रीवेंटिव हेल्थकेयर पर दी जा रही भारी-भरकम सब्सिडी भी इसका उदाहरण है।

अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाली दूसरी महिला हैं डुफ्लो

डुफ्लो अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाली दूसरी महिला और सबसे कम उम्र की अर्थशास्त्री हैं। उनसे पहले 2009 में अमेरिका की एलिनोर ऑस्ट्रोम को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। पुरस्कार की घोषणा के बाद डुफ्लो ने कहा, 'यह दिखाता है कि एक महिला के लिए सफल होना और उसकी सफलता को सम्मान मिलना संभव है। मुझे उम्मीद है कि इससे कई महिलाएं अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरित होंगी और पुरुष उन्हें उचित सम्मान देंगे।'

'पुअर इकोनॉमिक्स' ने बजाया डंका

बनर्जी और डुफ्लो की किताब 'पुअर इकोनॉमिक्स : ए रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी' ने दुनियाभर में डंका बजाया है। इस किताब को 2011 में फाइनेंशियल टाइम्स एंड गोल्डमैन सैक्श बिजनेस बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिल चुका है। इसका 17 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसमें अभिजीत लिखते हैं : मोरक्को में जिस आदमी के पास पर्याप्त भोजन नहीं है, वह टेलीविजन क्यों खरीदेगा? गरीबी वाले क्षेत्रों में स्कूल पहुंचने के बाद भी बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल क्यों है? क्या बहुत ज्यादा बच्चे होना आपको ज्यादा गरीब बना देता है? अगर हम वैश्विक गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है।

भारतीयों की बढ़ती धमक

अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल मिलने के साथ वैश्विक स्तर पर अर्थशास्त्र की दुनिया में भारतीय चेहरों की धमक और बढ़ गई है।

इनसे पहले कई भारतीय नाम अपनी मेधा का लोहा मनवा चुके हैं। बात चाहे नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की हो या वर्ल्ड बैंक ग्रुप की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर व मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत की, दुनिया में डंका बजाने वाली ऐसी भारतीय हस्तियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। रघुराम राजन, विरल आचार्य, अरविंद पानगड़िया और आइएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का नाम इनमें प्रमुखता से रखा जा सकता है।

'न्याय' के रहे सूत्रधार पेज>>11

सरोकार

कलाम की कलम से लिख रहे नए भारत की सुनहरी इबारत

नई दिल्ली : भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आज 88वीं जयंती है। कलाम ने शिक्षा को नए भारत के सृजन का आधार बताया था। 2012 में उनके द्वारा स्थापित संस्था कलाम सेंटर इस दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रही है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

हेलीकॉप्टर हादसा : दो अफसरों का होगा कोर्ट-मार्शल

नई दिल्ली : बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ उपजे तनाव के दौरान अपने ही एमआइ-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराने के मामले में भारतीय वायुसेना के दो अधिकारियों का कोर्ट-मार्शल होगा। ज्ञात हो, 27 फरवरी को श्रीनगर में बडगाम के पास हुए इस हादसे में वायुसेना के छह जवान शहीद हो गए थे।

महासमर ▶ पृष्ठ 4

अनुच्छेद-370 को हटाने से अनुसूचित पाएंगे लाभ : मोदी

फरीदाबाद : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद-370 के मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अनुसूचितों को भड़काने वालों ने सत्ता में रहते हुए यह भी नहीं सोचा कि जम्मू-कश्मीर में रहने वाला वाल्मीकि का बेटा चाहे कितना भी पढ़-लिख ले, उसे सरकारी नौकरियों में वह सुविधा नहीं मिलती थी जो पूरे देश में मिलती है। इसका कारण था अनुच्छेद 370। इसे हटाने का लाभ अब इस समाज को मिलेगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

उप्र के मऊ में सिलेंडर विस्फोट से 13 की मौत, 24 घायल

मऊ : उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बढ़ईटोला में सोमवार सुबह रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद विस्फोट हो गया जिससे 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि हादसे वाला मकान जमींदोज हो गया। साथ ही आसपास के चार घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

डोभाल ने अदालतों पर उठाए सवाल

एनएसए बोले ▶ आतंकवाद के मामलों में सामान्य आपराधिक केसों की तरह मांगे जाते हैं सुबूत

राज्यों के एटीएस प्रमुखों के साथ बैठक में इमरान के आरोपों का दिया जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने सोमवार को आतंकी मामलों में अदालतों की भूमिका पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, अदालतें आतंकवाद से जुड़े केस भी सामान्य आपराधिक मामलों की तरह लेती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आतंकवाद के मामलों में सामान्य केस जैसे चश्मदीद गवाह जुटाना संभव नहीं है। उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) में पाकिस्तान को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डलवाने की कोशिश के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के आरोपों का भी करारा जबाव दिया।

राज्यों के आतंकरोधी दस्तों के प्रमुखों की दो दिनी बैठक के उद्घाटन अवसर पर अजीत डोभाल ने कहा कि हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी की पहुंच के कारण उनके खिलाफ सुबूत जुटा पाना बेहद कठिन और मुश्किल काम होता है। लेकिन ऐसे मामलों में आतंकियों के प्रति अदालतों का व्यवहार सामान्य मामलों की तरह होता है। उन्होंने कहा, 'वे (अदालतें) वहीं बेंचमार्क और मानक अपनाती हैं। केस तैयार करने के लिए आपको गवाहों की जरूरत होती है। आतंकी मामलों में आप गवाह कहां से लाएंगे। पहली बात, ऐसे मामलों में गवाह बहुत कम होते हैं। दूसरा, जैश ए मुहम्मद या लश्कर ए तैयबा के आतंकी के खिलाफ एक सामान्य नागरिक के लिए अदालत में पेश होना बहुत-बहुत कठिन है।'

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भारत किसी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन आतंकी फंडिंग पर जो सुबूत हैं उसे दुनिया के सामने रखना हमारी जिम्मेदारी है। एफएटीएफ की निगरानी के बाद पाकिस्तान आतंकी फंडिंग को लेकर जितना दबाव में है, पहले कभी नहीं था। डोभाल ने कहा, आतंकवाद पाकिस्तान सरकार की आधिकारिक नीति है और इससे निपटना आसान नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद इमरान खान के जिहाद के आह्वान की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अहम चरण में पहुंच गई है। इससे निपटने के लिए सभी एजेंसियों को एकजुट होकर काम करना होगा।

आतंकी फंडिंग की जांच के लिए एनआइए की तारीफ : जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की तारीफ करते हुए डोभाल ने कहा, आतंकी फंडिंग को लेकर उसके द्वारा जुटाए गए ठोस सुबूतों के आधार पर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिली। उन्होंने आतंकरोधी दस्तों को सलाह दी कि आतंकियों को मार गिराना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उसके समर्थन में खड़े नेटवर्क को ध्वस्त करना है। उन्होंने एजेंसियों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मीडिया की अहम भूमिका की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को लेकर मीडिया को सही जानकारी उपलब्ध कराना एजेंसियों की जिम्मेदारी है, ताकि जनता को सही तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

दक्षिणी राज्यों में पैठ बढ़ा रहा जेएमबी : एनआइए के महानिदेशक वाईसी मोदी ने बताया कि किस तरह जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) भारत के दक्षिणी राज्यों में पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बेंगलुरु से पिछले दिनों जेएमबी आतंकियों की गिरफ्तारी इसका सुबूत है। वहीं, एनआइए के महानिरीक्षक आलोक मित्तल ने भारत में इस्लामिक स्टेट (आइएस) को रोकने में किए गए प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत में अभी तक आइएस के कुल 127 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 125 संदिग्धों की सूची को राज्यों के साथ साझा किया है।

आतंकी फंडिंग के सुबूत दुनिया के सामने रखना हमारी जिम्मेदारी

> आतंकी मामलों में आप गवाह कहां से लाएंगे। पहली बात, ऐसे मामलों में गवाह बहुत कम होते हैं। दूसरा, कुख्यात जैश ए मुहम्मद या लश्कर ए तैयबा के आतंकी के खिलाफ एक सामान्य नागरिक के लिए अदालत में पेश होना बहुत-बहुत कठिन है।
> **- अजीत डोभाल, एनएसए**

नई दिल्ली में राज्यों के आतंकरोधी दस्तों के प्रमुखों की दो दिनी बैठक के दौरान एनएसए अजीत डोभाल। प्रेट्र

आत्मघाती हमलावरों समेत 45-50 आतंकी ले रहे बालाकोट में प्रशिक्षण : सूत्र पेज>>7

एफएटीएफ की बैठक में अलग-थलग पड़ा पाक

- आखिरी चेतावनी के साथ 'डार्क ग्रे' लिस्ट में डाला जा सकता है
- अभी एफएटीएफ की 'ग्रे' लिस्ट में है पाकिस्तान

पेरिस, प्रेट्र : पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सख्त कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। फ्रांस की राजधानी में शुरू हुई एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है और उसे सुधार की आखिरी चेतावनी के साथ 'डार्क ग्रे' लिस्ट में डाला जा सकता है।

एफएटीएफ की बैठक में हिस्सा ले रहे अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि दहशतगर्दों और आतंकी संगठनों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने पर पाक को किसी देश का समर्थन नहीं मिलेगा। एक अधिकारी ने बताया कि पाक ने 27 कार्ययोजना में से सिर्फ छह पर मामूली कार्रवाई की है। ऐसे में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान अगर 'ब्लैक' लिस्ट में जाने से बच भी जाता है तो उसे 'डार्क ग्रे' लिस्ट में डाला जा सकता है। एफएटीएफ पाकिस्तान पर 18 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। नियमों के मुताबिक 'ग्रे' और 'ब्लैक' लिस्ट के बीच 'डार्क ग्रे' लिस्ट है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि 'डार्क ग्रे' लिस्ट का मतलब है कि संबंधित देश को सुधार के लिए आखिरी मौका दिया जाता है। एफएटीएफ ने पिछले साल जून में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला था और 27 बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए इस साल अक्टूबर तक का वक्त दिया था। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी रहता है या उसे डार्क ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो भी उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में उसके लिए विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ से वित्तीय मदद मिलनी मुश्किल हो जाएगी। रविवार से शुरू हुई एफएटीएफ प्लेनरी की बैठक में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बैठक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। एफएटीएफ मनी लांड्रिंग और आतंकियों के वित्तपोषण पर निगरानी रखता है।

बचाव के लिए पेरिस में जमा है पाक दल : ईरान और उत्तर कोरिया के साथ एफएटीएफ की 'ब्लैक' लिस्ट में नाम आने के जोखिम का सामना कर रहे पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अजहर के नेतृत्व में एक दल पेरिस पहुंचा है। यह दल आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लांड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए इस्लामाबाद के कदमों पर अपना पक्ष रखेगा।

उप्र में गो-संरक्षण में घोटाला, डीएम सहित पांच अधिकारी निलंबित

- गो-सदन में निराश्रित गोवंश के रखरखाव में लापरवाही के साथ मिलीं अनियमितताएं
- गैरकानूनी ढंग से 328 एकड़ भूमि अनुबंध कर किसानों और फर्मों को दे दी गई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण में घोटाला पकड़े जाने पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने महराजगंज के जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय समेत पांच अफसरों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को लोकभवन में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि महराजगंज जिले की निचलौल तहसील के मधवलिया गो-सदन में निराश्रित गोवंश के रख-रखाव में लापरवाही की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस पर शासन ने अपर आयुक्त प्रशासनिक, गोरखपुर मंडल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने पूरे मामले की जांच की। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं पकड़ में आईं। कागजों में कुल 2500 गोवंश होने की बात कही गई थी लेकिन मौके पर जांच के लिए पहुंची टीम को मात्र 954 गोवंश ही वहां मौजूद मिले।

इसके अलावा गो-सदन की 500 एकड़ भूमि को अफसरों ने गैरकानूनी ढंग से खुर्द-बुर्द किया गया। गो-सदन संचालन के लिए वन विभाग की भूमि का कब्जा पशुपालन विभाग को दिया गया था। इसमें से 328 एकड़ भूमि को किसानों, फर्मों व अन्य व्यक्तियों को गैरकानूनी तरीके से अनुबंध कर दे दिया गया। चारे और गोवंश के रख-रखाव के नाम पर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

तिवारी ने कहा, जांच में दोषी पाते हुए गो-सदन के अध्यक्ष व महराजगंज के डीएम अमरनाथ उपाध्याय, गो-सदन समिति के नामित सदस्य व तत्कालीन उप जिलाधिकारी निचलौल देवेंद्र कुमार, वर्तमान उप जिलाधिकारी सत्यम मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजीव उपाध्याय व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी निचलौल डा. वीके मौर्य को निलंबित कर अनुशासनिक जांच के निर्देश दिए गए हैं।

नौ दिनों में सरकारी बैंकों ने बांटे 81,781 करोड़ रुपये कर्ज

- कर्ज बांटने का अगला अभियान 21 से 25 अक्टूबर तक चलेगा
- एमएसएमई के बीच कर्ज वितरित करने पर खास जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दुर्गा पूजा के नौ दिनों के दौरान शामियाना लगा कर कर्ज बांटने का सरकारी बैंकों का फॉर्मूला काम करता दिख रहा है। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर शुरू किए गए अभियान के तहत कुल 81,781 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गए। इससे उत्साहित होकर अब सरकारी बैंकों को दीवाली से ठीक पहले 21 से 25 अक्टूबर तक फिर से कर्ज वितरण के लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ यहां हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में दूसरा अहम फैसला यह हुआ कि बेहद छोटे, मझोले व छोटे औद्योगिक इकाइयों (एमएसएमई) को कर्ज बांटने और बड़ी कंपनियों पर उनके बकाये का भुगतान कराने के लिए भी सरकार अभियान चलाएगी। इसमें कंपनी मामलों के मंत्रालय की भी मदद ली जाएगी। देश की बड़ी कंपनियों ने बताया है कि एमएसएमई सेक्टर का उनके ऊपर 40 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। अब सरकार ने सबसे पहले तो डीसीए को कहा है कि वह अपनी तरफ से इन बड़ी कंपनियों को इस बारे में पत्र लिखे कि वह छोटी व मझोली इकाइयों की राशि का भुगतान करे। दूसरा, बैंकों को कहा गया है कि वे एमएसएमई से संपर्क करें और उनसे पूछे कि क्या उन्हें अतिरिक्त कर्ज की जरूरत है। इसके लिए इन इकाइयों को बिल डिस्काउंट की सुविधा दी जाएगी।

सोमवार की बैठक में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और दिवालिया कानून (आइबीसी) का भी मुद्दा उठा। वित्त सचिव राजीव कुमार ने बताया कि एनबीएफसी को बैंकों की तरफ से वित्तीय मदद देने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आइबीसी के बारे में बैंकों की तरफ से आने वाली दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा हुई। पिछले तीन वर्षों में आइबीसी के तहत 21,000 मामले एनसीएलटी की विभिन्न बेंच में लाए गए हैं। इतने मामलों को निबटाने के लिए एनसीएलटी के पास ढांचागत सुविधा नहीं है। कुमार ने बताया कि अच्छी खासी चल रही कंपनी को सिर्फ एक शेयरधारक दिवालिया प्रक्रिया में डाल दे रहा है। इस बारे में नए सिर से सोचना होगा। एक सुझाव यह है कि सिर्फ बड़े बकाये (एनपीए-बैंकों के फंसे कर्जे) की राशि वाले मामले को भी दिवालिया प्रक्रिया के तहत आइबीसी में लाया जाना चाहिए। कम बकाये वाले राशि वाले मामले को आइबीसी के दायरे से बाहर सुलझाने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

हाईवे के गड्डे में पलटी कार, चार हॉकी खिलाड़ियों की मौत

होशंगाबाद : मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नेशनल हाईवे-69 स्थित ग्राम ब्यावरा में सोमवार सुबह करीब सात बजे भीषण सड़क हादसे में मप्र हॉकी अकादमी के चार खिलाड़ियों की मौत हो गई। तीन अन्य खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी खिलाड़ी होशंगाबाद के टर्फ मैदान पर चल रही अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता (ध्यानचंद ट्रॉफी) में शामिल होने के लिए इटारसी से आ रहे थे। (पेज-5)

अफवाहें फैलाने वाले संदेशों के स्रोत तक हो एजेंसियों की पहुंच

नई दिल्ली : वाट्सएप के जरिये प्रसारित होने वाले भ्रामक और झूठे संदेशों पर नियंत्रण की पैरवी करते हुए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत एंक्रिप्शन का सम्मान करता है। साथ ही कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों को भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने और अफवाहें व हिंसा फैलाने वाले संदेशों के स्रोत का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान पत्रकारों से बातचीत में रवि शंकर प्रसाद ने कहा, 'हम एंक्रिप्शन का सम्मान करते हैं। (पेज-12)

कोर्ट का आदेश

अहमदाबाद की पारिवारिक अदालत ने कहा, माता-पिता की जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता, बेटे को दस हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देना होगा

संन्यासी को भी निभाना होगा पुत्र धर्म

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

भले ही कोई संन्यासी बन जाए और माया मोह का त्याग कर दे, लेकिन वह माता-पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। गुजारा भत्ते के लिए माता-पिता की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अहमदाबाद की एक पारिवारिक अदालत ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने संन्यासी बने पुत्र को परिजनों की देखभाल करने तथा मासिक दस हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया।

सन्यासी बने धर्मेश गोल (27) ने प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआइपीआर) से फार्मेसी में मास्टर डिग्री प्राप्त की और जून 2015 में एक आकर्षक कारपोरेट नौकरी को ठुकराकर संन्यासी बन गए। वह भाडज स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा (इस्कॉन मंदिर) से जुड़कर भगवान श्रीकृष्ण का प्रचार-प्रसार करने लगे। धर्मेश गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अक्षयपात्र से भी जुड़ गए और समाजसेवा के कार्यों में भाग लेने लगे। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में रहने वाले पिता लीलाभाई (64) और माता भीखीबेन (55) से सभी संबंध तोड़ लिए। लीलाभाई और भीखाबेन ने धर्मेश को खूब तलाश किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। माता-पिता का आरोप है कि उनके बेटे के संन्यासी बनने की जानकारी इस्कॉन मंदिर वालों ने भी नहीं दी। आखिरकार पुलिस की मदद से पता चला कि उनका बेटा इस्कॉन मंदिर भाडज में सन्यासी बनकर रह रहा है।

गुजारा भत्ते के लिए माता-पिता ने दायर किया मुकदमा : बेटे को घर लौटने के लिए मनाने में विफल रहने के बाद माता-पिता ने अहमदाबाद की पारिवारिक अदालत में 50,000 रुपये गुजारा भत्ते के लिए मुकदमा दायर कर दिया। माता-पिता ने अदालत से कहा कि वे दोनों शारीरिक रूप से अक्षम हैं और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। पिता चार साल पहले सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी बचत बेटे की उच्च शिक्षा पर इस आशा से खर्च कर दी थी कि वह उनकी देखभाल करेगा। माता-पिता ने धर्मेश की पढ़ाई पर 35 लाख रुपये खर्च करने का दावा किया। माता-पिता ने दलील दी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेश 60,000 रुपये महीने वेतन की नौकरी को ठुकराकर इस्कॉन में सन्यासी बन गया।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका बेटा विभिन्न संस्थानों में व्याख्यान देता है और एनजीओ के लिए धन जुटाने का काम करता है। उनका दावा है कि धर्मेश ऐसा कर एक लाख रुपये जुटाता है। चूंकि इस मामले में धर्मेश ने बहस नहीं करने का फैसला किया था, इसलिए अदालत ने माता-पिता की दलील सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि धर्मेश ने बिना किसी कारण के माता-पिता को छोड़ दिया। दोनों बुजुर्ग असहाय स्थिति में हैं, क्योंकि बेटे ने उनके गुजारा भत्ते का कोई प्रबंध नहीं किया था। ऐसे में उसे माता-पिता को प्रति महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देना होगा।

> पारिवारिक अदालत द्वारा भरण-पोषण के संबंध में जितने पैसे देने की बात कही गई, वह नाकाफी है। ऐसे में हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
> **-लीलाभाई, संन्यासी बने पुत्र धर्मेश के पिता**

कश्मीर में बोले सूफी संत, मुस्लिमों के लिए दुनिया में भारत से बेहतर कोई मुल्क नहीं

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- सूफी संतों ने कहा, पाक कर रहा है कश्मीर पर दुष्प्रचार
- चिश्ती बोले-हर मुसलमान करे देश की परवाह

ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के मुख्य संरक्षक और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान के उत्तराधिकारी सईद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं है। यहां रहने वाले मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित हैं।

उन्होंने कहा, पाक के पीएम इमरान खान जिस जिहाद के लिए मुस्लिमों को उकसा रहे हैं, वह शर्मनाक है। इमरान बदसुलूकी का हवाला देकर बयान देते रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन व चीन में मुसलमानों की अनदेखी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। उन्हें इन दोनों देशों के खिलाफ जंग शुरू करनी चाहिए। सईद नसीरुद्दीन ने कहा, भारत में हरेक मुसलमान को अपने देश की परवाह करनी चाहिए। कुछ दिनों में वह कश्मीर में कई जगह पर गए। लोगों से मिले, उनसे बातचीत भी की लेकिन किसी ने भी मानवाधिकार उल्लंघन का मामला नहीं उठाया। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर कश्मीर के बारे में जो दुष्प्रचार कर रहा है, वह गलत है। कश्मीर में मोबाइल सेवाएं जरूर ठप थीं, जिससे लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन जब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं तो ऐसे प्रतिबंध स्वाभाविक है।

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के मुख्य संरक्षक व अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान के उत्तराधिकारी सईद नसीरुद्दीन चिश्ती (बाएं)।

मीडिया प्रभारी बोले, कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य पेज>>6

कश्मीर में 72 दिन बाद बजी मोबाइल की घंटी

जम्मू : कश्मीर के तेजी से सुधरते हालात के बीच सोमवार को प्रशासन ने 72 दिन बाद पोस्टपेड मोबाइल सेवा को बहाल कर दिया। इसके साथ ही कश्मीर में 40 लाख पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन शुरू हो गए हैं। लोग एक-दूसरे को मोबाइल सेवा शुरू होने की बधाई देते दिखे। हालांकि प्रीपेड व मोबाइल इंटरनेट सेवा अब भी बंद है। (पेज-6)

11 नवंबर को किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के तीसरे दीक्षा समारोह का आयोजन। स्थापना के 50वें वर्ष का जश्न मना रहे जेएनयू के इस दीक्षा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू शिरकत करेंगे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 15 अक्टूबर 2019

आज से राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटेगा ग्रेप

सख्ती ▶ डीजल जेनरेटर पर रहेगा प्रतिबंध, निगरानी टीमें भी बढ़ाएंगी रात्रि गश्त, प्रावधान 15 मार्च तक रहेंगे मान्य

प्रदूषण रहित जिग जैग तकनीक नहीं अपनाने वाले ईंट-भट्ठे भी बंद रहेंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ रही आबोहवा से अब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) निपटेगा। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने मंगलवार से इसे लागू करने की औपचारिक घोषणा कर दी है। यह प्लान 15 मार्च तक लागू रहेगा। इस प्लान में चार अलग-अलग चरणों के तहत वायु प्रदूषण की विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के प्रावधान हैं। इसके साथ ही शादियों का मौसम सिर पर होने के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। प्रदूषण रहित जिग जैग तकनीक नहीं अपनाने वाले ईंट-भट्ठे भी बंद रहेंगे। प्रदूषण जांच केंद्रों को भी सख्ती बरतने के आदेश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि हवा की दिशा में बदलाव के कारण दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में चल रही है। अगले कुछ दिनों में यह खराब और बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। सफर इंडिया और मौसम विभाग दोनों ने इस आशय का पूर्वानुमान भी जारी किया हुआ है। ईपीसीए ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सभी को साफ कर दिया गया है कि अबकी बार ग्रेप के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

ईपीसीए सदस्य सुनीता नारायण ने बताया कि डीजल जेनरेटर सेट पर प्रतिबंध को लेकर पहली बार दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा रहा है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी जगह डीजल जेनरेटर सेटों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। हालांकि एनसीआर के सभी शहर इस बार भी पूरी तैयारी न होने के नाम पर छूट की मांग कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक होटल, रेस्तरां और ढाबों में कोयला और लकड़ी जलाने पर भी रोक रहेगी। हॉट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर पर धूल बैठाने वाले उपाय किए जाएंगे। वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब होने से बचाने के लिए पानी के छिड़काव और मैकेनाइज स्वीपिंग जैसे उपाय भी पहले से उठाए जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 46, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की 16 टीमों सहित स्थानीय निकाय भी खुले में आग जलाने, कंस्ट्रक्शन साइटों पर हो रही लापरवाही पर नजर रखेंगे। ट्रैफिक पुलिस प्रदूषण फैला रही गाड़ियों का चालान करेंगी। ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने कहा कि रात के अंधेरे में भी प्लास्टिक, रबड़ और प्रतिबंधित ईंधन नहीं जलने दिया जाएगा। रात्रि गश्त की टीमों का गठन किया जा चुका है, नियमित निरीक्षण भी चल रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। जिन औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का इस्तेमाल होता पाया जाएगा, उन्हें सील किया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से जंग के लिए इस बार 19 हॉट स्पॉट चिह्नित किए गए हैं। इन जगहों की विशेष निगरानी की जाएगी। ईपीसीए ने इन सभी जगहों के लिए अलग से एक्शन प्लान बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। एक्शन प्लान में इन सभी जगहों पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों और उन्हें दूर करने के उपायों की पूरी जानकारी रहेगी।

राजधानी की फिजां में अब पराली जलाने का असर दिखने लगा है। सोमवार को धुंध से ओझल दिख रहा है कनॉट प्लेस का पूरा इलाका। संजय

पड़ोसी राज्यों से आ रहे धुएं ने बढ़ाया दिल्ली में प्रदूषण : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। पिछले चार साल में प्रदूषण के रोकथाम के लिए सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले चार महीने में दिल्ली की हवा का गुणवत्ता गुड की श्रेणी में रही। मगर अब दूसरे राज्यों से आने वाला धुआं फिर से प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहा है। वहां खुलेआम पराली जलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं सभी सरकारों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो प्रदूषण को बढ़ने से रोकें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी समेत सभी संस्थाओं से गुजारिश करते हुए कहा कि प्रदूषण रोकथाम के लिए वह कुछ करें। केजरीवाल ने कहा कि ऑड-इवेन हमेशा के लिए लागू नहीं कर सकते। लेकिन, नवंबर में दिल्ली सरकार 4 से 15 तक ऑड-इवेन लेकर आ रही है।

स्कूली बच्चों में मास्क बांटेगी दिल्ली सरकार : मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि उन्हें दिल्लीवालों की चिंता है। प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है।

दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ी हवा से बढ़ी केंद्र की बेचैनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर की तेजी से खराब हो रही आबोहवा ने केंद्र की बेचैनी बढ़ा दी है। यह स्थिति तब है, जब इससे निपटने के लिए पहले से ही काफी तैयारियां और बैठकें हो चुकी हैं। अब केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित उसके सभी पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की 19 अक्टूबर को एक अहम बैठक बुलाई है।

हालांकि, पर्यावरण मंत्रालय में सोमवार को पूरे दिन दिल्ली- एनसीआर की हवा को लेकर चली लंबी बैठकों में पिछले साल के मुकाबले हवा की गुणवत्ता में सुधार के दावे किए गए। यह उम्मीद भी जताई गई कि इस बार हवा की गुणवत्ता खराब के स्तर से और नीचे नहीं जाएगी। दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा में इस बार बदलाव का सिलसिला एक अक्टूबर के बाद से शुरू हुआ। एक अक्टूबर को हवा में पीएम (पार्टिकुलेट मैटर)-10 की मात्रा 90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। जो दो अक्टूबर को बढ़कर 101 हो गई। सोमवार तक स्थिति और खराब हो गई और पीएम-10 की मात्रा 222 तक पहुंच गई है।

बता दें कि हवा की गुणवत्ता के खराब या बेहद खराब स्तर का आकलन पीएम-10 और पीएम-2.5 के स्तर के आधार पर किया जाता है। हवा की अच्छी गुणवत्ता के लिए पीएम-10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे कम होना चाहिए।

मौसम का बदला मिजाज भी कारण : पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक हवा की गुणवत्ता में जिस तरह से बदलाव आया है, उसके पीछे सिर्फ पराली ही वजह नहीं है, बल्कि मौसम में आया बदलाव भी एक बड़ा पहलू है। मौसम में बदलाव के चलते हवा की चाल धीमी हो गई है जिसके चलते दिल्ली और एनसीआर में पैदा होने वाला प्रदूषण बाहर नहीं निकल पा रहा। पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की घटनाओं को लेकर ब्योरा मांगा है।

हकीकत जानने जाएगी टीम : बैठक में मौके की हकीकत को देखने के लिए कृषि और पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम भी दोनों राज्यों में भेजने को लेकर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि यह टीम 19 अक्टूबर से पहले दोनों ही राज्यों के पराली के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर सकती है। दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर केंद्र एक मुहिम भी छेड़े हुए है। इसके तहत करीब 12 सौ करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया है।

हर जोन में दिन-रात होगी प्रदूषण फैलाने वालों पर निगरानी

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। इसलिए स्थानीय निकाय प्रदूषण का स्तर कम करने में जुट गए हैं। इसके लिए निगमों ने विस्तृत योजना बनाकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सहायक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रत्येक जोन में उपायुक्त को निर्देश देकर कहा गया है कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्रवाई करें। उन स्थानों पर छिड़काव के भी आदेश दिए हैं जहां से धूल उड़ने की शिकायतें रहती हैं। साथ ही दिन-रात प्रदूषण फैलानों वालों पर निगरानी रखने को भी कहा गया है।

ई-ऑटो चलाने के लिए ईपीसीए ने दी सहमति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

ई-रिक्शा के बाद अब दिल्ली में ई- ऑटो भी चल सकते हैं। 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के इस प्रस्ताव पर निकट भविष्य में मंजूरी मिल सकती है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है। हालांकि ईपीसीए ने इसके परिचालन से पूर्व इस दिशा में एक विस्तृत पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट से 15 हजार ई-ऑटो चलाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने इस पर ईपीसीए से रिपोर्ट देने को कहा था। सोमवार को ईपीसीए ने इंडिया हैबिटेट सेंटर स्थित कार्यालय में इस पर बैठक की। इस बैठक में ईपीसीए ने प्रस्ताव को तो सही बताया, लेकिन पुरानी बैटरियों के निस्तारण, बैटरी चार्जिंग, पार्किंग एवं किराया आदि तमाम मुद्दों पर विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा।

डीएमआरसी अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों पर विशेष डिपो बनाकर ई ऑटो उपलब्ध कराने की योजना है। सीएनजी की बजाय यह ऑटो बैटरी से संचालित होंगे। इनसे प्रदूषण भी नहीं होगा। इस पर ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने कहा कि ई ऑटो के परिचालन को लेकर विस्तृत योजना आनी चाहिए। इसकी वजह से मेट्रो ज्यादा महंगी सेवा न हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं, ईपीसीए सदस्य सुनीता नारायण ने कहा कि बैटरी से चलने वाले ई-ऑटो पर यह गाइडलाइंस सामने आनी चाहिए कि इस्तेमाल होने के बाद बैटरियों का क्या होगा। इन्हें चार्ज करने की व्यवस्था कैसे की जाएगी।

सभी मेट्रो स्टेशन से मिलेगी सुविधा : डीएमआरसी की योजना है कि ई- ऑटो को अपने सभी 184 मेट्रो स्टेशनों से उपलब्ध कराए। मेट्रो स्टेशन पर पिक एंड ड्रॉप के लिए विशेष जगह बनाई जाएगी। इनके लिए बनाए गए डिपो में ही ई-ऑटो को चार्ज करने की जगह बनाई जाएगी। फिलहाल पांच एजेंसियां दिल्ली मेट्रो के साथ इस योजना को लेकर संपर्क में हैं।

ई-ऑटो पर एक ही कंट्रोल रूम से निगरानी की बात कही जा रही है। सुनीता नारायण ने कहा कि इसे लेकर ठोस योजना बनानी चाहिए कि सभी ई-ऑटो पर जीपीएस लगा हो और एक ही कंट्रोल रूम से उनकी निगरानी की जा सके। अलग-अलग कंट्रोल रूम होने से उन पर निगरानी रखना एक मुश्किल काम साबित होगा।

नौकरी की गारंटी वाली पढ़ाई कराएगी दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के प्रयास की तमाम योजनाएं शुरू करने के बाद अब दिल्ली सरकार ने नौकरी की गारंटी वाली पढ़ाई कराने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेसवार्ता कर योजना की विस्तृत जानकारी दी।

केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के युवाओं को उद्योगों की जरूरत व नौकरी के हिसाब से तैयार करने के लिए दिल्ली में स्किल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। इसमें डिप्लोमा से लेकर रिसर्च तक की पढ़ाई होगी। छह माह से 2 वर्ष तक के कोर्स होंगे। इस प्रस्ताव को अब उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा से शीतकालीन सत्र में पास कराया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में 85 फीसद सीटें दिल्ली के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। यह देश में इस तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा।

सभी आइटीआइ और पॉलिटेक्निक सेंटरों का होगा विलय : इस विश्वविद्यालय में दिल्ली के सभी आइटीआइ और पॉलिटेक्निक सेंटरों का विलय किया जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि स्कूल स्तर से बच्चे स्किल (हुनर) से संबंधित कोर्स करने को प्रेरित होंगे।

ओखला में स्थापित होगा मुख्यालय : इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय ओखला स्थित टेली टूल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित होगा। इसके कोर्स व फीस को डिजाइन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनेगी।

विदेश, औद्योगिक संघ व उद्योग से विश्वविद्यालय का गठजोड़ होगा : विश्वविद्यालय के छात्रों को नौकरी के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय का दूसरे देशों से गठजोड़ होगा। साथ ही औद्योगिक संघ व उद्योग से गठजोड़ होगा। जिससे इनके हिसाब से छात्रों को तैयार करने में मदद मिलेगी।

जरूरत के हिसाब से बदलेगा कोर्स : विश्वविद्यालय में कोर्स को जरूरत के हिसाब से बदला जाएगा। इसके लिए मार्केट का लगातार रिसर्च होगा। फिर नौकरी के हिसाब से रिसर्च होगा। फिर उसी हिसाब से कोर्स को समय -समय पर बदला जाएगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि विश्वविद्यालय की परिकल्पना फिनलैंड, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर के मॉडल को आधार बनाकर तैयार की गई है।

छात्रों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना मकसद : यह विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, व्यवसाय, कला, संस्कृति और अन्य ऐसे क्षेत्रों में उद्योग के साथ सहयोग के माध्यम से छात्रों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली और व्यावसायिक शिक्षा के बीच की खाई को पाटेगा। यह व्यावहारिक कौशल की कमी को दूर करेगा।

राजधानी में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व साथ में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। जागरण

प्रस्तावित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम

- कौशल विकास मॉड्यूलर कार्यक्रम, व्यापार के आधार पर तीन महीने से बारह महीने तक।
- सीबीएससी के तहत क्रेडिट की पेशकश करने वाले एक से दो साल के विभिन्न ट्रेडों के व्यावसायिक शिक्षा में सर्टिफिकेट प्रोग्राम।
- दो से तीन वर्षों के विभिन्न विषयों में व्यावसायिक डिप्लोमा कार्यक्रम
- वोकेशनल एजुकेशन में बैचलर डिग्री प्रोग्राम।
- पोस्ट ग्रेजुएट, एम .फिल और पीएचडी प्रोग्राम इन वोकेशनल एजुकेशन।
- संस्कृति, व्यवसाय, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बैचलर डिग्री प्रोग्राम और मास्टर डिग्री प्रोग्राम।

गोपाल राय ने कहा- केंद्र के खिलाफ चलाएंगे पोल खोल अभियान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में बढ़ते अपराध और भाजपा शासित नगर निगम की नाकामियां इस बात को साबित करती हैं कि भाजपा दिल्ली की जनता को सुरक्षा एवं स्वस्थ वातावरण देने में सक्षम नहीं है। गोपाल राय ने कहा कि भाजपा नेता दिल्ली में हुई हर घटना को घुसपैठियों के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं तो वे ये बताएं कि कितने बांग्लादेशियों को हत्या, झपटमारी तथा अन्य अपराध करने के अंतर्गत इन्होंने गिरफ्तार किया है। गोपाल राय ने कहा कि आप इनके खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करेगी।

गोपाल राय ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी के साथ हुई लूटपाट की वारदात का हवाला देते हुए कहा कि अगर खुद प्रधानमंत्री की भतीजी सुरक्षित नहीं है, तो देश की आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा क्योंकि यह घटना प्रधानमंत्री के परिवार से जुड़ी थी, तो दिल्ली पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ लिया। लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि इस साल सितंबर तक दिल्ली में दो लाख बारह हजार सात सौ तिहत्तर केस दर्ज किए गए। अधिकतर में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।

चैनलकर्मी और कैब चालक को गोली मारकर लूटपाट के मामले में चार्जशीट दायर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

चैनल कर्मी पर फायरिंग करने और कैब चालक को गोली मारकर सवारी को लूटने के मामले में क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। दोनों मामलों के मुख्य आरोपित शहादरा निवासी तैय्यब की मौत हो चुकी है, जबकि दो आरोपित शाहदरा निवासी शाहिद और साबिर इस समय जेल में हैं। आरोपितों से लूट का सामान भी बरामद किया है। इस मामले में 20 लोगों को पुलिस ने गवाह बनाया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार की तरफ से कोर्ट में 113 पेज की चार्जशीट दायर की गई है।

चार जून की देर रात आइजीआइ एयरपोर्ट से गाजीपुर जाते समय रात में करीब ढाई बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने खिचड़ीपुर के पास पिस्टल दिखाते हुए एक कैब को रुकने का इशारा किया था। कैब नहीं रोकने पर बदमाशों ने चालक पर गोली चला दी थी। गोली कोहनी में लगी तो चालक ने कैब रोक दी। इस पर बदमाशों ने कैब में बैठे साजिद अख्तर से मोबाइल, पर्स, डेबिट व क्रेडिट कार्ड लूट लिया था। आठ जून की रात करीब डेढ़ बजे इन दोनों के अलावा एक अन्य बदमाश ने बारापुला फ्लाई ओवर पर एबीपी न्यूज चैनल कर्मियों की कैब को रोक कर लूटपाट का प्रयास किया था। यहां भी कैब न रोकने पर बदमाशों ने चालक पर गोली चलाई थी।

क्राइम ब्रांच की टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज खंगाल 500 से अधिक बदमाशों से पूछताछ की थी। 17 दिनों की जांच के बाद शाहिद को 26 जून को पकड़ा गया था। उससे पूछताछ के आधार पर तीन जुलाई को तैय्यब को पकड़ा था।

राष्ट्रीय स्तर के शूटर की संदिग्ध हालात में मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पुल प्रह्लादपुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के शूटर की मौत का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में मौत का कारण नहाने के दौरान गीजर से करंट लगना बताया जा रहा है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रियांशु (15) तुगलकाबाद स्थित डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। वह पुल प्रह्लादपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। रविवार दोपहर वह गेस्ट हाउस में कमरे के बाथरूम में नहाने के लिए गए थे। संभवतः इसी दौरान गीजर से करंट लगने के कारण उनकी मौत हुई। उनके साथ में कमरे में रुके हुए यश ने बताया कि जब प्रियांशु नहाने गए तो बाथरूम से उनके चिल्लाने की आवाज आई। इसके बाद उन्होंने गेस्ट हाउस के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। इस पर कर्मचारियों ने तुरंत गेस्ट हाउस की लाइट काट दी और कमरे में पहुंचकर बाथरूम का दरवाजा खोला। बाथरूम में प्रियांशु जमीन पर पड़े हुए थे। उनके मुंह से खून निकल रहा था और उनकी सांसें रुक चुकी थीं। गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है। सोमवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद प्रियांशु का शव परिजनों को सौंप दिया गया। वे अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार गए हैं। प्रियांशु मूलरूप से बिहार के नवादा जिले के छतरवाह गांव के रहने वाले थे। उनके पिता राजेंद्र प्रसाद झारखंड के चक्रधरपुर स्थित हाईस्कूल में प्रिंसिपल हैं। उनकी माता विमला देवी गृहिणी हैं। प्रियांशु देहरादून के एक निजी स्कूल में 11वीं में पढ़ते थे। राष्ट्रीय व राज्य स्तर की शूटिंग प्रतियोगिताओं में वह अब तक 30 मेडल अपने नाम कर चुके थे। तुगलकाबाद में स्थित डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में नॉर्थ जोन चैंपियनशिप में उनकी प्रतियोगिता आठ अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलनी थी। उन्होंने एक ऑनलाइन एप से पुल प्रह्लादपुर के गेस्ट हाउस में कमरा बुक किया था।

कोच व दोस्तों के पसंदीदा खिलाड़ी थे प्रियाशुं : प्रियांशु छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन चुके थे। वह अपने दोस्तों व कोच के भी पसंदीदा खिलाड़ी थे। 10 साल की उम्र से ही उन्होंने शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। उनका छोटा भाई हिमांशु व माता-पिता उन पर काफी गर्व करते थे। प्रियांशु ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था जिसके बाद उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की टीम के लिए हो गया था। पिछले साल उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भी मेडल जीता था। उत्तराखंड निशानेबाजी प्रतियोगिता व ऑल इंडिया शूटिंग मैच में भी अपना परचम लहराया था।

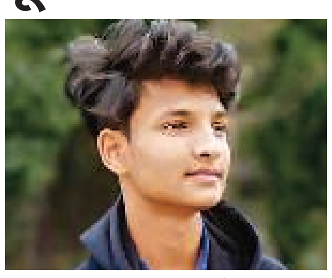

प्रियांशु सौजन्य : परिजन

▶ राष्ट्र व राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिताओं में जीत चुके थे 30 मेडल

अब सरकार ने किया टैक्सियों का भी फिटनेस शुल्क माफ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ऑटो वालों के बाद अब दिल्ली के टैक्सी वालों पर भी मेहरबान हो गई है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को टैक्सी वालों की फिटनेस, जीपीएस और सिम का शुल्क माफ कर दिया। इसके अलावा परमिट शुल्क को 2000 से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इससे करीब 80 हजार टैक्सी वालों को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सचिवालय में बैठक कर इस बारे में फैसला लिया। जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और सरकार की योजना है कि अधिसूचना जारी कर इसे एक नवंबर तक लागू कर दिया जाए। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ उस टैक्सी को ही मिलेगा जो टैक्सी किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत होगी।

सरकार की योजना के अनुसार टैक्सी की फिटनेस शुल्क 600 रुपये है। इसके अलावा जीपीएस की फीस 1420 रुपये और जीपीएस सिम की फीस 584 रुपये है। सरकार ने इसे माफ कर दिया है। इसके अलावा फिटनेस लेट होने पर पहले दिन एक हजार रुपये लगते हैं। इसके बाद प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना देना होता था। मगर अब 1000 की जगह पहले दिन 300 रुपये और 50 रुपये प्रतिदिन की जगह 20 रुपये देने होंगे। टैक्सियों के लिए परमिट शुल्क 2 हजार रुपये है। इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। ऑटो वालों को राहत मिलने के बाद टैक्सी वाले भी इसकी मांग कर रहे थे।

इससे पहले गत 13 अगस्त को केजरीवाल सरकार ने ऑटो की फिटनेस, जीपीएस और डिम्ट्स शुल्क पूरी तरह माफ कर दिए थे। उसके तहत ऑटो वालों को इन तीनों शुल्कों के रूप में कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। सरकार के इस कदम से 90 हजार ऑटो चालकों को फायदा पहुंच रहा है।

रहें सावधान

एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने कहा- यदि अचानक आवाज लड़खड़ाने लगे तो हो सकता है लकवा का लक्षण

जिम में संभलकर करें व्यायाम, लापरवाही से हो सकता है लकवा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

शहरों में जिम का चलन तेजी से बढ़ा है। शरीर को सेहतमंद रखने के लिए व्यायाम जरूरी भी है, लेकिन जिम में भारी भरकम उपकरणों से संभलकर व्यायाम करें। जिम में लापरवाही व व्यायाम का गलत तरीका लकवा जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। एम्स में ऐसे मामले सामने आए हैं। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिम में व्यायाम करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश में लकवा की बीमारी बढ़ रही है। युवा भी इससे पीड़ित हो रहे हैं। हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। हर दो मिनट पर देश में लकवा से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण लोगों में जागरूकता का अभाव व समय पर इलाज नहीं मिलना है। मौजूदा समय में यदि लकवा होने के 24 घंटे के अंदर भी मरीज अस्पताल पहुंच जाए, तो उसका इलाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि लकवा के 14 फीसद मामलों में जिम, डांस सहित हादसा इस बीमारी का कारण बनता है।

लकवा से पीड़ित 25 फीसद मरीज होते हैं युवा : डॉ. एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने कहा कि जीवनशैली लकवा का बड़ा कारण बन रहा है। जिसमें गलत खानपान भी शामिल है। यह देखा गया है कि अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले लकवा के मरीजों में करीब 25 फीसद युवा होते हैं। जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम होती है। इस बीमारी से पीड़ित हर चौथा मरीज कम उम्र का होता है। गलत जीवनशैली के कारण युवा इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं।

अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाए तो न करें नजरअंदाज : एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के डॉ. रोहित भाटिया ने कहा कि अक्सर लोग इस बीमारी के लक्षण पहचान नहीं पाते। दरअसल अचानक आवाज लड़खड़ाने लगे, आंख के समाने अंधेरा छा जाए और दिखाई न दे, चलने में परेशानी होने लगे, अचानक तेज दर्द व चक्कर आए तो इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह लकवा का लक्षण हो सकता है।

जिला अस्पतालों में प्राथमिक इलाज की हो सुविधा : डॉक्टर कहते हैं कि यह देखा गया है कि ज्यादातर लकवा पीड़ित समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। इसलिए इलाज का फायदा नहीं होता। खासतौर पर दूरदराज के इलाकों में यह समस्या अधिक है। इसलिए जिला अस्पतालों में स्ट्रोक के प्राथमिक इलाज की सुविधा विकसित करना जरूरी है। इसके तहत सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, मस्तिष्क के नसों में ब्लॉकेज दूर करने की दवा और एक ऐसा डॉक्टर होना जरूरी है जो सीटी स्कैन देखकर दवा दे सके। इससे मरीजों का इलाज सुनिश्चित हो सकेगा।

लकवा से बचने के लिए यह उपाय जरूरी : रक्तचाप, मधुमेह व कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखें। धूमपान व शराब का सेवन न करें। हरी सब्जियों व फलों का इस्तेमाल अधिक करें। मोटापा से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें।

ब्रेन स्टोक के बाद लकवा से पीड़ित होने वाले मरीजों का कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एम्स और आइआइटी दिल्ली के विशेषज्ञों ने आधुनिक उपकरण बनाए हैं। इनमें हाथों का दस्ताना, बाजुओं में पहना जाने वाला ब्रेन नियंत्रित एक्सोस्केलेटन तैयार किया है। ये उपकरण मरीजों के निष्क्रिय हो चुके अंगों में संवेदनाएं पहुंचाकर उनकी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। डॉ. एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। इन उपकरणों की मदद से मरीज लकवाग्रस्त अंगों को अपने दिमाग के बल पर इस तकनीक की मदद से चलाने में सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम अभी ऐसे उपकरणों को अधिक दक्ष बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध उपकरणों के मुकाबले सस्ते होंगे। वह सोमवार को एम्स में ब्रेन स्ट्रोक पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रही थीं।

मरीजों के लिए स्ट्रोक मैप तैयार होंगे : डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए स्ट्रोक मैप तैयार करने जा रही है। ब्रेन मैप के जरिये यह पता चल सकेगा कि ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को किस अस्पताल ले जाना है। डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदूषण और जलवायु का न्यूरो समेत तमाम बीमारियों से क्या संबंध है इसका पता लगाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक शोध कर रहा है। फिलहाल देखा गया है कि प्रदूषण न्यूरो की बीमारियों के लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है।

आज से मिलनी थी नौकरी लेकिन रद हुए नियुक्ति आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मंगलवार से नौकरी पर आने वाले 3788 निगम प्राथमिक शिक्षकों को झटका लगा है। निगम ने नियुक्ति से एक दिन पहले उनके नियुक्ति आदेशों को रद कर दिया है। निगम ने यह कदम केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के निगम प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के परीक्षा परिणाम को रद करने के बाद उठाया है।

कैट के फैसले के बाद दक्षिणी और पूर्वी निगम ने शिक्षकों के नियुक्ति के आदेश रद कर दिए हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त वर्षा जोशी ने कहा कि सोमवार को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की लिस्ट बेवसाइट पर अपलोड की थी। इसको लेकर कुछ कानूनी कार्रवाई हुई है, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं हैं और न ही कोई औपचारिक कोर्ट का आदेश मिला है। आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश मिलने के बाद की जाएगी।

बताया जा रहा है कि एक अभ्यर्थी ने डीएसएसएसबी के परीक्षा परिणाम को कैट में चुनौती दी थी। इसमें अभ्यर्थी ने दावा किया था प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ऑनलाइन हुई थी और अलग-अलग बैच में परीक्षा आयोजित होने के बाद भी कई प्रश्न हर बैच में एक जैसे आए थे। उल्लेखनीय है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की नोडल एजेंसी है। डीएसएसएसबी के परीक्षा परिणाम आने के बाद निगम ने तीनों नगर निगम में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया था। यह परीक्षा 2018 में सितंबर-अक्टूबर माह में चार चरणों आयोजित की गई थी। 29 मार्च, 2019 को इसका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था।

गौरतलब है कि यह तीसरी बार है जब निगम शिक्षकों के भर्ती परीक्षा रद हुई है। इससे पहले दो बार पेपर लीक होने की वजह से सरकार ने इस परीक्षा को रद कर दिया था।

90 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है भारत-नीदरलैंड के बीच 2018-19 में। भारत में निवेश के मामले में नीदरलैंड पांचवां सबसे बड़ा राष्ट्र है। भारतीय मूल के लगभग ढाई लाख नीदरलैंड में निवास करते हैं।

पूजा का अधिकार होने से क्या मुस्लिमों का दावा कमजोर नहीं हो जाता

बड़ा मामला ▸ एकाधिकार जताने पर मुस्लिम पक्ष से संविधान पीठ ने किया सवाल

सवालों से घिरे राजीव धवन ने कहा - कोर्ट उन्हीं से सवाल करता है, हिंदू पक्ष से नहीं

अयोध्या की पुकार
सुनवाई का 38वां दिन

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद का दावा करते हुए एकाधिकार और मालिकाना हक मांग रहे मुस्लिम पक्ष की दलील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि अगर वहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार था तो क्या इससे मुसलमानों का एकाधिकार का दावा कमजोर नहीं हो जाता? सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के लगातार सवालों से मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन झल्ला गए और कहा कि कोर्ट सिर्फ उन्हीं से सवाल पूछता है।

सोमवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी अपील पर बहस पूरी कर ली। मंगलवार को हिंदू पक्ष उनकी दलीलों का जवाब देगा। कोर्ट में आज फिर सुनवाई के शेड्यूल पर चर्चा हुई। जब वकीलों ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि गुरुवार तक सुनवाई पूरी हो जाएगी, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि बुधवार तक सुनवाई पूरी कर लेंगे। हालांकि बुधवार तक सुनवाई पूरी होना मुश्किल है, क्योंकि अभी हिंदू पक्ष को जवाब देना है और उसके बाद कोर्ट वैकल्पिक मांग पर भी सुनवाई करेगा।

यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से विवादित स्थान पर मालिकाना हक का दावा करते हुए राजीव धवन ने कहा कि वहां 1528 से जबसे मस्जिद बनी है, सिर्फ मुसलमानों का ही अधिकार रहा है। मुसलमान ही उस जगह के मालिक हैं। उनका मुकदमा समयबाधित नहीं है।

यह तो इतिहास दोबारा लिखने जैसा : धवन ने कहा कि कोर्ट को मुगल शासन और उसकी वैधानिकता पर नहीं विचार करना चाहिए। यह एक तरह से इतिहास को दोबारा लिखने जैसा होगा, जिससे पिटारा खुल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या दिल्ली में कोई नया शासक आए तो नया इतिहास लिखा जाए। हिंदुस्तान और यूरोप में अंतर है। वहां बहुत युद्ध हुए और जीते गए। उन्होंने अशोक का भी उदाहरण दिया।

इस्लामिक लॉ के कम ज्ञान की टिप्पणी पर पीएन मिश्रा ने एतराज : धवन ने कहा कि कुछ चीजें कुरान और हदीस से चुनकर यह नहीं कहा जा सकता कि कुरान के खिलाफ काम किया गया। वहां लोगों को इस्लामिक लॉ का सीमित ज्ञान है और वे सवाल उठा रहे हैं। इस पर राम जन्मभूमि पुनरोद्धार समिति की ओर से पेश वकील पीएन मिश्रा ने एतराज जताया। मिश्रा ने कहा कि धवन को कम ज्ञान है, तो वह सबके लिए यह बात कैसे कह सकते हैं। हाई कोर्ट ने विचार के तय प्रश्नों में एक प्रश्न रखा था कि क्या मस्जिद इस्लाम के मानकों के मुताबिक है और इसी पर मैंने बहस की। धवन ने कहा कि हाई कोर्ट का यह प्रश्न तय करना गलती थी। धवन ने वहां मस्जिद का दावा करते हुए कहा कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहती है। छह दिसंबर, 1992 को ढहाए जाने के बावजूद उसकी प्रकृति समाप्त नहीं होगी।

चार सौ साल पहले बनी मस्जिद के नीचे खुदाई करना ठीक नहीं : धवन ने कहा कि मस्जिद बनने के 450 साल बाद उसके नीचे खुदाई करके यह पता लगाना ठीक नहीं है कि पहले वहां कुछ था कि नहीं था। उन्होंने हाई कोर्ट के एएसआइ से खुदाई कराने के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि अगर इस तरह होगा तो फिर इन लोगों का कहना है कि 500 मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गईं।

दोबारा बनाई जाए मस्जिद : धवन ने कहा कि कोर्ट अगर वैकल्पिक मांग रखा है तो उनकी यही मांग है कि वहां पांच दिसंबर, 1992 की स्थिति बहाल की जाए। दोबारा मस्जिद बनाई जाए। उन्होंने छह दिसंबर की घटना की निंदा की।

यूं चले सवाल जवाब, झल्लाए धवन

राजीव धवन - 1857 के बाद के रिकॉर्ड से साफ है कि अथॉरिटी ने मुसलमानों के अधिकार को वहां मान्यता दी है। बाबर द्वारा मस्जिद को दिए जा रहे अनुदान को ब्रिटिश सरकार ने भी जारी रखा था। 1886 में हिंदुओं ने मुकदमे में मालिकाना हक का दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने दावा नहीं माना था।

जस्टिस अशोक भूषण - उस मुकदमे में मालिकाना हक नहीं मांगा गया था। चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी गई थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ - वह मुकदमा मालिक घोषित करने की मांग का नहीं था।

राजीव धवन - तो मंदिर बनाने की इजाजत का मतलब क्या होता है? निर्मोही अखाड़ा का सिर्फ पूजा प्रबंधन का अधिकार था। मुसलमानों का वहां कभी मालिकाना हक समाप्त नहीं हुआ।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ - बाहरी अहाते में हिंदुओं का कब्जा था। इस केस में यह स्वीकार्य बात है कि 1855 के आसपास वहां राम चबूतरा बना। पूजा की इजाजत दी गई।

राजीव धवन - मुसलमान लगातार मुख्य द्वार का उपयोग करते थे।

जस्टिस एसए बोबडे - अगर हिंदुओं के पास पूजा का अधिकार था, तो क्या इससे आपका एकाधिकार का दावा कमजोर नहीं होता।

राजीव धवन - लंबे समय तक उस जगह का उपभोग करने के कारण उनके पास पूजा का अधिकार था। लेकिन मालिकाना हक नहीं था। अगर कोई मेरे घर आए और कहे कि क्या मैं आपके यहां हाथ धो सकता हूं और मैं उसे इसकी इजाजत दे दूं। वह रोजाना पांच बार हाथ धोने आए तो क्या वह मेरे घर का मालिक हो जाएगा।

जस्टिस एसए बोबडे - लेकिन कब तक यह जारी रह सकता है।

राजीव धवन - यह अधिकार कितना भी लंबा हो सकता है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ - मामले में कहा गया है कि बैरागी वहां बाहरी अहाते में रहते थे। वहां 1855 में जो रेलिंग लगाई गई थी, वह वहां संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं थी। वह रेलिंग हिंदू और मुसलमान को अलग करने के लिए थी।

राजीव धवन - ऐसा कानून व्यवस्था के लिए किया गया था। यह सवाल तो हिंदू पक्ष से पूछा जाना चाहिए था। जवाब की जिम्मेदारी तो उन पर बनती है। इस केस में कोर्ट मुझसे ही सवाल पूछता है। इन लोगों (हिंदू पक्ष) से नहीं पूछता।

रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन - इस तरह की बात नहीं की जा सकती।

रामलला के वकील के. परासरन - कोर्ट से ऐसे सवाल नहीं कर सकते।

राजीव धवन - मुझसे सवाल पूछे जाते हैं और मैं उनका जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान करे : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दे। फारुकी ने जान के खतरे की आशंका जताई है। सोमवार को जब अयोध्या मामले की सुनवाई खत्म हुई तो मुख्य न्यायाधीश ने पक्षकारों के समक्ष मध्यस्थता पैनल के सदस्य वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचु की ओर से कोर्ट को ज्ञापन भेजे जाने की जानकारी दी। पीठ ने कहा कि इसमें कहा गया है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी ने पंचु को पत्र लिखकर जान के खतरे की आशंका जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले में अहम पार्टी है ऐसे में वह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हैं कि वह फारुकी को तत्काल समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्य भाटी और कमलेंद्र मिश्र ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आदेश का पालन होगा और फारुकी को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से मामले में पेश हो रहे राजीव धवन ने कहा कि फारुकी को खतरा उत्तर प्रदेश सरकार से ही होगा। हालांकि रामलला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने उनकी दलील का विरोध किया। जिस पर धवन ने कहा कि इन लोगों को भी फारुकी का पत्र मिला है जिसमें कुछ वकीलों को हटाने की बात कही गई है। हालांकि कोर्ट ने इन सब बातों पर गौर नहीं किया।

फारुकी ने ही किया था दोबारा मध्यस्थता शुरू करने का अनुरोध : बता दें कि पिछले महीने फारुकी की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता पैनल को पत्र भेजकर दोबारा मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा निर्वाणी अखाड़ा की ओर से भी पैनल को मध्यस्थता शुरू करने का पत्र भेजा गया था। मध्यस्थता पैनल ने इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए निर्देश मांगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन अगर पक्षकार मध्यस्थता जारी रखना चाहते हैं तो जारी रख सकते हैं।

नीदरलैंड के शाही जोड़े से मोदी ने की द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा

▸ पांच दिन की यात्रा पर भारत आए हैं राजा अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। शाही जोड़ा मंत्रियों, अधिकारियों और उद्यमियों के बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ पांच दिन की यात्रा पर रविवार शाम यहां पहुंचा था। 2013 में गद्दी संभालने के बाद राजा अलेक्जेंडर की यह पहली भारत यात्रा है।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शाही जोड़े ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने वाले क्षेत्रों पर चर्चा की। इससे पहले दिन में राष्ट्रपति भवन में शाही जोड़े का भव्य स्वागत किया गया। राजा और रानी मुंबई और कोच्चि भी जाएंगे। पिछले पांच साल के दौरान भारत और नीदरलैंड के संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच 2018-19 में 12.87 अरब डॉलर (करीब 90 हजार करोड़ रुपये) का कारोबार हुआ था। नीदरलैंड भारत में पांचवां सबसे बड़ा निवेशक भी है। 2000-2017 के दौरान उसने लगभग 23 अरब डॉलर का निवेश किया है। नीदरलैंड में लगभग ढाई लाख भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं। शाही जोड़ा मंगलवार को 25वें प्रौद्योगिकी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत करेगा। नीदरलैंड इस सम्मेलन का साझेदार देश है। इसमें नीदरलैंड के लगभग 140 औद्योगिक घराने भाग ले रहे हैं।

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक के दौरान नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ पीएम नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

लोटुशर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू

नीदरलैंड की सहायता से दिल्ली के सन डायल पार्क में बने लोटुशर (लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रियूज) प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को शाही जोड़े की मौजूदगी में शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत बारापुला नाले के पानी के यमुना में गिरने से पहले साफ करने का प्लांट लगाया गया है। 2017 में इस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी।

उप्र के विवि और डिग्री कॉलेजों में मोबाइल का इस्तेमाल प्रतिबंधित

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज

▸ परिसर या क्लास में प्रयोग करने पर जब्त कर लिया जाएगा फोन

▸ शिक्षक कक्षा से बाहर कर सकते हैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल

उत्तर प्रदेश में पठन-पाठन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। कक्षा या परिसर में मोबाइल पर बात करते अथवा वाट्सएप चलाते मिलने पर इसे जब्त कर लिया जाएगा। बाद में इसे अभिभावकों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि मोबाइल रखने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन, उसका प्रयोग परिसर के बाहर ही होगा। छुट्टी होने पर ही परिसर के अंदर मोबाइल का प्रयोग किया जा सकता है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह निर्देश पठन-पाठन को दुरुस्त करने के लिए दिया है।

राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। इसके पीछे एक कारण मोबाइल को भी माना गया है। कक्षा में छात्र-छात्राएं पढ़ने के स्थान मोबाइल से बात करने, फेसबुक चलाने और वाट्सएप पर चैटिंग करने में व्यस्त रहते हैं। कुछ तो पढ़ाई के समय कक्षा के बाहर इधर-उधर बैठकर मोबाइल का प्रयोग करते हैं। नियम के अनुसार, शिक्षक कक्षा से इतर जरूरत पड़ने पर मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सीसीटीवी से होगी निगरानी : उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में वायस रिकॉर्डिंग युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। उसके जरिए छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। हाल के दिनों में उच्च शिक्षण संस्थानों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आयी हैं, जिनसे संस्थान की छवि को धक्का लगा है।

प्रतीकात्मक

> पठन-पाठन का माहौल बनाने के लिए विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेज परिसर में मोबाइल के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। मोबाइल रखने व परिसर के बाहर प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं है।
> **-डॉ. वंदना शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा**

हेलीकॉप्टर हादसे में वायुसेना के दो अफसरों का होगा कोर्ट-मार्शल

नई दिल्ली, एएनआइ : बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत-पाक के बीच उपजे तनाव के दौरान जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाके में अपने ही एमआइ-17 हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराने के मामले में वायुसेना के दो अधिकारियों का कोर्ट-मार्शल होगा। 27 फरवरी को श्रीनगर में बडगाम के पास हुए इस हादसे में वायुसेना के छह जवान शहीद हो गए थे और आम नागरिक की भी मौत हो गई थी। इस मामले में चार अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। इनमें दो एयर कोमोडोर (सेना में ब्रिगेडियर के बराबर) और दो फ्लाइट लेफ्टिनेंट (सेना में कैप्टन के बराबर) शामिल हैं।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि लापरवाही के लिए ग्रुप कैप्टन और विंग कमांडर रैंक के दो अधिकारियों का कोर्ट-मार्शल होगा। श्रीनगर स्थित 154 हेलीकॉप्टर इकाई का यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही दुर्घटना का शिकार हो गया था, जबकि, जहां यह हादसा हुआ वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारत में हमले की कोशिश की थी, जिन्हें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान समेत भारतीय पायलटों ने खदेड़ दिया था। वायुसेना के नवनियुक्त प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने पद संभालने के तुरंत बाद कहा था कि गलती से वायुसेना ने अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराया था और इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हो चुकी है। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर को स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ट उड़ा रहे थे।

ऑनलाइन आरटीआइ पर केंद्र और राज्यों को और चार हफ्ते का समय

▸ सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, कहा-जवाब दाखिल करने के लिए आगे और नहीं मिलेगी मोहलत

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम की वेबसाइट बनाने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र और 25 राज्यों को और चार हफ्ते का समय दिया है। सोमवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह चेतावनी भी दी कि उसके आगे और मोहलत नहीं मिलेगी।

याचिका में ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल के गठन की मांग की गई है, ताकि लोगों, खासकर विदेश में रहने वाले भारतीयों, को आरटीआइ आवेदन दाखिल करने के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और वो ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकें।

जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र और राज्यों की तरफ से इस मामले में अब तक जवाब नहीं दाखिल किए जाने पर नाराजगी भी जताई। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र और राज्यों को 26 अगस्त को हो नोटिस जारी किया था।

शीर्ष अदालत दिल्ली स्थित एनजीओ प्रवासी लीगल सेल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनजीओ का कहना था कि आरटीआइ कानून के सही उद्देश्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब लोगों को सही समय पर सूचना मिले।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल बनाया है। केंद्र ने राज्यों से भी अपने यहां इस तरह की सेवा शुरू करने को कहा था। लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़कर किसी भी राज्य ने ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल का गठन नहीं किया है। आरटीआइ कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभागों से सूचना मांग सकता है और विभागों को 30 दिन के भीतर उसका जवाब देना होता है।

सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने की मांग वाली अर्जी खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार को सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से लिंक करने के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने से मना कर दिया। जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता और भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय को इस संबंध में संबंधित हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, 'हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। मामला मद्रास हाई कोर्ट में लंबित है, आप वहां जाइए।' उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि फर्जी व पेड न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र को फर्जी मीडिया अकाउंट्स को निष्क्रिय करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही फेसबुक इंक की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आधार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से लिंक करने की मांग वाली याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई है।

नौकरियों में गरीब सवर्णों को आयु में छूट की मांग पर सुनवाई नहीं

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को आयु सीमा में छूट देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। याचिका में आर्थिक रूप से गरीबों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के कोटे के तहत आयु सीमा में छूट देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं हैं। केके रमेश नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा कि सेवा के मामले में याचिका का सवाल नहीं है।

देश की पहली दृष्टिबाधित महिला आइएएस अफसर ने संभाला पद

▸ तिरुअनंतपुरम की उप कलेक्टर बनीं प्रांजल पाटिल

▸ पहले प्रयास में ही संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में हासिल की 733वीं रैंक

तिरुअनंतपुरम, एएनआइ : देश की पहली दृष्टिबाधित महिला आइएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल ने सोमवार को तिरुअनंतपुरम की उप कलेक्टर का पद संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के लिए यहां पहुंचने पर प्रांजल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इससे पहले उन्होंने 2018 में एर्नाकुलम में सहायक कलेक्टर के पद पर एक साल तक काम किया था।

पद संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रांजल ने कहा कि उन्हें यहां आकर बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। उन्हें इस जिले को अच्छे से जानने का मौका मिलेगा और वह इसकी बेहतरी के लिए अच्छी योजनाएं बना पाएंगी। उन्होंने अपने सहकर्मियों और जिले के लोगों से भी सहयोग की उम्मीद जताई।

महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली प्रांजल पाटिल की आंखों की रोशनी शुरू से ही कमजोर थीं। लेकिन छह साल की अवस्था में उनकी दृष्टि पूरी तरह से जाती रही। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पाटिल ने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन करने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मास्टर की डिग्री ली थी।

प्रांजल ने 2016 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में 733वां रैंक हासिल किया था। उसके अगले साल की परीक्षा में उनकी 124वीं रैंक आई।

युवाओं को संदेश देते हुए प्रांजल ने कहा, 'हमें कभी पराजित और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने प्रयासों से, हम हमेशा ही जो चाहते हैं उसे हासिल करने में सक्षम होते हैं।'

दृष्टिबाधित आइएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल ने सोमवार को केरल के तिरुअनंतपुरम में उप कलेक्टर के रूप में पदभार संभाल लिया। प्रेट्र

बीएसएफ ने की आधुनिक ड्रोन भेदी प्रणाली की मांग

▸ हाल में सीमा के पास कई ड्रोन देखे जाने के बाद की है यह मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने आधुनिक 'ड्रोन भेदी प्रणाली' की मांग की है ताकि संचालन क्षेत्रों में संदिग्ध हवाई प्लेटफॉर्म्स को नष्ट किया जा सके। हाल में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास कई ड्रोन देखे जाने के बाद बीएसएफ ने यह मांग की है।

बीएसएफ ने ड्रोन का पता लगाने वाली ऐसी प्रणाली की मांग की है जिसमें रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, जैमर और सभी ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए प्रणाली नियंत्रक हों। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ से कहा है कि शत्रु के ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करे। बल से कहा गया है कि जवानों को प्रशिक्षित किया जाए जो जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इन प्रणालियों को संभाल सकें।' बीएसएफ ने ड्रोन भेदी ऐसी प्रणाली की मांग की है जिसे या तो जमीन पर स्थापित किया जा सके या किसी वाहन पर लगाया जा सके। बीएसएफ की मांग में यह भी कहा गया है कि प्रणाली अकेले उड़ रही किसी वस्तु या समूह में उड़ रहे ड्रोन को दूर से ही पहचानने में सक्षम हो और 10 सेकेंड के अंदर लक्ष्य का पता लगा सके।

अनुमान के मुताबिक, भारत में छह लाख से अधिक शत्रु ड्रोन या बिना नियंत्रण वाले यूएवी हैं और सुरक्षा एजेंसियां 'स्काई फेंस' और 'ड्रोन गन' जैसे आधुनिक ड्रोन भेदी हथियारों का विश्लेषण कर रही हैं ताकि इन हवाई वाहनों के माध्यम से आतंकवाद फैलाने या तोड़फोड़ की किसी घटना को रोका जा सके। बता दें कि हाल में पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमा के पास ड्रोन से हथियार गिराने की घटनाएं हुई थीं जिसके बाद सरकार ने सेना को इन ड्रोन को मार गिराने के अधिकार दे दिए हैं।

वाट्सएप ग्रुप पर चाइल्ड पोर्न शेयर करने पर सात पर केस

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने इंटरनेशनल वाट्सएप ग्रुप में चाइल्ड पोर्न (बच्चों की अश्लील तस्वीरें) साझा करने के मामले में सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद केस दर्ज किया गया है। सीबीआइ की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन सेल (आइपीसीसी) को 31 जनवरी, 2019 को जर्मनी के दूतावास से इस संबंध में सूचना मिली थी। जर्मनी ने साचा ट्रेपके नामक अपराधी के बारे में सीबीआइ को जानकारी दी थी। ट्रेपके को जर्मनी में बच्चों के यौन उत्पीड़न और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रसार के आरोप में पांच साल कैद की सजा हुई थी। सीबीआइ ने जांच में पाया कि जिन 29 इंटरनेशनल वॉट्सएप ग्रुप पर चाइल्ड पोर्न को साझा किया जा रहा था, उसमें ट्रेपके भी शामिल था। इन ग्रुप में सात भारतीय मोबाइल नंबर भी शामिल थे।

फैसला

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लिया फैसला, भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले पर जताया एतराज

राजस्थान में मीसा बंदियों की पेंशन व सुविधाएं बंद

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए मीसा और डीआरआइ बंदियों की पेंशन बंद करने का निर्णय लिया है। अब तक प्रदेश में 1120 मीसा और डीआरआइ बंदियों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन, रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल रही थी। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने प्रदेश की सभी स्थानीय निकायों में महापौर एवं सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्णय किया है। इसके तहत अब महापौर एवं सभापति का चुनाव आम जनता के बजाय पार्षद करेंगे। उधर, भाजपा ने गहलोत सरकार के इन दोनों फैसलों की आलोचना की है।

प्रदेश की पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सलाह पर आपातकाल के दौरान जेल गए 1120 मीसा और डीआरआइ बंदियों को लोकतंत्र सेनानी नाम दिया था। भाजपा सरकार ने इन 1120 लोगों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन, यात्रा भत्ता एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया था। इसके लिए सरकार ने लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि योजना लागू की थी। अशोक गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद करने पर विचार करने की बात कही थी। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि तत्काल प्रभाव से मीसा और डीआरआइ बंदियों को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बेवजह का भार थी। इससे बचने वाले पैसे का उपयोग राज्य के विकास में हो सकेगा।

अशोक गहलोत फाइल फोटो

क्या है मीसा व डीआइआर

आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक राजनीतिक बंदियों को आंतरिक सुरक्षा कानून (मीसा, मेंटिनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) के तहत तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने बंदी बनाया था। बाद में जनता सरकार ने इस कानून को समाप्त किया था। आपातकाल के दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स (डीआइआर) के तहत भी राजनीतिक बंदियों को जेलों में बंद किया गया था। हालांकि, अधिकतर राजनीतिक बंदियों को मीसा कानून के तहत ही जेलों में भेजा गया था।

भाजपा ने कहा-यह है ओछी मानसिकता : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीसा व डीआरआइ बंदियों की पेंशन बंद करने पर नाराजगी जताते हुए कहा, मुख्यमंत्री तानाशाही की राजनीति करते हैं। आपातकाल के दौरान इन बंदियों ने लोकतंत्र की रक्षा की थी। सरकार ने पेंशन बंद कर ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। महापौर एवं सभापति का चुनाव अप्रत्यक्ष कराने के निर्णय पर पूनिया ने कहा, कांग्रेस जनघोषणा-पत्र से मुकर गई है।

डीके शिवकुमार की पत्नी और मां को समन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग के आरोपों में घिरे कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने अब शिवकुमार की पत्नी और मां को तलब किया है। इसके पहले ईडी उनकी बेटी से पूछताछ कर चुका है। डीके शिवकुमार फिलहाल जेल में बंद हैं और दिल्ली की स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिवकुमार की पत्नी और मां को गुरुवार को पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। उन्होंने कहा, शिवकुमार से पूछताछ और छापे में मिले दस्तावेजों की छानबीन के बाद 50 लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने मनी लांड्रिंग में उनकी मदद की थी। जल्द ही इन सभी को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कर्नाटक में प्रदर्शन भी कर चुकी है। जबकि ईडी का कहना है कि उसके पास डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लांड्रिंग के पुख्ता सुबूत हैं और इन सुबूतों के आधार पर वह जल्द ही अदालत में आरोपपत्र दाखिल करेगा।

कह के रहेंगे माधव जोशी

70 की उम्र पार कर चुके सबसे ज्यादा सात उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। युवाओं को टिकट देने के मामले में इनेलो सबसे आगे है। उसके 25 उम्मीदवार 40 साल से कम आयु के हैं।

5 हजार रुपये मासिक भत्ता शिक्षित बेरोजगार युवकों को देने का वादा किया है कांग्रेस-राकांपा ने महाराष्ट्र में अपने संयुक्त घोषणा पत्र में। मजदूरों को न्यूनतम 21 हजार रुपये मासिक मजदूरी देने की भी बात कही गई है।

अनुच्छेद 370 हटाने से अनुसूचित जाति को मिलेगा लाभ : मोदी

चुनावी रण ▸ पीएम ने फिर दी चुनौती, हिम्मत है तो 370 बहाल करने का वादा करे कांग्रेस

राफेल के पूजन पर शोर मचाने के लिए भी की विपक्ष की आलोचना की

विजेंद्र बंसल, फरीदाबाद

हरियाणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी दल सिर्फ वोट के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि की जयंती से संत रविदास के नाम पर दलितों को भड़काने वालों ने सत्ता में रहते हुए यह भी नहीं सोचा कि जम्मू-कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि का बेटा चाहे कितना भी पढ़-लिख ले, उसे सरकारी नौकरियों में यह सुविधा नहीं मिलती थी जो पूरे देश में मिलती है। इसका कारण था अनुच्छेद 370। इसे हटाने का लाभ अब इस समाज को मिलेगा।

देश की राजधानी दिल्ली से महज 35 किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ में हरियाणा विधानसभा चुनाव की अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री का संबोधन अनुच्छेद 370 पर फोकस रहा। उन्होंने कहा, 'ये मोदी ही है, जिसने जम्मू-कश्मीर में चार पीढ़ियों से चला आ रहा अन्याय खत्म कर दिया। कांग्रेस को यदि अनुच्छेद 370 से इतना ही लगाव है तो वह इसे बहाल करने का वादा करे। कांग्रेस नेता हरियाणा के लोगों के बीच जाएं और कहें कि चुनाव जीतकर आए तो अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। विपक्ष कहे कि मोदी ने जो किया है, उसको पलट देंगे। हिम्मत है तो अपने चुनाव घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 के बहाल करने की बाबत लिखे।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। ध्रुव कुमार

ये भी कहा

- राफेल के पूजन पर शोर मचाने वाले यह समझ लें कि मोदी को देश की सीमा में तैनात सैनिक बिना गोली-बारूद और हथियार के मारे जाएं, यह मंजूर नहीं।
- तीन तलाक कानून का विरोध करने वालों को यह भी सोचना चाहिए था कि एक भाई और पिता के रूप में मुसलमान इसका कैसे विरोध करते।
- दुनिया को देश की एकता का संदेश मिल चुका है कि अब भारत को बांटा नहीं जा सकता।
- अनुच्छेद 370 और 35ए हटने से जिनके हितों पर चोट हुई है, केवल वही सदमे में हैं।

सैनिकों के प्रदेश में 370 हटाने का मतलब समझा गए पीएम

सभा में पीएम ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए का विरोध करने वाले हरियाणा के गांवों में जाकर उन मां, बहनों, पत्नियों से मिलें, जिनके बेटे, भाई व पति जम्मू-कश्मीर में तैनात थे और उनको आतंकियों ने शहीद कर दिया। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस ने कभी उनसे मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया है, जिन्होंने अपनों को खोया है।

प्रदेश का एक-एक कर्ज चुकाने का वादा कर गए मोदी

सुभाष डागर, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा से अपने रिश्ते का उल्लेख करने से नहीं चूकते। अपनी रैली में बल्लभगढ़ की पथवारी माता को नमन करते हुए कहा कि यहां पर आकर उन्हें ऐसे लगता है, जैसे वह अपने घर में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने उन्हें ऐसे संस्कार दिए हैं, जिनसे वह पूरी तरह से भरे हुए हैं। इन संस्कारों की बदौलत वह एक के बाद एक कदम आगे उठाते जा रहे हैं। उनका इशारा लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिली 10 की 10 सीटों की तरफ था। इसका आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वह हरियाणा का एक-एक कर्ज चुकाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद के सेक्टर-61 में विधानसभा चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अपने पुराने रिश्तों को याद किया। वह 2000 से 2003 तक हरियाणा भाजपा के प्रभारी रहे चुके हैं। पीएम ने इस दौरान यह भी कहा कि उन्होंने प्रदेश में बहुत काम किया है। उन्होंने यहां से बहुत कुछ सीखा है और उन्हें वह सब कुछ याद है। बल्लभगढ़ राजा बलराम उर्फ बल्लू ने बसाया था और उनके वंश के अंतिम राजा नाहर सिंह 1857 की क्रांति के अग्रणी योद्धा थे। उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक पर अंग्रेजों ने फांसी दी थी। उनके बलिदान को भी पीएम याद किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में स्थानीय लोगों को पूरी तरह से यह बताने का प्रयास किया कि वह यहां के इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं। इसलिए उन्होंने यहां पर पैदा होने वाली फसल सरसों, सूरजमुखी, बाजरा को सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने के बारे में बात कही।

भटकाने और भावनाओं की अपनी उम्र पूरी कर चुकी है भाजपा : सैलजा

लोकसभा चुनाव में मिली निराशा को पीछे छोड़ने के लिहाज से हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद अहम बन गया है, मगर पार्टी की चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। इस कठिन दौर में भी पार्टी के हौसले और उम्मीद बुलंद होने का दावा कर रहीं हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री **कुमारी सैलजा** यह कहने से गुरेज नहीं कर रहीं कि सूबे के मुद्दों को लेकर खट्टर सरकार बैकफुट पर है। इसीलिए, भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों को उछालने की कोशिश कर रही है। चुनावी व्यस्तता के बीच कुछ घंटों के लिए दिल्ली आईं सैलजा ने दैनिक जागरण के सहायक संपादक **संजय मिश्र** से खास बातचीत की। पेश हैं इसके अंश...

● **हरियाणा विधानसभा चुनाव को कई राजनीतिक विश्लेषक नो-कांटेस्ट चुनाव मान रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कहां खड़ी है?**

भाजपा हमेशा झूठ की राजनीति करती है और इसी कड़ी में उसका यह प्रायोजित दुष्प्रचार है। सच्चाई यह है कि खट्टर सरकार के खिलाफ जमीन पर जनता की नाराजगी दिख रही है। भाजपा के झूठ का अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में उसने 150 झूठ बोले थे और इस बार यह आंकड़ा बढ़ाकर 250 कर दिया है। खट्टर सरकार की कोई उपलब्धि होती तो भाजपा क्या उस पर वोट नहीं मांगती? आखिर काम पर वोट मांगने से भाजपा क्यों डर रही है? चुनाव को एकतरफा बताने वाले लोग और भाजपा हरियाणा की जनता के विवेक पर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव नतीजे जब आएंगे तो सत्ता पाने के भाजपा के सपने धरे रह जाएंगे।

● **क्या यह हकीकत नहीं कि कांग्रेस का अपना घर ही बंटा हुआ है? चुनाव के दौरान पार्टी में बिखराव तेजी से हुआ है?**

राजनीतिक पार्टियों में चुनाव के समय हमेशा ऐसी कुछ बातें होती हैं, लेकिन आज के दिन हरियाणा में कांग्रेस एकजुट होकर जीत के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की ताकत इसके लाखों कार्यकर्ता हैं। पार्टी के बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी सूबे में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

● **कांग्रेस खट्टर सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बना रही है, मगर विमर्श में तो अनुच्छेद 370 और तत्काल तीन तलाक कानून जैसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। क्या आपके लिए यह मुश्किल चुनौती नहीं है?**

राष्ट्रीय मुद्दे को राज्य में उठाने की यह कोशिश जाहिर करती है कि सूबे के मसलों पर चर्चा करने की भाजपा की अब हिम्मत नहीं है। पांच वर्षों में इन्होंने लोगों का काम किया नहीं तो हरियाणा के मुद्दों की बात करेंगे कैसे। चाहे अनुच्छेद 370 हो या एनआरसी, पांच साल हरियाणा में इनकी कोई बात नहीं हुई। फिर मौजूदा चुनाव में इन्हें उठाना महज नाटक है। इससे साफ है कि हरियाणा के मुद्दों पर भाजपा बैकफुट पर है और उनके जिक्र से भाग रही है।

● **मगर पिछले कुछ समय में यह देखा गया है कि सूबों के चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे हैं। क्या कांग्रेस इनकी अनदेखी का जोखिम नहीं उठा रही?**

भाजपा देश में भटकाने और भावनाओं की राजनीति करती रही है। अब उसकी यह सियासत चरम पर पहुंच गई है, जहां से इसका गिरना तय है। जनता भाजपा के इस खेल को बखूबी समझ चुकी है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि भटकाने और भावनाओं की भी अपनी एक उम्र होती है। भाजपा के साथ मनोहर लाल खट्टर सरकार अपनी यह उम्र पूरी कर चुकी है।

● **राष्ट्रीय मुद्दों को सूबे के चुनाव में आप प्रासंगिक नहीं मानतीं तो कांग्रेस के लिए अहम चुनावी सवाल क्या हैं?**

हरियाणा के मुद्दे जो यहां के लोगों से ताल्लुक रखते हैं, वे हमारे लिए सबसे अहम हैं। बेरोजगारी, युवाओं में नशे की लत, राज्य में हावी होते ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया व भ्रष्टाचार जैसे मसले बेहद ज्वलंत हैं, जिनका हल तत्काल जरूरी है। किसानों की हालत काफी खराब है। कृषि लागत दोगुनी हो गई है, जबकि आमदनी पहले से भी ज्यादा घट गई है। अपराध और महिला अपराध में हरियाणा एकदम ऊपर आ गया है। दलित वर्ग के साथ न्याय नहीं हुआ। किसी गरीब दलित को घर बनाने के लिए एक गज का भी प्लाट नहीं दिया गया। असलियत है कि भाजपा ने सूबे के सभी वर्गों को छला है।

● **चुनावी गर्मी में अब सियासी पार्टियां भाषा की मर्यादा लांघ रहीं हैं। क्या यह उचित है?**

लोकतंत्र में राजनीतिक और वैचारिक विरोध विमर्श का केंद्र होता है। इसमें दुश्मनी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा ने हमारे प्रजातंत्र में विरोध और दुश्मनी के बीच का अंतर मिटा दिया है। इसीलिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत भाजपा के बड़े नेता शिष्टाचार की सीमाएं लांघ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भद्दी और अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। खट्टर साहब ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में जो ओछी टिप्पणी की है, वह उनकी और भाजपा की मानसिकता को दर्शाती है। यही कारण है कि हरियाणा में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब सूबे का मुखिया ही महिला की इज्जत नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा।

चुनाव आयोग चाहे कुछ कर ले, फरसा रहेगा साथ : जयहिंद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : कंधे पर फरसा लेकर जनसभाओं में पहुंचने से विवादों में आए आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रधान नवीन जयहिंद ने फतेहाबाद के रिटर्निंग अधिकारी को तीखा जवाब भेजा है। जयहिंद ने कहा कि चुनाव आयोग उन पर चाहे जो एक्शन ले, वह फरसा नहीं छोड़ेंगे।

फतेहाबाद में आयोजित जनसभा में फरसा लेकर पहुंचने पर रिटर्निंग अधिकारी ने जयहिंद को नोटिस थमाते हुए दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा था। लिखित जवाब में आप प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यह फरसा मैंने आत्मरक्षा के लिए अपने साथ रखा हुआ है। क्या कानून व संविधान की पालना चुनाव के दौरान व पहले अलग-अलग होती है। उन्होंने कहा कि फरसा एक धार्मिक चिह्न है। चुनाव आयोग के लिए अगर फरसा शस्त्र है तो गदा भी तो शस्त्र है जिसे सत्तारूढ़ पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से बड़े नेताओं को दे रहे हैं। फिर उन्हें नोटिस क्यों नहीं थमाया जा रहा।

राहुल ने राफेल और अर्थव्यवस्था के मुद्दों को फिर दी धार

सत्येंद्र सिंह, नूंह

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों के लिए मुस्लिम बहुल नूंह में आयोजित हरियाणा की अपनी पहली रैली में एक-एक कर उन तमाम मुद्दों को फिर से धार दी, जिन्हें वह लोकसभा चुनाव के दौरान उठाते रहे। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों रहे। राफेल, अर्थव्यवस्था व बेरोजगारी को लेकर उन्होंने तीखे व्यंग्य किए और सत्ता में आने पर किसानों की कर्ज माफी का वादा भी किया।

सोमवार को ही दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) की रैली में अनुच्छेद 370 पर राहुल और कांग्रेस को घेरा था, लेकिन राहुल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने देश और प्रदेश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र व राज्य सरकार की तीखी आलोचना की। नोटबंदी, जीएसटी व कुप्रबंधन को इसकी वजह बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ द्वारा राफेल की पूजा पर वह संतुलित रहे। बोले, मीडिया कहीं राफेल की पूजा दिखा रहा है कहीं कुछ दिखा रहा है। तेजी से बढ़ती बेरोजगारी, देश व प्रदेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, किसानों व गरीबों से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं।

मोदी मन की, हम करते हैं काम की बात : राहुल बोले, मोदी हर दसवें दिन मन की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम काम की बात करते हैं। वही वादे करते हैं जो पूरा कर देते हैं। कांग्रेस की सरकारों ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ व राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ किया। इससे किसानों और गरीबों की क्रय क्षमता बढ़ी, जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। उन्होंने कहा, मोदी जी, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आप युवाओं को बेवकूफ बनाकर लंबे समय तक सरकार नहीं चला सकते। सच्चाई एक दिन बाहर आएगी। फिर देखना क्या होता है। उन्होंने अपनी न्याय योजना का फिर से जिक्र किया।

हरियाणा के नूंह में सोमवार को कांग्रेस की परिवर्तन रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद सोच-विचार में डूबे नजर आए। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। संजय गुलाटी

राहुल ने यह भी कहा

- मोदी की गलत नीतियों के कारण मारुति व टाटा जैसी कंपनियां बंद पड़ी हैं। करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं।
- हमारी लड़ाई विचारधारा की है। हम जोड़ते हैं, जबकि भाजपा और आरएसएस देश को तोड़ने का काम करते है। इनका काम लड़ाने का है।
- मोदी से पूछा, अगर आप खुद को देशभक्त कहते हो तो पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को क्यों अपने अरबपति मित्रों को बेच रहे हो?
- नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी के लाउडस्पीकर हैं।

सही समय आने पर बौद्ध धर्म अपना लूंगी : मायावती

नागपुर, एजेंसियां : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को एलान किया कि वह उचित समय पर बौद्ध धर्म अपना लेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए मायावती ने यहां यह घोषणा की।

रैली में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के फैसले का उल्लेख करते हुए मायावती ने कहा, 'बाबा साहब ने अपने देहांत से पहले अपना धर्म बदल लिया था। आप लोग सोचते होंगे कि कब बहनजी बाबा साहब के रास्ते पर चलते हुए बौद्ध धर्म को अपनाएंगी। मैं कहना चाहती हूं कि मैं भी बौद्ध धर्म की अनुयायी बनने के लिए दीक्षा अवश्य लूंगी लेकिन यह तब होगा जब इसका सही समय आएगा। बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ धर्मांतरण करेंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'धर्मांतरण की यह प्रक्रिया तब संभव है जब बाबा साहब के अनुयायी राजनीतिक जीवन में भी उनके बताए रास्ते पर चलें।'

संघ प्रमुख के हिंदू राष्ट्र के बयान से सहमत नहीं : मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के 'हिंदू राष्ट्र' वाले बयान से सहमत नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर संविधान बनाया था। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी धर्म के लोगों का ख्याल रखा था। आरएसएस प्रमुख को इस तरह का बयान देने से पहले सच्चर समिति की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए।

बता दें कि विजयादशमी के अवसर पर नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है और यहां के मुस्लिम बहुत खुश हैं।

केंद्र की विफल नीतियों से मंदी : बीएसपी प्रमुख ने केंद्र सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विफल नीतियों की वजह से मौजूदा आर्थिक सुस्ती आई है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए दलितों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को रोकने के लिए आंतरिक समझ है। दलितों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए बनाए गए कानूनों को सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया है। इससे देश में वंचितों का शोषण करने वालों को बढ़ावा मिला है।

महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को चुनावी रैली में लोगों का अभिवादन करतीं बसपा सुप्रीमो मायावती। प्रेट्र

सुपरसोनिक स्पीड से भाजपा ऊपर और कांग्रेस जा रही नीचे : राजनाथ

मुंबई, एएनआइ : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भाजपा सुपरसोनिक स्पीड से ऊपर की ओर जा रही है और कांग्रेस उसी स्पीड से नीचे की ओर जा रही है।

महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनाथ सिंह यहां एक रोडशो कर रहे थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पिछले पांच साल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगा रही है। अगर हमारी पार्टी सुपरसोनिक स्पीड से ऊपर की ओर जा रही है तो कांग्रेस सुपरसोनिक स्पीड से नीचे की ओर जा रही है।' ओम लिखकर राफेल युद्धक विमान की शस्त्र पूजा करने के लिए आलोचना का सामना कर रहे रक्षा मंत्री ने कहा, 'जो लोग राफेल युद्धक विमान पर ओम लिखने के लिए मुझसे सवाल कर रहे हैं वे भारतीय संस्कृति को नहीं समझते। ओम हर चीज का उद्गम है और अलग-अलग धर्मों में इसे उनके अपने तरीकों से बताया गया है।'

महाराष्ट्र में बोले योगी, अनुच्छेद 370 का खात्मा आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील

पुणे, प्रेट्र : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी भाजपा के लिए प्रचार करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। सोमवार को लोनावला में चुनावी रैली में योगी ने कहा कि इस अनुच्छेद को खत्म किया जाना आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। भाजपा प्रत्याशी संजय भेगड़े के समर्थन में आयोजित रैली में आदित्यनाथ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाकर प्रधानमंत्री ने 'एक राष्ट्र, महान राष्ट्र' की सोच को हकीकत में बदल दिया है।

महाराष्ट्र

उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद ने पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को नरक में बदल दिया था। आतंकवादी आम लोगों और सैनिकों की हत्याएं कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी ने देश में 'दो प्रधान, दो निशान, और दो संविधान' की सोच का सख्त विरोध किया था। जनसंघ को ही बदलकर बाद में भारतीय जनता पार्टी बनाया गया था।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में काम करने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा भी की, जो पहले सिर्फ नारों तक ही सिमट कर रह गया था। उन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'उज्जवला योजना' जैसी योजनाओं और तीन तलाक को अपराध बनाने के फैसले का भी उल्लेख किया। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि फड़नवीस ने अपनी कई जनकल्याणकारी योजनाओं से राज्य का कायाकल्प कर दिया है। इन योजनाओं से न सिर्फ किसानों को लाभ हुआ है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

योगी ने राज्य में अपराध पर काबू पाने के लिए भी फड़नवीस सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि पहले डी (दाऊद इब्राहिम) कंपनी के बदमाश लोगों से उगाही करते थे। आए दिन बम धमाके होते थे, लेकिन पिछले पांच साल के दौरान सारे बदमाश लापता हो गए और राज्य में सुरक्षित माहौल बना।

महाराष्ट्र के नागपुर में चुनावी सभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते पार्टी कार्यकर्ता। प्रेट्र

- 'एक राष्ट्र, महान राष्ट्र' को हकीकत में बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की
- महाराष्ट्र के विकास और अपराध पर नियंत्रण के लिए फड़नवीस सरकार की पीठ थपथपाई

दांव-पेच

लोकसभा चुनावों में आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण कांग्रेस-राकांपा गठबंधन को हुआ काफी नुकसान

फिर खेल बिगाड़ने को तैयार बैठे हैं प्रकाश आंबेडकर

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र में दलित नेता प्रकाश आंबेडकर एक बार फिर खेल बिगाड़ने वाले दल की भूमिका निभाने को तैयार बैठे हैं। लोकसभा चुनाव में आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के कारण कांग्रेस-राकांपा गठबंधन को करीब एक दर्जन सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार उनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) सूबे की 288 में से 274 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले उनके 65 वर्षीय पौत्र प्रकाश आंबेडकर ने लोकसभा चुनाव में जहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लमीन (एआइएमआइएम) के साथ गठबंधन किया था, वहीं इस बार वह महाराष्ट्र में अकेले ताल ठोंक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एमआइएम के साथ गठबंधन करके लड़ने के कारण औरंगाबाद की एक सीट पर एमआइएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील तो बाजी मार ले गए, लेकिन आंबेडकर का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। इससे खीझे प्रकाश आंबेडकर ने यह कहते हुए एमआइएम से नाता तोड़ लिया कि गठबंधन होने के बावजूद दलित वोट तो एमआइएम को मिल जाते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बाकी गैरमुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं मिलते।

दलित नेता रामदास अठावले के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाने के बाद दक्षिणपंथी विचारधारा से दूरी रखनेवाला नवबौद्ध दलित समाज बेसहारा महसूस कर रहा था। दो साल पहले हुई भीमा-कोरेगांव की घटना के बाद जब इस वर्ग के दलितों की कमान प्रकाश आंबेडकर ने थामी, तो इस वर्ग को नेतृत्व मिल गया। वर्षों से राजनीतिक वनवास झेल रहे प्रकाश आंबेडकर की उसके बाद से पौ बारह हो गई। लोकसभा चुनाव में उन्होंने दलित-मुस्लिम गठजोड़ बनाने के लिए हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेकर वीबीए बनाई। इस गठबंधन ने राज्य में कांग्रेस-राकांपा गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया। वीबीए को लोकसभा चुनाव में करीब 40 लाख से ज्यादा वोट मिले, जिसके कारण कांग्रेस को करीब छह, राकांपा को दो और उनके सहयोगी दल स्वाभिमानी शेतकरी संगठन को दो सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। वीबीए का नुकसान औरंगाबाद में शिवसेना को भी उठाना पड़ा, जहां उसके दिग्गज नेता चंद्रकांत खैरे चुनाव हार गए। इस सीट पर कांग्रेस तो चौथे स्थान पर जा पहुंची थी।

प्रकाश आंबेडकर की वीबीए को करीब आधा दर्जन सीटों पर डेढ़ लाख से ज्यादा और लगभग इतनी सीटों पर एक लाख से ज्यादा वोट मिले थे। 50 हजार से अधिक मत तो उसे कई सीटों पर हासिल हुए थे। स्वयं प्रकाश आंबेडकर सोलापुर और अकोला, दो स्थानों से लड़े थे। सोलापुर में कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की हार का कारण आंबेडकर को 1,70,007 वोट मिलना रहा। अकोला सीट पर भी प्रकाश को 2,78,848 वोट मिले। नांदेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण की हार में भी वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही।

लोकसभा चुनाव में दिखी उनकी इस ताकत के कारण कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उनसे समझौता करना चाहती थी। प्रकाश आंबेडकर कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें देने को तैयार थे। इसके अलावा उनकी एक शर्त यह भी थी कि कांग्रेस उनसे समझौता कर रही है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दे। कांग्रेस को यह शर्त मान्य नहीं थी जिसके कारण उनका कांग्रेस से समझौता नहीं हो सका। अब 274 सीटों पर वीबीए के उम्मीदवार खड़े करके वह चुनाव मैदान में हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी उनकी पार्टी कांग्रेस-राकांपा को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाएगी।

बहरहाल कांग्रेस-राकांपा इससे सहमत नहीं है। युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अभिजीत भोसले कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में आंबेडकर की भूमिका से भाजपा को मिले लाभ की बात अब उनका मतदाता जान चुका है, इसलिए इस बार वह सिर्फ वोट काटने के लिए उनके साथ नहीं जाएगा।

अभिजीत की बात को बल मिलता है- कभी प्रकाश आंबेडकर के ही साथी रहे दलित चिंतक लक्ष्मण माने द्वारा उनका साथ छोड़ देने से। माने साफ कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रकाश आंबेडकर की भूमिका ने उनके समर्थक दलितों को निराश किया है। उन्हें बड़े पैमाने पर मिले वोटों का सीधा लाभ भाजपा को हुआ। माने कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसी कई सीटें हैं, जहां वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोट ले सकते हैं। इसका नुकसान कांग्रेस-राकांपा गठबंधन को ही होगा।

- ओवैसी की पार्टी से गठबंधन तोड़कर आघाड़ी ने अपने दम पर विधानसभा चुनावों में उतारे 288 में से 274 सीटों पर उम्मीदवार
- लोकसभा चुनाव में करीब 40 लाख से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही थी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए

प्रकाश आंबेडकर फाइल

हरियाणा में इनेलो प्रत्याशी ने छोड़ा मैदान भाजपा में शामिल

जागरण संवाददाता, नारनौल : इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के टिकट पर हरियाणा की नारनौल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राजेश यादव सिहार ने चुनाव मैदान छोड़ने के साथ ही भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश यादव का समर्थन किया है। राजेश सिहार ने चितवन वाटिका में सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में इनेलो छोड़कर भाजपा का दामन थामा। जनसभा के मंच पर सीएम ने उनको भाजपा का पटका पहनाकर स्वागत किया। राजेश सिहार ने कहा, 'मैंने 20 साल इनेलो में इमानदारी से सेवा दी है। मेरे साथ भितरघात होने के कारण ईमानदार प्रत्याशी ओमप्रकाश यादव का समर्थन कर रहा हूं।' भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश यादव ने कहा कि राजेश सिहार ने इनेलो छोड़कर भाजपा में आस्था जताई है। इससे हमारी ताकत बढ़ी है। हम उनका सम्मान करते हैं।

45 फीसद तक बढ़ी है पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस साल 630 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। वहीं, पंजाब के कृषि सचिव केएस पन्नू ने कहा कि उपग्रहों से ली गई तस्वीरों की जानकारी सही नहीं है।

न्यूज गैलरी

15 साल से क्या पाखंड के पकौड़े तल रहे थे मोदी : राबड़ी

पटना : पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के जलजमाव मामले में ट्वीट कर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने अपने ट्वीट में कहा कि 15 साल से क्या पाखंड की जलेबी और झूठ के पकौड़े तल रहे थे। ट्वीट में लिखा कि 15 साल में जो आदमी अपने मोहल्ले का नाली ठीक नहीं करा सका वो अब खाक पटना को कठिन दौर से निकालेगा। (राब्यू)

बिहार में एक दिन में बढ़े डेंगू के 177 मरीज

पटना : बिहार में समय बीतने के साथ ही डेंगू का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। महज एक दिन में डेंगू के 177 नए मरीजों की पहचान हुई है। जबकि चिकनगुनिया के भी 15 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की मानें तो पटना में रविवार को डेंगू के मरीजों की संख्या 1135 थी, जो सोमवार को बढ़कर 1273 हो गई। (राब्यू)

संपादक ने मांगी माफी, निरस्त हुई अवमानना की कार्रवाई

नई दिल्ली : तमिल भाषा की एक पत्रिका के संपादक स्वामीनाथन गुरुमुर्ति के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति मनमोहन व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के खिलाफ विवादित लेख लिखने वाले लेखक के माफी मांगने के बाद कार्रवाई निरस्त की। (जासं)

हाईवे के गड्ढे से पलटी कार चार खिलाड़ियों की मौत

दर्दनाक ▶ हॉकी के तीन अन्य खिलाड़ियों की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के थे सभी खिलाड़ी

नईदुनिया, होशंगाबाद

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नेशनल हाईवे-69 स्थित ग्राम ब्यावरा में सोमवार सुबह करीब सात बजे भीषण सड़क हादसे में मप्र हॉकी अकादमी के चार खिलाड़ियों की मौत हो गई। तीन अन्य खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी खिलाड़ी होशंगाबाद के टर्फ मैदान पर चल रही अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता (ध्यानचंद ट्रॉफी) में शामिल होने के लिए इटारसी से आ रहे थे।

जानकारी के अनुसार, उक्त सभी खिलाड़ियों का सुबह साढ़े सात बजे मैच होने वाला था। मैच के लिए पहुंचने में हो रही देरी के कारण कार की गति काफी तेज थी। ब्यावरा के पास एक जीप को ओवरटेक करते समय कार सड़क के गड्ढे में आ गई और अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ से टकराने के बाद कार पलटकर नाले में जा गिरी। हादसे में तीन खिलाड़ियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घायल खिलाड़ियों की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक, हादसे में अनिके

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हादसे में चकनाचूर हो गई कार। नईदुनिया

> हमने अपने होनहार खिलाड़ी खो दिए। मामले की जांच कराई जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से खिलाड़ियों के परिजन को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है।
>
> **– जीतू पटवारी, खेल मंत्री, मध्य प्रदेश**

त पुत्र राजकुमार वरण (17), आदर्श हरदुआ पुत्र आलोक हरदुआ (17), शाहनवाज हुसैन पुत्र हमीद अब्दुल (18) और आशीष पाल पुत्र बाबूलाल (17) की मौत हुई है। साहिल चौरे पुत्र विजय चौरे (19), अजय अवस्थी पुत्र कुल्दीप अवस्थी (18) और शॉन ग्लेडविन पुत्र गिडियन ग्लेडविन (22) की हालत गंभीर है। कार शॉन ग्लेडविन चला रहा था। राज्य सरकार ने मृतक खिलाड़ियों के परिजन को बीमा के पांच-पांच लाख रुपये व दो-दो लाख रुपये की तत्काल सहायता राशि देने की घोषणा की है।

टीम के कोच लोकेंद्र शर्मा भोपाल चले गए थे और खिलाड़ियों को इटारसी जाने की अनुमति सहायक कोच ने दी थी।

पंजाब के पांच पुलिसकर्मियों को रिहा करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने पंजाब पुलिस के पांच कर्मचारियों को रिहा करने का फैसला किया है। पंजाब में आतंकवाद के दौरान की घटनाओं के लिए ये सभी पुलिसकर्मी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। पंजाब सरकार ने इनकी रिहाई के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है।

पंद्रह दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आठ सिख कैदियों को रिहा करने का निर्णय किया था। आतंकवाद के दौरान किए गए अपराध के लिए इन्हें देश की विभिन्न जेलों में बंद रखा गया है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से पांचों पुलिसकर्मियों को विशेष माफी देते हुए उन्हें रिहा करने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। आतंकवाद के दौरान किए गए अपराध के लिए इन पुलिसकर्मियों को सजा मिली थी। अधिकारी ने बताया कि मानवीयता के आधार पर उक्त फैसला किया गया है और आवश्यक कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है।

गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को आठ सिख कैदियों को रिहा करने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा था कि श्री गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती पर मानवीय आधार पर इन कैदियों को रिहा किया जाएगा। मंत्रालय ने उसी दिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को भी उम्र कैद में बदलने की घोषणा की थी।

माल्या–नीरव जैसे भगोड़े दबोचने को इंटरपोल बनाएगा नई रणनीति

राजीव सोनी, भोपाल

- चिली में आयोजित होगी कांफ्रेंस, पांच आइपीएस अफसर पहुंचे
- विदेश में छिपे अपराधियों को भारत लाने पर होगी चर्चा

सेंटियागो (चिली) में इंटरपोल की ओर से आयोजित कांफ्रेंस में इस बार विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को दबोचने की पुख्ता रणनीति बनेगी। आतंकवाद, बैंक, सायबर और संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी देशों के पुलिस व सुरक्षा अधिकारी विचार मंथन करेंगे। 15 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली 88वीं इंटरपोल जनरल असेंबली में सीबीआइ निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला सहित मध्य प्रदेश कैडर के तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी (देश से पांच) भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

इंटरपोल के तत्वावधान में होने वाली इस कांफ्रेंस में इस साल भारत का फोकस देश से भागे लोगों को दबोचने के लिए दूसरे देशों के साथ आम सहमति बनाने पर रहेगा। इसके अलावा इंटरपोल की नीतियों को ज्यादा सशक्त बनाने, दूसरे देशों के कानूनों की जटिलता दूर करने, अपराधियों को संबंधित देश को सौंपने और राजनीतिक उत्पीड़न की आड़ में कानून से भागने वालों को दंडित कराने पर भी विचार-विमर्श होगा। गौरतलब है कि भारत में आतंकी कार्रवाई एवं वित्तीय अपराध कर दूसरे देशों में छिपे लोगों की इंटरपोल के पास लंबी सूची है। इंटरपोल की इस महत्वपूर्ण कांफ्रेंस के लिए भारत से चयनित पांच पुलिस अफसरों में से तीन मध्य प्रदेश कैडर के हैं। इनमें सीबीआइ निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला, मप्र के डीजीपी वीके सिंह एवं सीबीआइ में तैनात मप्र कैडर के साईं मनोहर शामिल हैं। इनके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक एवं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के एक अन्य अफसर भी शामिल हैं।

इंटरपोल जारी करता है रेड कार्नर नोटिस

दूसरे देशों में कानून तोड़कर भागे लोगों को पकड़कर संबंधित देश को सौंपने के लिए इंटरपोल की मदद से ही 'रेड कार्नर' सहित अलग–अलग रंग के नोटिस जारी होते हैं। भारत से भागे किसी भी अपराधी पर कार्रवाई के लिए सीबीआइ ही समन्वय करती है। महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के आधार पर अन्य देशों में इंटरपोल तत्काल कार्रवाई कराता है। अंतरराष्ट्रीय महत्व के आयोजनों की सुरक्षा में भी इंटरपोल की भूमिका रहती है। उल्लेखनीय है कि सभी देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने के लिए ही इंटरपोल का गठन हुआ है। इस समय करीब 190 देश इंटरपोल के सदस्य हैं।

कोर्ट ने दिया आम्रपाली ग्रुप की जब्त संपत्तियों की नीलामी का आदेश

- मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन को दी जिम्मेदारी, अदालत की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी रकम

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बंद हो चुकी आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों की जब्त संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया है। यह जिम्मेदारी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) को देते हुए शीर्ष अदालत ने नीलामी से प्राप्त रकम अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश भी दिया।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने इस मामले में कोर्ट रिसीवर और वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमानी की सलाह पर उक्त आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त रकम से रुकी हुई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी और गृह खरीददारों का भरोसा कायम होगा। अदालत ने कर्ज वसूली न्यायाधिकरण को निर्देश दिया कि वह जब्त संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज एमएसटीसी को सौंप दे ताकि वह उनकी नीलामी कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा राज्य आवासीय बोर्ड को भी शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 34 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया। यह रकम आम्रपाली ग्रुप ने आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए जमा कराई थी। अदालत ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप द्वारा जमा कराई गई कोई भी रकम जब्त नहीं की जाएगी क्योंकि यह गृह खरीददारों का पैसा था जिसे कंपनी ने अन्य जगहों पर स्थानांतरित कर दिया था।

इसी तरह, शीर्ष अदालत ने रायपुर विकास प्रधिकरण को भी 19 करोड़ रुपये अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया। रायपुर विकास प्राधिकरण के वकील ने बताया कि आम्रपाली ग्रुप ने 19 करोड़ रुपये हाउसिंग सोसायटी विकसित करने के उद्देश्य से तीन भूखंडों की लीज के लिए जमा कराए थे। चूंकि समझौता पूरा नहीं किया गया इसलिए प्राधिकरण को अनुबंध रद करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अनुपालन में सुरेखा ग्रुप द्वारा गृह खरीददारों का पैसा नहीं जमाए कराए जाने पर गहरी नाराजगी जताई।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

शीर्ष अदालत सुरेखा ग्रुप के निदेशकों विष्णु सुरेखा, नवनीत सुरेखा और अखिल सुरेखा को निर्देश दिया कि अगर छह हफ्तों में उन्होंने अदालत की रजिस्ट्री में 167 करोड़ रुपये जमा नहीं कराए तो दो दिसंबर को उन्हें अदालत में मौजूद रहना होगा। शीर्ष अदालत ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा आम्रपाली हार्टबीट सिटी की जमीन पर किसी तरह का अधिकार सृजित करने या उसे अलग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। आम्रपाली हार्टबीट सिटी की जमीन की लीज को हाल ही में निरस्त कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता मामले में केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में गुजारे भत्ते के लिए पारिवारिक अदालतों में आने वाले मामलों में पति और पत्नी से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समान मानक प्रारूप तैयार करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'सिटीजन राइट्स ट्रस्ट' की जनहित याचिका पर सामाजिक न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को चार सप्ताह में नोटिस का जवाब देना है। पीठ ने इसके साथ ही पहले से लंबित मामले के साथ इस याचिका को संलग्न कर दिया और इसे चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और अनीता शिनाय को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया। न्यायालय ने ऐसे विवाद में गुजारा भत्ते का निर्धारण करने के लिए पति–पत्नी द्वारा तमाम जानकारियां देने के लिए एक माडल हलफनामा तैयार करने के बारे में न्याय मित्रों को भी सुझाव देने के लिए कहा है।

चिदंबरम ईडी की हिरासत में जाएंगे या नहीं, फैसला आज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम की रिमांड मांगने की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने कहा कि वह फैसला मंगलवार को सुनाएंगे।

इससे पहले ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। ईडी ने याचिका में कहा कि मनी लांड्रिंग एक अलग मामला है और इसमें चिदंबरम को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिए जाने की जरूरत है। चिदंबरम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि सीबीआइ पहले ही हिरासत में ले चुकी है। ऐसे में अब ईडी के हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं है। आरोप है कि पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं।

सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई आज

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइएनएक्स मीडिया घोटाले में आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ सीबीआइ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। जांच एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान चिदंबरम को जमानत तो नहीं दी थी। लेकिन यह कहा था कि चिदंबरम न तो देश से बाहर भाग सकते हैं और न ही सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। सीबीआइ ने हाइ कोर्ट के इस कथन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यह मामला मेंशन हुआ था। सीबीआइ के वकील रजत नायर ने जल्द सुनवाई की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर भी सुनवाई करेगा।

अल्पसंख्यकों के लिए भारत स्वर्ग, पाकिस्तान नर्क : नकवी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारत बना दुनिया में समावेशी विकास–सर्वस्पर्शी सशक्तीकरण का रोल मॉडल

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से मानवाधिकारों की दुहाई दे रहे पाकिस्तान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को तीखा प्रहार किया है। नकवी ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों के लिए नर्क करार देते हुए भारत को स्वर्ग बताया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में समावेशी विकास-सर्वस्पर्शी सशक्तीकरण का रोल मॉडल बन गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि देश के हर जरूरतमंद तक बेहतर शिक्षा, रोजगारपरक कौशल विकास, आधारभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए मोदी सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है। उन्होंने सरकार की अल्पसंख्यक समाज के लिए बनाई गई नीतियों से मिले फायदे का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि एनएमडीएफसी ने पिछले पांच वर्षों में 8 लाख 30 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को विभिन्न रोजगारपरक गतिविधियों, स्टैंडअप, स्टार्टअप आदि के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के किफायती ऋण मुहैया कराए हैं।

नकवी ने कहा कि मोदी सरकार-2 के पहले दिन से ही अल्पसंख्यक मंत्रालय शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में मजबूती से काम कर रहा है। देश भर के मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के 150 से ज्यादा मदरसा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है।

नकवी के अनुसार पांच वर्षों में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से अल्पसंख्यक समाज के रिकॉर्ड 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा छात्र लाभान्वित हुए। इनमें लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं हैं।

उन्होंने कहा कि हुनर के उस्ताद कारीगरों, दस्तकारों व खानसामों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अवसर मुहैया कराने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश के अलग-अलग स्थानों पर 100 हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा।

गुजरात में गांधीजी की हत्या को आत्महत्या बताने के सवाल पर बिफरी कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पार्टी प्रवक्ता रागिनी ने कहा, गांधी को किसी ने नहीं मारा की धारणा बनाने की हो रही कोशिश

कांग्रेस ने सरकारी सहायता प्राप्त गुजरात के कुछ स्कूलों में गांधीजी की आत्महत्या करने के बारे में पूछे गए सवाल को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि हिंदू महासभा और संघ परिवार पर गांधीजी की हत्या के लगे धब्बे को साफ करने की सुनियोजित रणनीति के तहत नई पीढ़ी को झूठ और भ्रम परोसा जा रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने पार्टी की ब्रीफिंग के दौरान गुजरात के 'सुफलाम शाला विकास संकुल' के बैनर तले चल रहे स्कूलों में नौंवी कक्षा की परीक्षा के दौरान गांधीजी की आत्महत्या का कारण पूछे जाने वाले प्रश्न को हैरतअंगेज करार दिया।

उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर है, क्योंकि ये स्कूल गुजरात सरकार की आर्थिक सहायता से चलाए जाते हैं। इसीलिए, कांग्रेस का साफ मानना है कि सूबे की भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसलिए, मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रागिनी ने कहा, ऐसा लगता है कि संघ से जुड़े संगठन अब यह धारणा बनाने में जुट गए हैं कि 'गांधी को किसी ने नहीं मारा।'

रागिनी नायक। फाइल

रागिनी ने कहा कि गांधीजी की हत्या के धब्बे को मिटाने के लिए संघ से जुड़े संगठन लंबे समय से प्रयास करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान गांधीजी को लेकर साध्वी प्रज्ञा का अपमानजनक कथन हो या उनकी 150वीं जयंती के दिन सोशल मीडिया पर हत्यारे नाथूराम गोडसे को अमर रहें कहते हुए ट्रेंड कराने की घटना, इनसे संबंधित संगठनों की सोच जाहिर होती हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, दुर्भाग्य कि बात है कि गोडसे का महिमामंडन करने वाले ऐसे कुछ लोगों को सत्ता के शिखर पर बैठे लोग भी सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। पार्टी की ओर से उन्होंने जनता से गांधीजी के विचारों को संकीर्णता के दायरे में बांधने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ मुखर आवाज उठाने की अपील की।

रागिनी ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के इलाके में किसान की आत्महत्या को बेहद गंभीर बताते हुए भाजपा की नीतियों को किसान विरोधी करार दिया। महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार को आड़ेहाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात खूब की गई, मगर इस सरकार ने कोई चीज दोगुनी की है तो वह किसानों की आत्महत्या है।

ट्रांसजेंडरों को यौन अपराधों से कानूनी सुरक्षा नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार का जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय दंड संहिता ट्रांसजेंडरों को अप्राकृतिक और अन्य यौन अपराधों से सुरक्षा नहीं देता है। याचिका में आइपीसी की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

अधिवक्ता जमशेद अंसारी की तरफ से दायर याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कानून और न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका के मुताबिक आइपीसी की धारा 377 में ट्रांसजेंडर को इसके संरक्षण से बाहर रखा गया है, क्योंकि यह किसी पुरुष, महिला या जानवर के खिलाफ किए गए अप्राकृतिक यौन अपराध से संबंधित है। आइपीसी-1860 ट्रांसजेंडर या तीसरे लिंग के खिलाफ होने वाले अप्राकृतिक अपराध पर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। याचिका में आइपीसी की धारा 8 और 10 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जो लिंग, पुरुष व महिला के शब्दों को परिभाषित करती है। इसमें ट्रांसजेंडर शामिल नहीं हैं। उन्होंने दलील दी कि लिंग पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव गरिमा के लिए अपमानजनक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के जनादेश के खिलाफ है।

पति ने उठाए सवाल तो सरकार के बचाव में उतरीं वित्त मंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य पर विपक्ष के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपने घर में सवालों का सामना करना पड़ा है। सीतारमण के पति ने अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठाए, तो वित्त मंत्री ने उनके सामने भी सरकार का बचाव किया। सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए उनके पति पी. प्रभाकर के एक आलेख पर पूछे सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच सरकार ने कई आधारभूत बदलाव किए हैं और आप उसे आसानी से देख सकते हैं।

सीतारमण ने कहा, 'इस सरकार ने जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) लागू करने और आधार के सिस्टम में व्यापक उपयोग का रास्ता खोलने जैसे बेहद साहसिक फैसले लिए। उज्ज्वला जैसी स्कीम को आठ करोड़ घरों तक पहुंचाकर हमने डिलीवरी सिस्टम की मजबूती दिखाई, करोड़ों घरों को बिजली कनेक्शन देने और कॉरपोरेट टैक्स घटाकर भारत को दुनिया में सबसे कम दर वाले देशो में शामिल करने जैसे फैसले लिए। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। इनकी तरफ देखना और इनकी प्रशंसा करना काफी अच्छा रहेगा।' टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के साथ काम करने वाले प्रभाकर ने अपने आलेख में लिखा है कि राजग सरकार को पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों से सबक सीखनी चाहिए और हर गलती के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।

विवादों में फंसे बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के बारे में वित्त मंत्री ने कहा, 'पूरे प्रकरण पर मेरी पैनी नजर है। इस बारे में आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास से भी बात हुई है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द मामले को सुलझाने की भी बात कही है।

इसके साथ ही सरकार की एजेंसियां इस बात में भी जुटी है कि प्रवर्तकों से ज्यादा से ज्यादा राशि वसूली जाए, ताकि बैंक के ग्राहकों की राशि लौटाई जा सके।' उन्होंने यह भी कहा कि वह आरबीआइ गवर्नर से यह गुजारिश करेंगी कि अगर प्रवर्तकों के पास इतनी ज्यादा राशि है तो ग्राहकों को जल्द से जल्द रकम लौटाने की केंद्रीय बैंक व्यवस्था करे।

समापन

छह दिवसीय चतुर्वेद स्वाहाकार महायज्ञ का हुआ समापन, देश विदेश समेत कई गणमान्य लोगों ने लिया हिस्सा

हर वर्ग के लोग कर सकते हैं वेदों का अध्ययन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विश्व हिंदू परिषद् व अशोक सिंघल फाउंडेशन के तत्वावधान में लक्ष्मी नारायण मंदिर (बिड़ला मंदिर) में छह दिवसीय चतुर्वेद स्वाहाकार महायज्ञ का सोमवार को समापन हो गया। इस महायज्ञ में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ कई देशों के साधु-संतों ने हिस्सा लिया। सोमवार को समापन के मौके पर पूर्ण आहुति सत्र रखा गया था। इसमें भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नॉर्वे, थाईलैंड, सिंगापुर सहित अनेक देशों के वेद प्रेमी लोग शामिल हुए। इतना ही नहीं उन्होंने अपने-अपने देशों में चतुर्वेद महायज्ञ करने के लिए संतों से आग्रह किया। हॉलैंड के प्रिंस लुईस सहित सभी विदेशी अतिथियों ने वैदिक गणवेश में उपस्थित होकर पूजा अर्चना की।

समापन के मौके पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद्र ने बताया कि विश्व के कल्याण के लिए यह यज्ञ है। वेद के विषय में अनेक भ्रांतियां फैली हैं जैसे महिलाएं वेद नहीं पढ़-सुन नहीं सकतीं, कोई विशेष वर्ग नहीं सुन सकता यह सच नहीं है। उन्होंने बताया कि यजुर्वेद के 26वें मंडल के दूसरे अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वेदों का ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नारी, सेवक कोई भी श्रवण, अध्ययन और पठन कर सकता है। दिनेश चंद्र ने कहा कि इसको लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए दिल्ली में पहली बार ऐसा महायज्ञ हुआ है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से यह ऐतिहासिक है। दिनेश चंद्र ने कहा कि आज हमारी संस्कृति बचेगी तभी हमारा भविष्य और भविष्य की संततियां बचेंगी।

श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर (बिड़ला मंदिर) परिसर में चतुर्वेद स्वाहाकार महायज्ञ में दी जाती पूर्णाहूति। पारस कुमार

सोमवार को महायज्ञ में मुख्य यजमान स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, मुनि वत्सल जी महाराज, विहिप केंद्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे एवं विहिप संयुक्त महामंत्री डा. सुरेंद्र जैन और अन्य लोग उपस्थित रहे।

पुलिस की दूसरी टीम ने मुठभेड़ में माफिया को मारा : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

झांसी के पुष्पेंद्र यादव की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर जहां पिछले एक हफ्ते से विपक्ष सरकार पर चौतरफा हमलावर है वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस का बचाव करते हुए दो टूक कहा है कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होगी। उन्होंने कहा कि झांसी में माफिया ने इंस्पेक्टर पर हमला किया और गाड़ी लूटी। पुलिस की दूसरी टीम को जब सूचना मिली तो आमने-सामने की मुठभेड़ में माफिया को मारा गया और कई घायल हुए।

सोमवार को एक न्यूज चैनल को दिये गये साक्षात्कार में मुख्यमंत्री ने पुष्पेंद्र यादव मामले में पहली बार चुप्पी तोड़ी। इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी का दौरा किया था और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए थे। अन्य राजनीतिक दलों ने सरकार और पुलिस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। सोमवार को योगी ने अखिलेश पर पलटवार

योगी आदित्यनाथ। जागरण

करते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए माफिया, गुंडे और अपराधियों को संरक्षण देना अखिलेश यादव की प्रवृत्ति रही है। जो लोग भी सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, सभी इनके सगे थे। अब जबकि कानून के राज में ऐसे तत्वों के अंदर भय पैदा हुआ तो इन्हें बुरा लगना स्वाभाविक है। योगी ने कहा कि पहले इंस्पेक्टर को गोली मारी गई जो अस्पताल में भर्ती थे। बाद में दूसरी टीम ने कार लूट के घटनास्थल से करीब 40 किलोमीटर दूर आरोपित पुष्पेंद्र को रोकने की कोशिश की तो आमने-सामने की मुठभेड़ हुई।

न्यूज चैनल के एंकर की पत्नी की हत्या

जासं, इटावा : उप्र की इटावा सदर कोतवाली क्षेत्र में लड़ैती भवन के पास वाली गली में सोमवार दोपहर एक न्यूज चैनल के एंकर की पत्नी की हत्या कर दी गई। दिल्ली में न्यूज चैनल के एंकर अजितेश मिश्रा की 27 वर्षीय पत्नी दिव्यांशी उर्फ वर्ष घर की तीसरी मंजिल पर रहती थीं। 15 दिन पहले ही वह दिल्ली से ससुराल आई थीं और मंगलवार को वापस जाना था। अजितेश की मां और भाई भी दिल्ली में हैं। दोपहर दिव्यांशी की हत्या हुई तो घर में केवल ससुर थे। उन्हें वारदात की भनक तक नहीं लगी। किसी काम के लिए बहू को आवाज लगाई और जवाब नहीं मिला तो उसके कमरे में पहुंचे। कमरे में दिव्यांशी का शव पड़ा था। ससुर ने जानकारी पड़ोसियों को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। अभी तक हत्यारे और हत्या का कारण नहीं पता चल सका है। दिव्यांशी का मायका शहर के फ्रेंड्स कालोनी में है।

सीओ सिटी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि सिर पर वजनदार वस्तु से प्रहार कर हत्या की गई है। सिर पर चोट के निशान मिले हैं। अलमारी के पास दो बैग अस्त-व्यस्त मिले हैं।

18 अक्टूबर से जम्मू रवाना होने लगेंगे श्रीनगर सचिवालय के तीन दर्जन विभागों के कर्मचारी। जम्मू-कश्मीर के अंतिम दरबार मूव (सचिवालय स्थानांतरण) के लिए श्रीनगर सचिवालय तैयार है। 25 अक्टूबर को सचिवालय में दरबार बंद हो जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 15 अक्टूबर 2019

कश्मीर में 72 दिन बाद बजी मोबाइल की घंटी

सुधर रहे हालात ▶ 40 लाख पोस्टपेड कनेक्शन हुए बहाल, लोगों ने की अपनों से बात

उत्साहित लोगों ने एक-दूसरे को दी मोबाइल सेवा शुरू होने की बधाई

राज्य ब्यूरो, जम्मू

कश्मीर के हालात में तेजी से हो रहे सुधार के बीच सोमवार को प्रशासन ने 72 दिन बाद पोस्टपेड मोबाइल सेवा को बहाल कर दिया। इसके साथ ही कश्मीर में करीब 40 लाख पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन शुरू हो गए हैं। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। लोगों की खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई लोग एक-दूसरे को मोबाइल सेवा शुरू होने की बधाई देते दिखे। हालांकि प्रीपेड और मोबाइल इंटरनेट सेवा अब भी बंद है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने गत शनिवार को पोस्टपेड मोबाइल सेवा को बहाल करने की घोषणा की थी। सोमवार दोपहर को जैसे ही कश्मीर में मोबाइल सेवा शुरू हुई, लोगों ने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों, मित्रों को फोन कर हालचाल पूछा। विशेषकर युवाओं के चेहरों पर मोबाइल शुरू की खुशी साफ झलक रही थी। कई लोगों ने बाहरी राज्यों में पढ़ रहे अपने बच्चों से संपर्क साधा।

कश्मीरी बोले, उम्मीद है अब समान्य रहेंगे हालात : श्रीनगर शहर के निवासी बशीर खान ने कहा कि मैंने अपने पांच-छह रिश्तेदारों को फोन कर 72 दिन बाद उनका हाल चाल लिया। वहीं, एक अन्य युवक अरशद ने कहा कि मोबाइल शोपीस बन चुके थे। मैंने सुबह इसको पूरा चार्ज कर लिया, ताकि दोपहर बाद जैसे ही सेवा शुरू हो अपने सभी दोस्तों से बात कर सकूं। आज मैंने अपनी एक मित्र से आधा घंटा बात की। यह मेरे लिए सुखद पल थे। उम्मीद है अब हालात सामान्य ही रहेंगे और मोबाइल सेवा बंद करने की नौबत नहीं आएगी।

खैरियत है जनाब... कश्मीर के सामान्य हो रहे हालात के बीच सोमवार को प्रशासन ने घाटी में 72 दिन बाद पोस्टपेड मोबाइल सेवा को बहाल कर दी है। इस दौरान अपनों की खैरियत लेते लोग। कामरान रशीद बट

पुलिस और प्रशासन हुए ज्यादा सतर्क

राज्य प्रशासन ने कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरू करने के बाद सुरक्षा प्रबंधों को और कड़ा कर दिया है। पुलिस सतर्कता के साथ हर गतिविधि पर नजर रख रही है। सरकार के प्रवक्ता पहले ही साफ कर चुके हैं कि कश्मीर से 99 प्रतिशत पाबंदियां हटा ली गई हैं। पिछले सप्ताह पर्यटकों के लिए एडवाइजरी को भी वापस ले लिया गया था। कश्मीर में स्कूलों के बाद पिछले दिनों कॉलेज और कश्मीर विश्वविद्यालय भी खोल दिया गया था। चार सितंबर से कश्मीर में 50 हजार लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन बहाल कर दिए गए थे। ऐसे में आतंकी और अलगाववादी शांति भंग न कर सकें। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी निगाह बनाए हुए हैं।

जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ी

पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रशासन ने एहतियातन कश्मीर समेत जम्मू के भी कुछ जिलों में मोबाइल सेवा बंद कर दी थी। जम्मू संभाग में पहले ही मोबाइल सेवा बहाल की जा चुकी है और सबकुछ सामान्य चल रहा है। हालांकि जम्मू में अभी मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद रखा है। उम्मीद है कि कश्मीर में मोबाइल सेवा शुरू होने के बाद हालात की समीक्षा कर जम्मू में मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की जा सकती है।

मीडिया प्रभारी बोले, कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीं काउंसिल के मीडिया प्रभारी दीपक शर्मा ने कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं। देश के विभिन्न भागों से कश्मीर दौरे पर आए सूफी संतों ने स्वयं लोगों के बीच जाकर यह बात देखी है। वे तीन दिनों तक कश्मीर के विभिन्न भागों में स्थित दरगाहों पर गए। कई प्रतिनिधिमंडलों से मिले और लोगों से बातचीत करने के बाद पाया कि पाकिस्तान कश्मीर के बारे में जो दुष्प्रचार कर रहा है, वह सही नहीं है। शर्मा ने कहा कि पहली बार कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला हुआ है और एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। सबकुछ सामान्य है और हालात में तेजी से सुधार हो रहा है।

हालात के बारे में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को देंगे जानकारी : दीपक शर्मा ने कहा कि कश्मीर के हालात के बारे में वे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी जानकारी देंगे। उनका प्रयास होगा कि कश्मीर के लोगों की जो चंद शिकायतें हैं, उन्हें भी दूर किया जाए। उनका यह कश्मीर का पहला दौरा था, लेकिन सूफी परंपरा को बढ़ावा देने और शांति स्थापित करने के लिए वे बार-बार यहां आएंगे।

बंगाल ही नहीं असम, झारखंड और बिहार में भी फैला जेएमबी का जाल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- 2014 में बंगाल में विस्फोट के बाद चर्चा में आया था बांग्लादेशी आतंकी संगठन
- एनआइए के मुखिया ने जताई है चिंता, एटीएस प्रमुखों को सतर्क रहने को किया है आगाह

आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) ने अपना नेटवर्क बंगाल में ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार और असम में भी फैला रखा है। झारखंड में वह प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के सहयोग से पांव पसार रहा है। बिहार में भी इसके आतंकी पकड़े जा चुके हैं। असम के बरपेटा में भी इसने अपना ठिकाना बना लिया था। बंगाल के बर्द्धमान में हुए विस्फोट के मामले में तो अनवर, युसूफ और जहीदुल इस्लाम सहित इसके दस से अधिक आतंकियों को दबोचा गया था। गौरतलब है कि आतंकरोधी दस्तों (एटीएस) के प्रमुखों की बैठक में एनआइए (नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी) के मुखिया योगेशचंद्र मोदी ने जेएमबी के खतरे के प्रति आगाह किया है। उन्होंने पूरे देश में इसके प्रसार के खतरे को रेखांकित करते हुए सतर्क रहने की नसीहत दी है।

बर्द्धमान विस्फोट के बाद हुआ था राजफाश : दो अक्टूबर 2014 को बर्द्धमान जिले के खागड़ागढ़ में बम विस्फोट के बाद पहली बार बंगाल में जेएमबी की सक्रियता का पर्दाफाश हुआ था। विस्फोट की जांच का जिम्मा संभालने के बाद एनआइए ने जब गुत्थी खोलनी शुरू की तो इसका दायरा बंगाल ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की सीमा से लगे कई राज्यों तक जा पहुंचा। बंगाल के कई मदरसों में एक विशेष समुदाय के युवाओं को आतंकी प्रशिक्षण देने के साक्ष्य मिलने के साथ बेहद खतरनाक हथियार तैयार करने का साजोसामान भी मिला था। यह भी पता चला था कि भारत और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ कर दोनों देशों में शरिया कानून स्थापित करने के मकसद से भारत में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी जेएमबी के शीर्ष नेताओं को सौंपी गई थी। जेएमबी ने बंगाल के कई जिलों में आतंकी प्रशिक्षण व बम बनाने का केंद्र भी स्थापित कर लिए थे। आतंकी संगठन के संभावित ठिकानों पर छापेमारी के दौरान इस्लामिक स्टेट (आइएस) से संबंधित कई दस्तावेज मिले थे। इससे आशंका जताई जा रही है कि जेएमबी आतंकियों का आइएस के साथ भी संबंध है। उधर, कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जेएमबी के कई आतंकी पकड़े थे।

बिहार से भी दबोचे गए आतंकी: एनआइए और बिहार पुलिस की जांच में बोधगया ब्लास्ट में जेएमबी के हाथ होने के सुबूत मिले हैं। इसी आधार पर कोलकाता एसटीएफ के इनपुट पर पुलिस ने गया के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के पठान टोली से मो. एजाज अहमद को गत 26 अगस्त को दबोचा था। एजाज अहमद पर जेएमबी के सक्रिय सदस्य के रूप में काम करने की पुष्टि भी हुई है।

पुलिस एजाज से कई आपत्तिजनक समान भी बरामद कर चुकी है। एजाज ने 2008 में जेएमबी ज्वाइन किया था। खागड़ागढ़ में धमाके के बाद हुईं गिरफ्तारियों के बाद भारत में एजाज को जेएमबी का प्रमुख बनाया गया था।

पीएफआइ के सहयोग से झारखंड में पांव पसार रहा : झारखंड में प्रतिबंधित पीएफआइ के साथ मिलकर जेएमबी तेजी से पांव पसार रहा है। राज्य की खुफिया एजेंसी की मानें तो उसके आतंकी व उनके सहयोगियों ने राज्य में फर्जी तरीके से अपना आधार कार्ड भी बनवा लिया है। ऐसा संताल के इलाके में हुआ है। पूर्व में झारखंड में जेएमबी के तीन सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें बंगाल के मुर्शीदाबाद का रहने वाला इब्राहिम वर्ष 2015 में पाकुड़ से पकड़ा गया था। इसी तरह, तरिकुल इस्लाम को एनआइए के सहयोग से एटीएस ने रामगढ़ से पकड़ा था। बंगाल का रहने वाला रिजाउल साहिबगंज से पकड़ा जा चुका है।

300 जगहों पर धमाके कर चुका

झारखंड पुलिस मुख्यालय की सूचना के अनुसार जेएमबी ने 2005 में बांग्लादेश व भारत में 300 जगहों पर धमाके किए थे। बाद में इसके नेता को फांसी हो गई थी।

मिल रहा है अलकायदा का साथ

हाल ही में झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार अलकायदा के कुख्यात आतंकी कलीमुद्दीन मुजाहिरी से भी जेएमबी के बारे में जानकारी जुटाई गई है। अब तक छानबीन में जांच एजेंसी को यह जानकारी मिली है कि जेएमबी को अलकायदा के आतंकियों का सहयोग मिल रहा है। जेएमबी को असम के बोडो उग्रवादी भी सहयोग कर रहे हैं।

आत्मघाती हमलावरों समेत 45-50 आतंकी ले रहे बालाकोट में प्रशिक्षण

नई दिल्ली, एएनआइ : पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मुहम्मद के आतंकी शिविर में आत्मघाती हमलावरों समेत 45-50 कुख्यात आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी साल फरवरी में भारतीय वायुसेना के हमले के बाद इस शिविर को छह महीने के लिए बंद कर दिया गया था।

सरकार के शीर्ष स्तरीय सूत्रों ने बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस आशय की ठोस जानकारी मिली है। खुफिया एजेंसियां इस प्रशिक्षण शिविर पर लगातार नजर रख रही हैं। इसमें तकनीक के जरिये निगरानी शामिल है। वहां प्रशिक्षण हासिल कर चुके कुछ आतंकवादियों को भारतीय सुरक्षा कैंपों को निशाना बनाने के लिए कश्मीर भेजा भी जा चुका है। बता दें कि पिछले महीने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बताया था कि पाकिस्तान ने हाल ही में बालाकोट स्थित आतंकी शिविर को पुनःसक्रिय कर दिया है।

मालूम हो कि इसी साल 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान में अंदर घुसकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में स्थित जैश के आतंकी शिविर पर बम बरसाए थे। वायुसेना ने उक्त कार्रवाई 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में की थी जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।

कश्मीर से हिजबुल के दो आतंकी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जम्मू : सुरक्षाबलों ने सोमवार को गांदरबल जिले के गंगबल इलाके से हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आतंकियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि गंगबल इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकी छिपे हुए हैं। इस आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष टीम (एसओजी), सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षाबलों को देखकर आतंकियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकियों के कब्जे से दो राइफल, चार मैगजीन और चार ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, पकड़े गए दोनों आतंकी राजौरी के रहने वाले हैं। ये पहले आतंकियों के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करते थे।

लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता ने संभाली 16 कोर की कमान

राज्य ब्यूरो, जम्मू : सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर जम्मू संभाग की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली महत्वपूर्ण 16 कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता ने संभाल ली है।

उत्तरी कमान की यह अहम कोर जम्मू संभाग में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ सक्रिय आतंकियों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए भी मुहिम चला रही है। हर्ष गुप्ता ने 16 कोर मुख्यालय नगरोटा में सेना की इस सबसे बड़ी ऑपरेशनल कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह से संभाली है। परमजीत सिंह सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन (डीजीएमओ) का महत्वपूर्ण पद संभालने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। वह 15 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान से डीजीएमओ का पद्भार संभालेंगे।

नए कोर कमांडर हर्ष गुप्ता ने सोमवार को कोर मुख्यालय के अश्वमेघ शौर्य स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर कोर की जिम्मेदारी संभाली। देश की खातिर प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

टेलीफोन से ज्यादा जिंदगी जरूरी : सत्यपाल मलिक

जागरण संवाददाता, कठुआ

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को कठुआ में पुलिस की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में कहा कि टेलीफोन इतना जरूरी नहीं है, जितनी जिंदगी जरूरी है। कभी बिना टेलीफोन के भी जीवन चलता था।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में एहतियातन मोबाइल फोन सेवा पर पाबंदियां लगाई गई थीं क्योंकि कुछ शरारती तत्व इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोमवार से कश्मीर में मोबाइल फोन शुरू हो गए हैं। पर्यटकों के रास्ते खोल दिए गए हैं। जल्द ही इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी जाएंगी। हालांकि कश्मीर में कई जगह इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं।

राज्यपाल कठुआ के सरदार पृथ्वीनंदन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षुओं के 26वें बैच की पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफों के पुल बांधते हुए उनकी कुर्बानियों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अनंतनाग में केंद्रीय व अन्य सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था। हमले के बाद भाग रहे आतंकियों को कुछ ही दूरी पर खड़े जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने मार गिराया। इसके साथ ही अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। यह है जम्मू कश्मीर पुलिस का देश पर मर मिटने का जज्बा। सब इंस्पेक्टर ने यह नहीं देखा कि आतंकियों ने किस पर हमला किया। उसने हमले की सूचना मिलते ही अपना फर्ज निभाया। उसकी इस बहादुरी से आठ से 10 पुलिस कर्मियों की जान बच गई। उनकी बहादुरी को देखते हुए केंद्र सरकार से आतंकी ऑपरेशन में मारे जाने वाले पुलिस कर्मी के परिवार के लिए एक करोड़ की राशि की मांग की गई है।

सत्यपाल मलिक। फाइल

बीपीएससी के परिणाम जारी, 355 अभ्यर्थी सफल

जागरण संवाददाता, पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने सोमवार को सुबह 63वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अंतिम रूप से 11 विभागों के लिए 355 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। टॉप-10 में चार छात्राओं ने स्थान बनाया है। प्रथम स्थान भोपाल में कार्यरत श्रीयांश तिवारी ने प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर नालंदा जिले के नगरनौसा गांव के अनुराग कुमार, तीसरे पर पूर्णिया के मेराज जमील, चौथे पर पटना के आनंदपुरी मोहल्ले की सुनिधि और पांचवी रैंक विश्वनाथगंज खगड़िया की श्रेया सलोनी ने प्राप्त किया है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 924 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इसमें 824 ही उपस्थिति हुए। कुल 807 अभ्यर्थियों की मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की गई है। इस बार आयोग के रिजल्ट में सबसे चौंकाने वाला कटऑफ रहा है। सामान्य से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कटऑफ गया है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का कटऑफ 588, जबकि ओबीसी कैटेगरी का कटऑफ 595 अंक है।

एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में शामिल नक्सली पुणे से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दुमका

- पुणे में रह रहा था नाम बदलकर, एक निजी कंपनी में कर रहा था काम
- एक लाख का इनामी नक्सली है साहेबराम हांसदा उर्फ आकाश

पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या समेत पांच अन्य नक्सली हमलों में शामिल नक्सली आकाश मुर्मू उर्फ हांसदा उर्फ साहेबराम हांसदा को पुलिस ने रविवार को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार नक्सली आकाश पुणे की एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। रामगढ़ लखनपुर गांव के रहने वाले नक्सली आकाश पर सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर करने की तैयारी में है।

सोमवार को नक्सली की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए दुमका एसपी वाइएस रमेश ने बताया कि इनामी नक्सली आकाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबाव बनाए हुए थी। पुलिस दबिश के कारण अपने ठिकानों से फरार होकर पुणे के चाकन में शरण लिए हुए था। यहां अपना नाम साहेबराम बताकर वह एक निजी कंपनी में काम कर रहा था।

नक्सली के पुणे में होने की जानकारी मिलने के बाद साइबर डीएसपी श्रीराम समद, इंस्पेक्टर वकार हुसैन व सुखविंदर सिंह चहल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर उसे दबोच लिया गया।

माओवादी आकाश दो जुलाई 2013 को दुमका के काठीकुंड में पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत सिंह बलिहार समेत छह जवानों की हत्या करने, दुमका के शिकारीपाड़ा में लोकसभा चुनाव के दौरान 25 अप्रैल 2014 को पोलिंग पार्टी पर हमला कर आधा दर्जन जवान व कर्मियों की हत्या करने, 21 नवंबर 2014 को शिकारीपाड़ा में आगजनी करने, 4 अक्टूबर 2014 को रामगढ़ में लेवी वसूली के लिए वाहन में आगजनी करने और 10 अप्रैल 2013 को लिट्टीपाड़ा में आगजनी की वारदात में शामिल था। बताया जाता है कि नक्सली आकाश की ससुराल काठीकुंड के कुलकांठ गांव में है। वर्ष 2013 में नक्सलियों का एक दस्ता उसके ससुर के घर आया। तभी से नक्सलियों के बहकावे में आकर वह उनके दस्ते में शामिल हो गया था।

एनआइ कोर्ट ने सिमी के स्लीपर सेल से आइएम कनेक्शन पर पूछे सवाल

नईदुनिया, रायपुर: बोधगया और पटना बम धमाकों के आतंकियों को पनाह देने के मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार सिमी के स्लीपर सेल अजहरुद्दीन से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बिलासपुर स्थित कोर्ट ने भी सवाल किए। कोर्ट ने उसके इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों से संपर्क की जानकारी ली। कोर्ट ने उसे 24 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

बता दें कि 2013 में गुजरात तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान बम धमाके हुए थे। इसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की संलिप्तता मिली थी। इस बीच रायपुर पुलिस ने आइएम आतंकियों को छत्तीसगढ़ में पनाह देने और बम धमाकों से पूर्व आतंकियों के सामान पहुंचाने वाले स्लीपर सेल का पर्दाफाश किया था। सभी प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट (सिमी) के सदस्य थे। इस मामले में सिमी के स्टेट चीफ समेत 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उस दौरान अजहरुद्दीन उर्फ अजहर उर्फ केमिकल फरार होने में कामयाब रहा था। फरारी के दौरान वह उत्तर प्रदेश में भी रहा और हैदराबाद में रहकर पासपार्ट और कार्मिक वीजा तैयार करा कर सऊदी भाग गया था।

हरियाणा में मोदी की रैली में जेब काटने आया मोस्ट वांटेड गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र

- पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की भी काट चुका है जेब
- कुरुक्षेत्र समेत अंबाला व पंजाब में 680 से ज्यादा लोगों को बना चुका निशाना

जिला पुलिस की अपराध शाखा-दो ने एक मोस्टवांटेड जेबकतरे को गिरफ्तार किया है। मोस्ट वांटेड इसलिए कि वह अब तक 680 लोगों की जेबें कतर चुका है। यहां तक कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की जेब भी काट चुका है। वह कुरुक्षेत्र में मंगलवार को प्रधानमंत्री की रैली में जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर यहां आया था, लेकिन हाइप्रोफाइल सुरक्षा के चलते धरा गया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। वह नशे की लत के चलते जेब काटता रहा है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वह प्रधानमंत्री की रैली में लोगों की जेब काटने के मकसद से आया था।

एसपी कुरुक्षेत्र आस्था मोदी ने बताया कि 12 अक्टूबर को गांव नूरपुर बुच्ची निवासी प्रगट सिंह ने थाना इस्माईलाबाद में जेब कटने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह नौ अक्टूबर को गुरुद्वारा मांडी साहिब नगर कीर्तन में शामिल होने गया था। माथा टेकते वक्त किसी ने जेब काट ली और पर्स चुरा लिया। उसमें चार हजार रुपये और आधार कार्ड था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी की रैली के चलते ब्रह्मसरोवर के समीप गश्त कर रही पुलिस टीम ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया। उसकी पहचान अंबाला के जगाधरी गेट निवासी नीतिक कुमार के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह एक जेबकतरा है। उसकी निशानदेही पर प्रगट सिंह का आधार कार्ड व दो हजार रुपये पुलिस ने बरामद कर लिए। उसने बताया कि कुरुक्षेत्र में उसने एक ही वारदात की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री बादल की भी काटी थी जेब: पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया कि वर्ष 2007-08 में पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में खेलों के उद्घाटन के समय भारी सुरक्षा के बीच पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की जेब भी काटी थी। उनकी जेब में 23 हजार रुपये थे। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने अब तक लगभग 680 लोगों की जेबें काटी हैं।

एक श्रद्धालु साल में एक ही बार जा पाएगा श्री करतारपुर साहिब

जागरण संवाददाता, डेरा बाबा नानक(गुरदासपुर): कॉरिडोर के होकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने वाले श्रद्धालु साल में सिर्फ एक बार ही वहां जा सकेंगे। दूसरी बार जाने के लिए उन्हें एक साल बाद ही अनुमति मिलेगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को डेरा बाबा नानक में मीडिया को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि श्री करतारपुर साहिब जाने के लिए श्रद्धालुओं को 30 दिन पहले आवेदन करना होगा। जिस श्रद्धालु को परमिट मिलेगा, उसे चार दिन पहले फोन, मैसेज और ईमेल से सूचित किया जाएगा। अगर किसी को परमिट नहीं मिलता है, तो उसे 30 दिन बाद दोबारा आवेदन करना होगा। एक दिन में पांच हजार श्रद्धालु करतारपुर साहिब के दर्शन कर सकेंगे। गुरु पर्व व अन्य बड़े समागमों में 10 हजार श्रद्धालु दर्शन करने जा पाएंगे। आवेदन करने के लिए वेबसाइट एक या दो दिन में शुरू हो जाएगी। रंधावा ने कहा कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए डेरा बाबा नानक आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पंजाब सरकार व एसजीपीसी की ओर से संयुक्त स्टेज लगाई जाएगी।

जागरण विशेष

ख्वाजा के दर से कश्मीर पहुंचा शांति का पैगाम, कट्टरपंथियों के बहकावे में न आने का संदेश

सूफी संतों ने युवा पीढ़ी से कहा, वादी-ए-कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाएं, कश्मीर को सूफी संस्कृति का केंद्र बनाने पर भी दिया जोर

रोहित जंडियाल, जम्मू

कश्मीर अपनी सूफियाना संस्कृति के लिए विख्यात रहा है। कभी देश में सूफियत का गढ़ था जम्मू-कश्मीर। यहां हर कोई आपस में प्यार, भाईचारे और शांति के साथ रहता था, लेकिन अमन के दुश्मनों को यह रास नहीं आया। हमें अपने इन दुश्मनों को, इनकी चाल और इनके मकसद को समझने में अब कोई उलझन नहीं रह गई है। लिहाजा, कट्टरपंथ की आड़ में अपने मनसूबे पूरे करने में जुटे रहे इन दुश्मनों के बहकावे में कश्मीर की युवा पीढ़ी अब कभी नहीं आएगी। आइए, वादी-ए-कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाएं...।

अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय किए जाने के बाद देश के विभिन्न भागों से कश्मीर पहुंचे सूफी संतों और मुस्लिम धर्म गुरुओं को कश्मीर के लोगों ने गंभीरतापूर्वक सुना और समझा। कश्मीर को पाकिस्तान पोषित कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाने वाली इस बहुप्रतीक्षित पहल का जहां अलगाववादी तत्वों ने विरोध किया, वहीं कश्मीरी आवाम ने इसके मायने अच्छे से समझे। दरअसल, कश्मीर की वर्षों पुरानी सूफी संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए कश्मीर को सूफी संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

अजमेर दरगाह के प्रमुख जैनल अबेदीन अली खान की पहल पर उनके बेटे नसीरुद्दीन चिश्ती कश्मीर में 17 सदस्यीय दल के साथ पहुंचे।

उनके साथ जयपुर, अजमेर, झुनझुनु, हैदराबाद, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और बिहार के सूफी संत भी शामिल थे। इन संतों का मकसद कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रायोजित दुष्प्रचार का माकूल जवाब देना और 370 निष्क्रिय होने के बाद कश्मीर की जमीनी हकीकत से रूबरू होना था। वे हजरतबल, मकदूम साहिब, सोनावर सहित कई मस्जिदों में गए और वहां नमाज अदा की। वह जीबी पंत अस्पताल में गए। लाल चौक व आसपास के क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात की। कश्मीर के हालात पर लोगों से बात की। स्थानीय लोगों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटरों सहित हर वर्ग से मिले। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीं काउंसिल के प्रमुख नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर में इस्लाम के नाम पर युवाओं को गुमराह करने वालों को आगाह किया।

कुलमिलाकर, यह साफ है कि राज्य के तीन दिवसीय दौरे में सूफी संतों और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कश्मीर के स्थानीय लोगों को स्पष्टता के साथ यह बताने का प्रयास किया कि अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थक निहित स्वार्थों के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

कुछ जगहों पर अलगाववादी समर्थकों का विरोध इन संतों को झेलना पड़ा, जिससे साफ हो गया कि अलगाववादियों को इनका यहां आना कतई रास नहीं आया।

बावजूद कश्मीर के लोग इन सूफी संतों से मिलने और उनके विचार सुनने को उत्सुक थे। ये संत अब कश्मीर के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उनका प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री से मिलकर कश्मीर के स्थानीय लोगों की जो शिकायतें हैं, उन्हें दूर किया जा सके।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

श्रीनगर में सोमवार को ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के सदस्य मीडिया से भी मुखातिब हुए। प्रेट्र

युवाओं का दिल जीतने का प्रयास

सूफी संतों ने कश्मीर में लोगों, विशेषकर युवाओं का दिल जीतने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वे युवाओं के दर्द को समझते हैं। ढाई महीने से उनकी पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए निश्शुल्क कोचिंग देने का प्रयास करेंगे। कश्मीरी युवा देश के जिस भाग में कोचिंग लेना चाहते हैं, उसकी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। उन्हें रोजगार दिलवाने के लिए कंपनियों के साथ बातचीत कर पूरा प्रयास करेंगे। सूफी संतों ने कश्मीर के लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि कश्मीर में इतना बड़ा बदलाव होने के बावजूद एक गोली नहीं चली। किसी की जान नहीं गई।

सूफीवाद से फिर निकलेगी अमन की राह

नई दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के ट्रस्टी और 2016 में दिल्ली में विश्व सूफी सम्मेलन के आयोजन से जुड़े सूफी अजमल निजामी मानते हैं कि कश्मीर में अमन की राह सूफीवाद ही दिखा सकता है। सूफी संगीत और विचारधारा रूह को भी बदल देगी। कश्मीर कभी सूफी संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। बीते कुछ वर्षों में कट्टरपंथियों ने लोगों के दिमाग में जहर घोला। अब यह बदलाव का समय है। आज कट्टरवाद के जनक भी सूफीवाद की ओर देख रहे हैं। ऐसे में कट्टरपंथ पोषित आतंकवाद को सूफीवाद आईना दिखाने का बड़ा काम कर सकता है।

11 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बदरीनाथ में दर्शन। वर्तमान में रोजाना चार हजार से अधिक यात्री दर्शन कर रहे हैं। 2018 में 1058490 यात्रियों ने दर्शन किए थे। प्रतिवर्ष दीपावली तक ज्यादातर स्थानीय व्यवसायी अपना सामान समेटकर घरों को लौट जाते हैं।

उप्र के मऊ में सिलेंडर विस्फोट, 13 मरे

दर्दनाक ▸ घर में चाय बनाते समय रिसाव से लगी आग, मकान ध्वस्त, 24 लोग घायल

मलबे में दो लोगों के दबे होने की आशंका, तीन का पता नहीं

जागरण संवाददाता, मऊ

मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में वलीदपुर कस्बे के बढ़ईटोला में सोमवार सुबह रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से हुए विस्फोट से 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 24 लोग घायल हो गए। हादसे वाला मकान जमींदोज हो गया और आसपास के चार घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में लगीं हैं। मलबा हटाने में पूरी रात गुजरने की उम्मीद है।

घटनाक्रम के मुताबिक वलीदपुर के बिचलापुरा के बढ़ई टोला में छोटू विश्वकर्मा के घर में सुबह 6:30 बजे चाय बनाने के लिए घर की बिटिया मोना ने रसोईं में जाकर चूल्हा जलाया। इतने में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, तभी सिलेंडर में धमाके के साथ विस्फोट हो गया।

इससे पूरा मकान ध्वस्त हो गया। आसपास के चार मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बचाव कार्य में लगे लोग भी मलबे में दब गए। घर के सामने से स्कूल जा रहे दो सगे भाइयों समेत सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में छह लोगों ने रास्ते और अस्पताल में दम तोड़ा। सूचना पर जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य और समेत कई थानों की पुलिस के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी व डीआइजी मनोज तिवारी भी पहुंचे। प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने भी जायजा लिया और पीड़ित परिवारों की हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। यहां उन्हें लोगों के आक्रोश का भी समाना करना पड़ा।

मुख्यमंत्री ने जताई शोक संवेदना

मऊ हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया और मृत लोगों की आत्मा की शांति की ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में हर कदम पीड़ित परिवारों के साथ है।

आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम

हादसे के बाद पहली सरकारी एंबुलेंस पहुंचने में डेढ़ घंटे विलंब हुआ। मलबा हटाने के लिए सरकारी मशीनरी पहुंचने में भी विलंब हुआ। इससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग पर दो घंटे जाम रखा। लोगों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा और नौकरी की मांग की है।

मऊ के वलीदपुर कस्बे के बढ़ईटोला में सिलेंडर विस्फोट होने के बाद ढहे मकान। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से मलबा हटाने काम जारी है। प्रेट्र

मृतकों के परिजनों को पांच व घायलों को दो लाख का मुआवजा

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एरिया मैनेजर अमरेश कुमार ने घटना से जुड़े प्रत्येक मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये तथा प्रत्येक घायलों को दो-दो लाख रुपये कंपनी द्वारा कराए गए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने की वजह से शासन या प्रशासन द्वारा किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की गई। नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

चिन्मयानंद प्रकरण

रंगदारी के आरोपितों की न्यायिक हिरासत 26 तक बढ़ी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद छात्रा व तीनों युवकों की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ओमवीर सिंह की कोर्ट में सोमवार को पेशी हुई। सीजेएम के आदेश पर चारों आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के सामने पेश किया गया, जहां से उनकी न्यायिक हिरासत 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई।

शाम चार बजे के बाद छात्रा, उसके दोस्त संजय सिंह, विक्रम सिंह व सचिन सेंगर को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन सीजेएम के आदेश पर पेशी सिविल जज जूनियर डिवीजन नितिशा चौधरी के समक्ष कराई गई। सिविल जज ने चारों आरोपितों की अगली रिमांड तिथि 12 दिन बाद तय की।

चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में तीनों युवकों को बीस व छात्रा को 25 सितंबर को एसआइटी ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। चारों आरोपितों की कोर्ट में यह दूसरी पेशी थी। सुरक्षा कारणों से दोनों बार पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही कराई गई है। पेशी के समय एसआइटी के सह-विवेचक दलवीर मौजूद रहे।

रंगदारी के आरोपित संजय सिंह की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है। मंगलवार को जिला जज की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।

पीएमसी बैंक के पूर्व एमडी ने जुनैद खान के नाम से खरीदी थीं संपत्तियां

- पुणे में नौ फ्लैट और एक बुटीक समेत 10 संपत्तियों को खरीदने के लिए किया था जुनैद नाम का प्रयोग
- अपनाया था इस्लाम धर्म, पूर्व सहयोगी से इस्लामिक रीति-रिवाज से की थी शादी

मुंबई, एएनआइ : पीएमसी बैंक मामले की जांच कर रही मुंबई की आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) को पता चला है कि पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थामस ने पुणे में दस संपत्तियों को खरीदने के लिए जुनैद खान नाम का प्रयोग किया था। ईओडब्ल्यू से जुड़े सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि थामस ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना नाम जुनैद खान रख लिया था और पुणे में ही काम करने वाली अपनी एक पूर्व सहयोगी से इस्लामिक रीति-रिवाज से 2012 में दूसरी शादी कर ली थी।

थामस ने जुनैद खान और दूसरी पत्नी के नाम से पुणे में 10 संपत्तियां खरीदी थीं। इसमें 9 फ्लैट और एक बुटीक शामिल है। थामस की दूसरी पत्नी जहां एक फ्लैट में रहती है, वहीं बाकी सभी संपत्तियां किराए पर हैं। अब ईओडब्ल्यू को यह साबित करना होगा कि इन संपत्तियों को गलत तरीके से अर्जित आय से खरीदा गया था। सूत्रों के अनुसार यह सभी संपत्तियां 2012 में बैंक घोटाला शुरू होने के बाद खरीदी गईं। सबसे खास बात यह है कि थामस ने अपने सभी बैंक खातों के लिए तो अपने मूल नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन पुणे में संपत्ति खरीदने के लिए जुनैद नाम का इस्तेमाल किया। थामस को पहली शादी से एक बेटा है और पहली पत्नी से तलाक की कार्यवाही ठाणे जिले की एक स्थानीय अदालत में चल रही है। यहीं पर पहली पत्नी और बेटा रहते हैं। बता दें कि थामस से संबंधित सभी बैंक खातों को अक्टूबर के पहले हफ्ते में जब्त कर लिया गया था।

कोर्ट ने तीन आरोपितों की रिमांड 16 अक्टूबर तक बढ़ाई : मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को एचडीआइएल के सीएमडी राकेश वधावन उनके बेटे सारंग वधावन और पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन एस वरयाम सिंह की पुलिस रिमांड 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी। वधावन पिता-पुत्र को जहां तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, वहीं वरयाम सिंह को पीएमसी बैंक में हुए 4355 करोड़ रुपये के घोटाले में संलिप्तता के आरोप में पांच अक्टूबर को पकड़ा गया था। बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थामस को भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी पुलिस रिमांड 17 अक्टूबर को समाप्त होगी।

कोर्ट के बाहर जमाकर्ताओं ने किया प्रदर्शन : आरोपितों की पेशी के दौरान ही कोर्ट के बाहर जमाकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। वे हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें 'नो बेल-ओनली जेल' और 'वोट फॉर नोटा' जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने घोटाले को आर्थिक आतंकवाद बताते हुए सरकार से जल्द से जल्द पैसा वापस दिलाने और आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कुछ जमाकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से लिखित आश्वासन मांगा कि उनका पैसा कब वापस दिया जाएगा।

पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा वरयाम सिंह : ईओडब्ल्यू ने सोमवार को कोर्ट को बताया कि पीएमसी बैंक के चेयरमैन वरयाम सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि उसे जानकारी मिली है कि वरयाम सिंह ने अवैध रूप से कमाए गए पैसे से अमृतसर में लेमन ट्री नामक एक पांच सितारा होटल खरीदा है। इतना ही नहीं, मुंबई के जुहू बीच पर सिटीजन होटल के बगल में एक जमीन का टुकड़ा भी है, जिसकी कीमत लगभग 2500 करोड़ है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में वह बार-बार बयान बदल रहा है।

एचडीआइएल प्रवर्तकों के इशारे पर काम कर रहा था वरयाम सिंह : मुंबई पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में बताया कि पीएमसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष वरयाम सिंह ने एचडीआइएल के प्रवर्तक राकेश वधावन और सारंग वधावन के इशारे पर काम किया और उनकी देनदारियों को छिपाने का काम किया। पुलिस के मुताबिक पीएमसी बैंक के अधिकारियों ने पिछले कर्जों का भुगतान नहीं करने के बावजूद 2008 से 2019 के बीच एचडीआइएल को ऋण दिया। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि वरयाम सिंह पहले एचडीआइएल की विभिन्न कंपनियों में निदेशक था और बाद में बैंक का चेयरमैन बन गया। पुलिस ने कहा कि वे मनमोहन आहूजा नामक एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, जिसका दावा है कि उसने वरयाम सिंह के इशारे पर ही सारे काम किए हैं।

अब तक 3,830 करोड़ की संपत्ति जब्त और चिह्नित : ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने पीएमसी बैंक से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में 3,830 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त और चिह्नित की है। इसमें दो निजी विमान और याट भी शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में मारे गए छापों के संबंध में ईडी ने कहा कि छापे से उसे कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिससे धन के दुरुपयोग का पता चला है। उदाहरण के लिए पीएमसी बैंक ने 98 करोड़ रुपये का लोन एम इस्टेट को दिया था। इस कंपनी का प्रवर्तक राकेश वधावन का कारोबारी सहयोगी था। ईडी ने दो विमान बांबर्डियर चैलेंजर-300 वीटी और फाल्कन-2000 वीटी एचडीएल को भी जब्त किया है। इनका संचालन प्रिविलेज एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड करती है, जिसके निदेशक राकेश वधावन और उसका पुत्र है। ईडी ने कहा कि वह एचडीआइएल, इसके निदेशकों, प्रवर्तकों और पीएमसी बैंक के अधिकारियों तथा अन्य की संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। चिह्नित की गई संपत्तियों को जल्द ही मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत कब्जे में लिया जाएगा।

न्यूज गैलरी

हैदराबाद में 8,900 किलो विस्फोटक जब्त, दो गिरफ्तार

हैदराबाद : क्रशर उद्योग के लिए लाए गए 8,900 किलोग्राम विस्फोटकों को वाहनों से अवैध तौर पर उतारने और लापरवाही से रखने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही विस्फोटक सामग्री भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 12 अक्टूबर को एक स्टोन क्रशर इकाई पर छापेमारी की गई। इस दौरान दो वाहनों पर लाद कर लाई गई विस्फोटक सामग्री जब्त कर ली गई। इनमें 376 बूस्टर व 165 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर शामिल थे। विस्फोटक को तेलंगाना के सिद्दीपेट व आंध्र प्रदेश के काडपा जिले में भेजा जाना था, लेकिन इन्हें यहां स्थित एक स्टोन क्रशर इकाई में अवैध तौर पर उतारते हुए लापरवाही के साथ रख दिया गया। (प्रेट्र)

बंगाल में अवैध कोयला खदान में तीन लोग फंसे

आसनसोल : बंगाल के पश्चिम बर्द्धमान जिले के कुल्टी में एक अवैध कोयला खदान में कोयला निकालते समय तीन लोग फंस गए। उनको निकालने के लिए रविवार देर रात से ही बचाव कार्य (रेस्क्यू ऑपरेशन) जारी है, मगर सोमवार को समाचार लिखे जाने तक उनको निकाला नहीं जा सका था। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने हमें कुल्टी के अल्धी गांव स्थित अवैध खदान में तीन लोगों के फंसे होने की जानकारी दी। उसके बाद हमारा बचाव दल जहरीली गैस के कारण दो बार खान में घुसने में नाकाम रहा। वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना रविवार रात को उस समय हुई जब चार लोग कोयला निकाल रहे थे। पुलिस ने बताया कि अंदर फंसे चार लोगों में से एक बाहर निकलने में कामयाब रहा, जबकि बाकी तीन अब भी उसमें फंसे हैं। (जासं)

मप्र में कार की छत फाड़कर घुसा पत्थर, युवक की मौत

बैतूल : मुलताई थाना क्षेत्र के उभारिया ग्राम में बैतूल नागपुर फोरलेन के किनारे पत्थर खदान में की जा रही ब्लास्टिंग (विस्फोट) से पत्थर उछलकर करीब 300 मीटर फोरलेन से जा रही कार की छत फाड़कर कार चला रहे युवक के सिर में घुस गया, जिससे युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इंडस बैंक बैतूल में कार्यरत होशंगाबाद निवासी अशोक वर्मा सोमवार सुबह मुलताई जा रहे थे। बैतूल-नागपुर फोरलेन के पास उभारिया ग्राम में अल्वी क्रशर की खदान में ब्लास्टिंग से पत्थर तोड़े जा रहे थे, तभी खदान से उछला पत्थर कार की छत फाड़ते हुए सिर में घुस गया। (नईदुनिया)

पराली मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए बनी टास्क फोर्स की सिफारिश पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली में रविवार रात 10 बजे तक समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 301 पहुंच गया और रात के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के सभी हिस्सों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में आ गई थी।

सोमवार को यह मुद्दा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष उठा। इस दौरान प्रदूषण मामले में कोर्ट की सहायता कर रहीं एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय से इस मुद्दे पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाना चाहिए। अपराजिता ने पीठ को बताया कि पिछले साल 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने के लिए तमाम निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने यह निर्देश केंद्र की उस दलील के बाद जारी किए थे, जिसमें उसने कहा था कि तीनों राज्यों में पराली जलाने के मामले की रोकथाम पर गठित एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स की उप समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

खेत में पराली जलाने वालों को नहीं मिलेगा कृषि अनुदान : नीतीश

राज्य ब्यूरो, पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दो टूक कहा कि खेतों में पुआल यानी पराली (फसल अवशेष) जलाने वालों को राज्य सरकार कृषि अनुदान से वंचित कर देगी। जबकि इसे नहीं जलाने वाले किसानों को मदद मिलेगी। इससे खेत और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। सरकार खेती के लिए किसानों को 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देती है।

वहीं, एक लीटर डीजल में 60 रुपए की सब्सिडी दे रही। अन्य अनुदान अलग से हैं। पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरा बचाए रखने को लोग अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर राजधानी स्थित ज्ञान भवन में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन के क्रम में मुख्यमंत्री ने ये बात कही।

पुआल से बढ़ेगी आमदनी तभी समझेंगे : मुख्यमंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे कृषि विज्ञानियों को कहा कि अगर पुआल से आमदनी बढ़ेगी तो लोग इसे खेतों में नहीं जलाएंगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार करें।

इसे सरकार कृषि रोड मैप में शामिल करेगी। सेमिनार के नतीजे पर पुस्तक प्रकाशन से ज्यादा लाभ इस बात का होगा कि कोई लघु फिल्म इस पर बनाई जाए और किसानों को दिखाया जाए। वहीं सोमवार को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि खेतों में पराली जलाने से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानी हो रही है।

फसल अवशेष प्रबंधन पर अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते नीतीश कुमार। जागरण

पंजाब में जलने लगी पराली, हवा होने लगी जहरीली

जागरण टीम, पटियाला/लुधियाना : धान की खरीद के तेजी पकड़ने के बाद अब पराली को जलाने के मामले बढ़ने से पंजाब की हवा खराब होनी शुरू हो गई है। खेतों में जलाई जा रही पराली से पर्यावरण पर इसका असर दिखने लगा है। पंजाब के प्रमुख शहरों पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ की हवा जहरीली होने शुरू हो गई है। इन शहरों में पिछले दिनों जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य चल रहा था वहीं अब आंकड़े खराब स्थिति के संकेत दे रहे हैं। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार बीते तीन सप्ताह में पिछले साल की अपेक्षा खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान में तो पराली को आग लगाई ही जा रही है इसके साथ ही पंजाब के सीमावर्ती जिलों में पराली को जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 42 फीसद बढ़ोतरी हुई है।

बंगाल में पुलिस हिरासत में मौत के बाद चौकी में आगजनी

- लोगों ने तोड़फोड़ के बाद पुलिस चौकी को किया आग के हवाले
- चार पुलिसकर्मी घायल, 15 लोग किए गए गिरफ्तार

जेएनएन, कोलकाता

बंगाल के मालदा जिले में पुलिस हिरासत में कथित तौर पर एक व्यक्ति की मौत के बाद इलाके में हिंसा भड़क उठी। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मिल्की पुलिस चौकी पर हमला करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया।

सोमवार को जिले के पुलिस अधीक्षक आलोक राजौरिया ने बताया कि रविवार देर रात स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। इस घटना में चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। आगजनी में पुलिस चौकी में रखे बहुत सारे जरूरी दस्तावेज जल कर खाक हो गए। बताया कि 55 वर्षीय ऐनुल खान को सात अन्य लोगों को साथ पुरातन भगवानपुर इलाके से जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था।

थाने लाने के बाद उसने तबियत बिगड़ने की शिकायत की। उसे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस उत्पीड़न से उसकी मौत का आरोप लगाकर अस्पताल नहीं ले जाने दिया। उन्होंने बताया कि भीड़ ने एक पुलिस वाहन को तोड़ दिया और पुलिस कर्मियों को भी जख्मी कर दिया।

इतना ही नहीं हमलावरों ने दूसरे आरोपितों को भी छुड़ा लिया और पुलिस चौकी में आग लगा दी। आगजनी में महत्वपूर्ण दस्तावेज जल कर खाक हो गए। पुलिस अधीक्षक के अनुसार, घटना के दौरान ऐनुल खान की मौत हो गई और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना के बाद छापेमारी कर हमले में कथित तौर पर शामिल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपितों को भी पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।

उन्होंने कहा कि पुलिस पर स्थानीय लोगों का इस तरह से हमला बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से इलाके में भारी तनाव का माहौल है। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी घटनास्थल पर तैनात की गई है।

दृष्टिबाधितों के लिए मोबाइल एप करें विकसित : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक मोबाइल एप विकसित करने की संभावना तलाशी जाएं ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भी स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से जीने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे के पत्र पर संज्ञान लेकर हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका शुरू की। दवे ने लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के बाहर चल रही अवैध पार्किंग व व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने की भी मांग की थी। पत्र में उन्होंने मथुरा रोड पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग की थी ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को एसोसिएशन के भवन तक सड़क पार कराई जा सके। अदालत मित्र एम सूफियान सिद्दकी ने पीठ को एक रिपोर्ट दायर कर ऐसा एप विकसित करने का सुझाव दिया है जो दृष्टिबाधितों को खरीदारी, रास्ते तलाशने व अन्य गतिविधियों में मदद करेगा। उन्होंने पीठ को बताया कि इस तरह के एप विदेशों में सफल रहे हैं।

विमान के लैंडिंग गियर में आई खराबी, रद की गई फ्लाइट

- मंगलवार को भी रद रह सकती है उड़ान, चार दिन पहले शुरू हुई थी सेवा
- दो घंटे 35 मिनट देरी से हिंडन पहुंचा था नौ सीटर विमान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए शुरू हुई फ्लाइट के लैंडिंग गियर में आई खराबी के बाद सोमवार को इसे रद कर दिया गया। फ्लाइट रद होने के बाद यात्रियों की विमान कंपनी के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। यात्रियों को किराये की राशि रिफंड कर दिया गया। एयरपोर्ट डॉयरेक्टर मामले की रिपोर्ट बनाकर नगर विमानन महानिदेशालय को भेजेंगे। वहीं देर रात तक खराबी ठीक नहीं होने के चलते मंगलवार को भी पिथौरागढ़ और हिंडन से फ्लाइट पर संशय बना हुआ है।

11 अक्टूबर से शुरू हुए नौ सीटर विमान को सोमवार को चौथे दिन पिथौरागढ़ के लिए रवाना होना था। हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए दोपहर एक बजे इसका समय निर्धारित था। पिथौरागढ़ से यह विमान ढाई घंटे की देरी से दोपहर तीन बजकर पांच मिनट पर हिंडन पहुंचा। सूत्रों की मानें तो विमान के उतरने के समय लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई। यात्रियों को उतारने के बाद दिशा बदलते हुए विमान का बाईं ओर का एक पहिया जाम हो गया। एयरपोर्ट की डायरेक्टर शोभा भारद्वाज ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते उड़ान रद की गई है। वहीं विमान संचालक कंपनी हेरिटेज एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित माथुर ने बताया कि इंजीनियर विमान की तकनीकी खराबी के समाधान में जुटे हैं। ठीक होते ही फ्लाइट उत्तराखंड जाएगी। हालांकि मंगलवार को उड़ान हो सकेगी या नहीं इसे लेकर संशय बरकरार है। गनीमत रही कि तकनीकी खराबी के चलते विमान की लैंडिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फ्लाइट को रद करने की घोषणा की गई।

खराबी आने के बाद खड़ा विमान जागरण

पंजाब में पबजी से डिप्रेशन में गए युवक ने की खुदकशी

संवाद सहयोगी, मोगा : पबजी गेम के कारण डिप्रेशन में गए एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मोगा के लाल सिंह रोड का रहने वाला 22 वर्षीय विजय कुमार फोकल प्वाइंट में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहा था। रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे उसने पंखे से फंदा लगा लिया।

हवलदार गुरप्रीत सिंह ने बताया कि मृतक के भाई बब्बू के अनुसार आत्महत्या के वक्त विजय कुमार ने शराब पी हुई थी। वह कई दिनों से परेशान था।

मृतक के जीजा निक्कू व ताया के बेटे जगदीश प्रसाद ने बताया कि विजय पबजी गेम खेलने का आदी हो गया था। वह पूरी-पूरी रात गेम खेलता था। रात को भी कम सोता था। इससे वह डिप्रेशन में चला गया था।

क्या कहते हैं मनोचिकित्सक : मथुरादास सिविल अस्पताल के मनो चिकित्सक डॉ. राजेश मित्तल ने बताया कि पबजी खेल दिल व दिमाग पर हावी हो जाता है। टारगेट पूरे न होने से खिलाड़ी डिप्रेशन में चला जाता है। जो एक्ट खेल में होता है, मन वही करने को करता है। बड़े शहरों में पबजी के कारण आत्महत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं।

सख्ती

किसानों को दी फल पौध खराब निकली तो होगी जेल

उत्तराखंड के नर्सरी एक्ट में सरकार करने जा रही यह प्रावधान, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में 10 गुना का इजाफा

केदार दत्त, देहरादून

औद्यानिकी को आर्थिकी का मुख्य जरिया बनाने की कोशिशों में जुटी प्रदेश सरकार अब नर्सरी के मानकों को सख्त करने जा रही है। इसके तहत निकट भविष्य में अगर किसी सरकारी अथवा निजी नर्सरी से किसानों को मुहैया कराई गई फल पौध खराब निकली तो नर्सरी स्वामी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसके साथ ही जुर्माने की राशि में 10 गुना की बढ़ोतरी कर इसे 50 हजार किया जाएगा। उत्तराखंड के प्रस्तावित नर्सरी एक्ट में ये प्रावधान किए जा रहे हैं। अन्य नियमों को भी सख्त करने के साथ ही जवाबदेही तय की गई है। एक्ट का मसौदा तैयार कर लिया गया है और अब इसे कैबिनेट की झंडी मिलने पर राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।

अभी तक राज्य में उत्तर प्रदेश के नर्सरी एक्ट से काम चलाया जा रहा है। इसे देखते हुए दिसंबर 2017 से राज्य का अपना नर्सरी एक्ट बनाने की कसरत शुरू हुई। अब इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार अब सरकारी व निजी क्षेत्र की सभी नर्सरियों को एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। अभी तक उद्यान विभाग की नर्सरियां इससे बाहर थीं। इसके पीछे जवाबदेही तय करने की मंशा है। नर्सरी में तैयार होने वाली पौध की गुणवत्ता के लिए नर्सरी स्वामी के साथ ही जिला स्तर के उद्यान विभाग के कार्मिकों पर भी कार्रवाई होगी। सूत्रों ने बताया कि एक्ट में दंड के प्रावधान कड़े किए गए हैं।

पूर्व में नियमों की अनदेखी करने वाली नर्सरियों के स्वामियों से पांच हजार का जुर्माना लिया जाता था। अब जुर्माने की राशि बढ़ाकर 50 हजार की जा रही है और छह माह के कारावास का प्रावधान भी किया है।

बिना लाइसेंस के नहीं चलेगी कोई नर्सरी

खराब फल पौध के कारण किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई की भी व्यवस्था होगी। इसका निर्णय जिला स्तर पर गठित होने वाली कमेटी करेगी। वह यह तय करेगी कि किसान को क्षति की भरपाई किससे वसूली जाएगी। यही नहीं, बिना लाइसेंस के कोई नर्सरी संचालित नहीं होगी और न कोई खरीद-फरोख्त ही होगी। साथ ही नर्सरी का हर दो साल में नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

ये भी प्रावधान
अब 0.2 हेक्टेयर से कम भूमि में पौधालय को माना जाएगा नर्सरी
30 वर्ष के भूमि पट्टे वाली भूमि में भी नर्सरी की जा सकेगी तैयार
प्रत्येक नर्सरी में मातृ वृक्ष (मदर ब्लॉक) तैयार करना जरूरी
नर्सरी के लिए तीन वर्ष का कैलेंडर बनाना अनिवार्य
नई प्रजाति की खोज करने पर इसे पेटेंट करा सकेंगी नर्सरी

'राज्य के नर्सरी एक्ट का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसमें किसानों के हितों का ख्याल रखने के साथ ही नर्सरी स्वामियों के साथ ही विभाग की जवाबदेही भी तय की जा रही है। अब एक्ट के मसौदे को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।'

-सुबोध उनियाल, कृषि एवं उद्यान मंत्री

रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुरी को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने रतुल पुरी को जेल भेज दिया। इस दौरान पुरी के अधिवक्ता ने मामले से जुड़े दस्तावेज जेल में ले जाने की अनुमति मांगी। अदालत ने जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के हिसाब से पुरी को दस्तावेज ले जाने की अनुमति देने के आदेश दिए।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में रतुल पुरी को गत 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। रतुल पुरी के ठिकानों पर सर्च के दौरान हिंदुस्तान पावर के दफ्तर से एक अनुबंध पत्र मिला है, जोकि इस मामले में आरोपित राजीव सक्सेना का हस्ताक्षर किया हुआ है। अब उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है।

सात दिन की पुलिस रिमांड पर आतंकी फंडिंग के आरोपित

- एटीएस ने अदालत से मांगी थी आरोपितों की 10 दिन की रिमांड
- अदालत का सख्त आदेश, नहीं करें थर्ड डिग्री इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, लखीमपुर

आतंकी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपित सात दिन तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान मामले की विवेचना कर रही एटीएस आरोपितों से आतंकी संगठनों को की जा रही फंडिंग और उसमें शामिल अन्य लोगों व उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाएगी। सीजेएम विकास श्रीवास्तव ने 14 अक्टूबर को शाम पांच बजे से 21 अक्टूबर शाम पांच बजे तक रिमांड स्वीकृत की है।

गुरुवार रात पलिया कस्बे के बस स्टैंड से पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने खमरिया निवासी उन्मेद अली, तिकोनिया निवासी संजय अग्रवाल, एराज अली व बरेली निवासी समीर सलमानी को गिरफ्तार किया था। उनके पास से मिली नेपाली व भारतीय मुद्रा के बारे में पूछताछ पर मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा पाया गया। सभी को षड्यंत्र रचने, धोखाधड़ी अन्य धाराओं में जेल भेजा गया और विवेचना एटीएस को सौंप दी गई।

सोमवार को एटीएस के सीओ शैलेंद्र राठौर ने सीजेएम की अदालत से आरोपितों की 10 दिनों की रिमांड मांगी। अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता ने बहस की जबकि आरोपित संजय अग्रवाल के अधिवक्ता ने विरोध भी किया।

रिमांड अवधि की होगी वीडियोग्राफी : अदालत ने रिमांड के दौरान वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। साथ ही यदि आरोपित अपने साथ अधिवक्ता रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन अधिवक्ता पूछताछ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और उचित दूरी पर रहेंगे। इसके साथ ही थर्ड डिग्री इस्तेमाल के लिए सख्ती से मना किया गया है।

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 15 अक्टूबर 2019

दैनिक जागरण
प्रार्थना हृदय की पुकार है

कश्मीर की चुनौती

कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल सेवाएं शुरू होना इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार घाटी के हालात तेजी के साथ सामान्य बनाने में लगी हुई है। पोस्ट पेड मोबाइल सेवाएं शुरू होने से कश्मीर के लोगों को तो सहूलियत मिलेगी ही, दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि भारत सरकार अपने उस वादे को पूरा करने के प्रति गंभीर है जिसके तहत यह कहा गया था कि भेदभाव भरे अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद देश के इस हिस्से में लगाई गई पाबंदियां अधिक समय तक नहीं रहेंगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पोस्ट पेड मोबाइल सेवाएं शुरू करने के पहले भी कई ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि मोदी सरकार कश्मीर के हालात सामान्य करने को लेकर हरसंभव उपाय कर रही है। जम्मू-कश्मीर को 31 अक्टूबर को औपचारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि तब तक कश्मीर के सभी 10 जिलों में लगाई गई हर तरह की पाबंदियों को हटा लेने की नौबत आ जाएगी। वैसे भी अब प्री पेड मोबाइल सेवाओं और इंटरनेट की बहाली के साथ कुछ प्रमुख नेताओं की नजरबंदी हटना ही शेष है। यह भी ध्यान रहे कि खुद प्रधानमंत्री की ओर से यह कहा गया है कि चार माह के अंदर कश्मीर के हालात सामान्य कर लिए जाएंगे।

जो लोग कश्मीर के मौजूदा हालात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने में लगे हुए हैं और इस क्रम में दुष्प्रचार का भी सहारा ले रहे हैं उन्हें इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कश्मीर घाटी बीते लगभग तीन दशकों से अशांत है। इस अशांति का कारण कश्मीर में अलगाववादियों के साथ ऐसे तत्वों का उभार है जो न केवल पाकिस्तानपरस्त हैं, बल्कि आतंकियों के समर्थक भी हैं। ऐसे तत्वों पर लगाम लगाना अभी भी एक चुनौती है। यह चुनौती इसलिए और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान इस ताक में है कि कश्मीर के हालात कैसे बिगाड़े जाएं? स्पष्ट है कि भारत सरकार को कश्मीर में सक्रिय अलगाववादियों और पाकिस्तानपरस्त तत्वों पर निर्णायक अंकुश लगाने के साथ ही पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ाना होगा। हालांकि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात से बुरी तरह त्रस्त है, लेकिन उसका कश्मीर राग शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत को यह देखना ही होगा कि पाकिस्तान कश्मीर पर आंसू बहाना कैसे बंद करें? इसी के साथ उसे इसके लिए भी सक्रिय होना होगा कि कश्मीर घाटी की अमन पसंद जनता अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ मुखर हो। इससे ही घाटी का माहौल बदलेगा। बीते 70-72 दिनों का अनुभव यही बताता है कि माहौल बदलने का यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं।

एक और गौरव

बंगाल में जन्मे एक और अर्थशास्त्री को नोबेल पदक मिला है। करीब 21 वर्ष पूर्व बंगाल में ही जन्मे अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में वर्ष 1998 में नोबेल मिला था। यदि बात नोबेल जीतने वालों की करें तो बंगाल में जन्मे अब तक तीन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। सर्वप्रथम कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर को साहित्य में और इसके बाद अमर्त्य सेन तथा अब अभिजीत बनर्जी को मिला है। यही नहीं बनर्जी की पत्नी एस्थर डुफ्लो भी को ग्लोबल गरीबी के लिए अपने प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत का जन्म 21 फरवरी, 1961 को कोलकाता में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही हुई जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने इसी विषय में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई की और इकोनॉमिक्स में ही पीएचडी के लिए 1988 में अमेरिका के हार्वड यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद वहां की नागरिकता ले ली। असल में उनके खून में ही अर्थशास्त्र है, क्योंकि उनके पिता दीपक बनर्जी भी बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, उनकी मां निर्मला बनर्जी भी कोलकाता के सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थीं। ऐसे में बेटा भी क्यों न अर्थशास्त्री बने और आज उन्होंने अपने माता-पिता के साथ-साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया है और खासकर बंगाल के लिए बड़े ही गौरव की बात है। पिछले साल भी अभिजात नोबेल के लिए नामित हुए थे, परंतु पिछड़ गए। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए शोध किया और किताबें लिखीं। 2019 के कांग्रेस के घोषणापत्र में गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाओं का खाका तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। अभिजीत की किताब जगरनॉट जल्द आने वाली है। अभिजीत फिलहाल अमेरिका में एक फाउंडेशन के साथ काम करते हुए वैश्विक गरीबी को दूर करने के उपायों पर काम कर रहे हैं। साथ ही वह फोर्ड फाउंडेशन के एक इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं। उन्हें 2009 में इन्फोसिस प्राइज भी मिल चुका है। फिलहाल ईस्थर और अभिजीत उस अब्दुल लतीफ जमीर पॉवर्टी एक्शन लैब के को फाउंडर है जिसके लिए काम करते हुए उन्हें यह नोबेल प्राइज मिला है। वे भारत में जन्मे हुए हैं तो अपनी मातृ भूमि से भी गरीबी हटाने की दिशा में उन्हें कार्य करना चाहिए ताकि भारत के लिए उन्हें नोबेल मिलना सार्थक सिद्ध हो।

संघ के प्रयोगों का लाभ उठाती भाजपा

बद्री नारायण

समय के साथ भाजपा की जो सियासी पैठ बढ़ी है, उसमें राजनीति के साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों को जोड़ने वाली हिंदुत्व की राजनीति ने बड़ी भूमिका निभाई है

असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पहाड़ियों की तलहटी में बसे हरे-भरे धान का एक बेहद सुंदर इलाका है जिसका नाम है म्योंग। स्थानीय भाषा में म्योंग का अर्थ है-माया का लोक। म्योंग क्षेत्र में तमाम गांव बसे हैं। यहां अनेक हिंदू अपने नाम के साथ गिरि टाइटल या उपनाम लगाते हैं। वे नाथपंथी हैं यानी नाथपंथ में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी के गुरु मच्छेंद्रनाथ ने यहां आकर इस पंथ का प्रसार किया था। इस क्षेत्र में बसे ये नाथपंथी हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। शिव के पूजक हैं और नाथपंथी हैं। इनमें से अधिकांश चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को वोट देते हैं। राजनीतिक रूप से भाजपा के साथ इनका जुड़ाव कोई बहुत पुराना नहीं है। नाथ पंथ के योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद इन नाथ पंथियों का ध्रुवीकरण भाजपा की ओर तेजी से बढ़ा है। इससे पहले ये भाजपा के प्रति इतने अधिक लामबंद नहीं थे।

ऐसे ही कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में नाथपंथी अब भाजपा की ओर उन्मुख हुए हैं। गोरखपुर के आसपास मुस्लिम नाथपंथी जोगी भी हैं। इन जोगियों की बस्ती में भाजपा के प्रति लगाव दिखता है। वहीं उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में बसे सपेरे भी नाथपंथ में विश्वास करते हैं। इन सपेरे सामाजिक समूहों में से अधिकांश योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से गौरवान्वित महसूस करते हैं। भाजपा से उनके लगाव की एक वजह यह भी है।

यहां इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि स्पष्ट हो सके कि भाजपा ने किस प्रकार हिंदुओं के विभिन्न वर्गों, धड़ों और मतों को अपने साथ जोड़ा है। अभी तक जब भी भाजपा के पक्ष में राजनीतिक विश्लेषक हिंदू ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो 'सांप्रदायिक ध्रुवीकरण' को इसका कारण मानते हैं। यह देखते हैं कि किस प्रकार हिंदुत्व की राजनीति ने हिंदू समाज की विभिन्न जातियों को जोड़ने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रणनीति का इस्तेमाल किया है। हम यह नहीं देखते कि किस प्रकार हिंदुत्व की राजनीति ने हिंदू धर्म में सक्रिय अनेक धार्मिक लोकप्रिय पंथों में निहित 'हेजेमोनी' या यूं कहें कि 'प्रभाव शक्ति' का उपयोग उनके समर्थकों को अपने साथ जोड़ने के लिए किया है। पूर्वोत्तर में शंकरदेव के भक्ति पंथ ने तो भाजपा को आधार प्रदान किया ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू धर्म जागरण के अभियान के तहत न केवल सनातन पंथों को वरन् अनेक भक्ति पंथों, छोटे-छोटे संप्रदायों और मठों को अपने साथ जोड़कर एक वृहत समग्र हिंदुत्व का वृत्त बनाने की कोशिश की है।

अनेक अखाड़ों, धार्मिक संगठनों की शक्ति का लाभ भारत में हिंदुत्व की राजनीतिक शक्ति को तो मिला ही है मठों, प्रवचन संघों एवं अनेक धार्मिक सामाजिक संगठनों की बुनावट से भाजपा एवं हिंदुत्व की राजनीति को ताकत मिली है। धार्मिक लोकजगत जैसे कथा मंडलियों, राम कथा प्रवचक संत संगठनों, भागवत कथा आयोजक संघों एवं संतों तथा हिंदू धर्म की अनेक कीर्तन मंडलियों से निर्मित लोकजगत एक प्रकार से हिंदुत्व की विचारधारा के लोकजगत की शक्ति के रूप में काम करते हैं। तमाम संत, कथा वाचकों को भी समय-समय पर भाजपा स्वयं से जोड़ने के लिए संगठन एवं अपनी राजनीति में जगह देती रही है। उमा भारती, साध्वी प्रज्ञा, साध्वी ऋतंभरा और योगी आदित्यनाथ जैसे अनेक संत, कथा वाचक एवं धार्मिक आयोजकों को भाजपा ने अपनी राजनीति में जगह देकर उन्हें एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराया।

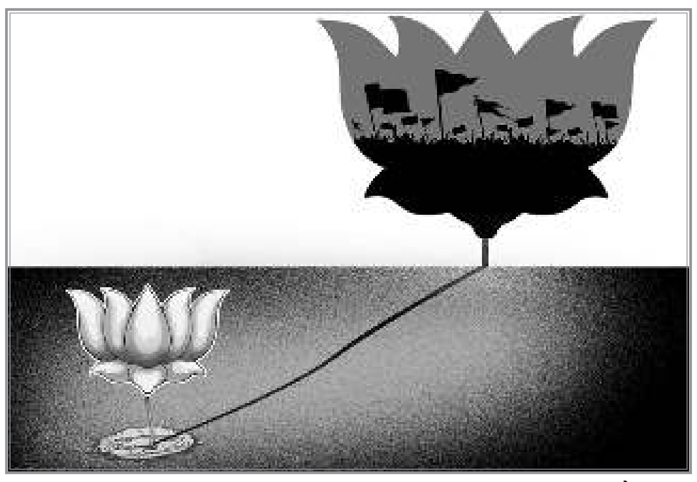

अवधेश राजपूत

अगर बौद्धिक रूप से देखें तो ये कीर्तन मंडलियां, कथा वाचन आयोजक संघ, धार्मिक संस्थाएं हिंदू धर्म की संस्कृति, मूल्यों की चर्चा तो करती ही हैं, राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी समय-समय पर इनमें विमर्श होता रहता है। ये ज्वलंत मुद्दे राष्ट्र एवं जनतंत्र की राजनीति से भी जुड़े होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, संघ से संबद्ध संगठन-धर्म जागरण मंच, ऐसे सार्वजनिक लोकजगत को संयोजित संगठित एवं जोड़ने का काम करते रहते हैं। प्रायः राजनीतिक विश्लेषक ऐसे धार्मिक लोकजगत की विमर्श रचना एवं राजनीतिक झुकाव पैदा करने में विकसित हो रही इनकी प्रभावी भूमिका को समझ नहीं पाते।

भाजपा और संघ से संबंध न रखने वाले लोग आज भी राजनीतिक आधारों के पारंपरिक अर्थ जाति एवं धार्मिक ध्रुवीकरण के सीमित दायरे में ही खोजते हैं। मीडिया कवरेज, राजनीतिक रैली एवं अन्य आयोजनों के अतिरिक्त ये अनौपचारिक रूप से राजनीतिक न होकर राजनीतिक मत सृजित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक लोकजगत उनकी निगाहों से छूट जाते हैं। किसी राजनीतिक तंत्र की तुलना में ये गैर राजनीतिक लोकजगत भारतीय समाज में राजनीतिक झुकाव पैदा करने में ज्यादा कारगर होते हैं। पश्चिमी समाजों में लोकजगत की अवधारणा से थोड़ा भिन्न भारतीय समाज के ये लोकजगत तर्क से ज्यादा विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। तर्क शक्ति से ज्यादा इन समूहों एवं संगठनों के विमर्शों में विश्वास की शक्ति प्रभावी होती है। हिंदू समाज का उच्च वर्ग एवं मध्य वर्ग का एक हिस्सा ऐसे लोकजगत से जुड़ा तो होता ही है। साथ ही कबीर पंथ, रविदास पंथी, शिवनारायण पंथ जैसे अनेक लोकप्रिय पंथों के अपने कार्यक्रमों से सृजित लोकजगत के माध्यम से दलित एवं पिछड़ी जातियों का एक बड़ा शिक्षित एवं गैर शिक्षित वर्ग भी इनसे प्रभावित होता है। यह ठीक है कि दलित पंथों से जुड़े पंथों के लोकजगत में हिंदुत्व का विमर्श पहुंचता ही है। साथ ही साथ बहुजन एवं दलित विमर्श में इनके विमर्शों का हिस्सा होता है। कई जगह ये दोनों प्रकार के विमर्श जुड़ जाते हैं तो कई जगह टकराते भी हैं।

दूरदराज और सीमा प्रांतों में भाजपा का प्रसार मात्र राजनीतिक गतिविधियों या सक्रियता से ही नहीं हुआ है। इन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पंथों एवं उनके द्वारा सृजित लोकजगत ने भी भारत में हिंदुत्व की राजनीति का सामाजिक आधार तैयार करने में महती भूमिका अदा की है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में भाजपा की जो पैठ बढ़ी है, उसमें राजनीति के साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों को जोड़ने की हिंदुत्व की राजनीति ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब राजनीति दिन-प्रतिदिन ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। राजनीति के पारंपरिक अर्थ बदलते जा रहे हैं। जरूरत है राजनीतिक आबद्धीकरण के लिए हो रहे इन नए प्रयासों को समझने की। इनके माध्यम से भारतीय राजनीति के बदलते पक्षों को समझने की जरूरत भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

(लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

खेती को बड़े सहारे की दरकार

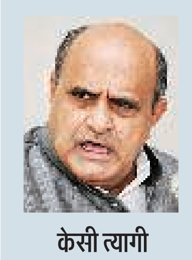

केसी त्यागी

आर्थिक मंदी की स्थिति में खेती-बाड़ी में जान फूंक कर ही अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाया जा सकता है

हरियाणा, महाराष्ट्र एवं झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किसानों के बीच रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों यानी एमएसपी में उत्साहजनक बढ़ोतरी को लेकर आस जगी थी, लेकिन कृषि मंत्रालय द्वारा रबी फसलों के लिए प्रस्तावित एमएसपी में पांच से सात फीसद तक की बढ़ोतरी किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा कदम है। दरअसल कृषि मंत्रालय द्वारा गेहूं, जौ, सरसों, मसूर तथा सूरजमुखी के एमएसपी में क्रमशः 4.61 फीसद, 5.9 फीसद, 5.35 फीसद, 7.26 फीसद और 5.4 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। ज्ञात हो कि पिछले मौसम के दौरान इनका समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल क्रमशः 1840 रुपये, 1440 रुपये, 4200 रुपये, 4475 रुपये तथा 4945 रुपये था। गत वर्ष की कीमतों को आधार मानकर देखें तो निःसंदेह मंत्रालय ने इस वर्ष एमएसपी में औसतन चार से सात फीसद तक की बढ़ोतरी की है, लेकिन यह नाकाफी भी है और किसानों की आय दोगुनी किए जाने के प्रधानमंत्री के आश्वासन को धूमिल करती भी प्रतीत हो रही है।

वर्ष 2019-20 के लिए खरीफ फसल-धान, मूंग, उड़द तथा कपास के एमएसपी में भी प्रति क्विंटल क्रमशः 65, 75, 100 एवं 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खरीफ वर्ष 2018-19 के लिए साधारण धान के एमएसपी में 200 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा निःसंदेह उत्साहित करने वाला रहा था। लंबे अर्से के बाद इसकी कीमत 1750 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी जो कि घोषित 1166 रुपये के लागत मूल्य से 50.09 फीसद अधिक थी। इससे पहले के वर्षों में एमएसपी में सिर्फ 50 से 60 रुपये प्रति क्विंटल जैसी सांकेतिक बढ़ोतरी ही प्रचलन में रही थी। नई कीमतों में आंकड़ों के लिहाज से वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन प्रति वर्ष लागत मूल्यों में हो रही बढ़ोतरी की तुलना में यह नाम मात्र ही है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया है, लेकिन कृषि मंत्रालय के अब तक के प्रयासों में कोई ठोस पहल देखने को नहीं मिली है। फसलों का उचित मूल्य न मिल पाना और साथ ही लागत मूल्यों में निरंतर वृद्धि होते रहना उनकी आमदनी में दोगुनी वृद्धि का संकेत नहीं दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश दलहन एवं तिलहनों की थोक कीमत अपनी तीन वर्ष पूर्व की कीमत से लगभग 15 से 30 फीसद के निचले स्तर पर है। फसलों के लिए निर्धारित एमएसपी भी न मिल पाना किसानों के लिए लंबे समय से बड़ी समस्या बनी हुई है। सिरिल की एक रिपोर्ट के अनुसार किसानों को धान, रागी, बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों आदि निर्धारित एमएसपी से कम कीमतों पर बेचना पड़ा है।

हालिया वर्षों में देश में फसल उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इसके अनुरूप मांग में वृद्धि न होने के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट भी देखी गई है। इसके साथ ही खेती में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि दर्ज हुई है। आरबीआइ की एक रिपोर्ट के अनुसार डीजल का थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआइ वर्ष 2016 में 65 था जो अब बढ़कर 94 तक पहुंच गया है। कीटनाशकों का डब्ल्यूपीआइ पिछले तीन वर्षों में 110 से 120 तक पहुंच गया है। इसी तरह पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्रैक्टर, बिजली, मवेशियों के चारे, मजदूरी आदि की दरों में भी प्रतिवर्ष लगभग पांच से 10 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है। गत वर्षों के दौरान कृषि मजदूरी में भी लगभग 15 फीसद की वृद्धि आंकी गई है। खासकर मजदूरी और खाद के मोर्चे पर बढ़ी महंगाई ने किसानों को सबसे ज्यादा परेशान किया है। इस सूरत में कृषि मूल्य एवं लागत आयोग को जमीनी सच्चाई को समझते हुए लागत मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता है।

मौजूदा सरकार ने फसलों की कीमत को डेढ़ गुना करने वाला अपना वादा निभाने का प्रयास भर किया है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा अनुसार फसलों का एमएसपी तय करने से अब तक परहेज ही किया है। वर्तमान लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के तहत ए-2 एफ-एल को आधार बनाकर फसलों की लागत मूल्य के अनुपातिक एमएसपी बढ़ाया गया है, जबकि किसान संगठनों की मांग रही है कि सी-2 प्रणाली को आधार बनाकर लागत मूल्य निर्धारित किया जाए और इस पर 50 फीसद का अतिरिक्त लाभ दिया जाए। स्पष्ट है कि गतिरोध लागत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को लेकर ही है। प्रक्रिया ए-2 एफ-एल के तहत खेती में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं जैसे-बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, मशीनों का किराया तथा पारिवारिक श्रम शामिल होती हैं जबकि सी-2 व्यवस्था में अन्य लागतों के साथ भूमि का किराया भी जोड़ा जाता है। इसके तहत लागत मूल्य निर्धारण से किसानों को मिलने वाले दाम और मौजूदा व्यवस्था के तहत मिलने वाले दाम में बड़ा अंतर है।

अपने यहां एक समस्या यह भी है कि किसान को हर हाल में घाटे का सामना करना पड़ता है। उत्पादन अच्छा हो तब भी और न हो तब भी। लगभग प्रत्येक वर्ष आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मौसमी सब्जियां आदि औने-पौने दामों पर बेच दी जाती हैं और जब वह दाम भी नहीं मिलता है तो रोष स्वरूप किसान उन्हें सड़कों पर फेंक देते हैं। वहीं शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट में यह बात कही गई थी कि मात्र छह प्रतिशत किसान ही एमएसपी से लाभान्वित हो पाते हैं। वर्ष 2016-17 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में उत्पादित गेहूं एवं चावल का क्रमशः 23 एवं 35 फीसद हिस्सा ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा गया था। इससे एमएसपी प्रणाली के क्रियान्वयन का अंदाजा लगाया जा सकता है। भंडारण क्षमता भी सवालों के घेरे में रही है। इनका प्रतिकूल असर यह है कि प्रतिवर्ष खेती का रकबा घट रहा है। किसान तेजी से मजदूर बन रहे हैं और गांवों से पलायन जोरों पर है। चूंकि वैश्विक मंदी के कारण शहर पहले से बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर हैं, ऐसे में एक बार फिर से खेती-बाड़ी में जान फूंकने जैसी कवायद ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने में कामयाब हो सकती है जिससे पलायन पर भी काबू पाया जा सकेगा। कुल मिलाकर लाभकारी एमएसपी के निर्धारण एवं क्रियान्वयन, उचित मुआवजा, ऋण, कृषि सब्सिडी, किसान पेंशन आदि सुविधाएं इस दिशा में कारगर साबित हो सकती हैं।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मनुष्य और संसार

मनुष्य का जीवन ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य दुर्लभ उपहार है। जो जीवन की विशेषता को समझ जाते हैं, उनका इस संसार में आना सार्थक हो जाता है। मनुष्य सत्य को समझने की कोशिश नहीं करता है और असत्य में आकंठ डूबा रहता है। सिर्फ नश्वर पदार्थों के उपार्जन में जीवन गुजार देता है। अंतिम समय में अंततः नेत्र बंद कर संसार से विदा हो जाता है। ईश्वर ने यह जीवन दिया है कि मनुष्य इस संसार में कुछ करके जाए। मगर वह कर्म और पुरुषार्थ की अनदेखी कर माया-मोह को ही असली संसार समझता रहता है। यह संसार किसी को कुछ देता नहीं है, सिर्फ लेता ही है। अतः आप संसार को अपने जीवन की सत्य पहचान दे करके अपनी कुछ निशानी छोड़ जाएं, ताकि संसार-वासी अपकी आरती उतारें, याद करें, आंसू बहाएं।

सबसे प्रेम-सहकार, सहयोग, परोपकार, सहानुभूति, आत्मीयता का बर्ताव रखें। फिर आपकी दुनिया निराली बन जाएगी। आप सबके चहेते बन जाएंगे। बुराइयों से दूर रहें। अपने जीवन का पल-पल सिर्फ सृजन में लगाएं। समझें कि यह दुनिया नश्वर है, मनुष्य का जीवन भी नश्वर है। शाश्वत, सत्य उसका किया गया पुण्य कर्म है। आजीवन इसी की उपासना-आराधना में राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और विवेकानंद जैसे महापुरुषों की तरह लगे रहें। आवश्यकता है आज जीवन और संसार को समझने की। अगर इन्हें आप समझ जाएंगे तो आपका संसार सुंदर बन जाएगा, संवर जाएगा। कहा जाता है कि जैसा विचार वैसा ही संसार। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। आप इस संसार में निर्विकल्प, निर्विकार, निर्दोष, निरंहकार, निश्च्छल जीवन जीने की आदत बनाएं। कुपरंपराओं ने जो आपके मन-मस्तिष्क को दूषित कर दिया है, जो दोष-दुर्गण भर दिया है, उनकी जड़ों को उखाड़ फेंकें। उन्हें सत्य नहीं मानें। सतत आत्मचिंतन, आत्मा-मनन करते रहें। सत्य की प्रेरणा, सहयोग स्वयमेव आपको मिलते रहेंगे। फिर आपका जीवन सुखमय और गौरवशाली होगा। मनुष्य के शाश्वत कर्म की विजय अवश्य होती है।

मुकेश ऋषि

भारी पड़ती सुरक्षा मानकों की अनदेखी

मीनाक्षी भटनागर

हम भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण कार्य नहीं कर रहे, बल्कि अंधाधुंध विकास की दौड़ में भागे जा रहे हैं

वास्तव में आज भी भूकंप की भविष्यवाणी कर पाने में हम नाकाम हैं। भूकंप को हम रोक नहीं सकते, लेकिन जापान जैसे देशों की तरह उससे बचने के प्रयास तो कर ही सकते हैं। जरूरी है कि हम उनसे जीने का तरीका सीखें। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोगों को भूकंप के बारे में बहुत कम जानकारी है। फिर हम भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्य भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंधाधुंध विकास की दौड़ में बेतहाशा भागे ही चले जा रहे हैं। दरअसल हमारे यहां सबसे अधिक संवेदनशील जोन में देश का हिमालयी क्षेत्र आता है। पूर्व में भुज, लातूर और उत्तरकाशी में आए भयावह भूकंप के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि सरकार निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों को लागू करने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएगी, लेकिन उससे नाउम्मीदी ही हाथ लगी? देश की राजधानी दिल्ली सहित सभी महानगरों में गगनचुंबी बहुमंजिली इमारतों, अट्टालिकाओं की शृंखला शुरू हुई जिसके चलते आज शहरों-महानगरों में आसमान छूती मीनारें दिखाई देती हैं। और यह सब बीते पंद्रह-बीस वर्षों के ही विकास का नतीजा है। जाहिर सी बात है कि इनमें से दो प्रतिशत ही भूकंप रोधी तकनीक से बनाई गई हैं। यही बहुमंजिली आवासीय इमारतें आज भूकंप आने की स्थिति में हजारों मानवीय मौतों का कारण बनेंगी।

समूची दुनिया की तकरीबन 90 फीसद जनता आज भी भूकंप संभावित क्षेत्र में पुराने तरीके से बने मकानों में रहती है जिसकी वजह से भूकंप आने की दशा में सर्वाधिक जनधन की हानि होती है। इसलिए भूकंप से बचने की खातिर ऐसे मकानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भवन निर्माण से पहले लोग भूकंपरोधी निर्माण दिशा-निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करें एवं भवन निर्माण उसके आधार पर करें। इसमें मात्र 5 फीसद ही अधिक धन खर्च होगा, अधिक नहीं। यह जान लें कि भूकंप नहीं मारता, मकान मारते हैं। इसलिए यह करना जरूरी है।

दरअसल संकट के समय खतरों के बारे में जानना एवं उसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए कुछ जरूरी वस्तुएं जैसे टार्च, मोमबत्तियां, माचिस, रेडियो, प्राथमिक उपचार की किट हमेशा तैयार रखें, खाद्य सामग्री एवं पीने के पानी का भंडार रखें तथा कांच की खिड़की और गिरने वाली सभी वस्तुओं से दूर रहें। भूकंप आने पर तुरंत खुले स्थान की ओर भागें, यदि न भाग सकें तो दरवाजे की चौखट के सहारे बीच में, पलंग, मेज के नीचे छुप जाएं, ताकि ऊपर से गिरने वाली वस्तु की चोट से बच सकें। यदि वाहन पर सवार हैं तो उसे सड़क किनारे खड़ाकर उससे तब तक दूर खड़े रहें जब तक आप आश्वस्त न हो जाएं कि अब खतरा टल गया है। इसमें दो राय नहीं कि भूकंप से हुए विध्वंस की भरपाई असंभव है। आज देशवासी मौत के मुहाने पर खड़े हैं। स्थिति की भयावहता को सरकार खुद स्वीकार भी कर चुकी है। निष्कर्ष यह है कि भूकंप से बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए समाज, सरकार, वैज्ञानिक और आम जनता सबको प्रयास करने होंगे।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

ए-वी मॉडल कम करेगा आपदाओं का असर

आपदाओं का असर घटाने की पहल शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल दिया है। वास्तव में आपदा जोखिम में अकाल, सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए और कुछ क्या किया जाना चाहिए इस पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मेरा मानना है कि आपदा रोधी एवं जलवायु रोधी अवसंरचना के लिए राष्ट्रव्यापी सिंचाई एवं जल निकासी नेटवर्क की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से आगामी वर्षों में जल प्रबंधन, जल उपलब्धता आदि बहुत कठिन हो जाएगी। सवाल है कि इसके समाधान के लिए कौन-सा मॉडल अपनाना चाहिए? मेरे विचार से इस मॉडल का एक प्रारूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कथन में समाहित है जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमि मानव शरीर की तरह ही है। इस मॉडल को वैज्ञानिकों ने ए-वी मॉडल नाम दिया है। आर्टरी-वेन मॉडल में आर्टरी जलापूर्ति की लाइन है और वेन जल निकासी की लाइन है। मेरा विश्वास है कि यह मॉडल हमारे बुनियादी ढांचे को लंबा जीवन दे सकता है। इससे जल संकट का समाधान भी हो सकता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति से देश में आपदा रोधी ढांचा बनाया जा सकता है। सरकार को इस मॉडल पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

प्रोफेसर मान सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

दिल्ली में अपराध

दिल्ली में एक बार फिर अपराध चरम पर है। रोजाना हो रही झपटमारी और लूट की घटनाओं से इस शहर की पहचान बनती जा रही है। लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह हाई प्रोफाइल लोगों को भी नहीं छोड़ रहे। चाहे दिन हो या रात लोगों में लूट का भय बना रहता है। ऐसे मामलों को अंजाम देते वक्त अक्सर अपराधी हथियार लेकर चलते हैं। विरोध एवं खतरा होने पर गोली चलाने से भी नहीं चूकते। अपराधियों के बढ़ते हौसलों के साथ-साथ आम नागरिकों में खौफ और भय बढ़ता जा रहा है। ऐसे मामलों में गिरफ्तार अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

raialokk97@gmail.com

अब आलू महंगा

पहले प्याज, फिर टमाटर और अब आलू की मार। ना जाने प्रकृति भारत के आम लोगों को महंगाई की मार से कब तक रुलाएगी? सबसे सस्ता और आम लोगों के लिए जीवन यापन का मुख्य साधन माने जाने वाला आलू भारी बारिश के कारण देर से खेतों में रोपा जाएगा। इस कारण नए आलू को बाजार में आने में देर लग सकती है। किंतु इन सब के बीच सरकार की क्या रणनीति रहती है, यह देखना होगा। क्या सरकार इस आलू की कमी की भरपायी कर पाएगी? इस भयानक मंदी के दौर में सरकार के आगे अनेक चुनौतियां हैं, किंतु आम जनता के हित के लिए सरकार को इस समस्या का हल खोजना ही होगा। उम्मीद है इस आलू के महंगाई के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी। दूसरी ओर सरकार से भी उम्मीद है कि वह इस चुनौती से निपटने के लिए कोई ठोस कदम अवश्य उठाएगी।

anupamyadavay943@gmail.com

खतरे की घंटी

दिल्ली में एक बार फिर वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। यह प्रदूषण पंजाब-हरियाणा में जलाई जा रही पराली के धुएं के आने से बढ़ा है। अभी दीपावली बाकी है, जब लोग पटाखे छोड़ेंगे। इससे और प्रदूषण बढ़ेगा। दिल्ली वालों को जहरीली आबोहवा में जीवन व्यापन करना होगा। सरकार को समय रहते इससे बचाव के उपाय करने चाहिए।

श्रीनिवास बिश्नोई, दिल्ली विवि

भाषा से देश की पहचान

कभी संस्कृत भाषा का ज्यादा प्रचलन था। धीरे-धीरे लोग हिंदी भाषा बोलने लगे और अब संस्कृत कुछ लोगों की भाषा बनकर रह गई है। आजकल जिस तरह माता-पिता अपने बच्चों को हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी पढ़ने पर जोर दे रहे हैं, अगर यही स्थिति बनी रही तो एक दिन हिंदी को लोग भूल जाएंगे। भाषा को लेकर यह शुभ संकेत नहीं है। हिंदी भारत में ही नहीं, बल्कि कई दूसरे देशों में भी बोली जाती है। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा से होती है, इसलिए अपनी भाषा को समृद्ध करने की जरूरत है। हर माता-पिता को अपने बच्चों को हिंदी जरूर पढ़ानी चाहिए।

मो. जमील, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

2025 तक 5जी स्पेक्ट्रम से एक ट्रिलियन डॉलर की कमाई करने में सक्षम हो सकता है भारत, अमेरिका की एक संबंधित कंपनी डेलोइट के एक अनुमान के अनुसार।

आजकल

पराली प्रबंधन से हो वायु प्रदूषण का निदान

दिल्ली एनसीआर में लगभग प्रत्येक वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। इसका बड़ा कारण इस दौरान पंजाब और हरियाणा में व्यापक तादाद में पराली को जलाना माना जाता है। हालांकि वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के लिए केवल यही कारक सर्वाधिक जिम्मेदार नहीं है, फिर भी सरकार को उन कारणों को समझना चाहिए कि आखिर किसान पराली क्यों जलाते हैं। सरकार को किसानों द्वारा पराली जलाने को हतोत्साहित करने के अलावा किसानों को इसके विकल्प अपनाने पर जोर देना चाहिए

पुष्पेंद्र सिंह
अध्यक्ष, किसान शक्ति संघ

धान की फसल की कटाई के साथ ही उत्तर भारत विशेषकर पंजाब और हरियाणा में धान की फसल के अवशेष (पराली) जलाने से इस पूरे इलाके में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इससे अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली एनसीआर की हवा भी बहुत खराब हो जाती है। परंतु इस समय बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के स्तर के लिए केवल आसपास के राज्यों में किसानों द्वारा पराली जलाना ही जिम्मेदार नहीं है। आइआइटी कानपुर के एक अध्ययन के अनुसार इन महीनों में दिल्ली के प्रदूषण में केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही पराली जलाने के कारण होता है। दिल्ली एनसीआर का अपना खुद का प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पराली जलाने की घटना में भारी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। हमें समझना होगा कि कृषि एक आर्थिक गतिविधि है। किसान स्वयं भी पराली जलाने के दुष्परिणाम जानते हैं और इनके प्रति सचेत हो रहे हैं। इस वर्ष धान की एमएसपी 1,815 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है, जबकि अन्य धान उत्पादक एशियाई देशों जैसे बांग्लादेश, चीन, फिलीपींस से लेकर थाईलैंड तक में यह भारतीय रुपये में 2,500 से लेकर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल है।

पराली जलाने वाले प्रदेशों पंजाब और हरियाणा में एक तो मजदूरी महंगी है और दूसरे धान की कटाई के वक्त पर्याप्त संख्या में मजदूर भी उपलब्ध नहीं हो पाते। दरअसल मनरेगा जैसी योजनाओं के चलते किसानों को सस्ते मजदूर नहीं मिलते। पंजाब और हरियाणा में पहले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मजदूर आते थे, परंतु अब स्थानीय स्तर पर अपने राज्यों में ही मनरेगा के माध्यम से मजदूरी मिलने के चलते कम संख्या में मजदूर पलायन करते हैं। किसानों को अक्टूबर-नवंबर में खेत खाली करने की जल्दी भी रहती है, क्योंकि उन्हें रबी की फसल आलू, मटर, सरसों, दलहन, गेहूं आदि की बोआई के लिए भी खेत तैयार करने के लिए कम दिनों का ही समय मिलता है। मशीन से कटाई तेज भी होती है और ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती, परंतु डीजल के प्रयोग से प्रदूषण जरूर होता है। मशीन से कटाई के बाद पराली जलाने से केवल प्रदूषण ही नहीं होता, बल्कि जमीन से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों और जमीन की उर्वरता का भी ह्रास होता है। इस कारण अगली फसल में और ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे देश पर खाद सब्सिडी का बोझ भी बढ़ता है और किसानों की लागत भी। चूंकि खाद का हम बड़ी मात्रा में आयात करते हैं तो इससे हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ता है, जिसके अपने अलग नुकसान हैं।

पराली जलाने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड समेत अनेक जहरीली गैसों से स्वास्थ्य का नुकसान तो होता ही है, धरती का तापमान भी बढ़ता है, जिसके बहुत से अन्य गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। इससे भविष्य में फसलों की पैदावार बड़ी मात्रा में घटने का अंदेशा भी विशेषज्ञों द्वारा जताया जाता है जिससे खाद्य संकट पैदा हो सकता है।

पराली से बिजली बनाने या उसका कोई अन्य प्रयोग करने वाले सुझाव भी सीधे या परोक्ष रूप से प्रदूषण को ही बढ़ाते हैं। मशीनों से पराली प्रबंधन के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं उनकी अपनी समस्याएं भी हैं। इसके लिए प्रचलित हैप्पी सीडर व अन्य मशीनों के प्रयोग के लिए 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-20 में दो वर्ष में इस मद में 1,152 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। मशीन से खेत काटने और बाद में हैप्पी सीडर या एसएमएस (पराली प्रबंधन प्रणाली) मशीन को चलाने में भी तो डीजल का ही प्रयोग होता है जिससे किसान का खर्चा और प्रदूषण दोनों बढ़ता है। किसानों का मशीनों से पराली निस्तारण में लगभग दस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। इस खर्च को वहन करने की ना तो किसान की क्षमता है और ना ही उसे इसमें कोई लाभ दिखाई देता है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने धान की कई नई उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं जो ना केवल अन्य प्रचलित प्रजातियों से ज्यादा उत्पादन देती हैं, बल्कि ये कम पानी, कम समय में तैयार हो जाती हैं और उनमें कीटों या बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। इन प्रजातियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके प्रयोग से अगली फसल की तैयारी के लिए किसान को ज्यादा समय मिलेगा। पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश भर में धान की पराली कहीं भी नहीं जलाई जाती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अधिकांश धान हाथ से काटा जाता है और फिर हाथ से ही झाड़ कर निकाला जाता है। हाथ से काटने और झाड़ने में एक तो कोई प्रदूषण नहीं होता, डीजल का खर्चा बचता है और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को खूब रोजगार भी मिलता है। धान झाड़ने के बाद पराली के गट्ठर बना लिए जाते हैं। धान की कुछ प्रजातियों की पराली तो कुट्टी के रूप में काटकर सारी सर्दी पशुओं के हरे चारे में मिलाकर उन्हें खिलाई जाती है जिसे पशु खूब चाव से खाते हैं। इस प्रक्रिया में कोई प्रदूषण नहीं होता।

इस तरह धान की पराली का प्रबंधन, इस्तेमाल और निस्तारण बहुत ही सरल, जैविक और प्रदूषण रहित तरीके से हो सकता है। इसके लिए सरकार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने वायदे के अनुसार कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित संबंधित लागत के डेढ़ गुने के आधार पर घोषित करे। दूसरा धान की कटाई और झड़ाई में लगे मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से सरकार अपनी तरफ से भुगतान करे। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले वर्ष धान की खरीद पर 300 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया था, तो पंजाब और हरियाणा की सरकारें भी केंद्रीय सहयोग से ऐसा कर सकती हैं। एक तरफ हम किसानों को बाकी देशों के मुकाबले धान की सबसे कम एमएसपी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि किसान अपने खर्चे पर पराली प्रबंधन करें, तो ऐसा कैसे संभव है?

उर्वरक सब्सिडी, व्यापार घाटे, प्रदूषण, बढ़ते तापमान, स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में बड़ी कीमत तो देश चुका ही रहा है। यदि इस कीमत का कुछ हिस्सा ही सीधे किसानों को धान की उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल की कटाई के लिए मनरेगा पोषित मजदूरों या प्रति हेक्टेयर सब्सिडी के रूप में दे दिया जाए तो कहीं कम कीमत चुकाकर हम पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से बच सकेंगे और बेहतर पर्यावरण संरक्षण कर सकेंगे।

ठोस पहल से हल होगा खेती का संकट

रवि शंकर

भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने बीते दिनों राजधानी दिल्ली की सीमा के निकट विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से वे स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे थे। दरअसल खेती- किसानी का सवाल पिछले कई वर्षों से देश की मुख्य समस्याओं में शुमार है, फिर भी कोई ठोस हल नहीं निकाला जा रहा। किसानों के सामने आज खेती घाटे का सौदा बनकर रह गई है। आर्थिक मानकों पर किसान आज बेहद असुरक्षित हैं। कम आय और बढ़ती लागत ने कृषि संस्कृति को संकट में डाल रखा है।

हालात यह है कि आज हमारे किसानों को अपनी उपज का दाम तय करने का हक नहीं है। सरकार द्वारा तय किया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य एक मजाक बनकर रह गया है। किसान के पास बचत की रकम जमा होने की हालत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और वह बैंको या साहूकारों के कर्जों से खर्च चलाता है। ऐसे में कर्जे चुकाने और नई फसल बोने के लिए उसे अपनी उपज तुरंत बेचनी पड़ती है। किसान के पास ना तो दूर-दराज के बाजारों तक फसल को ढोकर ले जाने के साधन हैं और ना ही उसके भंडारण की सुविधा। उपज की कम कीमत का फायदा उठाकर भंडारण करने वाले संगठन बेहद सस्ते दामों पर इस उपज को हथिया लेते हैं और बाद में मनमाने दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि किसान की चौतरफा लूट होती है। सबसे पहले उसे खेती की लागतों में लूटा जाता है। दूसरे, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ते जाने से बढ़ी महंगाई के जरिये किसान को लूटा जाता है। तीसरे, उसकी उपज सस्ते से सस्ते दामों पर हड़पी जाती है। चौथे, जब किसान की आय उसकी जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती तो मजबूरन उसे बैंको या साहूकारों से मोटे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। ये सब किसान की बदहाली की वजहें हैं।

इन्हीं कारणों से भारत में सबको अन्न देने वाला किसान आज कर्ज के तले दबा हुआ है या फिर आत्महत्या करने को विवश है। पुरानी कहावत है कि भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही पूरा जीवन जीता है और कर्ज में मर जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक घाटे का सौदा होने की वजह से हर रोज ढाई हजार किसान खेती छोड़ रहे हैं। और तो और, देश में अभी किसानों की कोई एक परिभाषा भी नहीं है। वित्तीय योजनाओं में, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और पुलिस की नजर में किसान की अलग-अलग परिभाषाएं हैं। यह उस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है जहां की 60 प्रतिशत आबादी खेती-किसानी से जुड़ी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों की समस्या का एक ही समाधान है- कृषि लागत पर नियंत्रण और कृषि उपज की वाजिब कीमतें सुनिश्चित करना। आज भी खाद्य पदार्थों की महंगाई को काबू में रखने के लिए किसानों को वाजिब कीमत नहीं दी जा रही है, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि अनाज उपजाने की उन्हें सजा ही दी जा रही है। सरकारों का खेती-किसानी के प्रति जो रवैया है उसे देखते हुए किसान यह नहीं समझ पाता है कि वह लाभ के लिए खेती करता है या घाटे के लिए करता है। असल में किसानों की विभिन्न चिंताएं दूर करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की आबादी का एक बड़ा भाग आज भी कृषि पर आश्रित है। कृषि क्षेत्र की अनदेखी कर विकास को स्थायित्व प्रदान करने की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बात सही है कि सरकार ने 2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को ठोस कार्य योजना से ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकार को कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। विकास दर में उछाल को बरकरार रखने के लिए विकास के सभी क्षेत्रों की ओर समान ध्यान देने की जरूरत है।

यह ठीक है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया कि किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसके तहत अब सभी किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। यह भी ठीक है कि सरकार के इस कदम से किसानों को कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उनके लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

आंसुओं की भी फितरत होती है

शांतिलाल जैन

कुदरत हैरान थी। इतना पानी बरसाया, मगर बांध लबालब नहीं हो पाया। कुदरत हार मानने को ही थी कि कचरू की आंख से एक आंसू छलका, सरोवर में गिरा और छलक गया बांध। चारों ओर पानी ही पानी। बैकवाटर है श्रीमान। एक चुल्लू पीकर तो देखिए। मीठा लग रहा है ना! आंसुओं की फितरत होती है, जब इंसान स्वयं के पीता है, तो वे खारे लगते हैं, जब दूसरों के पीता है तो फीके। मगर जब दूसरों के एंजॉय करता है तो मीठे लगते हैं। विकास जिनके घरों का बंधुआ है- मीठे आंसुओं की उनकी प्यास बुझती नहीं।

तो आइये श्रीमान, दिलकश नजारा है। जहां गांव थे, वहां पानी ही पानी है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेसिनेटिंग डेस्टिनेशन। एक्वाजॉगिंग, वाटर एरोबिक्स, स्कीइंग, कयाकिंग, केनोइंग या फिर रिवर राफ्टिंग हो जाए। क्या कहा आपने, राफ्टिंग कैसे करते हैं? कमाल करते हैं आप। कभी बाढ़ में डोंगियों पर जिंदगी बचाने का संघर्ष करते मजलूम नहीं देखे आपने?

आइए, जंगल सफारी एंजॉय कीजिए। अब ये आदिवासी-मुक्त क्षेत्र है। झोपड़े थे उनके, मिट्टी के चूल्हे, हंडा, कड़छी, चटाई, छोटी-सी एक पूरी दुनिया, जो अब डूब गई है। बस एक जिंदगी बच गई थी, जिसे लेकर वे मजदूरी करने शहरों की ओर निकल गए हैं। मिलेंगे आपको, शहर के लेबर चौक पर।

यहां से देखिए, जहां तक नजर जाएगी, पानी ही पानी दिखेगा आपको। डूबने को तो गांव के गांव डूब गए हैं, मगर चुल्लू भर पानी में कोई नहीं डूबा। डूबेगा भी नहीं। जो दूसरों को डुबोने की योजना पर काम करते हैं, वे चुल्लू भर पानी के पास भी नहीं फटकते हैं। बोतल में लिए चलते हैं, लीटर भर। वाटर ऑफ कॉर्पोरेट, वाटर फॉर कॉर्पोरेट। विकास की अट्टालिकाओं के निर्माण में पानी आंख का लगता है श्रीमान और जिनकी ये अट्टालिकाएं हैं, उनकी आंखों में बचा नहीं। सो, कचरू, दत्तू, मोहन, बेनीबाई, कमलाबाई या मानक काका की आंखों से छलकवा लेते हैं। कुदरत नदी में पानी लाती है, वे मजलूमों की आंख में लाते हैं।

बहरहाल, तब भी बद्दुआएं देना कचरुओं की तासीर में नहीं है। एक आंसू ढलका कर जी हल्का कर लेते हैं, फिर निकल जाते हैं रोजी-रोटी और नई झोपड़ी की तलाश में किसी शहर की ओर। जमाना उन्हें जीने नहीं देता, जिजीविषा है कि उन्हें मरने नहीं देती। जिजीविषा कुदरत को परास्त नहीं कर पाती, मगर वो उसे हैरान तो कर ही देती है।

ट्वीट-ट्वीट

अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने पर अभिभूत हूं। वह इसके सच्चे हकदार हैं। अभिजीत उसी जेएनयू के छात्र रहे हैं जिस संस्थान को बदनाम करने की हरसंभव कोशिश की गई। उनके शोध ने तमाम भारतीय युवा विद्वानों को प्रेरित किया है।

रामचंद्र गुहा@Ram_Guha

कुछ लोग इसलिए खुश हैं कि अभिजीत बनर्जी जेएनयू के हैं। वहीं कुछ इसलिए खुश हैं कि वह कोलकाता के हैं। मगर मुझे लगता है कि हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि वह भारतीय मूल के हैं और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भारत में गरीबी मिटाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

भारतीय क्रिकेट पहले से ही बहुत शानदार स्थिति में है और अगर सौरव गांगुली उसकी कमान वैसे ही संभालते हैं जैसे उन्होंने भारतीय टीम को नेतृत्व प्रदान किया था तो भारतीय क्रिकेट के भविष्य की तस्वीर और बेहतर एवं सुखद नजर आती है।

जॉय भट्टाचार्य@joybhattacharj

जागरण जनमत

कल का परिणाम

प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो से समुद्र तटों पर स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ेगी?

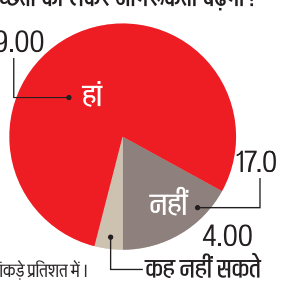

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या सौरव गांगुली का बीसीसीआइ प्रमुख बनना भारतीय क्रिकेट के लिए फायदेमंद होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कहने को हैं सभ्य पर दशा कही ना जाय,
जगह-जगह अब देश में भीड़ कर रही न्याय।
भीड़ कर रही न्याय चलन है यह हैवानी,
पुलिस तंत्र को आज पड़ रही मुंह की खानी।
आपस का सौहार्द्र लगा है अब तो ढहने,
जाओगे अब आप कहां कुछ सुनने-कहने!

– ओमप्रकाश तिवारी

महाराष्ट्र डायरी

कहानी 'थके हुए' चेले और 'स्मार्ट' गुरु की

ओमप्रकाश तिवारी
मुंबई ब्यूरो प्रमुख

पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का यह कहना कि हमारे तो नेता ही हमें छोड़कर चले गए, और फिर सुशील कुमार शिंदे का कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को थकी हुई पार्टी बताकर आपस में विलय का सुझाव देना कांग्रेस की अति हताश स्थिति का परिचय देने के लिए काफी हैं। दूसरी ओर शिंदे के इस बयान के बाद कांग्रेस के युवा नेता यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमें थकानेवाले लोग कौन हैं? सुशील कुमार शिंदे का यह बयान उस समय आया है, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर है, और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरे जाने की जरूरत है।

शिंदे ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को अपनी ही उम्र का बताते हुए कहा कि हम दोनों की तरह कई और नेता भी बुजुर्ग हो चले हैं, इसलिए हमारी पार्टियां थकी हुई महसूस कर रही हैं। अब इन दोनों पार्टियों का आपस में विलय हो जाना चाहिए। संभव है शिंदे ने यह बात पार्टी के हित में अच्छी भावना से कही हो, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी का शिखरकाल भी देखा है और अब बुरा वक्त भी देख रहे हैं। पार्टी की यह स्थिति उन्हें कचोटती होगी। पार्टी को इस बुरे वक्त से निजात दिलाने के लिए उनके मन में यह विचार आया होगा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक होकर भाजपा-शिवसेना का मुकाबला और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। शिंदे ने महाराष्ट्र में पवार का नेतृत्व देखा है। वास्तव में पुलिस सेवा से जुड़े रहे सुशील कुमार शिंदे को राजनीति में आने की प्रेरणा देनेवाले शरद पवार ही थे। उन दिनों शिंदे मुंबई की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में सब इंस्पेक्टर थे, और राजनीति जगत की सूचनाएं जुटाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन जाना पड़ता था। वहीं उनकी मुलाकात तब के युवा विधायक शरद पवार से हुई। उन्हीं की प्रेरणा से शिंदे ने राजनीति में कदम रखा और विधायक चुने गए। शिंदे की सोच इस मामले में सही हो सकती है कि इस समय कांग्रेस में (महाराष्ट्र

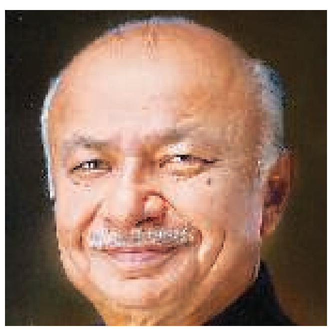

और दिल्ली दोनों जगह) उन्हें शरद पवार जैसा सूझ-बूझ वाला नेता दूसरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। हो सकता है, वह यह भी सोच रहे हों कि जब राहुल के रणछोड़दास साबित होने के बाद पुनः सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभाल सकती हैं, तो अपेक्षाकृत अधिक अनुभव वाले उनके पुराने मित्र शरद पवार में क्या कमी है? संभव है, उन्हें पवार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का तारनहार दिखाई दे रहा हो! लेकिन उनकी इन भावनाओं को समझे बिना फिलहाल तो उनकी आलोचना शुरू हो गई है। वह भी सबसे पहले शरद पवार ने ही उनकी बात काटते हुए बयान दे दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रमुख मैं हूं। मैं अपनी पार्टी की स्थिति शिंदे से ज्यादा बेहतर जानता हूं। हमारी पार्टी पूरी तरह ऊर्जावान है और हम चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। शिंदे अपनी पार्टी पर ध्यान दें।

दरअसल कांग्रेस-राकांपा के विलय की बात शिंदे के मुंह से पहली बार नहीं उठी है। पहले भी कई बार दोनों दलों के विलय की बात उठ चुकी है। लगभग छह माह पहले जब राकांपा प्रमुख सोनिया गांधी से मिलने गए थे, तब भी यह बात उठी थी। पवार ने तब भी इसका खंडन ही किया था। संभवतः शिंदे दोनों दलों का हित सोचते हुए खुले दिल से यह बात कही हो। लेकिन राकांपा अध्यक्ष राजनीति में शिंदे के गुरु तो हैं ही, वह शुरू से राजनीति के शातिर खिलाड़ी रहे हैं। उनकी नजर में हमेशा अपना, अपने परिवार और अपने समूह का हित सर्वोपरि रहा है। यही कारण है कि वह अब तक कई बार कांग्रेस छोड़कर पुनः उसी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जब अवसर मिला, वह एक राष्ट्रीय पार्ट के राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए, और जब वहां नहीं पटी तो क्षेत्रीय दल के छत्रप। इसी रणनीति के तहत उन्होंने 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया और तबसे लगातार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्वयं ही बने हुए हैं। तब उनका साथ देनेवाले तारिक अनवर और पीए संगमा को भले ही तब अमर-अकबर-एंथोनी की तिकड़ी माना गया हो, लेकिन वे कभी इस पार्टी के शीर्ष पद पर नहीं पहुंच पाए। अब संगमा रहे नहीं, और तारिक अनवर कांग्रेस में वापस जा चुके हैं। जानकार मानते हैं कि पवार के लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, वो चाहे किसी भी रूप में मिले।

यही कारण है कि 1999 में जिस कांग्रेस से अलग हुए, मौका मिलते ही उसी कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य की सत्ता हासिल करने में उन्होंने जरा भी गुरेज नहीं किया। इसी तरह 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब भाजपा सत्ता से 23 सीट पीछे, यानी 122 सीट पर सिमट कर रह गई, और शिवसेना उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, तो पवार ने अपने 40 विधायकों का समर्थन देकर देवेंद्र फड़नवीस की सरकार कई महीनों तक टिकाए रखी। इसमें बहाना तो राज्य को स्थिर सरकार देने का था, लेकिन लालसा मौका मिलने पर सत्ता में बने रहने की भी थी। आगे भी पवार का फायदा कांग्रेस जैसे बड़े राष्ट्रीय दल में शामिल होने में नहीं, बल्कि एक छोटे दल के रूप में मजबूती हासिल करने की है। ताकि अवसर मिलने पर जोड़तोड़ करके राज्य की सत्ता में वापसी की जा सके।

मुद्दा

5जी की तैयारी और आशंकाएं

दुनिया भर में 5जी शुरू करने की तैयारी के बीच कुछ देशों ने इस पर काम तेज कर दिया है। भारत में चीन की एक कंपनी को इसकी मंजूरी देने की आशंकाओं के बीच कई सवाल पैदा हुए हैं

पुष्परंजन
वरिष्ठ पत्रकार

फाइव-जी आते ही भारत में इंटरनेट क्रांति को और तेज गति मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कहा जा रहा है कि 5जी आभासी दुनिया को और स्पष्ट व करीब लाएगा। आप अपने स्मार्ट होम को बेहतर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। कार से लेकर कर्मचारी तक आपकी निगाहों में होंगे। सबसे बड़ी बात, इस तकनीक के माध्यम से ग्रामीण भारत, शहरी भारत के साथ और तेजी से जुड़ेगा। 5जी एयर वेब की नीलामी से भारत सरकार को इस वर्ष 84 अरब डॉलर की कमाई होगी, ऐसा अनुमान टेलिकॉम उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ लगा रहे हैं। अमेरिकी कंपनी डेलोइट ने इस अनुमान को और पंख लगा दिए हैं। डेलोइट का मानना है कि 2025 आते-आते भारत 5जी स्पैक्ट्रम से एक ट्रिलियन डॉलर की कमाई करने लगेगा।

इस समय चीन और अमेरिका के बीच भारत के 5जी मार्केट शेयर को हासिल करने की प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है। जी-20 की ओसाका बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी पैरोकारी कर चुके थे कि भारत एक ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित डिजिटल अर्थव्यवस्था में अमेरिका को प्राथमिकता दे। इस संबंध में एक अपुष्ट खबर यह भी है कि चीन की एक प्रमुख टेक कंपनी हुवावेई ने 5जी का ट्रायल शुरू कर दिया है। दरअसल फाइव-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी वर्ष के आखिर तक करने की तैयारी है, जिसे देखते हुए विदेशी प्रतिस्पर्धी सत्ता के गलियारे में पूरी तरह से सक्रिय है। भारत में मुकेश अंबानी की कंपनी इसके बड़े हिस्से को हासिल करना चाहेगी, इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए। एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां इसमें कहां तक टिकती हैं, यह भी दो महीने बाद बाजार का रोचक विषय होगा।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी मान रहे हैं कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी 70 अरब डॉलर के इर्द-गिर्द होगी। जो कंपनियां इतनी बड़ी राशि लगाएंगी, उन्हें बाजार से कमाई भी उसी रफ्तार में करनी होगी। 4जी से कंपनियों ने कितना पैसा वसूल किया, यह भी लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में जासूसी के लिए कुख्यात चीनी कंपनी हुवावेई को 5जी स्पेक्ट्रम में जगह क्यों दी जा रही? इसी वर्ष जून में सरकार के टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद हुवावेई की प्रोफाइल को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके थे। सरकार ने एक पैनल का गठन इस बात की जांच के वास्ते की है। मगर, क्या इससे पहले हुवावेई जैसी कंपनी 5जी तकनीक का ट्रायल कर सकती है? ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना सरकार की अनुमति के हुवावेई या कोई भी कंपनी ट्रायल कर ले? यह खबर गलत भी हो सकती है। जून में स्वयं टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सौ दिनों के भीतर हम परीक्षण की प्रक्रिया आरंभ करा देंगे। इसके सफल होने और ग्लोबल टेंडर हो जाने के बाद 5जी को 2020 की शुरूआत में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा।

पूरी दुनिया में सबसे पहले दक्षिण कोरिया ने 5जी तकनीक को व्यावसायिक रूप से आरंभ करने का श्रेय लिया है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सोल की एसके टेलीकॉम कंपनी ने अप्रैल 2019 से 5जी तकनीक को बाजार में उतारा है। चीन ने तीन टेलीकॉम ऑपरेटरों को इसका लाइसेंस जून के शुरू में जारी किया है।

चीनी कंपनी हुवावेई क्या साफ-सुथरी है? यह सवाल 12 जुलाई 2019 को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की एक संगोष्ठी में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य वी कामकोटि ने उठाया। उन्होंने आशंका जताई कि जिस कंपनी पर दुनिया के बड़े देशों ने जासूसी का आरोप लगाया है, उसे 5जी स्पेक्ट्रम का ठेका देने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। जवाब में चीनी दूतावास के अधिकारी ने कहा कि यह आरोप भर है, इस बारे में किसी ने ठोस प्रमाण नहीं दिया है।

सबसे दिक्कत वाली बात भारतीय डाटा तक चीन की कंपनियों की पहुंच को लेकर हो रही है। जर्मनी में इसी बात को लेकर आपत्ति आरंभ हो गई है। उनका कहना है कि चीनी फायरवॉल जर्मनी समेत किसी भी पश्चिमी मीडिया की साइट को अपने यहां खुलने नहीं देता। यह बात सौ फीसद सही है। पिछले वर्ष सितंबर में पेइचिंग और शंघाई में कुछ सप्ताह रहने के दौरान जब मैंने कोशिश की थी कि कोई भारतीय मीडिया या पश्चिम के अखबारों की वेबसाइट खोल कर देखूं, तो वह संभव नहीं हो पाया। आप भारत में चीनी मीडिया की साइटें खोल सकते हैं। चीन को नियंत्रित खबरें दुनिया को देनी हैं, पर वह नहीं चाहता कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से लोकतंत्र की बयार उसके दरीचे को पार करे। दुनिया में चीनी फायरवॉल को भेदने वाले कम ही होंगे। इसलिए चाहकर भी भारत या पश्चिमी देशों की खबरें चीन की जनता को हम नहीं दे सकते।

हुवावेई ने इस समय दुनिया भर में 5जी की पचास कॉमर्शियल डील को हासिल करने में सफलता पाई है। ऐसी महाकाय चीनी टेलीकॉम कंपनी को भारत में पांव पसारने से रोकने के वास्ते अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय संघ के अन्य देश सक्रिय हो जाएं, तो अपनेआप में यह बड़ी खबर है। जर्मनी के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डायचेवेले ने मोर्चा खोल दिया है। डायचेवेले के महानिदेशक पीटर लिंबुर्ग ने सवाल उठाया है कि हमारे टीवी, रेडियो, अखबारों के इंटरनेट एडीशन को चीनी फायरवॉल के जरिये ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो हम हुवावेई को 5जी नेटवर्क में क्यों घुसने दें? यह सवाल वाजिब है। कम से कम भारत सरकार के जो सक्षम अधिकारी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में हैं, उन्हें इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए।

(इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर)

6.79 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर हरियाणा के वृक्ष मौजूद हैं। हरियाली की दृष्टि से यह सबसे कम है। पंजाब 6.87 फीसद के साथ हरियाणा से बेहतर है।

डाटागीरी

डॉग पालने से कम होता है हार्ट अटैक का खतरा

जेएनएन, नई दिल्ली

अगर आपके घर में डॉग है तो आपका स्वास्थ्य दूसरों से बेहतर होगा और आपमें हार्ट अटैक (दिल का दौरा) और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होगा। यह दावा शोधकर्ताओं ने विस्तृत विश्लेषण करने के बाद अपने एक नए अध्ययन में किया है। यह अध्ययन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि डॉग को पालने वाले लोगों का जीवनकाल लंबा हो सकता है। साथ ही डॉग हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मरीजों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, खासकर तब जब वे अकेले रहते हों।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने डॉग पालने वाले और न पालने वाले मरीजों की तुलना की। उन्होंने पाया कि हार्ट अटैक के 1.82 लाख मरीजों में मात्र छह प्रतिशत ऐसे थे, जिनके पास डॉग था। वहीं, स्ट्रोक के 1.55 लाख मरीजों में मात्र पांच प्रतिशत के पास उनका यह पालतू जानवर था। शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन स्वीडन के मरीजों पर किया है। स्वीडिश नेशनल हेल्थ डाटा का अध्ययन करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि अस्पताल में भर्ती होने वाले डॉग मालिकों में मृत्यु का जोखिम कम था। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह संभवतः डॉग पालने से शारीरिक गतिविधि में वृद्धि और अकेलेपन में कमी आने के कारण होता है।

इस विश्लेषण में 1950 और मई 2019 के बीच प्रकाशित 10 अध्ययनों को कवर किया गया है, जिसमें 38 लाख लोगों को शामिल किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि डॉग पालने वालों को मृत्यु के संभावित सभी कारणों से 24 प्रतिशत तक कम खतरा रहता है और दिल के दौरे से मौत होने का खतरा भी 65 प्रतिशत तक घट जाता है। साथ ही हृदय रोग की अन्य बीमारियों से मृत्यु का जोखिम भी 31 प्रतिशत तक कम हो जाता है। बता दें कि पूर्व के कुछ अध्ययन भी यह बता चुके हैं कि पालतू जानवर खासकर डॉग को घर पर रखने से शारीरिक सक्रियता अधिक रहती है, जिसके चलते बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अब इस नवीन अध्ययन में भी इस बात को विस्तार से बताया गया है।

> डॉग पालना आपकी सेहत के साथ दिल के लिए भी फायदेमंद है। आपके इस पालतू जानवर का साथ आपमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। शोधकर्ताओं ने 38 लाख लोगों पर किए एक अध्ययन में बताया है कि डॉग पालना विभिन्न बीमारियों से होने वाली मौत का जोखिम 24 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

हार्ट अटैक के मरीजों के लिए

33 प्रतिशत मृत्यु का जोखिम डॉग पालने वालों में कम हो जाता है न पालने वालों की तुलना में अस्पताल में अकेले रहने के दौरान।

15 प्रतिशत तक मृत्यु का खतरा कम हो जाता है डॉग पालने वालों में जो अस्पताल के बाद अपने साथी या बच्चों के साथ रहते हैं।

स्ट्रोक के मरीजों के लिए

27 प्रतिशत मृत्यु का जोखिम डॉग पालने वालों में कम होता है न पालने वालों की तुलना में अस्पताल में अकेले रहने के दौरान।

12 प्रतिशत तक मृत्यु का खतरा कम हो जाता है डॉग पालने वालों में जो अस्पताल के बाद अपने साथी या बच्चों के साथ रहते हैं।

कलाम की कलम से लिख रहे नए भारत की इबारत

ज्ञान की ज्योति ▶ डॉ. कलाम के सपने को पूरा करने के लिए कलाम सेंटर से जुड़ अहम योगदान दे रहे शिक्षित युवा

डॉ. कलाम की जयंती पर विशेष

तेलंगाना के 270 सरकारी स्कूलों के 38 हजार बच्चों को कलाम बनने का सामर्थ्य देने का नाम है 'कलाम भारत' प्रोजेक्ट

अतुल पटैरिया, नई दिल्ली

सुशिक्षित समाज

महान वैज्ञानिक, शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की आज 88वीं जयंती है। कलाम ने शिक्षा को नए भारत का आधार बताया था। उनके द्वारा 2012 में स्थापित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर इस दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। कलाम सेंटर के नाम से ख्यात इस संस्था के सह-संस्थापक और सीईओ सृजन पाल सिंह इन प्रयासों का मर्म समझाते हुए उम्मीद जताते हैं कि कलाम सर का सपना जल्द पूरा होगा।

सृजन कहते हैं, 'शिक्षा का महत्व डॉ. कलाम भलीभांति समझते थे। लिहाजा, जीवनभर वह इस ध्येय की पूर्ति में रत रहे। आइआइएम शिलांग में छात्रों को संबोधित करते हुए ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उस क्षण भी मैं उनके साथ था। नई दिल्ली में जब उन्होंने कलाम सेंटर की नींव रखी थी, तब मुझे उनके इस महान उद्देश्य में बतौर सह-संस्थापक जुड़ने का सौभाग्य मिला। 2009 में आइआइएम, अहमदाबाद से प्रबंधन में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद मैं डॉ. कलाम का स्थायी सहायक बन गया था। राष्ट्रपति भवन में मैं बतौर स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर (एडवाइजर, पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी) नियुक्त था। मैंने कलाम सर के दर्शन और व्यक्तित्व को बेहद निकटता से देखा-समझा। यह मेरा परम सौभाग्य ही था कि उन्होंने देश के लिए अपने महान स्वप्न की पूर्ति में जुड़ने का मुझे अवसर दिया। उनका स्पष्ट संदेश था कि शिक्षा के दम पर ही भारत सफलता के स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर सकता है। शिक्षा उनका प्रिय विषय था और इसकी पूर्ति में उन्होंने हरसंभव प्रयास किया। कलाम सेंटर आज उनके इन उद्देश्यों की पूर्ति में जी-जान से जुटा हुआ है।'

स्कूली छात्रा से बात करते डॉ. कलाम की एक पुरानी तस्वीर। सौ. कलाम सेंटर

2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देशभर के जिलों में शिक्षा की स्थिति-प्रगति पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट जारी की। इसमें तेलंगाना पीछे छूटता दिख रहा था। स्कूली छात्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षा से नीचे चिह्नित हुआ। इसके अलावा, सर्वे में सामने आया कि देश के कई जिलों में स्कूली बच्चों में नैतिक मूल्यों का स्तर भी अपेक्षाकृत कमतर है।

डॉ. कलाम ने हमेशा कहा कि युवा ही देश की असल ताकत हैं, जिनके दम पर भारत विश्व शक्ति बनेगा। लिहाजा, तेलंगाना में स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने और देश की स्कूली शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश करने के लिए कलाम सेंटर ने व्यापक प्रयास प्रारंभ किए, ताकि नए भारत का सृजन करने वाली सामर्थ्यवान नई पीढ़ी हम गढ़ सकें। 'कलाम भारत' प्रोग्राम आज तेलंगाना सहित देश के अनेक हिस्सों में गतिशील हो चुका है। अनेक युवा इसमें अभूतपूर्व उत्साह और पूरी जिम्मेदारी के साथ सहभागिता कर रहे हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए देश के कोने-कोने से सुशिक्षित युवा कलाम सेंटर से संपर्क करते हैं। इन युवाओं को अपने जिले के एक-एक सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षक-स्वयंसेवक काम करने का मौका दिया जाता है।

वे वहां 16 सप्ताह में कुल 100 घंटे का योगदान देते हैं और ऐसा कर कलाम सर के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर स्वयं को कृतज्ञ महसूस करते हैं। ये वालंटियर सरकारी स्कूल के बच्चों को विज्ञान और भारतीय मूल्यों की शिक्षा देने में अहम योगदान दे रहे हैं। एक विशेष कोर्स भी बनाया गया है, ताकि बच्चों को कारगर युक्ति से सिखाया पढ़ाया जा सके। बच्चों से विशेष संवाद और सतत परामर्श भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है, ताकि जीवन में ऊंचे लक्ष्य रखने, बड़े सपने संजोने और इन्हें पूरा करने का साहस व सामर्थ्य उनमें भरा जा सके। हम अब तक 270 स्कूलों के 38 हजार से अधिक बच्चों को 'कलाम' बनने का बड़ा लक्ष्य दे चुके हैं।

तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते कलाम भारत प्रोजेक्ट के एक वालंटियर। सौ. कलाम सेंटर

कलाम लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज

डॉ. कलाम हमेशा मानते थे कि देश के हर बच्चे को सदुपयोगी पुस्तकों की आसान उपलब्धता आवश्यक है। कलाम भारत कार्यक्रम के तहत कलाम सेंटर द्वारा कलाम लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के रूप में तेलंगाना के 270 स्कूलों में पुस्तकालय भी खोले गए हैं, जिनका विधिवत उद्घाटन आज डॉ. कलाम की 88वीं जयंती पर किया जाएगा। पुस्तकालयों के अलावा इन स्कूलों में खेल उपकरण और संसाधन भी मुहैया कराए गए हैं।

> कलाम सर कहा करते थे कि युवा ही नए भारत का सृजन करेंगे। हम ऐसी पीढ़ी तैयार करने में जुट गए हैं, जिसके लिए अविश्वास और असंभव जैसा कुछ न हो। यही डॉ. कलाम चाहते थे।
> **– सृजन पाल सिंह, सह संस्थापक व सीईओ, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर**

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

उत्तराखंड में 16 साल बाद संरक्षित वन क्षेत्रों से लगे गांवों की ली जा रही सुध

विकास

केदार दत्त, देहरादून

- राष्ट्रीय पार्क, सैंक्चुरी व कंजर्वेशन रिजर्व से लगे गांवों में पुनर्जीवित होगा इको विकास कार्यक्रम
- ग्रामीणों की वन्यजीवों से सुरक्षा व उन्हें प्रकृति आधारित रोजगार के अवसर मुहैया कराने की मंशा
- समितियों के जरिये वन्यजीव संरक्षण में सुनिश्चित होगी ग्रामीणों की भागीदारी

वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे उत्तराखंड के संरक्षित क्षेत्रों यानी नेशनल पार्क, सैंक्चुरी व कंजर्वेशन रिजर्व से सटे 600 से अधिक गांवों की 16 साल के लंबे इंतजार के बाद सुध ली जा रही है। इन गांवों में 2003 से बंद पड़े इको विकास कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके तहत गठित होने वाली इको विकास समितियों के जरिये गांवों में वन्यजीवों से सुरक्षा को कदम उठाने के साथ ही उन्हें प्रकृति आधारित रोजगार के मौके भी मुहैया कराए जाएंगे। यही नहीं, वन्यजीव संरक्षण में ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

अविभाजित उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की मदद से वर्ष 1999 में संरक्षित क्षेत्रों से सटे गांवों में इको विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके तहत वहां इको विकास समितियां गठित कर स्थानीय समुदाय के सहयोग से संरक्षण व आजीविका के कार्य संचालित किए जाते थे। 2003 में प्रोजेक्ट खत्म होने पर यह मुहिम ठप पड़ गई। इको विकास समितियां भी छिन्न-भिन्न हो गईं। ऐसे में इन गांवों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। असल में बीते 16 सालों में परिस्थितियां बदली हैं। संरक्षित क्षेत्रों से लगे गांवों में मानव-वन्यजीव संघर्ष तेजी से बढ़ा है। वहां न घर आंगन सुरक्षित है, न खेत-खलिहान। कब कहां, बाघ, गुलदार, भालू, हाथी जैसे जानवर जान के खतरे का सबब बन जाएं कहा नहीं जा सकता। इसे देखते हुए सरकार का ध्यान फिर से इको विकास कार्यक्रम की ओर गया है। इसे पुनर्जीवित कर इसके विस्तार का निर्णय लिया गया है।

राज्य वन्यजीव बोर्ड की हाल में हुई बैठक में इस कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। अब इसके लिए वन्यजीव महकमे ने कदम बढ़ाए हैं। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजीव भरतरी के अनुसार, इसकी गाइडलाइन तैयार की जा रही है। जल्द ही संरक्षित क्षेत्रों से सटे गांवों में इको विकास कार्यक्रम शुरू होगा।

राज्य में संरक्षित क्षेत्र

नेशनल पार्क : कार्बेट, राजाजी, नंदादेवी, फूलों की घाटी, गंगोत्री व गोविंद

वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी : मसूरी, केदारनाथ, गोविंद, अस्कोट, सोनानदी, बिनसर व नंधौर

कंजर्वेशन रिजर्व : आसन, झिलमिल झील, पवलगढ़ व नैनादेवी

पंचायतों के जरिये चलेगा कार्यक्रम

भरतरी के मुताबिक, जिन गांवों में वन पंचायतें हैं, उनमें यह कार्यकम इनके जरिये चलेगा। कार्यक्रम के तहत सभी गांवों में इको विकास समितियां बनेंगी और फिर इन्हें विभिन्न कार्यों को धनराशि दी जाएगी। इसमें मुख्य फोकस इस बात पर होगा कि मानव व वन्यजीवों के बीच किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए।

अपनी कमजोरी को बनाएं ताकत : अमित

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज

टॉपर्स टॉक

> यूपी पीसीएस 2017 के गत सप्ताह जारी किए गए परीक्षा परिणाम में प्रयागराज के अमित शुक्ल ने शीर्ष स्थान हासिल किया। आइए जानते हैं उन्होंने कैसे हासिल किया यह मुकाम...

'कुछ करना या बनना है तो खुद का मूल्यांकन करना सीखना होगा। अपनी अच्छाइयों व कमजोरियों का आकलन स्वयं करें। फिर अपनी कमजोरी को ताकत बनाने का प्रयास करें। आपको जिस विषय की पढ़ाई से भय लगता है उसे मजबूत करने के लिए ज्यादा मेहनत करें। इससे वही आपकी ताकत बनेगी। आप जिस दिन खुद की कमजोरी को ताकत बनाना सीख जाएंगे, सफलता के द्वार वहीं से खुलने लगेंगे।' यह सीख है यूपी पीसीएस 2017 के टॉपर अमित शुक्ल की। उन्होंने इस बातों को अपने जीवन में उतारा और सफलता की कहानी लिखी। अमित पीसीएस 2015 व 2016 में भी शामिल थे। पीसीएस 2015 के मेंस में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पीसीएस 2016 में वाणिज्य अधिकारी के पद चयनित हुए। हालांकि, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और तैयारी में लगे रहे। समाज कार्य व भूगोल विषय से पीसीएस 2017 में टॉप करने वाले अमित बचपन में सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेटर बनना चाहते थे।

अमित के पिता उमाकांत शुक्ल डायग्नोस्टिक सेंटर में मैनेजर हैं, जबकि मां क्षमा शुक्ल कुंडा सीएचसी में एएनएम के पद पर कार्यरत हैं। उनका बचपन किलाहनापुर गांव में बीता और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यहीं के प्राइमरी स्कूल से की। शुरू से मेधावी रहे अमित ने किसी भी परीक्षा में 70 फीसद से कम अंक हासिल नहीं किए। सीबीएसई बोर्ड से 10वीं में 81 व 12वीं में 84 फीसद अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की।

इंजीनियर के तौर पर की नौकरी : अमित ने एनआइटी भोपाल से मैकेनिकल स्ट्रीम में बीटेक करने के बाद गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी की, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिली। मां व पिता से राय लेकर जनवरी 2015 में नौकरी छोड़कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट गए।

कभी किताबी कीड़ा नहीं रहे : अमित कभी किताबी कीड़ा नहीं रहे। जो पढ़ा मन से पढ़ा। 24 घंटे में सिर्फ पांच से छह घंटे ही पढ़ाई की। हर एक से दो घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक भी लिया।

आजाद व कलाम हैं आदर्श : अमित मौलाना अबुल कलाम आजाद व पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं। ईश्वर पर उनकी बहुत आस्था है। वह प्रतिदिन 20 से 25 मिनट पूजा करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करते हैं। बताते हैं कि पूजा करने से उन्हें आंतरिक शक्ति मिलती है।

अमित शुक्ल जागरण

जरूरी टिप्स

- खुद को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहेंगे तभी कोई काम मन से कर पाएंगे।
- घड़ी देखकर पढ़ाई न करें। मन जितना करे उतना ही पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें उसे मन से पढ़ें।
- एक दिन में क्या-क्या करना है उसे सुबह ही तय कर लें। पढ़ाई का समय भी उसमें शामिल करें।
- पढ़ाई के साथ मनोरंजन का भी समय तय करें।
- एजुकेशनल वेबसाइट जरूर देखें।

फोटो न्यूज

थाइलैंड में 150 सालों से मनाया जा रहा है 'विंग क्वाई'

यह तस्वीर थाइलैंड के पूर्वी तट पर स्थित चोनबुरी प्रांत में आयोजित भैंसा दौड़ की है। यह दौड़ यहां करीब 150 सालों से मनाए जा रहे विंग क्वाई त्योहार का एक अहम हिस्सा है, जिसमें किसान अपनी भैंसों पर नंगे पैर बैठकर भाग लेते हैं। थाइलैंड भारत की तरह ही कृषि प्रधान देश है और वहां के ज्यादातर त्योहार भी कृषि से जुड़े हुए हैं। विंग क्वाई हर वर्ष अक्टूबर माह में बारिश का मौसम खत्म होने पर मनाया जाता है। किसानों के अपनी भैंसों पर नंगे पैर बैठने की वजह उन्हें सम्मान देना होता है, जो उन्हें खेती में मदद करती हैं। यह दौड़ कीचड़ वाली जगह में होती है, जिससे सवार के गिरने पर उसे कम चोट लगे।

इनामी राशि कम, पर हिस्सा लेना है गौरव की बात

इस दौड़ से पहले भैंसों को सजाया भी जाता है। भैंसों को सजाने और उनकी रफ्तार दोनों के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। इस प्रतियोगिता की इनामी राशि भले ही महज नौ हजार रुपये हो, लेकिन इसमें हिस्सा लेना यहां के किसानों के लिए गौरव की बात होता है। इसकी वजह इस त्योहार का उनकी संस्कृति से जुड़ा होना है। इसके अलावा इस प्रतियोगिता के उपविजेता को खेती से जुड़े सामान बतौर इनाम दिए जाते हैं।

और भी होते हैं कार्यक्रम

विंग क्वाई के अवसर पर चोनबुरी में और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसे देखने और उसमें हिस्सा लेने के लिए केवल थाइलैंड के कोने-कोने से ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से भी पर्यटक पहुंचते हैं। एएफपी

मप्र में मुस्लिम इतिहासकार ने सहेज रखी है सिंधी भाषा की रामायण

युवराज गुप्ता, बुरहानपुर

- 1933 में इतिहासकर के दादा को भेंट में मिली थी

पाकिस्तान के लाहौर में प्रकाशित सिंधी भाषा की अनमोल तुलसी रामायण मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के इतिहासकार ने अपने संग्रह में सहेजकर रखी है। इस पवित्र ग्रंथ को सम्मान के साथ रखा गया है और समय-समय पर हिंदू भाइयों को इसके दर्शन का लाभ भी मिलता है। मुस्लिम इतिहासकार की ग्रंथ के प्रति आस्था और उसे सम्मानपूर्वक सहेजकर रखना अपने आप में सौहार्द्र की मिसाल पेश कर रही है। हम बात कर रहे हैं, बुरहानपुर के इतिहासकार मुहम्मद नौशाद खान की।

उन्होंने बताया कि सिंधी भाषा की पवित्र तुलसी रामायण बुरहानपुर में अपने जैसी एकमात्र पुस्तक है। इसके लेखक लोकरामजी हैं। उन्होंने बताया 'इसे मेरे दादा शेख अब्दुल्ला को दिल्ली में 1933 में समारोह में भेंट किया गया था। उनके के निधन के बाद यह पुस्तक पिता अहमद खान और उनके निधन के बाद मैंने इस पुस्तक को विरासत के रूप में संजोकर रखा है। पवित्र ग्रंथ होने के कारण इसे सम्मान दिया जाता है और लाल कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। पुस्तक लाहौर से 1905 में प्रकाशित हुई और 1933 में मेरे दादा इसे बुरहानपुर लेकर आए। कुछ वर्ष पूर्व सिंधी समाज के दो बुजुर्ग समाजसेवी इसे पढ़ने हमारे घर आया करते थे। कोई भी सिंधी भाई या अन्य इस पुस्तक को यदि देखना चाहे तो हमारे घर आ सकता है। कुछ विशेष अवसर पर इस पवित्र ग्रंथ को दर्शन के लिए रखा जाता है।'

अनूठा चित्रमयी वर्णन : इस पवित्र ग्रंथ में प्राचीन तस्वीरों के साथ अनूठा चित्रमयी वर्णन किया गया है। हिंदी रामायण के सभी अध्याय इसमें चित्र के साथ उल्लेखित हैं।

मप्र के बुरहानुपर में है सिंधी भाषा में लिखी गई तुलसी रामायण। नईदुनिया

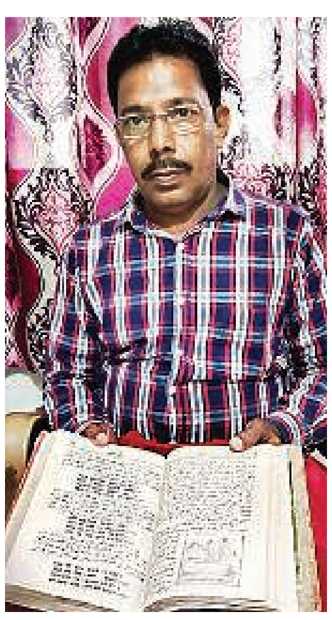

सिंधी भाषा में लिखी गई तुलसी रामायण दिखाते मप्र के बुरहानपुर के इतिहासकार मुहम्मद नौशाद खान। नईदुनिया

शुगर के मरीज भी चख सकेंगे खीर और हलवा

वैभव शर्मा, हिसार

- ज्वार, बाजरा सहित आठ प्रकार के कदन्न के जरिये स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक डिश बनाना सिखा रहा है आइआइएमआर

शुगर के मरीजों को अक्सर पकवानों से तौबा करने पड़ती है, क्योंकि यही उनके शरीर में शुगर की मात्रा को पल में बढ़ाते व पल में घटा देते हैं। अब ऐसे लोग दिल खोल के पकवानों का स्वाद ले सकेंगे क्योंकि भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (आइआइएमआर) ने ऐसी 150 से अधिक डिश तैयार की हैं जो ज्वार, बाजरा सहित आठ प्रकार के कदन्न से बनी हैं। करीब 20 वर्ष पहले ज्वार, बाजरा को लोग रोजाना खाने में प्रयोग करते थे, लेकिन बाजार में विकल्प आने के बाद से इनका प्रयोग कम हो गया। अब जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, उसमें मौजूदा समय में आ रहे गेहूं आदि का बड़ा रोल है। कदन्न आपके शरीर में धीमी रफ्तार से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, इस कारण से यह शुगर के मरीजों के लिए बेहतर है। हालांकि, नई पीढ़ी को ज्वार, बाजरा में स्वाद नहीं आता। इसलिए वे इसे नहीं खाते, लेकिन अब जिस तरीके ज्वार व बाजरे से व्यंजन तैयार किए गए हैं उन्हें जरूर भाएंगे।

हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में कदन्न पर कांफ्रेंस हुई, जिसमें आइआइएमआर से जुड़े विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। उन्होंने वहां छात्रों व आगंतुकों को दिखाया कि किस प्रकार से ज्वार, बाजरा से खीर, हलवा, बच्चों को पसंद आने वाली मफिन्स, केक जैसे 150 से अधिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनको चखने पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप ज्वार बाजरा जैसा कुछ खा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने इन खाद्य पदार्थों को तैयार करने में हर बारीकी का ध्यान रखा है। हालांकि, मौजूदा समय में एचएयू में बाजरे के बिस्किट, नूडल्स जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं।

भेलपुरी, पानीपुरी और कुकीज जैसे प्रोडक्ट भी : खाने के शौकीनों में अक्सर 40 से कम उम्र के लोगों की संख्या अधिक होती है। इसलिए ज्वार, बाजरा और रागी पर इतने प्रयोग किए कि मौजूदा समय में युवाओं को पसंद आने वाले व्यंजन भी तैयार हो गए। इंस्टीट्यूट में ज्वार से पानीपुरी, ज्वार नारियल चॉकलेट लड्डू, ज्वार आटे के गुलाब जामुन, ज्वार चॉकलेट ब्राउनी, ज्वार आटे का मैसूरपाक, कोदो से भेलपुरी, ज्वार अंडारहित रवा केक, ज्वार कुकीज, छोटे कदन्न से काजू नमकीन, बाजरा सेव आदि तैयार किए गए हैं। इंस्टीट्यूटी का लक्ष्य है कि वह देश में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे कदन्न खाद्य पदार्थों का रेस्तरां संचालित कर सकें। इससे लोगों की सेहत में तो सुधार होगा और साथ ही कदन्न फसलों को भी बढ़ावा मिलेगा।

कदन्न में आने वाली फसलें

ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो, कंगनी, सावां, चेना

ज्वार व बाजरे से तैयार रसगुल्ले, कुरकुरे व अन्य प्रोडक्ट्स। जागरण

फसलों की विशेषताएं

- इसमें विटामिन बी कॉम्पलेक्स व विटामिन ई अधिक मात्रा में पाया जाता है।
- इसमें विशेषकर खनिज, आयरन, मैग्नीशियम, फासफोरस व पोटेशियम ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।
- लंबे समय में मुक्त ग्लूकोज का प्रतिशत कम होता है। इस कारण मधुमेह का खतरा कम हो जाता है।
- कदन्न में प्रोटीन की मात्रा छह से 11 व वसा की मात्रा 1.5 से लेकर पांच तक भिन्न होती है।

86 हो गई है मलेरिया से जूझने वाले देशों की संख्या 106 से घटकर वर्ष 2000 से अब तक। 36 फीसद मलेरिया के मामले वैश्विक स्तर पर कम हुए हैं।

अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले भारतीय मूल के दूसरे अर्थशास्त्री हैं अभिजीत

अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले भारतीय मूल के दूसरे अर्थशास्त्री बन गए हैं। इससे पहले 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं।

जन्म : 21 फरवरी, 1961, मुंबई

माता-पिता : माता निर्मला बनर्जी कोलकाता के सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज में प्रोफेसर रहीं। पिता दीपक बनर्जी प्रेसीडेंसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे।

शिक्षा : 1981 में कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की। 1983 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए किया और 1988 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी किया।

कार्य : अभिजीत इस समय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है। 2003 में अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। 2013 में, उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने 2015 के बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अपडेट करने का काम सौंपा।

अन्य पुरस्कार

अभिजीत को 2004 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का फेलो चुना गया। 2009 में इंफोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में जर्मनी स्थित कील इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी ने बर्नहार्ड-हार्म्स-पुरस्कार से सम्मानित किया।

कई किताबें लिखीं

अभिजीत ने अर्थशास्त्र पर कई किताबें लिखी हैं। 2005 में पहली किताब वोलाटिलिटी एंड ग्रोथ लिखी। तब से लेकर आज तक वह कुल सात किताबें लिख चुके हैं। 2011 में आई पुअर इकोनॉमिक्स : ए रेडिकल रीथींकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी नामक किताब ने उन्हें खूब प्रसिद्धि दिलाई।

नोबेल जीतने वाले भारत से जुड़े 10 चेहरे

रविंद्रनाथ टैगोर

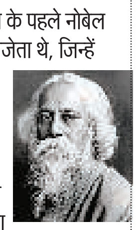

टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। टैगोर को 1913 में जब ये सम्मान मिला तब वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे।

वीएएस नायपॉल

ब्रिटेन में बसे नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल दिया गया।

कैलाश सत्यार्थी

वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला। कैलाश को बच्चों के लिए किए गए उनके काम को देखते हुए ये पुरस्कार दिया गया।

अमर्त्य सेन

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कोलकाता में जन्मे सेन अमेरिका में रहते हैं।

हरगोविंद खुराना

भारतीय मूल के जाने-माने वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। खुराना का शोध इस विषय पर था कि एंटी बायोटिक खाने का शरीर पर किस तरह का असर होता है। भारत के पंजाब में जन्मे खुराना बाद में अमेरिका में ही बस गए थे।

सीवी रमन

चेन्नई में जन्मे रमन ने प्रकाश से जुड़े जिन प्रभावों की खोज की थी, उन्हें रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

वेंकट रामाकृष्णन

भारतीय मूल के अमेरिकी-ब्रिटिश वैज्ञानिक वेंकट रामाकृष्णन को 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेंकट का जन्म तमिलनाडु में हुआ।

मदर टेरेसा

अल्बानिया मूल की मदर टेरेसा ने कोलकाता में गरीब, अनाथ और बीमार लोगों के लिए जो किया वो दुनिया में अभूतपूर्व माना जाता है। इसके उन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा अपनी मृत्यु तक कोलकाता में ही रहीं।

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर

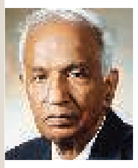

चंद्रशेखर का जन्म लाहौर में हुआ था और पढ़ाई अमेरिका में हुई थी। उनका विषय एस्ट्रोफिजिक्स था और उन्हें 1983 में सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इसके सैद्धांतिक शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।

आरके पचौरी

जलवायु परिवर्तन पर किए गए शोध के लिए पचौरी को 2007 में यूएन की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी आइपीसीसी कमेटी के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो लंबे समय तक टेरी (टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट) से भी जुड़े रहे।

नोबेल पुरस्कार पाने वाले पति-पत्नी

अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो से पहले भी पांच पति-पत्नी नोबेल जीत चुके हैं। यह पुरस्कार जीतने वाले दंपतियों पर एक नजर...

मैरी और पियरे क्यूरी

1903 में फ्रेंच वैज्ञानिक मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को दो नए तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

फ्रेडरिक जोलियट और इरीन जोलियट क्यूरी

मैरी क्यूरी की बेटी इरीन जोलियट क्यूरी और उनके पति फ्रेडरिक जोलियट को 1935 में रसायन का नोबेल दिया गया था।

गेर्टी और कार्ल कोरी

30 साल की मेहनत के बाद 1947 में अमेरिकी वैज्ञानिक ग्रेटी और कार्ल कोरी को ग्लाइकोजन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर अपने शोध के लिए संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था।

गुन्नार और अल्वा मायर्डल

स्वीडन के गुन्नार मायर्डल को 1974 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। उनकी पत्नी अल्वा मायर्डल को 1982 में शांति का नोबेल मिला था।

मे ब्रिट और एडवर्ड मोजर

दिमाग में पॉजिशिनिंग तय करने वाली कोशिकाओं की खोज के लिए 2014 में नॉर्वे के इस दंपती को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल दिया गया।

मां बोलीं- देश के लाल पर मुझे बेहद गर्व

गौरव का पल ▶ नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी की मां भी अर्थशास्त्र की शोधकर्ता रही हैं

कहा-अर्थव्यवस्था के जटिल मुद्दों को सरलता से समझा सकता है बेटा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए अभिजीत बनर्जी की मां निर्मला बेटे की उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रही हैं। कोलकाता स्थित घर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के लाल की सफलता पर गर्व है। अभिजीत केवल उनके बेटे नहीं बल्कि देश के लाल हैं। गौरतलब है कि निर्मला खुद अर्थशास्त्र की शोधकर्ता रही हैं। उन्होंने लंबे समय तक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। अभिजीत के पिता दीपक बनर्जी भी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। निर्मला ने बताया कि वह हमेशा अभिजीत को पढ़ाने में उनकी मदद करती थीं।

यह पूछे जाने पर कि मां के रूप में वह बेटे को क्या कहना चाहेंगी, इस पर उन्होंने कहा, 'मैं कर्म में विश्वास करती हूं। यही सीख मैंने अपने बेटे को भी दी है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप जितना काम करेंगे, उतना ही सीखेंगे, इसलिए अपने काम को जारी रखें। अभिजीत की एक खूबी यह है कि वह अर्थव्यवस्था के जटिल मुद्दों को बहुत सरलता से समझा सकता है। अभिजीत हमेशा कहता है कि गरीबी को खत्म करने के लिए हमें गरीबों की आकांक्षाओं को जानना जरूरी है।'

कोलकाता में सोमवार को अपने घर पर बेटे अभिजीत बनर्जी की तस्वीर और किताब 'पुअर इकोनॉमिक्स : ए रेडिकल रीथिंकिंग ऑफ द वे टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी' के साथ निर्मला बनर्जी। प्रेट्र

यह पूछे जाने पर कि अभिजीत कब कोलकाता आ रहे हैं, इसके जवाब में निर्मला ने कहा, 'वह इसी महीने कोलकाता आने वाला है। कुछ दिन पहले ही उससे बात हुई है। दरअसल, दिल्ली में उसकी एक किताब का लोकार्पण होना है। इसी सिलसिले में वह भारत आ रहा है। इसके बाद वह एक दिन के लिए कोलकाता आएगा।' गौरतलब है कि अभिजीत विनायक बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डुफलो और माइकल क्रेमर को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अमर्त्य सेन के बाद अभिजीत बंगाल से दूसरे शख्स हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है।

एक और बंगाली ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया : ममता अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया-'प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और साउथ प्वाइंट स्कूल के पूर्व छात्र अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई।

वह हमेशा से ही उज्जवल छात्र रहे : इशिता अभिजीत के बचपन की मित्र इशिता मुखर्जी ने बताया कि वह हमेशा से ही उज्जवल छात्र रहे और सभी चीजों में गहरी दिलचस्पी दिखाते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर इशिता ने कहा-'झिमा (अभिजीत का घरेलू नाम) और मैंने एक ही स्कूल-कॉलेज में समान स्ट्रीम की पढ़ाई की। वे संगीत से लेकर साहित्य और कला-संस्कृति में काफी दिलचस्पी लेते थे।

अभिजीत को नोबेल मिलना हमारे लिए गर्व की बात : प्रेसीडेंसी विवि

प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को कहा गया कि यह संस्थान के लिए गर्व की बात है कि उनके पूर्व छात्र और मार्गदर्शक समूह के सदस्य अभिजीत बनर्जी का चयन 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए हुआ है। विवि के रजिस्ट्रार ने कहा कि विवि को खुशी है कि उसके दो पूर्व छात्रों, अमर्त्य सेन और अब अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें विवि की तरफ से सम्मानित किया जाएगा।

'न्याय' के रहे सूत्रधार

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस की तरफ से पेश की गई 'न्याय' योजना के मुख्य परामर्शदाता अभिजीत बनर्जी थे। कांग्रेस ने नोबेल विजेता को बधाई देते हुए 'न्याय' योजना में उनकी भूमिका का जिक्र किया। इस योजना के तहत कांग्रेस ने गरीबों को सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अभिजीत को बधाई दी।

इस हफ्ते आएगी नई किताब : अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो की नई किताब 'गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स – बेटर आंसर्स टू अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स' 19 अक्टूबर को बाजार में आएगी। प्रकाशक जगरनॉट बुक्स ने सोमवार को यह एलान किया। प्रकाशक ने बताया, 'क्या प्रवासी लोग गरीब स्थानीय लोगों का रोजगार छीन लेते हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय कारोबार असमानता बढ़ाता है, जो इस समय चिंताजनक तरीके से बढ़ रही है? विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए? क्या पश्चिम में विकास का क्रम पूरा हो गया है? किताब में इसी तरह के कई प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की गई है।'

गुरु ने कहा, मुझे यकीन था कि अभिजीत को नोबेल मिलेगा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए अभिजीत विनायक बनर्जी का प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से गहरा नाता रहा है। उन्हें पुरस्कार मिलने की खुशी में जेएनयू गर्व से फूले नहीं समा रहा है।

1981 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल करने बाद अभिजीत इकोनॉमिक्स से एमए करने जेएनयू आ गए। 1983 में उनको पढ़ाने वाले जेएनयू के अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर अंजान मुखर्जी अपने छात्र की उपलब्धि से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि अभिजीत उत्कृष्ट छात्र रहे हैं। वह हमेशा दूसरे छात्रों से अलग रहे। कक्षा में बहुत ही ध्यान से सभी व्याख्यान सुनते थे।

अंजान मुखर्जी ने कहा कि मुझे यकीन था कि अभिजीत को नोबेल पुरस्कार जरूर मिलेगा क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए योगदान दिया है, वह तारीफ के योग्य है। उनके शोध को विस्तार से पढ़कर भारत की नीतियों में शामिल करना चाहिए। कई राज्य हैं जहां उनके शोध को लागू करना चाहिए। अभिजीत अर्थशास्त्र के कई छात्रों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने कहा कि जेएनयू को अपने पूर्व छात्र की उपलब्धि पर गर्व है। इससे अन्य छात्रों को काफी प्रेरणा मिलेगी। जेएनयू के सेक्टर-2 प्रो. संजय गारकोटी ने कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्र विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात है।

एक माह से ज्यादा समय से सूर्य पर नहीं बन पाए सन स्पॉट्स

जागरण संवाददाता, नैनीताल

करीब एक माह से ज्यादा समय से सूर्य पर सन स्पॉट्स नहीं उभर पाए हैं। सूर्य अभी मिनिमम फेज से गुजर रहा है, जिसके चलते वैज्ञानिक संभावना जता रहे हैं कि इस बार का सौर चक्र थोड़ा लंबा होने वाला है।

सोलर साइकिल का यह फेज मैक्सिमम स्तर पर आ चुका है, परंतु सन स्पॉट्स का उभरना अभी शुरू नहीं हुआ है। एक माह पूर्व सूर्य पर सन स्पॉट्स नजर आए थे। इसके बाद से अभी तक सूर्य पर एक भी सन स्पॉट्स नहीं उभरा है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के कार्यवाहक निदेशक डॉ. वहाबउद्दीन ने बताया कि सूर्य का 11 वर्ष का सौर चक्र होता है। कभी-कभी यह चक्र 14 साल तक चला जाता है। इस दौरान सूर्य को मैक्सिमम फेज पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह मिनिमम दौर पर ही ठहरा हुआ है। मैक्सिमम दौर की अवस्था में सूर्य सक्रिय हो जाता है, जिसमें सन स्पॉट्स उभरने शुरू हो जाते हैं। साथ ही फ्लेयर यानी भभूकाएं निकलने लगती हैं, जिनसे चार्ज पार्टिकल की बौछारें निकलती हैं।

उन्होंने कहा चार्ज पार्टिकल बेहद खतरनाक होते हैं, जिनसे हमारे सेटेलाइट के नष्ट होने का खतरा रहता है। इनके अलावा वह पृथ्वी पर मौजूद विद्युत व इलेक्ट्रोनिक उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।

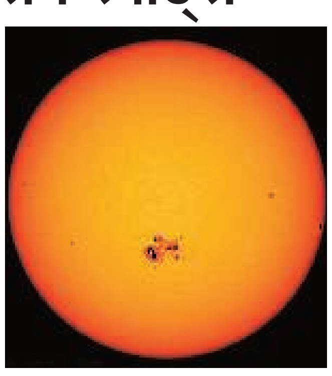

पूर्व में चार्ज पार्टिकल धरती में कई स्थानों पर मौजूद विद्युत उपकरणों को नुकसान पहुंचा चुके हैं, जिस कारण सोलर वैज्ञानिक हमेशा सूर्य पर नजर टिकाए रखते हैं।

एरीज का टावर टेलीस्कोप रखता है सूर्य पर नजर : सूर्य पर नजर रखने के लिए एरीज में टावर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। इस टेलीस्कोप के जरिये एरीज के वैज्ञानिक सूर्य की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हैं। पूर्व में इस दूरबीन से सन स्पॉट व सोलर फ्लेयर की कई तस्वीरें कैद की गई हैं। 28 अक्टूबर 2003 में विशाल आकार की फ्लेयर का चित्र इस टेलीस्कोप से लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण आब्जर्वेशन था। वर्ष 1990 में स्थापित किया गया यह ऑप्टिकल टेलीस्कोप 15 सेमी व्यास का है।

मछली और हर्बल से तैयार की किडनी और लिवर की दवाएं

जागरण संवाददाता, कानपुर : बिहार के प्रमुख सचिव राजस्व परिषद एसएम राजू ने मछली एवं हर्बल से किडनी और लिवर की दवाएं तैयार की हैं। उन्होंने इस दवा से पहले स्वयं, अपने पिता एवं पुत्र का इलाज किया। अब दूसरों को लाभान्वित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित एक गोष्ठी में आए 1991 बैच के आइएएस अधिकारी ने बताया कि वह आयुर्वेद आधारित कई दवाएं ईजाद कर चुके हैं। उनकी दवाओं का सेवन कर कई जानी-मानी हस्तियां पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हैं। अब अपना फॉर्मूला बेंगलुरु की एक कंपनी को दिया है, जो दवा बना रही है।

उन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान उन्हें गठिया हो गया था। 1987 से 1988 तक इंजेक्शन लगवाने पड़े। कृषि स्नातक की पढ़ाई के दौरान औषधीय पौधों की जानकारी होने पर उनसे दवाएं बनाकर सेवन किया। इससे राहत मिली। 2008 में किडनी खराब होने से पिता डायलिसिस पर आ गए। उनके इलाज के लिए मछली, हरी धनिया, अदरख, हरी मिर्च, लहसुन और पुदीना से दवा तैयार की। उसके प्रयोग से जबरदस्त लाभ हुआ। 2014 तक वह बिना डायलिसिस के रहे। उनका क्रिएटिनिन, पोटाश, सोडियम, यूरिक एसिड सामान्य रहा। इससे हौसला बढ़ने पर हार्ट, लिवर, किडनी समेत 170 प्रकार की बीमारियों की आठ दवाएं बनाईं। अब तक 14 दवाएं खोज चुके हैं।

ब्राजील से गिर नस्ल के सांड़ों के शुक्राणु मंगाने के फैसले का गुजरात में विरोध

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

विश्व प्रसिद्ध जूनागढ़ की गिर नस्ल की गायों के संरक्षण व उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने ब्राजील से शुक्राणु मंगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। स्थानीय पशुपालकों ने तो जूनागढ़ में आइवीएफ सेंटर बनाने की योजना पर काम भी शुरू कर दिया है।

ब्राजील व अमेरिका जैसे देश वर्ष 1850 से ही गुजरात की गिर नस्ल की गायों का आयात कर रहे हैं। वहां इनके संरक्षण व प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके उलट गुजरात में ही गिर नस्ल की गायों की संख्या लगातार घट रही है। इसे देखते हुए केंद्र व गुजरात सरकार ने इसी वर्ष ब्राजील से समझौता कर वहां से गिर नस्ल के सांड़ों के शुक्राणुओं को मंगाने का फैसला किया है।

ब्राजील से पशु वैज्ञानिक जोज ओटावियो के जूनागढ़ पहुंचने के बाद यह मामला और गर्म हो गया है। ओटावियो ने बताया कि गिर नस्ल को बचाने के लिए ब्राजील से 10 हजार शुक्राणु मंगाए जाने हैं। नस्ल सुधार की भी योजना है। भारत में सभी गायों को एक सा पशु आहार दिया जाता है, लेकिन ब्राजील में हर पशु को जरूरत के अनुरूप आहार दिया जाता है। कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई

सरकार ने ब्राजील से समझौता कर गिर नस्ल के सांड़ों के शुक्राणुओं को मंगाने का फैसला किया है। फाइल

कथीरिया ने कहा कि सरकार ने इसी वर्ष ब्राजील से शुक्राणु मंगाने के लिए समझौता किया था, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। आयोग गो संरक्षण व नस्ल सुधार के कई कार्यक्रम चला रहा है। ब्राजील से शुक्राणु लाने से गिर गायों की असली नस्ल खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां की प्रजातियां संकर हो चुकी हैं।

40 साल पहले 40 गिर गायें ले गया था ब्राजील, अब हैं 21 करोड़ : सरकार के निर्णय से गुस्साए पशुपालकों ने गिर गायों के संरक्षण व नस्ल को बढ़ाने के लिए गिर गाय गोरस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) सेंटर स्थापित करने व उन्नत तकनीक की गोशाला बनाने आदि की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पशुपालक बताते हैं कि 40 साल पहले ब्राजील यहां से गिर नस्ल की 40 गायें ले गया था। अब वहां 21 करोड़ गायें हैं। हमारे पास दो करोड़ गायें थीं जो घटकर 25 लाख रह गई हैं। हमें अपने स्वदेशी नस्ल को बचाना होगा।

अब श्रीलंका में बिकेगा छत्तीसगढ़ का कोसा

▶ जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा के हैंडलूम उत्पाद का होगा निर्यात

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के जांजगीर, रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा में बनने वाले कोसा सिल्क और अन्य हैंडलूम उत्पाद जल्द ही श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बाजार में नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच हैंडलूम उत्पादों को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोलंबो के बाद कोसा सिल्क और हैंडलूम उत्पाद श्रीलंका के अन्य शहरों में भी उपलब्ध होंगे। वहीं, श्रीलंका के हैंडलूम उत्पाद भारत के लोगों को मिल पाएंगे।

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 13 अक्टूबर को आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ बिलासा एम्पोरियम और श्रीलंका के सहकारिता विभाग की ओर से एक साझा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत आपसी व्यापार व सहयोग को और बढ़ावा दिया जाएगा। यह समझौता दो वर्षों के लिए हुआ है।

अनुबंध के अनुसार, दोनों देशों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने आइडिया और अनुभव को एक-दूसरे से साझा करें। एक-दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा देंगे और परस्पर सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ बिलासा एम्पोरियम के अधिकारियों को श्रीलंका सहकारिता विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर नीलांगा डी सोमपाल बताया है कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से कोसा साड़ियों के कुछ सैंपल श्रीलंका भेजे गए थे, जिसे वहां की महिलाओं ने काफी पसंद किया। उसके बाद अनुबंध का निर्णय लिया गया। सहकारी व्यापार मेले में आए श्रीलंका के ग्राहकों ने छत्तीसगढ़ के टसर सिल्क, घीचा सिल्क, लिनेन, रॉ सिल्क को भी काफी पसंद किया।

चिंताजनक

छत्तीसगढ़ की पांच नदियों का पानी बन रहा 'जहर', ऑक्सीजन हुई कम

मानक से सात गुना अधिक तक पाया गया हानिकारक कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया, राज्य सरकार ने तीन साल कराया केमिकल टेस्ट, नदियों को बचाने बनाया एक्शन प्लान

अनुज सक्सेना, रायपुर

छत्तीसगढ़ की पांच जीवनदायिनी नदियां हसदेव, खान, महानदी, शिवनाथ और केलो का पानी 'जहर' बनता जा रहा है। इन नदियों के पानी में एसिड की मात्रा लगातार बढ़ रही और ऑक्सीजन घट रही है। हानिकारक कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया भी मानक से सात गुना तक अधिक मिला है। इन नदियों के पानी के तीन साल के केमिकल टेस्ट की रिपोर्ट ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। न केवल नदियों, बल्कि उनके पानी से जनजीवन और फसलों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कराया है और उसके क्रियान्वयन के लिए अलग से कमेटी भी बनाई है।

राज्य सरकार ने पांच प्रमुख नदियों के पानी का 2016, 2017, 2018 में केमिकल टेस्ट कराया। इसकी जो रिपोर्ट आई है वह चौंकाने और चिंता में डालने वाली है। पानी में हाइड्रोजन की संभावना (पीएच) लगातार बढ़ती मिली है। हाइड्रोजन की मात्रा अधिकतम सीमा के करीब पहुंच गई है। भारतीय मानक के अनुसार, हाइड्रोजन की मात्रा न्यूनतम 6.5 और अधिकतम 8.5 होनी चाहिए।

राज्य सरकार ने पांच प्रमुख नदियों में रसायनों की जांच कराई है, जिसके परिणाम चिंताजनक हैं। फाइल

रिपोर्ट के अनुसार, पांचों नदियों के पानी में पीएच यूनिट सात को पार कर चुकी है। हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने का मतलब, पानी में एसिड बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन कम हो रही है। चार नदी हसदेव, खान, शिवनाथ और केलो के पानी में प्रति लीटर पर सात मिलीग्राम या उससे अधिक ऑक्सीजन कम पाई गई है। मानक के अनुसार छह मिलीग्राम तक सामान्य है। पांचों नदियों में कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की अधिकतम संख्या भी ज्यादा मिली है। भारतीय मानक के अनुसार, प्रति 100 मिलीलीटर में अधिकतम 50 कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन केमिकल रिपोर्ट के अनुसार, नदियों के पानी में कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया 46 से 350 तक मिला है। इस बैक्टीरिया से कमजोरी, अल्सर, अपचय, पेट में मरोड़ की समस्या होती है।

सात जिलों की जीवनदायिनी हैं ये नदियां

हसदेव कोरबा जिला, खान नदी रायपुर जिला, महानदी कांकेर, धमतरी, गरियाबंद जिला, शिवनाथ नदी बलौदाबाजार-भाटापारा जिला और केलो नदी रायगढ़ जिले के लोगों के लिए जीवनदायिनी है।

नौ विभाग और एजेंसियों को मिली है जिम्मेदारी

नदियों के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, उद्योग विभाग को मिली है।

राज्य सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए तैयार किया है एक्शन प्लान

उद्योगों से निकलने वाली गंदगी व केमिकलयुक्त पानी को साफ करने के बाद नदी में छोड़ा जाएगा, इसके लिए अलग से कैचमेंट एरिया बनाना है। जो उद्योग ऐसा नहीं करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। नालों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) व डिस्पोजल प्लांट बनेगा। औद्योगिक, व्यवसायिक व अन्य क्षेत्रों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सख्ती से लागू कराया जाएगा व बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में पौधरोपण कराया जाएगा। ठोस अपशिष्ट व प्लास्टिक को न केवल नदियों, बल्कि नाले-नालियों में भी जाने से रोका जाएगा, नदियों के बहाव का रिकॉर्ड नियमित रूप से बनेगा।

पीएमसी बैंक से अधिकतम निकासी सीमा बढ़ी

मुंबई, प्रेट्र : पीएमसी बैंक खाताधारकों के लिए राहत की खबर है। आरबीआइ ने बैंक से नकदी निकासी की सीमा 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दी है। बैंक पर प्रतिबंध लगाने के बाद से यह तीसरी बार है जब निकासी की सीमा बढ़ाई गई है। शुरुआत में निकासी की अधिकतम सीमा एक हजार रुपये रखी गई थी, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। गौरतलब है कि पीएमसी बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। इसके चलते आरबीआइ ने इसे अपने निर्देशों के अधीन लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं।

देश की अर्थव्यवस्था तेजी से गैस आधारित हो रही है। ऐसे में सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए।
— धर्मेंद्र प्रधान
पेट्रोलियम मंत्री

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
38,214.47	11,341.15	₹ 38,885	₹ 46,510	₹ 71.02	$ 59.29
▲ 87.39	▲ 36.10	▲ ₹ 145	▲ ₹ 240	▲ ₹ 0.21	

संकेत ▶ तीसरे इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने उद्योग से किया वादा

स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण में सुधार करेगी सरकार

तीन दिवसीय प्रदर्शनी में 750 बड़ी और स्टार्ट-अप कंपनियों की है भागीदारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद के बयान से निश्चिय ही 5-जी स्पेक्ट्रम की कीमतों को लेकर दूरसंचार उद्योग की चिंताएं कुछ हद तक दूर होंगी। सोमवार को तीसरे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में उन्होंने वादा किया कि सरकार स्पेक्ट्रम की कीमतों के मूल्य निर्धारण से जुड़ी विसंगतियों को दूर कर इसी वित्तीय वर्ष के दौरान स्पेक्ट्रम की नीलामी सुनिश्चित करेगी।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 2019 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा कि सरकार उद्योग के समक्ष मौजूद समस्याओं और चुनौतियों से वाकिफ है। 'स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी वर्ष होगी। ...और हम स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण की पद्धति में कुछ सुधार कर रहे हैं।'

गौरतलब है कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने पिछले वर्ष सरकार को 5-जी सेवाओं समेत लगभग 8644 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी का सुझाव दिया था। इसके लिए उसने कुल 4.9 लाख करोड़ रुपये की बेस प्राइस रखे जाने की सिफारिश की थी। परंतु वित्तीय दबाव झेल रहे कर्ज से दबे टेलीकॉम उद्योग ने इसे बहुत महंगा बताते हुए कीमतों में कमी का आग्रह किया था।

इस विषय में कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्रिटेन और इटली का उदाहरण दिया है जहां 5-जी बैंड की औसत कीमत सिर्फ 84 करोड़ रुपये प्रति मेगाहट्र्ज के आसपास है। जबकि ट्राई द्वारा सुझाई बेस प्राइस के हिसाब से भारत में कीमत लगभग 492 करोड़ रुपये प्रति मेगा हट्र्ज अर्थात छह गुना तक अधिक बैठती है।

इससे पहले सरकार ने 2016-17 में कुल 5.63 लाख करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर सात प्रकार के बैंड (3-जी व 4-जी) के तहत कुल 2354.44 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी। परंतु उसे केवल 965 मेगाहट्र्ज की बिक्री से मात्र 65,789 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे। नतीजतन सरकार ने 2017-18 तथा 2018-19 में स्पेक्ट्रम की कोई नीलामी नहीं की। चालू वित्त वर्ष 2019-20 में होने वाली नीलामी 5-जी स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी होगी।

तीन दिन तक चलने वाला इंडिया मोबाइल कांग्रेस मुख्यतया 5-जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन और निवेश आकर्षण पर आधारित है। सम्मेलन में देश-विदेश की 500 बड़ी तथा 250 स्टार्ट-अप कंपनियां भाग ले रही हैं।

इंडस्ट्री ने की स्पेक्ट्रम की निरंतर उपलब्धता की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

टेलीकॉम इंडस्ट्री ने देश में मोबाइल कम्यूनिकेशन के समुचित विकास के लिए जरूरत के वक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की मांग की है। इंडस्ट्री का कहना है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी में होने वाली देरी पूरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करती है। देश की तीनों सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक सुर में कहा कि टेलीकॉम सेक्टर की दशा सुधारने के लिए अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी में कीमतें वाजिब होनी चाहिए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के पहले दिन रिलायंस जियो के निदेशक बोर्ड के सदस्य महेंद्र नाहटा ने कहा कि सरकार को स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के संबंध में एक स्पष्ट रोडमैप बनाने की जरूरत है। दो नीलामियों के बीच जरूरत के मौकों पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध होना चाहिए। सरकार को पिछली नीलामी में तय कीमत पर अगली नीलामी से पहले किसी भी वक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। समय से स्पेक्ट्रम उपलब्ध होना मोबाइल कम्यूनिकेशन इंडस्ट्री के विकास की पहली जरूरत है।

भारती इंटरप्राइजेज के वाइस चेयरमैन राकेश भारती मित्तल ने आयोजन के दौरान कहा कि देश में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के कुल खर्च का 75 फीसद हिस्सा तो सिर्फ स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले विभिन्न शुल्कों में चला जाता है। स्पेक्ट्रम की मौजूदा रिजर्व प्राइस वैश्विक स्तर के मुकाबले सात गुनी ज्यादा है। अगर हम 5-जी का विकास चाहते हैं, तो हमें इन महंगे शुल्कों पर विचार करना होगा।

वहीं, वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला का कहना था कि नए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए नियामकीय वातावरण का उद्योग के लिए उपयोगी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, 'हम टेलीकॉम उद्योग के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि नियामकीय वातावरण भी उद्योग के बड़े निवेश के लिए उचित हों।'

नाहटा ने भी कहा कि टेलीकॉम क्षेत्र में 5-जी टेक्नोलॉजी में भारत की स्थिति मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि स्पेक्ट्रम की कीमतों की गंभीरता से समीक्षा हो। 5-जी स्पेक्ट्रम के ऊंचे आधार मूल्य इसके नेटवर्क को अव्यावहारिक तो बना बनाएंगे ही, बल्कि इसमें गैरजरूरी देरी भी होगी।

अफवाहें फैलाने वाले संदेशों के स्रोत तक हो एजेंसियों की पहुंच

नई दिल्ली में सोमवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला। प्रेट्र

- इंडिया मोबाइल कांग्रेस में संचार मंत्री ने की इसकी वकालत
- कहा, डेटा प्राइवेसी, इनोवेशन और उपयोगिता के बीच संतुलन आवश्यक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वाट्सएप के जरिये प्रसारित होने वाले भ्रामक और झूठे संदेशों पर नियंत्रण की पैरवी करते हुए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत एंक्रिप्शन का सम्मान करता है। साथ ही कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों को भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने और अफवाहें व हिंसा फैलाने वाले संदेशों के स्रोत का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान पत्रकारों से बातचीत में रवि शंकर प्रसाद ने कहा, 'हम एंक्रिप्शन का सम्मान करते हैं। परंतु जिन मामलों में एक ही मुद्दे पर एक ही संदेश को, एक ही क्षेत्र में एक ही समय पर बार-बार भेजा जाता है और झूठी सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जाती हैं, उनसे निपटने के लिए एंफोर्समेंट एजेंसियों के पास उनके स्रोत की पहचान की क्षमता होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इंटरनेट टिकाऊ और सुरक्षित हो।' विश्व में भारत से सर्वाधिक संदेश सृजित होने का हवाला देते हुए प्रसाद ने कहा कि वह भारत को डेटा एनालिटिक्स और डेटा रिफाइनिंग का बड़ा केंद्र बनाने को लेकर अत्यंत उत्सुक हैं। इसलिए डेटा की प्राइवेसी, डेटा के इनोवेशन और डेटा की उपयोगिता के बीच संतुलन की आवश्यकता है।

मालूम हो कि फेसबुक के स्वामित्व वाले वाट्सएप ने संदेशों के स्रोत की जानकारी देने के भारत के अनुरोध को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उसका कहना है कि ऐसा करने से उसकी प्राइवेसी और एंड-टू-एंड इनक्रिप्शन की नीति प्रभावित होगी। इस संबंध में पिछले महीने फेसबुक के वैश्विक प्रमुख निक क्लेग ने प्रसाद से मुलाकात की थी। इसमें उन्होंने संदेशों के स्रोत का पता लगाने के लिए 'मेटा डेटा' तथा मशीन इंटेलीजेंस जैसे वैकल्पिक रास्ते सुझाए थे। साथ ही एजेंसियों की मदद के लिए उन्हें वाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंकेज प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा था। उनका कहना था कि वाट्सएप के संदेश एंक्रिप्टेड होने से खुद कंपनी भी उन संदेशों को नहीं पढ़ सकती।

उस वक्त रवि शंकर प्रसाद ने उनसे कहा था कि वाट्सएप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, भारत में तकनीकी जागरूकता में वाट्सएप ने बड़ी भूमिका निभाई है। केरल में बाढ़ राहत में उसका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन साथ ही मॉब लिंचिंग, रिवेंज पॉर्न के मामले में इससे परेशानी भी खड़ी हुई है। वाट्सएप को इसका तकनीकी रास्ता निकालना पड़ेगा। उसे भारतीय कानून का पालन करना चाहिए और भारत में अपनी कॉरपोरेट शाखा स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा उसे भारत में अपना ग्रीवांस ऑफिसर भी नियुक्त करना चाहिए।

गौरतलब है कि डाटा लोकलाइजेशन के मुद्दे पर सरकार पहले ही किसी देश या कंपनी के प्रभाव में आने से इन्कार कर चुकी है। इसकी भी एक बड़ी वजह यही है कि किसी असामान्य परिस्थिति में संबंधित पक्षों पर कार्रवाई करने में भारत को उन देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जहां अभी डाटा सुरक्षित रखा जा रहा है।

शराब निर्माताओं पर मेहरबानी गन्ना किसानों पर भारी

अवनीश त्यागी, लखनऊ

यूपी में शीरा नीति विरोधाभासों में घिरी नजर आती है। शीरा बनाता कोई और है, नियंत्रण किसी और विभाग का है। किसानों का इससे सीधा कोई संबंध नहीं, लेकिन बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से सबसे अधिक असर उन्हीं पर है। बीमार होते चीनी उद्योग को भी इससे संजीवनी मिलने की उम्मीद नहीं क्योंकि शराब निर्माताओं के केंद्र में रखकर ही नीतियां तैयार की गईं। शीरा आरक्षण चीनी मिलों के लिए कोढ़ अलग से बना हुआ है, क्योंकि इससे उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है।

मदिरा निर्माताओं के लिए सरकार ने शीरे का आरक्षण कोटा 12 से बढ़ाकर 16.50 प्रतिशत किया है। यानि मिल मालिकों को कुल उत्पादित शीरे का 16.50 प्रतिशत हिस्सा बाजार से बेहद कम दर पर बेचना अनिवार्य है। जो शीरा बाजार में 450 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकता है, उसे देसी शराब बनाने के लिए मात्र 75 से 80 रुपये प्रति क्विंटल दर से बेचना पड़ता है। मिल संचालकों के अनुसार इससे उन्हें 350 से 400 करोड़ रुपये की हानि होती है जिसमें से लगभग सौ करोड़ रुपये का नुकसान सहकारी चीनी मिलों के हिस्से आता है। अधिकतर सहकारी मिलों की दयनीय दशा किसी से छिपी नहीं है। इनको चलाए रखने के लिए सरकार को प्रतिवर्ष मदद करनी पड़ती है। ऐसे में शीरा आरक्षण से होने वाला सौ करोड़ रुपये का नुकसान सहकारी क्षेत्र की मिलों के लिए कंगाली में आटा गीला होने जैसा है।

गन्ना सहकारी समिति अध्यक्ष महासंघ के महामंत्री अरविंद कुमार सिंह कहते है कि नया पेराई सत्र 30 अक्टूबर से आरंभ करने का दावा किया जा रहा है। परंतु अभी किसानों के पिछले सत्र के 4,611 करोड़ रुपये मिलों पर अटके हैं। सरकार चाहे तो देशी शराब निर्माताओं को अलग से मदद दे परंतु मिलों की आत्मनिर्भरता बनाए रखी जानी चाहिए।

स्थायी होती बकाया भुगतान समस्या

पिछले कई वर्षों से मिलों द्वारा समय से भुगतान नहीं कर पाने की समस्या बनी है। केवल चीनी बिक्री के भरोसे मिलों को चलाना मुश्किल हो रहा है। गन्ने की उपज बढ़ने से प्रदेश में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा चीनी की मांग में ठहराव और मूल्य नियंत्रित नीति के चलते प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश में करीब 50 लाख मीट्रिक टन चीनी अब भी गोदामों में है। इतना ही नहीं, चीनी बिक्री का कोटा भी सरकार तय करती है। मिल मालिक अपनी मर्जी से चीनी नहीं बेच सकते। औसतन प्रतिमाह सात लाख टन चीनी बेचने की अनुमति है। जाहिर है चीनी बिक्री पर कंट्रोल का असर गन्ने के भुगतान पर भी होता है।

विभागीय समन्वय का संकट : शीरे को लेकर दो विभागों में आपसी तालमेल बेहतर न होना भी आड़े आता है। शीरे का उत्पादन गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग के अधीन है परंतु इसका नियंत्रण आबकारी विभाग ही करता है। इस कारण भी किसानों को लाभ से वंचित रहना पड़ता है। शीरे का उत्पादन व नियंत्रण किसी एक विभाग के हाथ में होना बेहतर रहेगा। एथनॉल उत्पादन में प्रदेश अव्वल है। गत पेराई सत्र में 4.43 लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन के सचिव दीपक गुप्तारा कहते है कि प्रदेश में एथनॉल उत्पादन की अपार संभावना है। अभी कुल 121 चीनी मिलों में से 48 में ही एथनॉल उत्पादन हो रहा है।

शीरा निर्यात की भी संभावना : उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन लगातार शीरा आरक्षण का विरोध करता रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में भी उसने बार-बार कोटा बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि शराब निर्माण के लिए अनाज जैसे अन्य माध्यमों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। भारतीय शीरे की यूरोप में मांग बढ़ी है। निर्यात की संभावना को देखते हुए ही शीरा नीति तैयार हो तो बेहतर होगा।

प्रतीकात्मक

चालू वित्त वर्ष के प्रमुख लक्ष्य

आबकारी राजस्व	31600 करोड़ रुपये
देशी शराब से राजस्व	14500 करोड़ रुपये
देशी शराब उत्पादन लक्ष्य	43.64 करोड़ लीटर
शीरा उत्पादन लक्ष्य	500 क्विंटल
एथनॉल उत्पादन लक्ष्य	61 करोड़ लीटर

किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

मिलें	कुल गन्ना मूल्य	बकाया
निगम (3)	181.50	33.86
सहकारी (24)	2892.54	335.17
निजी (92)	29974.00	4242.09
कुल मिलें (119)	33048	4611.12

(नोट–बकाया गन्ना मूल्य करोड़ रुपये में)

शराब निर्माताओं को राहत देने से अधिक जरूरी चीनी उद्योग को बचाना है। यह 32 लाख गन्ना किसान परिवारों के हितों से जुड़ा मसला है। चीनी मिलें घाटे में रहेंगी तो गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या प्रतिवर्ष बनी ही रहेगी।
–अरविंद कुमार सिंह, महामंत्री, गन्ना सहकारी समिति अध्यक्ष महासंघ

प्रधान ने की पेट्रो उत्पादों पर जीएसटी की अपील

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आग्रह
- इंडिया इनर्जी फोरम के उद्घाटन में प्रधान ने जेट फ्यूल से शुरुआत का सुझाव दिया

प्रतीकात्मक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर वित्त मंत्रालय से आग्रह किया कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसकी शुरुआत जेट फ्यूल और नेचुरल गैस से करने का भी सुझाव दिया है। सोमवार को इंडिया एनर्जी फोरम के सेरावीक कार्यक्रम उद्घाटन करते हुए पेट्रोलियम मंत्री ने जब यह आग्रह किया तो उसके कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंचीं। प्रधान ने कहा, 'जीएसटी एक ऐतिहासिक सुधारवादी कदम और अब इसे लागू हुए दो वर्ष हो गए हैं। पेट्रोलियम सेक्टर लगातार यह मांग कर रहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी में शामिल किया जाए। मैं एक बार फिर वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे एटीएफ और गैस से इसकी शुरुआत करें।'

जीएसटी को लागू करते समय पेट्रोलियम सेक्टर (क्रूड, पेट्रोल, डीजल, गैस, एटीएफ) को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। इसकी वजह यह है कि कई राज्यों के राजस्व में इन उत्पादों से होने वाली वसूली का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है तो घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने की मांग होने लगती है। अभी जबकि सरकार पेट्रोलियम सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, तब देसी-विदेशी कंपनियां भी सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर एक समान टैक्स लगाने की मांग कर ही हैं। प्रधान की इस मांग के पीछे एक वजह यह भी है कि सभी पेट्रो उत्पादों पर समान टैक्स लगने पर गैस को बढ़ावा मिलेगा। सरकार चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी मौजूदा छह फीसद से बढ़कर वर्ष 2030 तक 15 फीसद हो जाए।

प्रधान के मुताबिक जिस तेजी से देश की अर्थव्यवस्था गैस आधारित हो रही है, उसे देखते हुए अगले कुछ वर्षों में 118 अरब डॉलर (आठ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) के निवेश की जरूरत होगी। इसमें से वर्ष 2023 तक ही 58 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। उसके बाद के वर्षों में पाइपलाइन लगाने, टर्मिनल स्थापित करने, आयात करने और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगाने में निवेश होगा। उन्होंने कहा कि अब वैश्विक पेट्रोलियम कंपनियां भी भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में भरोसा दिखाने लगी हैं। सउदी अरैमको, एडीएओसी, बीपी, शेल, टोटल व एक्सॉनमोबील जैसी कंपनियां भारत में निवेश करने लगी हैं। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम धीरे धीरे गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाकर पर्यावरण का भी संरक्षण करेंगे।

वित्त मंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत सरकार की तरफ से ऊर्जा सेक्टर में, खास तौर पर रिन्युअल सेक्टर में निवेश करने को इच्छुक कंपनियों को यह भरोसा दिलाया कि उन्होंने कानूनी तौर पर जो भी समझौता किया है उसका सम्मान किया जाएगा। भारत के ऊर्जा सेक्टर या इसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए निवेश करने वाले सभी समझौतों का पालन किया जाएगा। सीतारमण का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में सोलर इनर्जी सेक्टर की कुछ कंपनियों ने जो समझौते किये हैं उनके खिलाफ कई राज्यों में सुगबुगाहट हो रही है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सोलर इनर्जी प्लांट लगाने के समझौते को बदलने की बात कही है। इससे अनिश्चितता बन गई है और भारत के सोलर सेक्टर के लिए इसे एक बड़ा धक्का माना जा रहा है।

टोटल ने अडानी गैस में खरीदा हिस्सा भारत में बड़े निवेश की तैयारी

37.4 फीसद हिस्सेदारी के लिए 5,700 करोड़ रुपये का निवेश

- भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार फ्रांसीसी कंपनी टोटल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

फ्रांस की पेट्रोलियम कंपनी टोटल ने अडानी गैस में हिस्सेदारी खरीदते हुए अब भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाने का साफ संकेत दे दिया है। कंपनी ने अडानी गैस में 37.4 फीसद हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। इस इक्विटी के लिए कंपनी करीब 5,700 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। टोटल का यह निवेश तब हुआ है जब भारत सरकार पेट्रोलियम सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है टोटल और अडानी आगे चलकर पेट्रोलियम सेक्टर में भी संभावनाएं तलाशेंगी।

टोटल ने पहले भी भारत के गैस सेक्टर में उतरने की घोषणा की थी और इसके लिए दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी शेल के साथ एक संयुक्त उद्यम भी बनाया था। इसका उद्देश्य गुजरात के हजीरा में एक एलएनजी टर्मिनल बनाना था। लेकिन अगस्त, 2018 में टोटल इससे बाहर हो गई और उसने अडानी के साथ मिलकर एक अन्य संयुक्त उद्यम बनाया ताकि 10 वर्षों में 1,500 पेट्रोलियम पंप स्थापित किए जाएं। टोटल यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका में पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण के क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है। अब वह अडानी के साथ मिलकर सरकारी क्षेत्र की बीपीसीएल के लिए भी दांव लगा सकती है। वैसे टोटल हाल के दिनों में भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में बड़े पैमाने पर उतरने की घोषणा करने वाली दूसरी कंपनी है। इसके पहले सऊदी अरब की तेल कंपनी ने पेट्रोलियम सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 20 फीसद इक्विटी खरीदने का एलान किया था। यहां कुल निवेश तकरीबन 15 अरब डॉलर का होगा।

बहरहाल, अब टोटल की तरफ से बताया गया है कि अडानी गैस में पहले चरण में 25.2 फीसद इक्विटी खुली निविदा के जरिए खरीदी जाएगी। इसके बाद इक्विटी बढ़ाकर 37.4 फीसद की जाएगी। अडानी गैस में अभी अडानी समूह की इक्विटी 74.8 फीसद है जिसे आगे घटा कर टोटाल के बराबर (37.4) पर लाया जाएगा। यह कंपनी पहले ओडिशा में लगने वाले एलएनजी टर्मिनल का काम पूरा करेगी। यहां से भारत के साथ ही बांग्लादेश को भी गैस की आपूर्ति की जाएगी।

अडानी समूह की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि अगले 10 वर्षों में भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में भारी निवेश का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। कंपनी अभी 1,500 पेट्रोल पंप, 1,500 गैस स्टेशन और 60 लाख घरों को गैस आपूर्ति देने का नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रही है।

लेखाजोखा

उठापटक के बाद सकारात्मक स्तर पर बंद हुए बाजार

घरेलू और ग्लोबल मोर्चों से मिलेजुले संकेतों का असर दिखा, कारोबारी सत्र में 448 अंक ऊपर–नीचे गया सेंसेक्स

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 448 अंक ऊपर-नीचे होने के बाद 87 अंक यानी 0.23 परसेंट बढ़त के साथ 38,214.47 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह 38,513 अंक के उच्च स्तर और 38,066.13 अंक के निचले स्तर तक गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36.10 अंक यानी 0.32 परसेंट की बढ़त के साथ 11,341.15 के स्तर पर बंद हुआ।

सोमवार के सत्र में 5.32 परसेंट का उछाल के साथ टाटा मोटर्स टॉप गेनर रहा। इस दौरान इसके शेयरों में दर्ज किया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ओएनजीसी में स्टेक बेचने को लेकर दिए गए बयान के चलते इसके शेयरों में 4.73 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। अन्य बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो और टीसीएस के नाम रहे। दूसरी ओर इन्फोसिस शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दिन के कारोबार में कंपनी के शेयरों में 3.68 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, पॉवर ग्रिड, एसएंडटी, कोटक बैंक जैसी कंपनियों के शेयरों में 2.37 परसेंट तक की गिरावट देखी गई। जानकारों के मुताबिक अमेरिका-चीन के बीच प्राथमिक ट्रेड समझौते के चलते जहां निवेशकों में सकारात्मक धारणा बनी, वहीं विश्व बैंक द्वारा भारत की विकास दर के अनुमान में कमी करने की घोषणा से निवेशक हताश भी हुए। दूसरी ओर थोक महंगाई दर में गिरावट की सूचना ने भी बाजार को प्रभावित किया। इन सब वजहों से मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, हैंगसेंग, कोस्पी भी बढ़त के साथ बंद हुए।

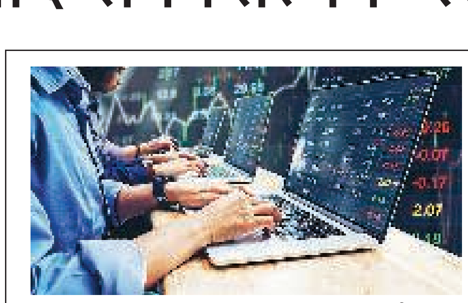

प्रतीकात्मक

बीएसई 16 कंपनियों पर लगाएगा प्रतिबंध

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीएसई के सेंसेक्स में सूचीबद्ध 16 कंपनियां चार नवंबर से अपने शेयरों की ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगी। स्टॉक एक्सचेंज ने तय समय में वित्तीय विवरण नहीं देने के चलते इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों में मनपसंद बेवरेजेज, बिनानी इंडस्ट्रीज सहित कुल 16 कंपनियां शामिल हैं।

इन्फोसिस के शेयर चार परसेंट लुढ़के

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमवार को इन्फोसिस के तिमाही मुनाफे में गिरावट की सूचना के चलते इसके शेयरों में लगभग चार परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। दिन के कारोबार में सेंसेक्स में कंपनी के शेयर 3.68 परसेंट गिरकर 785.65 प्रति शेयर के स्तर पर बंद हुए। वहीं निफ्टी में इसके शेयरों में 3.49 परसेंट की गिरावट देखी गई। यहां इसके शेयर 786.30 रुपये पर बंद हुए। सेंसेक्स में कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 12,905.99 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

एसबीआइ सबसे मूल्यवान कंपनियों में फिर शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : दो सप्ताह के बाद एसबीआइ फिर से शेयर बाजार की 10 सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनियों में शामिल हो गई है। एसबीआइ पहली अक्टूबर को इस सूची से बाहर हो गया था। इसका स्थान बजाज फाइनेंस ने ले लिया था। सोमवार को समाप्त हुए कारोबारी सत्र के बाद बीएसई में एसबीआइ का बाजार पूंजीकरण 2,27,979.20 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो कि बजाज फाइनेंस से 2,899.12 करोड़ अधिक है। पिछले कुछ समय के दौरान बैंकिंग शेयरों में उठापटक के चलते बैंक टॉप-10 से बाहर हो गया था।

सबसे परोपकारी भारतीयों की सूची में शिव नादर अव्वल

- मुकेश अंबानी को तीसरा स्थान, सबसे ज्यादा दान शिक्षा के क्षेत्र में
- इस वर्ष पांच करोड़ रुपये या अधिक दान करने वालों की संख्या दोगुनी रही

मुंबई, प्रेट्र : हुरून इंडिया ने परोपकारी भारतीयों की सूची जारी की है। इस सूची में टेक्नोलॉजी कंपनी एचसीएल के मालिक शिव नादर को पहला स्थान दिया गया है। सबसे अमीर भारतीय और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी इस सूची में तीसरे स्थान पर रहे हैं। परोपकारियों की सूची में दूसरा स्थान अजीम प्रेमजी को दिया गया है। प्रेमजी ने पिछले वर्ष अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था।

इस सूची के मुताबिक नादर और उनके परिवार ने 826 करोड़ रुपये दान किए, जबकि प्रेमजी ने 453 करोड़ और मुकेश अंबानी ने 402 करोड़ रुपये परोपकारी कार्यों में लगाए। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने मुकेश अंबानी को सबसे अमीर भारतीय बताया था। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पांच करोड़ या इससे अधिक रुपये दान करने वालों की संख्या दोगुनी रही। हालांकि इसमें धार्मिक दान को भी शामिल किया गया है।

हुरून इंडिया के मुताबिक परोपकारियों ने सबसे ज्यादा रुचि शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई। इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे ज्यादा दान दिया गया। इस दौरान एक रोचक बात यह देखी गई कि उम्र के साथ लोग ज्यादा परोपकारी कार्य करते हैं। इस सूची में दान करने वालों की औसत उम्र 64 वर्ष रही।

कॉरपोरेट परिवार पहले ही परोपकारी कार्यों में धन लगाते रहे हैं, लेकिन 2013 में भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में सुधार के जरिये इसे अनिवार्य कर दिया था। कानून के मुताबिक बड़ी कंपनियों को अपनी आय का दो परसेंट सीएसआर के तहत जनहित कार्यों में खर्च करना होता है। गौरतलब है कि इस वर्ष अगस्त में सुधारवादी कार्यक्रमों के तहत सरकार ने सीएसआर पर खर्च में विफलता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल लिया था।

2017 में केटलोनिया को स्पेन से अलग करने के लिए गैरकानूनी तरीके से जनमत संग्रह कराया गया था। इस क्षेत्र के लोगों ने अलगाव के पक्ष में मतदान किया था। लेकिन इस प्रयास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई समर्थन नहीं मिला।

वीडियो में विरोधियों का काम तमाम करते दिखे ट्रंप

न्यूयॉर्क टाइम्स से

▸ राष्ट्रपति के समर्थकों के सम्मेलन में दिखाया गया काल्पनिक वीडियो

वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी मीडिया के प्रति रवैया जगजाहिर है। वह मीडिया को कई बार फेक न्यूज करार दे चुके हैं। अब उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो दहला देने वाला है। इस वीडियो में चित्रित दृश्य हालांकि वास्तविक नहीं हैं। इसमें उन्हें अपने मीडिया और सियासी विरोधियों को गोली और चाकू मारते दिखाया गया है। इस काल्पनिक वीडियो को पिछले हफ्ते ट्रंप के मियामी स्थित रिजॉर्ट में उनके समर्थकों के सम्मेलन में दिखाया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित करने वालों में ट्रंप के पुत्र डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, पूर्व प्रवक्ता सारा सैंडर्स और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस जैसे लोग भी शामिल थे।

माना जा रहा है कि यह वीडियो अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप के प्रचार का हिस्सा है। सैंडर्स और ट्रंप जूनियर के एक करीबी ने हालांकि बीते रविवार को कहा कि उन्होंने सम्मेलन में वीडियो नहीं देखा। इस वीडियो में कई इंटरनेट मीम को शामिल किया गया है। इसमें ट्रंप के चुनाव प्रचार का लोगो भी दिखाया गया है। सबसे हिंसक दृश्य में ट्रंप सरीखे एक व्यक्ति को उन लोगों पर गोलीबारी करते दिखाया गया है, जिनके चेहरों पर सीएनएन, वाशिंगटन पोस्ट और एनबीसी टीवी के लोगो लगे थे। एक अन्य क्लिप में उन्हें विपक्षी रिपब्लिकन सीनेटर मिट रोमनी को जमीन पर पटकते और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को दीवार से टकराते दिखाया गया है। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में इस वीडियो को रिकार्ड कर न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के एक पत्रकार को भेज दिया था। सम्मेलन के आयोजकों ने एक बयान जारी कर कहा कि सम्मेलन में दिखाई गई क्लिप मीम प्रदर्शनी का हिस्सा थीं।

सौ ब्रिटिश भारतीय संगठनों ने की कश्मीर पर कॉर्बिन के रुख की निंदा

लंदन, प्रेट्र : सौ से ज्यादा ब्रिटिश भारतीय पेशेवर और सामुदायिक संगठनों ने सोमवार को ब्रिटेन में विपक्ष के नेता जेरेमी कॉर्बिन को पत्र लिखकर कश्मीर पर लेबर पार्टी के रुख की निंदा की। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लेबर पार्टी ने 25 सितंबर को अपनी वार्षिक बैठक में एक आपात प्रस्ताव पारित किया था।

इस पत्र में ब्रिटिश भारतीयों के विभिन्न वर्गों के संगठनों के नाम जुड़े हैं। इनमें भारतीय पेशेवर फोरम (आइपीएफ), भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (आइएनएसए), हिंदू काउंसिल यूके, मंदिरों के संगठन और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। पत्र में कॉर्बिन पर ऐसे विभाजनकारी आपात प्रस्ताव को अपनाकर भारत-पाक द्विपक्षीय रिश्तों को ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में लाने का आरोप लगाया गया है जिसमें इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की गई है। पत्र के मुताबिक, 'लेबर पार्टी के हालिया सम्मेलन में पारित आपात प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि इसमें तीसरे देशों के बीच और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की मांग की गई है और उसका मसौदा

जेरेमी कॉर्बिन। फाइल

भी एक पक्षीय व विभाजनकारी तरीके से तैयार किया गया है। हम कश्मीर मसले को ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में घसीटने के प्रयासों से भी बेहद चिंतित हैं, जिसके सामुदायिक सद्भाव पर बेहद गंभीर दुष्परिणाम होंगे।' ब्रिटेन स्थित मीडिया हाउस इंडिया इंक के सीईओ और लेबर पार्टी के भारतीय समुदाय वार्ता फोरम के पूर्व चेयरमैन मनोज लाडवा ने कहा, 'ब्रिटेन में भारतीय मूल के 15 लाख से ज्यादा लोग हैं जो पारंपरिक रूप से लेबर पार्टी को वोट देते रहे हैं। अगर जेरेमी कॉर्बिन को नहीं लगता कि उन्हें समस्या हो सकती है, तो वह निश्चित रूप से गंभीर मुश्किल में हैं।'

ब्रिटेन में पाकिस्तानी मॉडल लापता, मांगी थी शरण

इस्लामाबाद, आइएएनएस: कलाकारों के आरक्षित मनोरंजन वीजा पर ब्रिटेन आने के बाद एक पाकिस्तानी मॉडल और स्टेज डांसर लापता हो गई है। जियो न्यूज ने शनिवार को रिपोर्ट में कहा कि मूलरूप से पाकिस्तान के ओकारा की राबिका सहर लाहौर में रहती थीं। ब्रिटेन में विभिन्न मनोरंजन स्थलों पर डांस परफॉर्मेंस के लिए वह तीन महीने के लिए आठ सितंबर को देश पहुंची थी।

सूत्रों का कहना है कि उसने पांच दिन बाद गुलामी का हवाला देते हुए शरण देने का आग्रह किया था। मैनचेस्टर में अपने अगले शो में जाने से पहले लंदन में परफॉर्मेंस के आखिरी दिन सहर ने अपने साथी कलाकारों से कहा था कि उन्होंने ब्रिटेन में रहने का फैसला किया है और वह पाकिस्तान नहीं लौटेंगी। जियो न्यूज के मुताबिक सहर ने लंदन के एक जाने-माने स्थान पर निरीक्षण के लिए मारे गए छापे के दौरान शरण देने का अनुरोध किया था।

पोप फ्रांसिस को भेंट की पुस्तक

केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने वेटिकन सिटी में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को 'भागवत गीता एकॉर्डिंग टू गांधी' और भारत की प्राचीन परंपराओं को दर्शाने वाले केरल के प्रसिद्ध मंदिरों पर आधारित 'कैपरिसंड एलीफेंट' की प्रतियां भेंट की। मुरलीधरन रविवार को वेटिकन में आयोजित समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस समारोह में भारतीय नन मरियम थेरेसिया को पोप फ्रांसिस ने संत घोषित किया था। एएनआइ

ऑस्ट्रेलियाई पीएमओ ने पत्रकारों को भेज दिए गोपनीय दस्तावेज

सिडनी, एएनआइ : ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से बड़ी चूक होने की खबर सामने आई है। पीएमओ ने गलती से सत्तारूढ़ गठबंधन लिबरल-नेशनल पार्टी के सांसदों की जगह पत्रकारों को गोपनीय दस्तावेज भेज दिए। सांसदों को ये दस्तावेज सोमवार से शुरू होने वाले संसद सत्र की तैयारी करने के लिए भेजे जाने थे।

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईमेल के जरिये भेजे गए इन गोपनीय दस्तावेजों में ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगने वालों की बढ़ती संख्या, टैक्स, सीरिया में चल रहे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते और विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे जैसे तमाम मसलों पर बात की गई थी। इनमें सत्तारूढ़ सांसदों को यह भी बताया गया था कि उन्हें इन मसलों पर पत्रकारों और विपक्ष के सवालों का जवाब किस सियासी रणनीति के साथ देना है। 8,200 शब्दों के इस दस्तावेज में बताया गया था कि अगर जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट के बारे में कोई सवाल पूछा जाए तो सांसद उसका जवाब टाल जाएं या यह कह दें, 'हम कार्बन टैक्स लगाए बगैर लक्ष्य हासिल कर लेंगे।' ऑस्ट्रेलिया में जब विपक्षी लेबर पार्टी सत्ता में थी तो उसने कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया था।

गोपनीय दस्तावेज को लेकर हुई इतनी बड़ी चूक पर प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने इस चूक को महत्व नहीं देते हुए कहा, 'आधुनिक राजनीति की दुनिया में इस तरह की चीजें होती रहती हैं।'

नापाक हरकत ▸ कश्मीर मामले में मुंह की खाने के बाद भी नहीं सुधर रहा पड़ोसी देश

भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में बच्चों को इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान

बच्चों ने लगाए रटाए गए भारत विरोधी नारे, वीडियो हुआ वायरल

इस्लामाबाद, एएनआइ : कश्मीर मसले पर दुनियाभर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत को बदनाम करने के लिए वह आए दिन नए-नए हथकंडे आजमा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अब भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए मासूम बच्चों को इस्तेमाल किया है। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानी बच्चे उन्हें रटाए गए भारत विरोधी नारे लगाते दिख रहे हैं।

पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने वायरल हुए 45 सेकेंड के इस वीडियो को पोस्ट किया है। उन्होंने इसके साथ ट्वीट किया, 'भ्रमित किए गए पाकिस्तानी बच्चों की एक और पीढ़ी जो भारत को हराने का सपना देख रही है।' वीडियो में एक बच्चा भारतीय सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। जबकि दूसरा बच्चा कह रहा है, 'हम शहादत देने वाले हर मुस्लिम का बदला लेंगे और हिंद पाकिस्तान बनेगा।' जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वह इस मसले को कई वैश्विक मंचों पर उठा चुका है, लेकिन हर जगह उसे किसी देश का साथ नहीं मिला।

सोशल मीडिया में हो रही किरकरी

भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले इस वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पाकिस्तान की खूब किरकरी हो रही है। बच्चों के इस्तेमाल को लेकर यूजर्स पाकिस्तानी हुक्मरान को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने पूछा, 'क्या इन बच्चों के शिक्षक आत्मघाती हमले का लाइव डेमो भी देंगे?' जबकि एक दूसरे यूजर ने कहा, 'पाकिस्तानी मनोरंजन उद्योग इस तरह के वीडियो के जरिये भारत में खूब फल-फूल रहा है। वे रोजाना भारत को कॉमेडी वीडियो मुहैया करा रहे हैं।' अल्ला रहमान नाम के एक ट्विटर यूजर ने पूछा, 'क्या यही जिन्ना का सपना था?' एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, 'हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सेना में अधिकारी, पायलट और वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब भी जिहाद का सपना दिखाया जा रहा है।'

सेना के खिलाफ नारे लगाने वाला वकील अगवा

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान की एक अदालत में सेना के खिलाफ नारे लगाने वाले वरिष्ठ वकील काशिफ अली चौधरी को यहां दिनदहाड़े अगवा कर लिया गया। विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वकील चौधरी ने पिछले हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ अन्य वकीलों के साथ सेना विरोधी नारे लगाए थे।

चौधरी के भाई नाजिम हुसैन ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि उनके भाई को ठोकर नियाज बेग इलाके से उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वह वहां केबल वायर खरीदने गए थे। दो वाहनों में आए कुछ अज्ञात लोगों ने पहले उनका रास्ता रोका और इसके बाद उन्हें जबरन एक वाहन में बैठाकर ले गए। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे शरीफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सात साल जेल की सजा काट रहे हैं।

'हाफिज पर मुकदमा चलाए पाकिस्तान'

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर फिर सख्त हिदायत दी है। अमेरिका ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान को अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे आतंकी संगठनों को रोकना चाहिए। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद समेत लश्कर-ए-तैयबा के दूसरे बड़े आतंकियों पर मुकदमा चलाना चाहिए। अमेरिका का यह सख्त बयान ऐसे समय आया है, जब पाकिस्तान पर आतंकी फंडिंग को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की काली सूची में डाले जाने का खतरा मंडरा रहा है।

अमेरिकी विदेश विभाग की दक्षिण और मध्य एशियाई ब्यूरो की प्रमुख एलिस वेल्स ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के चार शीर्ष आतंकियों की गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए कहा, 'हम चार आतंकियों की गिरफ्तारी की खबर का स्वागत करते हैं। पीड़ित इस बात के हकदार हैं कि वे सईद समेत इन आतंकियों पर मुकदमा चलता हुआ देखें।'

दाऊद के गुर्गे मुन्ना झिंगड़ा को थाइलैंड ने पाक के हवाले किया

▸ इस कदम से भारत और बैंकाक के रिश्तों में आ सकती है खटास

▸ अखबार द नेशन थाइलैंड ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया

बैंकाक, एएनआइ : मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे मुन्ना झिंगड़ा उर्फ मुहम्मद सलीम को थाइलैंड ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। उसके इस कदम से नई दिल्ली और बैंकाक के रिश्तों में खटास आ सकती है। समाचार पत्र 'द नेशन थाइलैंड' के 11 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित रिपोर्ट में इस आशय का दावा किया गया है।

दरअसल पिछले दिनों बैंकाक की एक अदालत ने झिंगड़ा को पाकिस्तानी नागरिक घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद 9 अक्टूबर को दाऊद के खास गुर्गे को पाकिस्तान प्रत्यर्पित कर दिया गया। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से उपरोक्त मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि थाइलैंड के इस कदम से नई दिल्ली हैरान है। इसको लेकर भारत, थाइलैंड के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा भी कर सकता है। बता दें कि मुन्ना झिंगड़ा को भारत लाने की कोशिशें नवंबर 2016 में उस समय तेज हो गईं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकाक गए थे।

थाई अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि झिंगड़ा के प्रत्यर्पण के लिए भारत पिछले तीन साल से प्रयासरत था। इसको लेकर बैंकाक की अदालत में बकायदा दलील दी गई कि झिंगड़ा एक भारतीय नागरिक है। उसको सईद मुजक्किर मुदस्सर हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि के लिए झिंगड़ा के माता-पिता को विमान से बैंकाक लाने का प्रस्ताव भी दिया, ताकि उनका डीएनए परीक्षण कर थाई अधिकारी आश्वस्त हो सकें कि वह भारतीय नागरिक है। लेकिन भारत की इस दलील को नहीं माना गया। द नेशन थाइलैंड के अनुसार, झिंगड़ा के पाक प्रत्यर्पण से भारत बेहद खफा हैं।

दरअसल माफिया डॉन छोटा राजन पर जानलेवा हमला करने के मामले में बैंकाक की एक अदालत ने दो दशक पहले झिंगड़ा को 35 साल की सजा सुनाई थी। बाद में उसकी सजा को कम करके 16 वर्ष कर दिया गया। इसके चलते सजा पूरी होने पर वह 2016 में जेल से रिहा कर दिया गया। चूंकि, भारत ने उसकी रिहाई से पहले साल 2012 में ही थाइलैंड से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर दी थी, इसलिए झिंगड़ा एकबार फिर कानूनी लड़ाई में घिर गया। भारतीय अधिकारी दरअसल मुन्ना झिंगड़ा के जरिये दाऊद इब्राहिम को दबोचना चाहते थे। यही कारण है कि भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए पूरा जोर लगाया था।

बता दें कि भारत कई बार पाकिस्तान को दाऊद को सौंपने के लिए कह चुका है। लेकिन पड़ोसी देश ने उसे आज तक नहीं सौंपा है। पाकिस्तान का दावा है कि दाऊद उनके देश में नहीं है, पर पाक में मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार फरार अंडरवर्ल्ड डॉन की मौजूदगी जग जाहिर है।

श्रृंगला ने कहा– जनमत संग्रह 2020 एक बेकार का मुद्दा

▸ अमेरिका में भारतीय राजदूत ने इसे मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थक पाक एजेंटों की करतूत बताया

▸ कहा– इस मुहिम को सिखों का कोई समर्थन नहीं

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने जनमत संग्रह 2020 की बात करने वाले मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान का एजेंट करार दिया है। उनका आरोप है कि ये मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज करने की फिराक में हैं। श्रृंगला के अनुसार, चंद हताश लोगों के इस समूह को सिखों का रत्ती भर भी समर्थन प्राप्त नहीं है। उन्होंने जनमत संग्रह 2020 को एक बेकार का मुद्दा करार दिया।

दरअसल अमेरिका में सक्रिय कुछ अलगाववादी सिखों ने उपरोक्त मुहिम के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रखी है। ये लोग जनमत संग्रह 2020 के बहाने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर भारतीय राजदूत ने अलगाववादियों पर करारा हमला बोला है। बाल्टीमोर स्थित एक गुरुद्वारा में अरदास करने के बाद श्रृंगला बोले, 'इसके (जनमत संग्रह) आयोजक चंद लोग हैं। तथाकथित जनमत संग्रह 2020 एक बेकार का मुद्दा है।' संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यह तल्ख टिप्पणी की। उनके मुताबिक, 'ये लोग हताश हैं। आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है। इनका मकसद दहशतगर्दी फैलाना है। मेरा मानना है कि अब ये लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं। जल्द अतीत की बात हो जाएंगे।' भारतीय राजदूत का कहना था, 'हम जानते ही हैं कि ये वो लोग हैं, जिन्हें हमारे पड़ोसी दुश्मन देश से खुली मदद मिल रही है।

जनमत संग्रह की बात करने वाले दरअसल उसी देश (पाकिस्तान) के एजेंट हैं। इन लोगों ने झूठी अफवाह फैला रखी है। दुष्प्रचार में जुटे हैं।' उन्होंने कहा कि इन लोगों का सिख समुदाय में कोई समर्थन नहीं है। भारतीय राजदूत के अनुसार, भारत-अमेरिका दोस्ती को मजबूत करने में सिखों का अहम योगदान है। इससे पूर्व श्रृंगला ने सिख एसोसिएशन ऑफ बाल्टीमोर एवं सिख ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया।

सीरिया ने तुर्की सीमा पर भेजे अपने सैनिक

दमिश्क, एएफपी : तुर्की से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनाती के लिए सीरिया ने अपने सैनिक भेज दिए हैं। जाहिर है ये सैनिक सीरिया की संप्रभुता की रक्षा के अधिकार के तहत तुर्की के हमलों को रोकेंगे, जो वह सीरिया की सीमावर्ती कुर्द आबादी पर कर रहा है।

सीरिया की तुर्की से लगने वाली सीमा अमेरिकी सैनिकों के हटने के बाद खाली पड़ी है और तुर्की के लड़ाकू विमान और थल सेना मनमाने तरीके से सीरिया में घुसकर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कुर्दों से समझौते के तहत सीरिया की सेना सीमा पर आ रही है या अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैनात हो रही है।

सीरियाई कुर्दों पर तुर्की की हमले की चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना सीरिया की सीमा से हटी थी। अमेरिका के इस फैसले की दुनिया भर में निंदा हुई, क्योंकि सीरियाई कुर्दों ने आतंकी संगठन आइएस से लड़ाई में अमेरिकी सेना का साथ दिया था। यही कुर्द अमेरिका के समर्थन से सीरिया में लोकतंत्र की मांग को लेकर बशर अल असद सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़े हुए थे। अब जबकि सीरिया में आइएस की चुनौती खत्म हो चुकी है और कई महीनों से आतंकी हिंसा शांत है, तब तुर्की की

तुर्की के सांलिउर्फ के सीलियानपिनार के सीमावर्ती शहर में तैनात सेना की बख्तरबंद गाड़ियां। रायटर

हमले की धमकी के बाद अचानक अमेरिकी सैनिक सीरिया की सीमा से हट गए। अब तुर्की की साधन संपन्न सेना से कुर्द लड़ाकों और आबादी को बचाने के लिए कोई नहीं है। पिछले हफ्ते से जारी तुर्की के हमलों के बीच सीरिया सरकार ने साफ कहा था कि देश के साथ गद्दारी करने वाले कुर्दों से उसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। इसलिए तुर्की के हमलों से पैदा स्थिति में वह दूर ही रहेगी। लेकिन चंद रोज में बदले हालात में सीरिया की सेना अब अपनी सीमा पर जा रही है।

तुर्की अपनी सीमा पर 30 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाना चाहता है जिससे सीरिया के कुर्द चरमपंथी उसके इलाके में आकर वारदात न कर सकें। वह 36 लाख सीरिया शरणार्थियों को भी वापस सीरिया भेजना चाहता है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने अब तुर्की के हमलों को निंदा की है और उसे प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। लेकिन तुर्की चेतावनी की चिंता किए बगैर कुर्दों पर हमले जारी रखे है।

रूस ने अस्पतालों पर बमबारी से इन्कार किया: सीरिया में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके के चार अस्पतालों पर रूसी विमानों की बमबारी की अमेरिका के मीडिया में आई खबरों को रूस ने बेबुनियाद करार दिया है।

आइएस आतंकियों को छोड़ सकते हैं कुर्द

वाशिंगटन : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्षेत्र में अमेरिकी दखल बनाए रखने की मंशा से कुर्द लड़ाके कैद किए इस्लामिक स्टेट (आइएस) आतंकियों और उनके परिजनों को छोड़ सकते हैं। ज्यादातर आतंकी तुर्की और यूरोपीय देशों के हैं। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया से अपने एक हजार सैनिकों को वापस बुलाया है। इसी के बाद तुर्की की सेना ने अमेरिका के सहयोगी रहे कुर्दों पर हमले शुरू किए हैं। तुर्की के हमले झेल रहे कुर्द अब आतंकियों की हिरासत बनाए रख पाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं।

क्षतिग्रस्त तेल टैंकर की ईरान ने जारी कीं तस्वीरें

तेहरान, एएफपी : ईरान ने लाल सागर में अपने तेल टैंकर पर हुए हमले की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। शुक्रवार को सऊदी अरब की जल सीमा में हुए इस हमले में टैंकर में दो बड़े सूराख दिखाई दे रहे हैं। बताया गया है कि ये सूराख कम क्षमता की मिसाइल के हैं लेकिन तेल भरे टैंकर की तबाही के लिए ये पर्याप्त थे। लेकिन टैंकर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।

ईरान ने कहा है कि शुक्रवार को उसके टैंकर पर सऊदी अरब के जेद्दा बंदरगाह के नजदीक हमला हुआ। हमले में टैंकर पर अलग-अलग दिशाओं से दो विस्फोट किए गए। अमेरिका और ईरान के संबंधों में पैदा हुए तनाव के दौर में पहली बार किसी ईरानी जहाज पर हमला हुआ है। हमले के बाद की टैंकर की तस्वीरें नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी ने जारी की हैं। हमले का शिकार हुआ टैंकर इसी सरकारी कंपनी का है। हमले के चलते टैंकर से समुद्र में तेल का रिसाव शुरू हो गया जिसे बमुश्किल रोका जा सका।

खाड़ी क्षेत्र में मई और जून में तेल टैंकरों पर हुए हमलों और इसके बाद सितंबर में सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हुए हमलों का असर दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ा। अमेरिका और सऊदी अरब ने हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था।

मिले संकेत

गुरुवार और शुक्रवार को होने वाली ईयू समिट में समझौते पर लग सकती है मुहर, ब्रिटिश संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया

ब्रेक्जिट पर ईयू से समझौते का खाका तैयार !

लंदन, रायटर : यूरोपीय यूनियन (ईयू) से ब्रिटेन के अलगाव (ब्रेक्जिट) के लिहाज से चालू सप्ताह ऐतिहासिक महत्व वाला होगा। सोमवार को ईयू के वार्ताकारों ने संकेत दिया कि ब्रिटेन से कुछ सहूलियतों की अपेक्षा है लेकिन समझौते का खाका काफी हद तक तैयार हो गया है। गुरुवार और शुक्रवार को होने वाली ईयू समिट में समझौते पर मुहर लग सकती है और 31 अक्टूबर को व्यवस्थित तरीके से ब्रेक्जिट का रास्ता साफ हो सकता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भी ब्रेक्जिट को लेकर सरकार की प्राथमिकता घोषित कर दी है।

कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का अलग होना तय है। संसद की अपेक्षा के अनुरूप सरकार ईयू से समझौते की राह पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आयरलैंड ने भी समझौते के बिंदुओं पर सहमति जाहिर की है। ईयू ब्रिटेन से कुछ राहत चाहता है लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन यह अपेक्षा ऐसी नहीं है कि ब्रेक्जिट में कोई रुकावट पैदा हो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वार्ता के इस दौर में भी बिना शर्त ब्रेक्जिट की आशंका को दरकिनार नहीं किया है। कहा है कि समझौता संभव नहीं हुआ तो

बीते शुक्रवार को यूरोपीय यूनियन के मुख्यालय के बाहर ब्रेक्जिट के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। रायटर

31 अक्टूबर को बिना शर्त अलगाव होगा। तब वह संसद के बिना शर्त ब्रेक्जिट पर रोक के कानून की भी परवाह नहीं करेंगे। महारानी एलिजाबेथ सरकार की इस मंशा पर उसके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। महारानी ने कहा है कि 31 अक्टूबर को ब्रेक्जिट उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

तीन साल से ज्यादा की वार्ता के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उनमें लग रहा है कि ब्रेक्जिट की प्रक्रिया अब पूरी हो जाएगी। इसी के मद्देनजर रविवार को संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है। माना जा रहा है कि ईयू के साथ होने वाले समझौते को स्वीकृति के लिए संसद में रखा जाएगा। 1982 में हुए फाकलैंड युद्ध के बाद यह पहला मौका होगा जब ब्रिटेन में संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है।

स्पेन में 12 केटलन नेताओं को 13 साल तक की सजा

मैड्रिड, एपी : स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने केटलोनिया को देश से अलग करने की कोशिश से जुड़े मामले में इस क्षेत्र के 12 पूर्व नेताओं को सोमवार को 13 साल तक की सजा सुनाई। स्पेन के इस संपन्न पूर्वोत्तर क्षेत्र की आजादी के लिए 2017 में प्रयास किया गया था। इसे 1975 में तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको की मौत के बाद लोकतंत्र अपनाने वाले स्पेन के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है। माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले से केटलोनिया समर्थक फिर भड़क सकते हैं।

अदालत ने केटलन क्षेत्र के पूर्व उप राष्ट्रपति ओरियल जनक्वेरस को देशद्रोह और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों में 13 साल जेल की सजा सुनाई। आठ अन्य नेताओं को भी नौ से 13 साल कैद की सजा दी गई। बाकी तीन नेताओं को कम सजा मिली है। अभिभोजकों ने इन लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। सजा पाने वालों में क्षेत्रीय संसद के स्पीकर कार्मे फोरकाडेल भी शामिल हैं। उन्हें साढ़े ग्यारह साल की सजा सुनाई गई। पूर्व कैबिनेट सदस्यों जोकिम फोर्न और जोसेफ रूल को साढ़े दस साल की सजा दी गई।

पापा राष्ट्रपति बने तो विदेशी कंपनियां छोड़ दूंगा : हंटर बिडेन

▸ यूक्रेन और चीन में अपने कारोबार को लेकर जो बिडेन के बेटे ने दी सफाई

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति और डेमोक्रेट नेता जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ने यूक्रेन और चीन में अपने कारोबार का बचाव किया है। साथ ही कहा है कि अगर उनके पिता 2020 में चुनाव जीतकर देश के राष्ट्रपति बने तो वह किसी विदेशी कंपनी में काम नहीं करेंगे। हंटर के अटॉर्नी ने कहा कि वह अपना कारोबार स्वतंत्र तरीके से करते हैं। उन्हें इस बारे में पिता से बात करना उचित नहीं लगता है और उन्होंने ऐसा कभी किया भी नहीं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हंटर पर यूक्रेन में भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते रहे हैं। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बिडेन और हंटर के खिलाफ जांच का दबाव भी बनाया था। इसी मामले में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग जांच शुरू की है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव बनाया। वहीं, ट्रंप ने अपने खिलाफ महाभियोग को अमेरिकी जनता से धोखे की संज्ञा दी है। बिडेन को 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से ट्रंप के खिलाफ सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

जांच में सहयोग करेगा रक्षा मुख्यालय

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि महाभियोग की जांच में रक्षा मुख्यालय पेंटागन पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता से जुड़े जो भी दस्तावेज डेमोक्रेट्स चाहेंगे, उन्हें मुहैया कराए जाएंगे। एस्पर का यह बयान ऐसे समय में आया है, जबकि व्हाइट हाउस इस जांच में सहयोग से इन्कार कर चुका है। एस्पर के बयान को जांच को लेकर ट्रंप की नीति के उलट माना जा रहा है।

महेंद्र सिंह धौनी में अभी बहुत फुर्ती है, उन्हें कब संन्यास लेना है यह उनका फैसला है।
— शेन वॉटसन, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर

डेनमार्क ओपन में सिंधू पर होंगी नजरें

ओडेंसे, प्रेट्र : विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाली भारत की अग्रणी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू मंगलवार से यहां शुरू हो रहे डेनमार्क ओपन में भारत की अगुआई करेंगी। उनके साथ लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल पर भी सभी की नजरें होंगी।

बिखरे बोर्ड को समेटना मेरी प्राथमिकता : गांगुली

नई चुनौती ▶ सौरव समेत अन्य उम्मीदवारों ने भरा बीसीसीआइ चुनाव के लिए नामांकन

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, मैंने अध्यक्ष पद के लिए इच्छा जाहिर नहीं की

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के नए अध्यक्ष बनने जा रहे सौरव गांगुली ने अपनी नई जिम्मेदारी को बहुत चुनौतीपूर्ण मानते हुए कहा कि यह उनके लिए बड़ा मौका है और बिखरी बीसीसीआइ को समेटना उनकी पहली प्राथमिकता है। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि मैंने इस पद के लिए कभी भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की थी। मौजूदा हालात और लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। मुझे काफी दिन तक पता नहीं था कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। इसके बाद मुझे बताया गया कि मैं अध्यक्ष हूं और मेरी टीम यह रहेगी। मुझे सदस्यों ने चुना है। सदस्य ही हमेशा चुनते हैं। उन्होंने मुझे चुना तो मैंने हां कहा।

भरा नामांकन : सोमवार को मुंबई स्थिति बीसीसीआइ कार्यालय में गांगुली ने अध्यक्ष, जय शाह ने सचिव, अरुण सिंह धूमल ने कोषाध्यक्ष, माहिम वर्मा ने उपाध्यक्ष, जयेश जॉर्ज ने संयुक्त सचिव पद के लिए नामांकन भरा। इन सभी पदों पर सिर्फ एक ही नामांकन भरे गए हैं जिससे इनका निर्विरोध चुनाव जीतने का रास्ता साफ हो गया है। 23 अक्टूबर को चुनाव होने है।

पद संभालना चुनौतीपूर्ण : गांगुली ने बीसीसीआइ अध्यक्ष पद की चुनौतियां और भविष्य पर अपनी सोच बताई। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा अहसास है क्योंकि मैं देश के लिए खेला हूं और कप्तान रहा हूं। मैं ऐसे समय में कमान संभालने जा रहा हूं जब पिछले तीन साल से बोर्ड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसकी छवि बहुत खराब हुई है। मेरे लिए यह कुछ अच्छा करने का सुनहरा मौका है।

प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों की आर्थिक स्थिति पर जोर : पूर्व कप्तान और अब खेल प्रशासक का इरादा भारतीय क्रिकेट के सभी पक्षों से मिलने का और सारे काम करने का है जो पिछले 33 महीने में प्रशासकों की समिति नहीं कर सकी।

बीसीसीआइ के पूर्व दिग्गजों के साथ पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली। प्रेट्र

उन्होंने अपनी योजना स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले मैं सभी से बात करूंगा और फिर फैसला लूंगा। मेरी प्राथमिकता प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों की देखभाल करना होगा। मैं तीन साल से सीओए से भी यही कहता आया हूं, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। सबसे पहले मैं प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों की आर्थिक स्थिति ठीक करूंगा।

निर्विरोध चुने जाने को बताया बड़ी जिम्मेदारी : कूलिंग ऑफ पीरियड के कारण उन्हें जुलाई 2020 में पद छोड़ना होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 18000 से अधिक रन बना चुके पूर्व कप्तान ने कहा कि निर्विरोध चुना जाना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा संगठन है और जिम्मेदारी तो है ही, चाहे आप निर्विरोध चुने गए हों या नहीं। भारत क्रिकेट का महाशक्ति है तो यह चुनौती भी बड़ी होगी। यह पूछने पर कि कार्यकाल सिर्फ नौ महीने का होने का क्या उन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा कि हां, यही नियम है और हमें इसका पालन करना है। जब मैं आया तो मुझे पता नहीं था कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। पत्रकारों ने मुझसे पूछा तो मैने बृजेश का नाम लिया। मुझे बाद में पता चला कि हालात बदल गए हैं। मैने कभी बीसीसीआइ चुनाव नहीं लड़ा तो मुझे नहीं पता कि बोर्ड रूम राजनीति क्या होती है।

क्रिकेटरों का आना अच्छा : गांगुली ने कहा कि क्रिकेटरों का प्रशासन में आना अच्छी बात है। इससे भारत में खेल को फायदा होगा। गांगुली ने कहा कि पहले भी क्रिकेटर प्रशासन में आते रहे हैं लेकिन इतने बड़े पद पर कोई नहीं आया। गांगुली ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। यह पूछने पर कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में क्या वह बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने ना में जवाब दिया उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का जिक्र आने पर गांगुली भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस पद पर मैं भी काबिज हो सकूंगा। वह मेरे लिए पितातुल्य थे। बीसीसीआइ के कई बेहतरीन अध्यक्ष हुए हैं, श्रीनिवासन, अनुराग जिन्होंने अच्छा काम किया। यह कप्तानी से अलग होगा। भारतीय टीम का कप्तान होने से बढ़ कर कुछ नहीं है।

हितों का टकराव चिंता का विषय : गांगुली ने कहा कि हितों का टकराव भारतीय क्रिकेट के सामने सबसे बड़े मुद्दों में से एक है क्योंकि इसके विवादास्पद नियम सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को इस खेल के प्रशासन में आने से रोक रहे है। गांगुली खुद भी हितों के टकराव के मुद्दे का सामना कर चुके है। उन पर बंगाल क्रिकेट संघ और दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर रहने के कारण दोहरी भूमिका निभाने का आरोप लगा था। वह पहले ही दिल्ली कैपिटल्स से अलग हो चुके हैं जबकि 23 अक्टूबर को बीसीसीआइ अध्यक्ष का पद भार संभालने के बाद वह कैब के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे देंगे। गांगुली ने कहा कि हितों का टकराव का मुद्दा बड़ा है और मुझे यह नहीं पता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सेवाएं ले पाऊंगा या नहीं क्योंकि उनके पास दूसरे विकल्प भी मौजूद होंगे। गांगुली ने साफ किया कि 'एक व्यक्ति एक पद' के मौजूदा नियम क्रिकेट के पूर्व दिग्गजों को प्रशासन में आने से रोकेगा क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका कमाने की भी जरूरत होगी।

गांगुली के खिलाफ हुई थी शिकायत : पूर्व भारतीय कप्तान क्रिकेट सलाहकार समिति का हिस्सा थे जिसके खिलाफ मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ के सदस्य संजीव गुप्ता ने आचरण अधिकारी डीके जैन को कई शिकायतें की। इन शिकायतों के बाद सीएसी को भंग कर दिया गया था। गांगुली ने कहा कि इस उपबंध से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अगर आप विभिन्न नियुक्तियों को देखे सब के साथ कुछ ना कुछ मामला है। इसमें एनसीए या सीएसी या बल्लेबाजी, क्षेत्ररक्षण कोचों की नियुक्ति पर भी सवाल उठे।

9 मार्च, वर्ष 2000 को बतौर कप्तान पहली बार उतरे थे सौरव गांगुली मैदान में

1996 में पहले ही टेस्ट में गांगुली ने लॉर्ड्स मैदान पर जड़ा था शतक

2003 विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को पहुंचाया

2008 में पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान ने लिया था संन्यास

2012 में आखिरी बार आइपीएल में बतौर खिलाड़ी खेले

2015 में बने थे बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष

करियर पर एक नजर

वनडे

मैच	रन	शतक	औसत	अर्धशतक
311	11,363	22	41.02	72

टेस्ट

मैच	रन	शतक	औसत	अर्धशतक
113	7212	16	42.17	35

राज्य संघों को मिली तीन दिन बाद की तारीख

नई दिल्ली : बीसीसीआइ के चुनाव अधिकारी ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, हरियाणा, महाराष्ट्र संघों के एजीएम (आम सभा) में भाग लेने से रोक लगा दी थी। इसकी वजह से इन संघों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी संघों को सुनवाई के लिए तीन दिन बाद की तारीख दी है।

सौरव गांगुली को सर्वसम्मति से बीसीसीआइ अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। आपके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। आपने भारत और बांग्ला को गौरवान्वित किया है। हम कैब अध्यक्ष के तौर पर आपके कार्यकाल से गौरवान्वित हैं। हम एक और महान पारी की ओर देख रहे हैं।
– ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, बंगाल

अब कोच रवि शास्त्री की राह होगी मुश्किल

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री और बीसीसीआइ के नए अध्यक्ष बनने जा रहे सौरव गांगुली के मतभेद किसी से छुपे नहीं है। बीसीसीआइ की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) में रहते गांगुली शास्त्री को कोच के लिए नहीं चुनना चाहते थे। वहीं एक बार एक टॉक शो में भी शास्त्री ने गांगुली के बारे में एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद दोनों के बीच में तल्खी किसी से भी छुपी नहीं थी। अब जब गांगुली बीसीसीआइ अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो शास्त्री के लिए मुश्किल खड़ी होना तय है।

शास्त्री ने दिया था विवादित बयान : एक टॉक शो में टीम इंडिया के मुख्य कोच शास्त्री ने कहा था कि मुझे समय की पाबंदी पसंद है। मैं इससे कभी समझौता नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि यह एक आदत है। एक बार 2007 में बांग्लादेश दौरे पर मैं टीम इंडिया का मैनेजर था। हम सभी बस में बैठे थे और गांगुली ने देर कर दी। तब हम उन्हें छोड़कर चले गए थे। अगर मुझे नौ बजे बस लेकर निकलना है तो मैं नौ बजे ही निकलूंगा। तब गांगुली ने इसका जवाब दिया था कि आप शास्त्री का सुबह इंटरव्यू नहीं कर सकते हो। आप उन्हें ब्रेकफास्ट शो पर मत बुलाइए क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता है वह क्या कहते हैं। जब मैं उनसे मिला तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने क्या कहा। मुझे लगता है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन अच्छा यही है कि उनका सुबह की जगह शाम में इंटरव्यू किया जाए क्योंकि वह तब सभी बात याद रख पाएंगे।

जब हुए थे मतभेद : 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में तब के कोच अनिल कुंबले से कप्तान विराट कोहली के मतभेद होने की वजह से पूर्व दिग्गज स्पिनर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कोहली ने सीएसी से अंदरखाने शास्त्री को ही कोच बनाने की मांग की थी। गांगुली शास्त्री को कोच बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति और सचिन तेंदुलकर के कारण सौरव को पीछे हटना पड़ा। हालांकि, समय-समय पर गांगुली कोच के रवैये की आलोचना करते रहे। यही नहीं, शास्त्री ने भी कई बार कहा कि कुछ लोग जानबूझकर टीम और मेरी बुराई करते हैं।

कठिन डगर

- जगजाहिर हैं पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली और कोच रवि के मतभेद
- सौरव के बीसीसीआइ अध्यक्ष बनने पर बढ़ेगी भारतीय कोच की मुश्किल

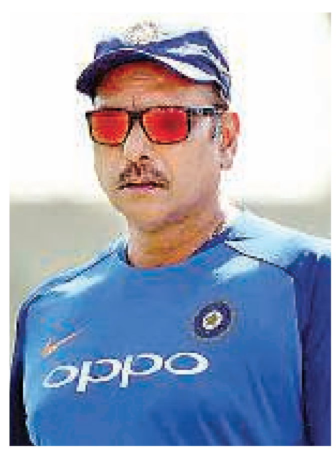

भारतीय कोच रवि शास्त्री। फाइल फोटो

अब नहीं चलेगा एकछत्र राज : कोहली और शास्त्री टी-20 विश्व कप की तैयारियों के लिए अपने नियमित अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की जगह युवाओं को लगातार मौका दे रहे हैं। टीम में कुछ भी गलत हो रहा हो कोहली और शास्त्री ने एक लय में उसका समर्थन किया। फिर चाहे वह विदेशी टेस्ट दौरों पर खराब निर्णय हो या फिर विश्व कप में विजय शंकर जैसे खिलाड़ी का गलत चयन। अब गांगुली के अध्यक्ष बनने से इन एकतरफा फैसलों पर लगाम लगेगी।

कुलदीप-चहल का किया समर्थन : गांगुली ने हमेशा ही स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्रा सिंह चहल का समर्थन किया है। गांगुली हमेशा कहते आए हैं कि कुलदीप को तीनों प्रारूपों में टीम का मुख्य स्पिनर बनाना चाहिए। साथ ही वह टीम के मामलों पर भी खुलकर अपनी राय देते आए हैं जो अब शास्त्री के लिए मुश्किल खड़ी जरूर करेगी।

गुरु डालमिया की राह पर शिष्य सौरव

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता : कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) पर लंबे समय तक जगमोहन डालमिया की बादशाहत रही और अब सौरव गांगुली की दादागिरी चलने वाली है। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार सौरव डालमिया के परम शिष्य माने जाते हैं। डालमिया के निधन के बाद उन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) का अध्यक्ष पद संभाला था और अब उनके नक्शेकदम पर बीसीसीआइ की शीर्ष कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं।

कैब के एक अधिकारी ने बताया कि दादा के काम करने का अपना एक स्टाइल है, जिससे वे किसी तरह का समझौता करना पसंद नहीं करते। कैब अध्यक्ष के तौर पर उनकी सफलता की यह एक बड़ी वजह रही है। जाहिर है कि वह बीसीसीआइ में भी अपने तरीके से ही काम करना चाहेंगे। चूंकि वे काफी समय तक बीसीसीआइ से जुड़े रहे हैं, इसलिए वहां की काम करने की शैली से भली-भांति परिचित हैं। ईडन गार्डेंस स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय व आइपीएल मैचों के आयोजन के समय सौरव जितने सक्रिय रहते हैं, उतना कोई नहीं रहता। सौरव को 10 महीने ही मिलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वह इस छोटी सी अवधि में भी कमाल कर दिखाएंगे।

कारण, उनके काम करने की शैली बेहद ईमानदार है। दादा टीम से जुड़े मामलों पर हमेशा बेबाकी से बोलते आए हैं। कई खिलाड़ियों की उन्होंने खुलकर वकालत भी की है। ऐसे में उन खिलाड़ियों के लिए संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सौरव का बीसीसीआइ अध्यक्ष बनना बंगाल के क्रिकेटरों के लिए फायदेमंद तो है लेकिन उन्हें मैदान में शानदार प्रदर्शन कर अपनी काबिलियत भी साबित करनी होगी।

पहले कप्तान, अब अध्यक्ष लेकिन चुनौतियां एक जैसी

निखिल शर्मा, नई दिल्ली

तीन अक्टूबर साल 2000, आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। यहां से पहली बार सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट के खोए वजूद को वापस दिलाने की कारीगरी शुरू की। पिछले छह महीने मैच फिक्सिंग की वजह से भारतीय क्रिकेट की जमीन उखाड़ फेंक देने वाले थे। 19 वर्ष के बाद एक बार फिर गांगुली को अपनी कारीगरी दिखानी है। इस बार अध्यक्ष पद पर बैठकर बीसीसीआइ के खोए वजूद को वापस दिलाना है।

बदल दिए थे हालात : फिक्सिंग प्रकरण के बाद पहली बार गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम किसी आइसीसी टूर्नामेंट में उतरी थी। इस नॉकआउट टूर्नामेंट के फाइनल तक का सफर तय करके गांगुली टीम इंडिया के एक नए योद्धा के रूप में सामने आए थे। फाइनल में न्यूजीलैंड से जरूर हारे, लेकिन करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों की चोट को भरने में भारतीय टीम कामयाब रही थी।

मनवाया अपनी कप्तानी का लोहा : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में खेली गई टेस्ट सीरीज हो या फिर साल 2000 में श्रीलंका में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी। गांगुली की कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट के लिए नए रास्ते खोल दिए थे। हरभजन सिंह, जहीर खान, युवराज सिंह, मुहम्मद कैफ जैसी युवा फौज को तैयार करके गांगुली चमत्कार करते जा रहे थे। 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत ने भारतीय युवा खिलाड़ियों के दिलों दिमाग में एक सुनहरी छाप छोड़ी। खुद गांगुली का लॉर्ड्स की बालकनी में टी-शर्ट लहराना दिखा रहा था कि यह कप्तान मुंह बंद करके सुनने वालों में से नहीं है। 2003 विश्व कप फाइनल तक टीम को पहुंचाना गांगुली की बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

बदले हालात नहीं बदले दादा : बीसीसीआइ के लिए ग्रेग चैपल को कोच बनाना खाई में कूदने जैसा हो गया। गांगुली को टीम से बाहर किया गया। चैपल ने खुलेआम गांगुली पर आरोप लगाए। दादा हार नहीं मानने वाले थे। अपने प्रदर्शन से दादा ने वापसी की और शान के साथ 2008 में नागपुर के क्रिकेट मैदान पर क्रिकेट को अलविदा कहा।

क्रिकेट को फिर दादा की जरूरत : सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सीओए की मनमानी के बाद से ही भारतीय बोर्ड चरमरा गया है। एक बार फिर क्रिकेट को दादा की जरूरत है। कप्तान के बाद बीसीसीआइ अध्यक्ष का पद जरूर अलग है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां एक जैसी हैं।

- बीसीसीआइ के बुरे दौर के बीच गांगुली फिर बनकर आए मसीहा

नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद गांगुली। फाइल

भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आज पहुंचेंगी रांची

जागरण संवाददाता, रांची : तीन मैचों की सीरीज हार चुकी दक्षिण अफ्रीका की टीम शनिवार से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच में पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहेगी ताकि वह क्लीन स्विप से बच सके। जेएससीए स्टेडियम रांची में सीरीज के तीसरे व अंतिम टेस्ट मैच के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम बुधवार को रांची पहुंचेगी।

बुधवार को मेहमान टीम जहां अभ्यास करेगी वहीं मेजबान टीम इस दिन आराम करने के मूड में है। सीरीज में अब तक दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज व गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं इसलिए टीम प्रबंधन ने बुधवार से अभ्यास करने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के सचिव संजय सहाय ने बताया कि मेहमान टीम बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार तीनों दिन अभ्यास करेगी जबकि टीम इंडिया के सदस्य बुधवार को भी आराम करेंगे। भारतीय खिलाड़ी गुरुवार से अभ्यास करेंगे।

मयंक-रोहित ओपनिंग जोड़ी के तौर पर फिट

वीवीएस लक्ष्मण
वेरी-वेरी स्पेशल

भारत ने घर में 11 लगातार टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती दो टेस्ट मैचों में भारत ने एक टीम के रूप में प्रदर्शन किया है और इससे टीम को खुश होना चाहिए।

कैरेबियाई दौरे पर भारत का शीर्ष क्रम रन बनाने के लिए जूझ रहा था, लेकिन रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन करके सलामी जोड़ी के रूप में टेस्ट टीम में जगह पक्की की। एक सलामी बल्लेबाज के रूप में अपने पहले टेस्ट में रोहित ने विशाखापत्तनम में दो शतक जड़े जबकि मयंक ने अपने पहले शतक को दोहरे में बदला और फिर पुणे में एक और शतक लगा दिया।

विराट कोहली ने अपने मानकों के आधार पर एक बड़ा दोहरा शतक जड़कर दमदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनके रन बनाने की भूख और उनकी फिटनेस देखने लायक थी।

भारत में जब मेजबान टीम टॉस जीतती है और रनों का पहाड़ खड़ा करती है तो अधिक अनुभवी टीमों के लिए भी अपनी पकड़ बनाना मुश्किल हो जाता है। पहली बार हमने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजी आक्रमण की कमजोरी को उजागर किया। कैगिसो रबादा ने पिच पर पड़ी दरार का अच्छा फायदा उठाया लेकिन उनके आक्रमण में कमी थी। भारत ने अपनी पारियों में बड़े स्कोर खड़े किए। पिछले 18 महीनों में भारत के शानदार प्रदर्शन का एक कारण उनकी गेंदबाजी भी रहा है। अच्छी टेस्ट पिचों पर गेंदबाजों के लिए बिना किसी मदद के भी भारतीय आक्रमण सनसनीखेज था। रविचंद्रन अश्विन ने दोहराया कि मौजूदा समय में वह देश के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। उनका गेंद पर नियंत्रण प्रेरणादायी है जबकि रवींद्र जडेजा की विकेट लेने की मानसिकता साफ दिखती है। तेज गेंदबाजी समूह ने बल्लेबाजों को धीमी विकेटों पर आउट किया है और इसका श्रेय उनके कौशल और फिटनेस को जाता है।

व्यक्तिगत तौर पर मैं विकेटकीपर साहा के लिए बहुत खुश हूं जो चोट के कारण लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं। उनकी प्रतिबद्धता किसी से भी पीछे नहीं है और पुणे में उन्होंने जो कैच लपके थे वो शानदार हैं। सीरीज हमने जीत ली है, लेकिन मैं भारतीयों से मेहमान टीम पर कोई रहम की उम्मीद नहीं करता हूं। दुनिया की नंबर एक टीम भारत को अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है।

टेस्ट रैंकिंग में स्मिथ के करीब पहुंचे कोहली

दुबई, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली आइसीसी टेस्ट रैंकिंग में चोटी पर काबिज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के काफी करीब पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट में 254 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले कोहली अब स्मिथ से सिर्फ एक रेटिंग अंक पीछे हैं। स्मिथ 937 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं जबकि कोहली 936 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं।

सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। वह शीर्ष-20 में पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 108 रनों की पारी खेलने वाले अग्रवाल 17वें स्थान पर आ गए। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे क्रमशः चौथे और नौवें स्थान पर हैं। शीर्ष-10 में कोहली के अलावा ये दोनों अन्य भारतीय बल्लेबाज हैं। रविचंद्रन अश्विन को भी तीन स्थान का फायदा हुआ है। वह अब सातवें स्थान पर हैं वहीं बुमराह अभी तीसरे स्थान पर कायम हैं। ऑलराउंडरों की बात करें तो रवींद्र जडेजा दूसरे पायदान पर हैं और वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर पहले स्थान पर हैं। वहीं अश्विन पांचवें नंबर पर हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद कोहली जनवरी 2018 के बाद पहली बार 900 अंक से नीचे आए थे। वह अब 936 अंक पर पहुंच गए हैं जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग से एक अंक कम है। कोहली बीते साल अगस्त में वहां पहुंचे थे।

दुनिया के नंबर वन वनडे बल्लेबाज के पास दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19 अक्टूबर से रांची में खेले जाने वाले सीरीज के आखिरी मैच में स्टीव स्मिथ से आगे निकलने का मौका होगा।

आइसीसी रैंकिंग

- दोनों के बीच हुआ मात्र एक रेटिंग अंक का फासला, शीर्ष पर मौजूद हैं स्मिथ

टेनिस डायरी

लिंज ओपन के फाइनल में कोरी ने ओस्टापेंको को हराया, 2004 के बाद डब्ल्यूटीए खिताब जीतने वालीं सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनीं

कोरी गॉफ ने जीता पहला डब्ल्यूटीए खिताब

लिंज, एएफपी : अमेरिका की युवा सनसनी कोरी गॉफ ने लिंज ओपन के फाइनल में जेलेना ओस्टापेंको को 6-3, 1-6, 6-2 से हराकर अपना पहला डब्ल्यूटीए खिताब जीता।

क्वालीफाई करने से चूकने के बावजूद 15 वर्षीय गॉफ किस्मत का साथ पाकर लिंज ओपन के मुख्य ड्रॉ में पहुंची थीं। वह 2004 में निकोल वैदिसोवा के बाद डब्ल्यूटीए खिताब जीतने वालीं सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी हैं। करीब 3000 उत्साही दर्शकों की मौजूदगी में गॉफ ने जीत के बाद कहा कि मैं इस दिन को ताउम्र याद रखूंगी। मेरे लिए यह सप्ताह शानदार रहा है और आगे भी ऐसी ही उम्मीद करती हूं। इस खिताबी जीत के बाद गॉफ का सोमवार को जारी होने वाली डब्ल्यूटीए विश्व रैंकिंग में जबरदस्त फायदा मिलने की संभावना है।

गॉफ ने 2017 की फ्रेंच ओपन चैंपियन जेलेना ओस्टापेंको के खिलाफ तीन सेट तक चले मुकाबले में जोरदार खेल दिखाया। पहले सेट को आसानी से नाम करने के बाद उन्हें दूसरे सेट में शिकस्त मिली। तीसरे सेट में गॉफ 5-0 से आगे थीं, लेकिन अगले दो गेम में उन्हें हार मिली, लेकिन अगले गेम को उन्होंने अपने नाम करके खिताब पर कब्जा जमाया। गॉफ इस साल विंबलडन और यूएस ओपन में अपनी खेल की वजह से सुर्खियों में आई थीं। मुकाबले के बाद ओस्टापेंको ने भी गॉफ की जमकर सराहना की।

खिताब के साथ अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी कोरी गॉफ। एएफपी

मेदवेदेव ने जीता शंघाई मास्टर्स का खिताब

शंघाई, एएफपी : शानदार लय में चल रहे रूस के युवा टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव ने रविवार को जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को एकतरफा मुकाबले में 6-4, 6-1 से हराकर शंघाई मास्टर्स का खिताब हासिल किया। लगातार छठे टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे 23 मेदवेदेव का यह इस साल का चौथा खिताब है। विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज मेदवेदेव के लिए 22 वर्षीय ज्वेरेव के खिलाफ पिछले पांच मुकाबलों में यह पहली जीत है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि इस सप्ताह मुझे हरा पाना असंभव लग रहा था। हालांकि, अगले सप्ताह क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मेदवेदेव को मास्को में खेलना है। इस टूर्नामेंट से पहले रूसी खिलाड़ी मेदवेदेव ने यूएस ओपन के फाइनल तक का सफर तय किया था।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का क्लीन स्वीप

वडोदरा, प्रेट्र : अपनी गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सोमवार को यहां रिलायंस स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को छह रनों से हरा दिया। इसके साथ भारत ने तीन मैचों की इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। भारत ने बुधवार को पहले वनडे में एक विकेट से जीत हासिल की थी जबकि शुक्रवार को उसे मेहमान टीम को पांच विकेट से हराया था।

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.5 ओवरों में सभी विकेट गंवाकर 146 रन बनाए और मेहमान टीम को 140 रनों पर ढेर कर दिया। भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर ने सबसे अधिक 38 रन बनाए जबकि शिखा पांडे ने 35 रनों की पारी खेली। इसके अलावा पूनम राउत (15), कप्तान मिताली राज (11) और मानसी जोशी (12) ही दहाई तक पहुंच सकीं।

दक्षिण अफ्रीका की ओर से मेरिजाने कॉप ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए जबकि शबनम इस्माइल और अयाबोंगा खाका को दो-दो सफलता मिली। जवाब में खेलने उतरी मेहमान टीम 48 ओवरों का सामना करते हुए 140 रनों पर ढेर हो गई। इसमें एकता बिष्ट का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 32 रन देकर तीन विकेट लिए। दीप्ति शर्मा ने 24 रन देकर दो और राजेश्वरी गायकवाड ने 22 रन देकर दो सफलता हासिल की। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लाउरा वोल्वार्ट ने 23, कप्तान सुन लुस ने 24 और कॉप ने 29 रन बनाए। बिष्ट को वुमैन ऑफ द मैच चुना गया जबकि कॉप को वुमैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला।

महिला क्रिकेट

- एकता ने लिए सबसे ज्यादा तीन विकेट
- तीन मैचों की सीरीज में दर्ज की 3-0 से जीत

कोसगेई ने शिकागो मैराथन में तोड़ा विश्व रिकॉर्ड

शिकागो, आइएएनएस : केन्या की दिग्गज महिला धावक ब्रिगिड कोसगेई ने शिकागो मैराथन में नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोसगेई ने दो घंटे 14 मिनट और चार सेकेंड में रेस पूरी की। कोसगेई ने रविवार को पिछले विश्व रिकॉर्ड से एक मिनट तेज समय निकाला। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाउला रेडक्लिफ के नाम था, जो उन्होंने 2003 लंदन मैराथन में दो घंटे 15 मिनट और 25 सेकेंड का समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

भारत को अच्छा खेलना है तो जरूरी नहीं टीम को मेरी जरूरत पड़ेगी।
– सुनील छेत्री, कप्तान भारतीय फुटबॉल टीम

पोलैंड-रूस ने हासिल किए यूरो चैंपियनशिप टिकट

फुटबॉल ▸ क्वालीफायर में पोलैंड ने नॉर्थ मेसेडोनिया को 2-0 से हराया

रूस ने साइप्रस को 5-0 से करारी शिकस्त देकर हासिल की पात्रता

गोल करने के बाद जश्न मनाते पोलैंड के फ्रांकोवस्की। एएफपी

पेरिस, एएफपी : पोलैंड और रूस की फुटबॉल टीमों ने 2020 यूरो चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है जबकि जर्मनी और नीदरलैंड्स की टीमें भी अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के करीब पहुंच गई हैं। ग्रुप-जी में पोलैंड ने नॉर्थ मेसेडोनिया को 2-0 से हराया जबकि ग्रुप-आइ में 10 खिलाड़ियों से खेल रही साइप्रस की टीम को रूस ने 5-0 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले बेल्जियम और इटली ने अगले साल 12 जून से शुरू हो रही यूरो चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया था।

स्टानिस्लाव चेरिशेव की रूसी टीम को अगले दौर में पहुंचने के लिए केवल निकोसिया में साइप्रस के खिलाफ ड्रॉ की जरूरत थी। अपने घरेलू मैदान पर हुए पिछले फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली रूसी टीम की ओर से डेनिस चेरिशेव (नौवें और 90+2वें मिनट) ने दो गोल दागे जबकि मागोमेद ओजदोयेव (22वें मिनट), आर्टेम डिज्युबा (79वें मिनट) और एलेक्जेंडर गोलोविन (89वें मिनट) ने एक-एक गोल किए।

उधर नॉर्थ मेसेडोनिया के खिलाफ पोलैंड को यूरो की पात्रता हासिल करने के लिए जीत की जरूरत थी और उसने वह कर दिखाया। परजेमस्लाव फ्रैंकोवोस्की (74वें मिनट) ने स्थानापन्न के तौर पर उतरने के एक मिनट के अंदर ही गोल करके पोलैंड को शुरुआती बढ़त दिलाई और फिर अर्काडियूस मिलिक (80वें मिनट) ने गोल करके पोलैंड की जीत करीब-करीब पक्की कर दी। अपने ग्रुप में आठ मुकाबलों में 19 अंकों के साथ पोलैंड शीर्ष पर है।

जर्मनी और नीदरलैंड्स जीते : ग्रुप-सी में नीदरलैंड्स की टीम ने बेलारूस को 2-1 से हराकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। नीदरलैंड्स की ओर से जॉर्जिनियो विज्नाल्डम (32वें मिनट और 41वें मिनट) ने दोनों गोल किए जबकि बेलारूस की ओर से स्टानिस्लाव ड्रागुन (53वें मिनट) ने इकलौता गोल दागा। इसी ग्रुप के एक अहम मुकाबले में 10 खिलाड़ियों से खेलने वाली जर्मनी की टीम ने इस्टोनिया को 3-0 से हराया। मुकाबले के 14वें मिनट में ही जर्मनी के ईमरी कान को रेड कार्ड दिखाकर बाहर किया गया। हालांकि इल्के गुंडोगन ने (51वें और 57वें मिनट) ने दो और टिमो वार्नर (71वें मिनट) ने एक गोल करके जर्मनी को क्वालीफाई करने के करीब पहुंचा दिया। इस ग्रुप में नीदरलैंड्स और जर्मनी के 15-15 अंक हैं लेकिन बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड की वजह से नीदरलैंड्स की टीम शीर्ष पर है।

ग्रुप-ई के एक अन्य मुकाबले में वेल्स ने क्रोएशिया को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। निकोला व्लासिक ने नौवें मिनट में क्रोएशिया को बढ़त दिलाई लेकिन पहले हाफ के इंजुरी टाइम में गेरेथ बेल ने गोल करके वेल्स को बराबरी दिलाई।

आइएसएल का देश का शीर्ष लीग बनना तय

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) अब आइ-लीग को पछाड़कर देश का शीर्ष लीग बन जाएगा। भारतीय फुटबॉल की घरेलू संरचना में सुधार के लिए एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन (एएफसी) ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें आइ-लीग की जगह आइएसएल को शीर्ष घरेलू लीग बनाना शामिल है। इसका खाका सोमवार को कुआलालंपुर में एएफसी मुख्यालय में आइएसएल और आइ-लीग के अधिकारियों के साथ एएफसी और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बैठक में तैयार हुआ। आइएसएल का आगामी सत्र कोच्चि में 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में यह लीग के लिए खुशखबरी है। अब तक देश का शीर्ष लीग रहा आइ-लीग अब दूसरे स्तर का लीग होगा। आइएसएल में 2023-24 के सत्र तक प्रमोशन और रेलीगेशन नहीं होगा। 2024-25 के सत्र से प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन और रेलीगेशन होगा लेकिन दो एक जैसी लीगों का आयोजन नहीं होगा। इसके मुताबिक आइएसएल की विजेता टीम को एएफसी चैंपियंस लीग के प्लेऑफ में खेलने का मौका मिलेगा जबकि आइ-लीग की विजेता टीम एएफसी कप में भाग लेगी।

प्रियम गर्ग का शतक उत्तर प्रदेश जीता

विजय हजारे ट्रॉफी

उत्तर प्रदेश के युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग। फाइल

वडोदरा, प्रेट्र : मध्य क्रम के युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग की 120 रनों की शानदार पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश ने सोमवार को यहां गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन काउंसिल ग्राउंड पर खेले गए मैच में विदर्भ को सस्ते में समेट 109 रनों जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवरों में 211 रन पर सिमट गई थी। विदर्भ की मजबूत बल्लेबाजी के सामने यह लक्ष्य आसान लग रहा था लेकिन उत्तर प्रदेश के स्पिनर सौरभ वर्मा ने छह विकेट लेकर विदर्भ को मुश्किल में डाल दिया। विदर्भ ने 40 रनों पर ही अपने सात विकेट खो दिए थे। अंत में अक्षय कारनेवर और दर्शन नालकंडे ने क्रमशः 23 और 26 रनों की पारी खेल कुछ संघर्ष किया लेकिन यह टीम को जरूरी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सके। विदर्भ के लिए यश ठाकुर और कारनेवर ने तीन-तीन विकेट लिए।

दिल्ली ने पंजाब को हराया : एक अन्य मुकाबले में दिल्ली ने पंजाब को पांच रनों से रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी। दिल्ली ने ललित यादव की 54 गेंद में 53 रनों की पारी की बदौलत 50 ओवर में आठ विकेट पर 220 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान ध्रुव शौरी ने 46, नीतीश राणा ने 39 रन बनाए। पंजाब की ओर से सिद्धार्थ कौल ने सबसे ज्यादा पांच विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की की टीम नौ विकेट 215 रन ही बना सकी। पंजाब की ओर से अनमोलप्रीत ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए।

हिमाचल प्रदेश दो विकेट से हारा : एक अन्य मुकाबले में बड़ौदा ने हिमाचल प्रदेश को दो विकेट से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए हिमाचल की टीम 44 ओवर में 161 रनों पर सिमट गई। बड़ौदा की ओर से भार्गव भट्ट और निनाद रथवा ने तीन-तीन विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी बड़ौदा ने 34.5 ओवर में आठ विकेट पर 165 रन बनाकर यह मैच दो विकेट से जीत लिया। बड़ौदा के लिए स्वपनिल सिंह ने 66 गेंद में नाबाद 85 रन बनाए।

नगालैंड से हारा चंडीगढ़

जागरण संवाददाता, देहरादून : प्लेट ग्रुप मुकाबले में यहां सोमवार को नगालैंड ने चंडीगढ़ को एक विकेट से हरा दिया। नगालैंड ने टॉस जीतकर चंडीगढ़ को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बिपुल शर्मा के 55 रन की बदौलत चंडीगढ़ ने 220 रन बना बनाए। नगालैंड की तरफ से तहमीद व इमलीवती ने तीन-तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए नगालैंड की तरफ से ओसाशी ने 76 रनों की शानदार पारी खेली। इसके दम पर नगालैंड ने आठ गेंद शेष रहते ही मैच एक विकेट से जीत लिया। चंडीगढ़ के श्रेष्ठ निर्मोही ने पांच विकेट झटके।

बंगाल और रेलवे की टीमों में मैच हुआ टाई

जयपुर : विजय हजारे ट्रॉफी में सोमवार को ग्रुप सी में यहां बंगाल और रेलवे के बीच खेला गया मुकाबला टाई रहा। बंगाल पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 223 रनों पर ऑलआउट हो गई। बंगाल की ओर से श्रीवत्स गोस्वामी ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। रेलवे की ओर से हिमांशु सांगवान ने तीन विकेट लिए। जवाब में रेलवे भी 50 ओवर में 223 रन पर ऑलआउट हो गई। रेलवे की ओर से प्रथम सिंह ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए।

बिहार के खिलाफ पांच विकेट से जीती सेना : जयपुर में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में सेना ने बिहार को पांच विकेट से हरा दिया। बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सात विकेट पर 267 रन बनाए। उनकी ओर से शाशीम राठौर ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए। जवाब में सेना ने रवि चौहान के 86 रनों की बदौलत 48.4 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाकर मैच जीत लिया।

गुजरात से हारा जम्मू-कश्मीर : ग्रुप सी के ही एक अन्य मुकाबले में गुजरात ने जम्मू-कश्मीर को आठ विकेट से हरा दिया। जम्मू-कश्मीर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में आठ विकेट पर 279 रन बनाए। उनकी ओर से अब्दुल समद ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 37.3 ओवर में दो विकेट पर 282 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात की ओर से प्रियंक पांचाल ने सबसे ज्यादा नाबाद 135 रनों की पारी खेली।

दुति चंद ने स्वर्ण के साथ किया एथलेटिक्स सत्र का समापन

जागरण संवाददाता, रांची

सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप

फर्राटा धाविका दुति चंद ने रविवार को समाप्त हुई 59वीं सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यहां 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक के साथ सत्र का समापन किया।

मौजूदा चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली दुति ने 200 मीटर में 23.17 सेकेंड का समय लिया जो इस साल किसी भी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ समय है। उन्होंने दूसरे स्थान पर रही अर्चना सुशींद्रन (23.41 सेकेंड) को पीछे छोड़ा। ओडिशा की इस खिलाड़ी को महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया, जबकि शनिवार को अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले गोला फेंक एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया। पुरुष त्रिकूद में करीबी मुकाबला देखने को मिला जहां एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता अरपिंदर सिंह की गैरमौजूदगी में छह प्रतिभागियों ने 16 मीटर से अधिक दूरी तय की। कार्तिक उन्निकृष्ण 16.78 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ शीर्ष पर रहे।

महिलाओं की 3000 मीटर बाधा दौड़ में चिंता यादव ने रेलवे की अपनी टीम की खिलाड़ी पारुल चौधरी को पछाड़ कर उलटफेर किया। चिंता ने 10 मिनट 11.70 सेकेंड का समय लिया। रेलवे की पीयू टूर्नामेंट में दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरी खिलाड़ी रहीं। 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली रेलवे की इस खिलाड़ी ने 1500 मीटर में दो मिनट 04.59 सेकेंड के समय के साथ शीर्ष पर रही। रेलवे 264.5 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि सर्विसेज (174 अंक) दूसरे और हरियाणा (88.5 अंक) तीसरे स्थान पर रहे। महिला हैमर थ्रो में दिल्ली की रेखा ने 56.38 मीटर की दूरी नाप कर सोना अपने नाम किया। पंजाब के अर्शदीप ने 77.37 मीटर भाला फेंक कर सोना जीता।

डब्ल्यूटीए रैंकिंग में गॉफ की लंबी छलांग

टेनिस डायरी

▸ 39 पायदान की छलांग लगाकर 71वें नंबर पर पहुंचीं कोरी, महिला सिंगल्स के शीर्ष-20 में कोई बदलाव नहीं

पेरिस, एएफपी : अमेरिका की युवा टेनिस खिलाड़ी कोरी गॉफ पहली बार डब्ल्यूटीए सिंगल्स रैंकिंग के शीर्ष 75 में पहुंचने में कामयाब रहीं। मिंज ओपन का खिताब जीतने वाली गॉफ सोमवार को जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 39 पायदान की छलांग लगाकर 71वां स्थान पर पहुंच गईं। पिछले सप्ताह कोरी की रैंकिंग 110वीं थी।

वहीं तायंजिन ओपन का खिताब जीतने वालीं रेबेका पीटरसन भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 44वीं रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। हालांकि शीर्ष 20 महिला सिंगल्स खिलाड़ियों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं है और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी शीर्ष पर बनी हुई हैं। गॉफ ने लिंज ओपन के फाइनल में रविवार को जेलेना ओस्टापेंको को हराकर अपना पहला डब्ल्यूटीए खिताब जीता था और 2004 के बाद डब्ल्यूटीए खिताब जीतने वालीं सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनीं थीं। हाल के समय में गॉफ ने अपने खेल से प्रभावित किया है जिनकी 2018 के समाप्ति के समय विश्व रैंकिंग 686 थी। उनके पास अब इस सप्ताह होने वाली लक्जमबर्ग टेनिस टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन के दम पर शीर्ष-50 में पहुंचने का मौका होगा।

गॉफ के काम आया फेडरर का सुझाव : लिंज ओपन की खिताबी जीत के बाद कोरी गॉफ ने स्विस स्टार रोजर फेडरर की जमकर सराहना की और बताया कि कैसे उनके सुझाव ने उन्हें मदद की। गॉफ ने कहा कि उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 के दौरान कुछ सुझाव दिए थे जहां मैं पहले दौर में हार गई थी। उन्होंने मुझसे दबाव और कोर्ट से बाहर के ड्रामा पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की नसीहत दी थी।

मेदवेदेव ने बनाया फेडरर पर दबाव : शंघाई मास्टर्स की खिताब जीत के बाद रूस के डेनिल मेदवेदेव ने एटीपी विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज रोजर फेडरर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मेदवेदेव चौथे स्थान पर बने हुए हैं लेकिन एलेक्जेंडर ज्वेरेव पर चीन में जीत के बाद उन्होंने 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन से अंकों का फासला कम कर लिया है। ताजा रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविक शीर्ष पर बने हुए हैं जबकि स्पेन के राफेल नडाल भी दूसरे स्थान पर काबिज हैं। मेदवेदेव लगातार अपने खेल में बेहतर कर रहे हैं।

2020 टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगे रोजर फेडरर

पेरिस, एएफपी : स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में खेलने की घोषणा की। फेडरर ने कहा कि कुछ समय से मैं अपनी टीम के साथ 2020 में विंबलडन के बाद और यूएस ओपन से पहले क्या करना चाहिए इसको लेकर चर्चा कर रहा था। अंत में मेरे दिल ने कहा कि मुझे फिर से ओलंपिक गेम्स में खेलना चाहिए। फेडरर ने अब तक अपने करियर में सभी चारों ग्रैंडस्लैम खिताब के अलावा एटीपी टूर फाइनल्स भी छह बार जीते हैं लेकिन 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन अब तक ओलंपिक में सिंगल्स में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। ओलंपिक डबल्स में भी उनके नाम स्वर्ण पदक है। फेडरर 2012 लंदन ओलंपिक फाइनल में एंडी मरे से हारे थे।

विविध

आतंकी हिलाल व नफीफुल को कहां से मिले जमानतदार

जागरण संवाददाता, जौनपुर

श्रमजीवी विस्फोट कांड

श्रमजीवी विस्फोट कांड की सुनवाई के दौरान अदालत में बड़ा सवाल उठा कि विस्फोट कांड में आरोपित बांग्लादेशी के लिए भारत में कौन जमानतदार है। कांड में आरोपित बांग्लादेशी आरोपित हिलाल एवं नफीकुल विश्वास कड़ी सुरक्षा में सोमवार को कोर्ट में पेश किए गए। हिलाल पर ट्रेन में बम रखने का एवं नफीकुल पर विस्फोट कांड में सहयोग का आरोप है।

एडीजीसी अनूप शुक्ला ने बताया कि दोनों आरोपितों ने अदालत में कहा कि वे बहस के पूर्व जमानतदार देने को तैयार हैं। आरोपितों का कहना था कि उनके अधिवक्ता ने बिना उनसे पूछे ही पिछली तिथि पर प्रार्थना पत्र दे दिया कि उनके पास जमानतदार नहीं हैं और उनका व्यक्तिगत बंधपत्र स्वीकार किया जाए।

अधिवक्ता श्याम शंकर ने बताया कि दोनों से पूछा गया था और दोनों ने कहा कि उनके पास जमानतदार नहीं हैं इसलिए दोनों की ओर से व्यक्तिगत बंधपत्र का प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। अधिवक्ता के अनुसार अब दोनों अपनी बात से मुकर रहे हैं। प्रश्न यह भी उठता है कि बांग्लादेशी आतंकी के पास जमानतदार आए कहां से। एक तरफ वे कहते हैं कि उनका यहां कोई नहीं है और दूसरी तरफ लखनऊ, आजमगढ़ और यहां के अधिवक्ता उनके मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं जबकि शुरू में आरोपितों ने बताया था कि उनका कोई अधिवक्ता नहीं है तब उनके लिए सरकारी खर्च पर न्याय मित्र नियुक्त किया गया। वर्तमान में उनके न्याय मित्र ताजुल हसन हैं लेकिन आरोपितों ने अपने व्यक्तिगत खर्च पर तीन अन्य महंगे वकील पैरवी के लिए नियुक्त किया है। वकीलों के खर्च की फंडिंग कौन करता है यह पर्दे के पीछे है। गत 28 जुलाई 2005 को हरपालगंज के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट के मामले में बांग्लादेशी आतंकवादी रोनी उर्फ आलमगीर एवं ओबैदुर्रहमान को फांसी की सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ अपील हाईकोर्ट में लंबित है। सजायाफ्ता दोनों आतंकवादियों ने हाईकोर्ट में महंगे वकील कर रखे हैं। पूर्व में अपने अधिवक्ता को लिखी चिट्ठी में आतंकवादी रोनी ने खर्च की चिंता न करने एवं कट्टरपंथी संगठन से जुड़े लोगों द्वारा पैरवी करवाने का उल्लेख किया था।

उत्तराखंड में भाजपा ने विधायकों को पढ़ाया मर्यादा व अनुशासन का पाठ

राज्य ब्यूरो, देहरादून

विधायकों के विवादित बोल और पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाने से असहज भाजपा नेतृत्व ने सोमवार को हुई बैठक में अपने विधायकों को नसीहत देते हुए अनुशासन का पाठ पढ़ाया। हाल में कुछ विधायकों की बयानबाजी को आपत्तिजनक करार देते हुए कहा गया कि विधायकों को वाणी पर संयम रखने के साथ ही मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय नेताओं ने दो टूक कहा कि अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं होगी, फिर चाहे कोई किसी भी पद पर क्यों न हो।

भाजपा विधायकों के एक के बाद एक सामने आ रहे बिगड़ैल बोल और इनसे संबंधित ऑडियो-वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं। साथ ही पार्टी की छवि पर भी असर पड़ रहा है। इस सबने पार्टी नेतृत्व को असहज किया हुआ है। हाल में दो विधायकों उमेश शर्मा काऊ व राजकुमार ठुकराल के ऑडियो व वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए। इनमें दोनों को नोटिस जारी किए और वे अपना जवाब दे चुके हैं। इन पर फैसला होना बाकी है, लेकिन विधायकों के विवादित बोलों ने विपक्ष को भी मुद्दा दे दिया।

यह नजारा है देहरादून में भाजपा के प्रदेश कार्यालय का। सोमवार को राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिवप्रकाश जब वहां चल रही बैठक से बाहर निकले तो ऑडियो प्रकरण में नोटिस का सामना कर रहे विधायक उमेश शर्मा काऊ ने प्रकरण के बारे में जानकारी देनी चाही। इस पर शिवप्रकाश ने कहा कि ये अवसर नहीं है, आप दिल्ली आइए। जब वह आगे बढ़े तो विधायक राजकुमार ठुकराल उनके पास आए और आशीर्वाद मांगा। इस पर सह महामंत्री ने उनकी पीठ पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। अनिल डोगरा

पार्टी के सांसदों, विधायकों, प्रांतीय पदाधिकारियों, दायित्वधारियों व जिला स्तर पर गठित समितियों के अध्यक्षों की सोमवार को प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में भी यह मसला उठा। बैठक में राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश ने इशारों ही इशारों में विधायकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत से कार्य एक साथ करने हैं। ये तभी सफलता के साथ पूरे हो सकते हैं, जब हम मिलकर इन्हें करें।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि पार्टी का विस्तार होने के साथ ही कार्यों का विस्तार भी हुआ है।

हापुड़ में हिरासत में थर्ड डिग्री से सिक्योरिटी गार्ड की मौत

जागरण संवाददाता, हापुड़

▸ इंस्पेक्टर सहित तीन निलंबित, 25 लाख में समझौता

▸ परिजनों का आरोप, पुलिस की बेरहम पिटाई से हुई मौत

उप्र पुलिस की बढ़ती निरंकुशता की खबरों के बीच उसका दामन एक बार फिर दागदार हो गया। हापुड़ में एक निजी कंपनी में तैनात सुरक्षाकर्मी की पुलिस अभिरक्षा में सोमवार देर रात हालत बिगड़ गई। जिसे मेरठ में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित की मौत हो गई। सोमवार सुबह मेरठ पहुंचे परिवारीजनों और ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस से लेकर कमिश्नर ऑफिस तक जमकर बवाल किया। पुलिस से धक्का-मुक्की कर शव छीनने का प्रयास भी हुआ। करीब दस घंटे तक प्रदर्शन किया। बाद में पूर्व विधायक धर्मेश तोमर की अगुवाई में 25 लाख में समझौता हो गया। दूसरी ओर हापुड़ पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली प्रभारी, एक उपनिरीक्षक और एक सिपाही को निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं।

हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के गांव लाखन निवासी एवं निजी कंपनी में सुरक्षाकर्मी के तौर पर तैनात प्रदीप तोमर भारतीय किसान संगठन के सदस्य थे। परिवारीजनों के अनुसार रविवार दोपहर भाई कुलदीप से फोन कॉल कराकर पुलिस ने प्रदीप तोमर को छिजारसी टोल प्लाजा के निकट बुलाया, जहां पहुंचने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले कर छिजारसी पुलिस चौकी में बंद कर दिया। परिवारीजनों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने प्रदीप की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस उसे निजी अस्पताल लेकर गई। वहां से मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से गुस्साए परिवारीजनों और ग्रामीणों ने मेरठ में पोस्टमार्टम हाउस से सुबह सात बजे शव उठाने की कोशिश की तो पुलिस ने नहीं उठाने दिया। इस पर करीब दो घंटे तक परिवारीजनों व ग्रामीणों की कई चक्र में पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई हुई। दोपहर ढाई बजे पूर्व विधायक धौलाना धर्मेश तोमर की मध्यस्थता के बाद पुलिसकर्मियों और पीड़ित पक्ष में 25 लाख में समझौता हो गया। नकदी मिलने के बाद दोनों पक्षों में लिखित समझौता हुआ। परिजन कानूनी कार्रवाई से इन्कार करते हुए शव को लेकर चले गए। दूसरी ओर, हापुड़ पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह का कहना है कि प्रकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश बालियान, छिजारसी चौकी प्रभारी अजब सिंह और सिपाही मनीष कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

हापुड़ कप्तान को पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
– आलोक सिंह, आइजी मेरठ

शाम लगभग छह बजे पूर्व विधायक धौलाना धर्मेश तोमर से अफसरों ने बात की। उन्हीं के माध्यम से अफसरों ने ग्रामीणों को समझाया और पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार किया। – अनीता सी मेश्राम, कमिश्नर, मेरठ

मैग्निफिसेंट एमपी से ठीक एक दिन पहले 856 करोड़ के प्रोजेक्टस का होगा लोकार्पण

नईदुनिया, भोपाल

▸ केंद्र सरकार के साथ मिलकर तैयार की गई है जल प्रदाय योजना

मध्य प्रदेश में उद्योगों की जरूरत और सहूलियतों को मद्देनजर रखते हुए मप्र की कमलनाथ सरकार नए औद्योगिक पार्क विकसित करने के साथ पानी का पुख्ता इंतजाम करने की परियोजना पर काम कर रही है। इसके मद्देनजर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आगामी 40 साल की जरूरत को देखते हुए नर्मदा-क्षिप्रा लिंक आधारित जल योजना तैयार की गई है। इसके सहित 856 करोड़ रुपये के पांच प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री कमलनाथ मैग्निफिसेंट एमपी (इन्वेस्टर समिट) शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 17 अक्टूबर को करेंगे।

उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में हर साल गर्मी के समय पानी का संकट खड़ा हो जाता था। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार के साथ मिलकर 300 करोड़ रुपए की लागत वाली 90 एमएलडी जल मात्रा की जल प्रदाय योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार ने इसमें जरूरी अंशदान नहीं दिया तो कमलनाथ सरकार ने पहले दिए अंशदान को लौटाने का फैसला करते हुए परियोजना का नियंत्रण पूरा अपने हाथ में रखने का निर्णय किया है। इस परियोजना के कारण मौजूदा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र और पीथमपुर-धार-महू निवेश क्षेत्र में आगामी 40 साल तक पानी की कोई समस्या नहीं आएगी। पानी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सिमरोल स्थित पंप से दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नेशनल ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को मुहैया कराई 16 सौ हेक्टेयर जमीन में से 478 हेक्टेयर वापस लेकर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की है। यह प्रदेश की पहली टाउनशिप है, जिसमें 262 हेक्टेयर भूमि उद्योगों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा आवासीय, व्यावसायिक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, आईटी के लिए भूखंड आरक्षित हैं। इंदौर से लगे सिंहावा में आइटी पार्क बनाया गया है। 107 एकड़ क्षेत्र में 116 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए इस पार्क में एक लाख वर्गफीट क्षेत्रफल का आइटी भवन बनाया गया है। वहीं, इंदौर विकास प्राधिकरण ने अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और नगर निगम का आइटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किया है।

उद्योगों की महंगी बिजली से निजात दिलाने की मांग को पूरा करने के लिए सरकार परंपरागत बिजली की जगह सोलर एनर्जी का उत्पादन बढ़ाएगी। इसके लिए आठ हजार करोड़ रुपये के पांच प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा।

काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▸ अयोध्या पर प्रस्तावित फैसले को देखते सुरक्षा-व्यवस्था हो सख्त

काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा से इन दिनों खिलवाड़ हो रहा। हाई पावर कमेटी के निरीक्षण और बैठक में यह बात सामने आने पर डीजी सुरक्षा दीपेश जुनेजा ने एसपी सुरक्षा को चेतावनी दी है। डीजी ने चेताया कि विश्वनाथ धाम कारिडोर के निर्माण के दौरान लोगों की आवाजाही पर पैनी नजर रखी जाए। इस ओर आने-जाने वालों की सूची बना ली जाए। उनकी नियमित जांच-पड़ताल कराई जाए। राम मंदिर की सुनवाई के मद्देनजर सुरक्षा के प्रबंध और चुस्त करें। किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या व मथुरा के मंदिरों की सुरक्षा-व्यवस्था को गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सोमवार को डीजी सुरक्षा दीपेश जुनेजा की अध्यक्षता में वाराणसी में हुई। दीपेश जुनेजा बैठक से पूर्व एडीजी जोन बृजभूषण शर्मा, आइजी जोन विजय सिंह मीना समेत अन्य अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ पहुंचे और निरीक्षण किया।

लापरवाही ठीक नहीं : डीजी सुरक्षा ने कमिश्नरी के अनुश्रवण कक्ष में हाई पावर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। एसपी सुरक्षा की ओर से मॉक ड्रिल को लेकर दी गई रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए डीजी सुरक्षा ने कहा कि मॉक ड्रिल को लेकर जिस तरह से हाल के महीनों में लापरवाही बरती गई है, यह ठीक बात नहीं। यह निर्धारित समय में हो जानी चाहिए। निर्माण कार्य के चलते रेड जोन में सरस्वती फाटक, शनिदेव चैनल समेत अन्य द्वार पर लगे हाईड्रोलिक गेट के खराब होने की जानकारी पर डीजी सुरक्षा ने एसपी सुरक्षा को निर्देश दिया कि सुरक्षा के प्रबंध और कड़े करने की जरूरत है।

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में सुबह हल्की धुंध रहेगी। दिन गर्म रहेगा। इन राज्यों के शहरी इलाकों में प्रदूषण में बढोत्तरी होगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सुबह ठण्डी व सुहावनी रहेगी। दिन आंशिक बादलों के साथ आरामदायक व हल्का गर्म रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	36/25/व	अहमदाबाद	36/26/व
कोलकाता	34/25/आंबा	बड़ौदा	36/25/व
चेन्नई	33/26/व	नागपुर	34/23/व
हैदराबाद	31/21/सा	इन्दौर	31/22/सा
बंगलूरू	29/21/सा	रांची	30/22/आंबा
त्रिवेन्द्रम	30/24/आंबा	पटना	31/22/सा
गुवाहाटी	31/24/आंबा	जमशेदपुर	31/22/आंबा
गंगटोक	14/04/व	पुणे	31/22/व

एयर इंडिया की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी

1932 में आज ही भारतीय विमान सेवा एयर इंडिया की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। उस समय इसको टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना जेआरडी टाटा ने की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया।

ग्लोबल हैंड वाशिंग-डे मनाने की शुरुआत हुई

2008 में आज ही ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर हैंडवाशिंग नामक संस्था ने ग्लोबल हैंड वाशिंग-डे मनाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य लोगों को साबुन से हाथ धोने के प्रति जागरूक करना है। प्रत्येक वर्ष 100 से अधिक देशों के लोग इस दिवस को मनाते हैं।

भारत के मिसाइल मैन थे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

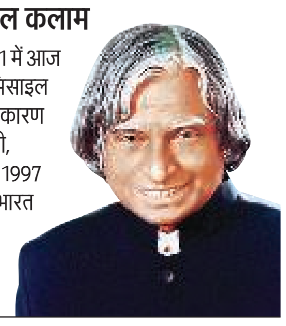

पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में आज ही तमिलनाडु में हुआ था। भारत को बैलेस्टिक मिसाइल और लांचिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही उनका नाम मिसाइल मैन पड़ा। उन्होंने भारत के लिए पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस समेत कई मिसाइल बनाईं। 1997 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1998 में भारत के पोखरण-2 परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई। 2002 में देश के राष्ट्रपति चुने गए। 27 जुलाई, 2015 को उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

मेहनताना मांगा तो पीछे छोड़ा पालतू शेर

इस्लामाबाद, एजेंसी : पाकिस्तान में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक धर्मस्थल की देख-रेख करने वाले व्यक्ति ने एक इलेक्ट्रिशियन के पीछे इसलिए अपना पालतू शेर छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपना मेहनताना मांग लिया था। यह घटना पंजाब प्रांत के लाहौर शहर की है। एक इमाम बारगाह के प्रबंधक ने इस घटना को अंजाम दिया है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। इस गंभीर घटना में इलेक्ट्रिशियन बुरी तरह घायल भी हो गया था। रफीक कई दिनों से अली रजा से पैसे की मांग कर रहा था। इस दौरान वह एक दिन जब पैसे मांगने आरोपित के यहां गया तो उसने पैसे देने के बजाए उसपर अपना पालतू शेर छोड़ दिया। शेर ने रफीक के चेहरे और हाथ को खरोंच लिया, जिससे वो घायल हो गया। हालांकि गनीमत तो ये रही कि पास से गुजर रहे राहगीर रफीक के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए और उसे बचा लिया।

एआइ स्किन से लैस पहला रोबोट तैयार

- अब अपने परिवेश और शरीर को भी महसूस कर सकेंगे रोबोट
- टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने विकसित की त्वचा

बर्लिन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किन से लैस रोबोट तैयार किया है। संवेदनशील सिंथेटिक स्किन रोबोट को अपने परिवेश और शरीर को महसूस करने में सक्षम बनाती है। ऐसे में रोबोट को पता होगा कि वे किस जगह पर और किसके संपर्क में हैं।

जर्मनी की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख (टीयूएम) के गार्डन चेंग और उनकी टीम द्वारा विकसित की गई कृत्रिम त्वचा में लगभग एक इंच के व्यास वाली षट्कोणीय (हेक्सागोनल) कोशिकाएं हैं।

'प्रोसीडिंग्स ऑफ द आइईईई' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, प्रत्येक कोशिका में माइक्रो प्रोसेसर और सेंसर लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से रोबोट संपर्क, निकटता और तापमान का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये कोशिकाएं टीयूएम में कांग्निटिव सिस्टम (संज्ञानात्मक प्रणाली) के प्रोफेसर चेंग ने दस साल पहले विकसित की थीं।

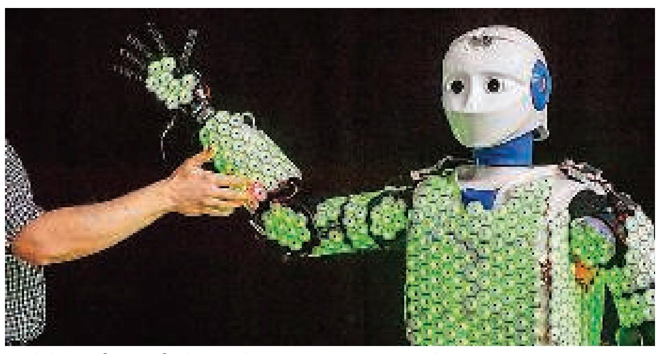

यह रोबोट अपनी त्वचा की कोशिकाओं से आस-पास के परिवेश को महसूस करता है। फाइल

इस तरह की कृत्रिम त्वचा रोबोट को अपने परिवेश को अधिक संवेदनशीलता के साथ अनुभव करने में सक्षम बनाती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस कृत्रिम त्वचा के माध्यम से रोबोट न केवल इधर-उधर आसानी से चल-फिर कर सकते हैं, बल्कि इसके आस-पास काम करने वाले लोग भी सुरक्षित रहेंगे।

शोधकर्ताओं ने बताया कि इसे विकसित करने में सबसे बड़ी बाधा हमेशा से कंप्यूटिंग क्षमता थी। मानव त्वचा में लगभग पचास लाख रिसेप्टर्स होते हैं, जो संवेदनाओं को तुरंत महसूस कराते हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार, कृत्रिम त्वचा में सेंसर से प्राप्त डाटा पर तुरंत प्रतिउत्तर देना मुश्किल काम है। पुराने सिस्टम केवल कुछ सौ सेंसर के डाटा से ही ओवरलोड हो जाते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए शोधकर्ताओं ने त्वचा की कोशिकाओं की जांच की और इसकी प्रोसेसिंग को 90 फीसद तक कम कर दिया और जरूरी सूचनाओं को ही एकत्र कर ओवरलोडिंग की समस्या दूर की।

शोधकर्ताओं ने कहा, 'इससे पहले तक लोग केवल अनुमान लगाते थे कि कृत्रिम त्वचा की मदद से रोबोट इंसानों की तरह संवेदनाओं को महसूस करेंगे, लेकिन अब यह अनुमान साकार होते देख रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे रोबोट भी तैयार होंगे जो सेंसर की मदद से पता लगा सकते हैं कि उनके आस-पास कौन-कौन मौजूद हैं।'

सिनेमा को नया जीवन देने वाले जोसेफ को किया याद

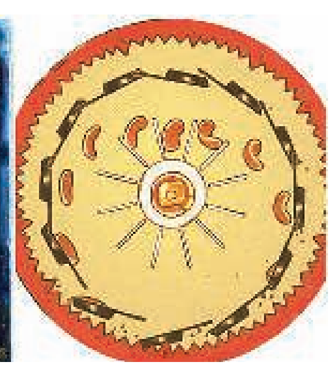

भौतिक विज्ञानी जोसेफ एंटोनी फर्डिनेंड प्लेट्यू और गूगल का डूडल। फाइल

- जन्मदिन पर गूगल ने डूडूल बनाकर भौतिक विज्ञानी के काम को सराहा
- बेल्जियम के वैज्ञानिक ने दुनिया को दिया था चलती तस्वीरों का तोहफा

नई दिल्ली, आइएएनएस : गूगल ने सोमवार को बेल्जियम के भौतिक विज्ञानी जोसेफ एंटोनी फर्डिनेंड प्लेट्यू को उनकी 218वीं जयंती पर डूडल समर्पित कर याद किया। 1832 में प्लेट्यू ने फेनाकिस्टिस्कोप का आविष्कार किया था, जो एक चलती तस्वीरों से भ्रम पैदा वाला पहला उपकरण था। उस समय प्लेट्यू शायद ही जानते होंगे कि वह एक ऐसे उद्योग की आधारशिला रख रहे हैं जो सिनेमा को नया जीवन देगा।

यह एक ऐसा आविष्कार था जिसका इस्तेमाल अब फिल्मों में एनिमेशन के लिए किया जाता है। इसी तकनीक के कारण आज सिनेमा जगत में शानदार और अच्छी फिल्मों का निर्माण हो रहा है। गूगल ने एक विशेष डूडल के जरिये उनके आविष्कार की सराहना की है। इस डूडल को एनिमेटर और फिल्म निर्माता ओलिविया हुयन ने बनाया है। आइए एक नजर डालते हैं जोसेफ एंटोनी फर्डिनेंड प्लेट्यू की जीवनी पर...

- 14 अक्टूबर, 1801 को ब्रसेल्स में जन्मे जोसेफ चलती तस्वीरों का भ्रम प्रदर्शित करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- उनकी विलक्षणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि छह साल की उम्र में ही उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था।
- यूनिवर्सिटी ऑफ लीज में पढ़ाई की और 1829 में भौतिक और गणितीय विज्ञान में स्नातक की उपाधि ली।
- 1827 में वह ब्रसेल्स के एक स्कूल गणित के शिक्षक बने और 1835 में गेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए।
- 1832 में जोसेफ ने एक स्ट्रोबोस्कोपिक उपकरण का आविष्कार किया, जिसे बाद में 'फेनाकिस्टोस्कोप' के नाम से ख्याति मिली।
- 15 सितंबर, 1883 को उत्तर-पश्चिमी बेल्जियम के गेंट में उनका निधन हुआ।
- गूगल के मुताबिक, आंखों की रोशनी जाने के बाद भी जोसेफ ने विज्ञान का काम जारी रखा।

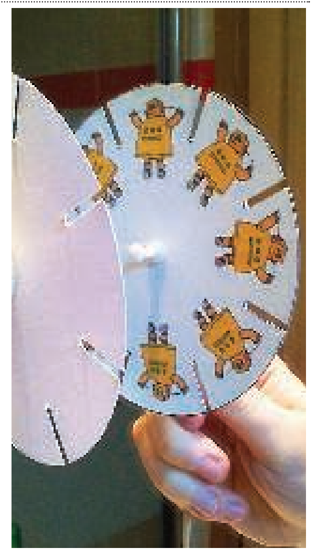

फेनाकिस्टोस्कोप की मदद से तस्वीरों में एनिमेटेड प्रभाव पैदा किया जाता है। फाइल

अब इंसुलिन के इंजेक्शन से मिलेगी मुक्ति

आविष्कार ▸ अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विकसित किया कैप्सूल

आंत के किनारों से चिपककर दवा को करता है रिलीज

बोस्टन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया है, जो इंसुलिन व अन्य ऐसी दवाओं को शरीर में पहुंचाने में सक्षम है, जिन्हें आमतौर पर इंजेक्शन के जरिये शरीर में पहुंचाया जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बहुत सी दवाएं, खासकर प्रोटीन से बनी दवाएं गोली या कैप्सूल के रूप में नहीं गटकी जा सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसी दवाएं अक्सर पाचन तंत्र पहुंचते ही अपना असर दिखाने से पहले नष्ट हो जाती हैं। इंसुलिन के साथ भी ऐसा ही है। अब वैज्ञानिकों ने ऐसा कैप्सूल बनाया है, जो छोटी आंत में पहुंचकर सूक्ष्म सुइयों के रूप में दवा को रिलीज (मुक्त) करता है। ये सुइयां आंत के किनारों से चिपककर धीरे-धीरे दवा को खून में पहुंचा देती हैं और घुलकर खत्म हो जाती हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कैप्सूल जरूरत के मुताबिक दवा को शरीर में पहुंचाने में सक्षम है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) के शोधकर्ताओं ने एक फार्मा कंपनी के साथ मिलकर यह कैप्सूल तैयार किया है।

- पेट के भीतर ही घुल कर खत्म हो जाता है कैप्सूल
- हर दिन इंसुलिन लेने से भी दिलाएगा छुटकारा

यह अध्ययन नेचर मेडिसिन नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

इंसुलिन और प्रोटीन की दवाओं का संवाहक : अमेरिकी शोधकर्ताओं का यह अध्ययन नेचर मेडिसिन नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने कहा, 'नया कैप्सूल डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि उन्हें हर दिन इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है।' उन्होंने कहा कि नए कैप्सूल में इंसुलिन और प्रोटीन से बनी दवाओं को ले जाने की क्षमता है। साथ ही यह आंतों की जटिल कार्यप्रणाली से भी निपट सकता है।

एमआइटी के प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगर ने कहा, 'हम नई दवा के परिणामों को देखकर बहुत खुश हैं, जिसे हमने अपने सहयोगियों के साथ प्रयोगशाला में तैयार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह भविष्य में मधुमेह रोगियों के साथ-साथ अन्य लोगों की मदद करने में सक्षम होगी।'

बढ़ता है रक्त प्रवाह : सूअरों पर किए गए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि इस कैप्सूल को खाने के बाद यह उतनी ही मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता है, जितनी शरीर को जरूरत होती है। पेट में जाने के बाद जब यह कैप्सूल रक्त में घुलना शुरू होता है तो इससे रक्त का प्रवाह भी बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं की टीम ने इससे पहले भी कई ऐसी गटक कर खाई जाने वाली दवाओं को विकसित किया था, जिन्हें इंजेक्शन के जरिये शरीर में डाला जाता है।

पहले भी बना चुके हैं दवाएं : एमआइटी के सहायक प्रोफेसर जियोवानी ट्रेवर्सो ने कहा, 'हमारा अध्ययन मरीजों और चिकित्सकों को इंजेक्शन की बजाय गोलियों के रूप में दवाओं को लेने के लिए प्रेरित करता है।' उन्होंने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में उन्होंने एक ब्लूबेरी के आकार का कैप्सूल विकसित किया था, जिसमें इंसुलिन की छोटी सुइयां रखी गई थीं। पेट में पहुंचने के बाद ये सुइयां दवाओं को रिलीज करती थीं। नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक ऐसा कैप्सूल तैयार किया है जो अपनी सामग्री को आंतों की दीवारों में इंजेक्ट कर सकता है।

प्रभावी तरीके से होता है दवाओं का वितरण: एमआइटी शोधकर्ता एलेक्स अब्रामसन ने कहा, 'हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पशुओं ऊतक पर इनका परीक्षण किया कि इन कैप्सूलों का शरीर पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा? सूअरों के परीक्षणों के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि 30 मिलीमीटर लंबे कैप्सूल इंसुलिन की खुराक को प्रभावी ढंग से वितरित कर सकते हैं।

शोध अनुसंधान

डायबिटीज और मोटापे से निजात दिलाएगा नया डिवाइस

वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है, जिसे मोटापा कम करने, फैटी लिवर और डायबिटीज को नियंत्रित करने में पारंपरिक बेरियाट्रिक सर्जरी जितना ही कारगर पाया गया है। इस डिवाइस को 'स्लीवबलून' नाम दिया गया है। ऑपरेशन के जरिये इस डिवाइस को पेट में पहुंचाया जाता है। वहां पहुंचकर यह डिवाइस छोटी आंत के शुरुआती हिस्से को ढंक लेता है। इससे व्यक्ति कम भोजन ग्रहण कर पाता है और धीरे-धीरे वजन नियंत्रित होता है। प्रयोग के दौरान इसकी मदद से खुराक को 60 फीसद तक और फैट मास को 57 फीसद तक कम करने में सफलता मिली। ग्लूकोज का स्तर भी 65 फीसद तक कम किया गया। आमतौर पर गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी में भी व्यक्ति की खुराक को कम करते हुए मोटापे और अन्य समस्याओं को ठीक किया जाता है। - आइएएनएस

जीन थेरेपी से हो सकता है दृष्टिहीनता का प्रभावी इलाज

जीन थेरेपी की मदद से वेट एज-रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन (एएमडी) का इलाज किया जा सकता है। हालिया शोध में यह दावा किया गया है। एएमडी को दृष्टिहीनता के सबसे बड़े कारणों में शुमार किया जाता है। इसमें आंख की कुछ कमजोर रक्त नलिकाओं के कारण रेटिना का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी की वार्षिक बैठक में जीन थेरेपी की सफलता को लेकर आंकड़े सामने रखे गए। आमतौर पर एएमडी के मरीज को चार से छह हफ्ते के बीच आंखों में इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। वहीं, जीन थेरेपी से इलाज के बाद एएमडी से जूझ रहे छह मरीजों को छह महीने तक किसी तरह के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जीन थेरेपी एएमडी के मरीजों को हर महीने आंख में इंजेक्शन लगवाने की तकलीफ से निजात दिला सकती है। - एएनआइ

34 देश लेंगे रक्षा प्रदर्शनी में हिस्सा

दक्षिण कोरिया के सियांगनम में सोमवार को सियोल मिलिट्री एयरपोर्ट पर सियोल इंटरनेशनल एयरोस्पेस एंड डिफेंस एक्जिबिशन 2019 के तहत प्रदर्शित हो रहे विमान। 15 अक्टूबर से शुरू हो रही इस विमानन प्रदर्शनी में 34 देशों की 420 कंपनियां भाग ले रही हैं। 20 अक्टूबर तक चलने वाली प्रदर्शनी में युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर आकर्षण का प्रमुख केंद्र होंगे। एपी

अग्नि युद्ध समारोह

इंडोनेशिया में बाली के डेनपसार द्वीप स्थित मंदिर में प्रतिवर्ष अग्नि युद्ध समारोह मनाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से सियाट जिनी उत्सव कहा जाता है। इस समारोह में मुख्य रूप से युवा हिस्सा लेते हैं, जो एक-दूसरे पर आग के गोले फेंककर मारते हैं। मान्यता है कि इससे युवाओं में साहस पैदा होता है और उन्हें बुरी किस्मत से छुटकारा मिलता है। इस खतरनाक उत्सव में युवकों का शरीर आग से बुरी तरह झुलस जाता है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

तेलुगु फिल्म 'जर्सी' के रीमेक में दिखेंगे शाहिद कपूर

फिल्म 'कबीर सिंह' 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली शाहिद कपूर की पहली फिल्म है। इस फिल्म के बाद शाहिद बतौर निर्माता 'डिंग्को सिंह' का निर्माण करने वाले थे, जो भारतीय बॉक्सर की जिंदगी पर बननी थी। किन्हीं कारणों से यह फिल्म अटक गई और उनकी अगली फिल्म को लेकर अटकलें तेज हो गईं। अब खबर है कि वह सुपरहिट तेलुगु फिल्म 'जर्सी' के हिंदी रीमेक में काम करेंगे। यह दूसरा मौका होगा, जब वह बैक टू बैक सुपरहिट तेलुगु फिल्मों का हिस्सा बनेंगे। उनकी फिल्म 'कबीर सिंह' सुपरहिट तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की हिंदी रीमेक थी। 'जर्सी' के हिंदी संस्करण का निर्देशन भी मूल फिल्म के निर्देशक गौतम टीनौरी ही करेंगे। फिल्म ऐसे शख्स के इर्दगिर्द है, जो क्रिकेटर है, लेकिन राजनीति के चलते उसे टीम से अलग कर दिया जाता है। गौतम के मुताबिक, वह हिंदी फिल्म का निर्देशन करने के लिए उत्साहित हैं। वह फिल्म को देश भर में पहुंचाना चाहते हैं। उनके मुताबिक फिल्म के लिए शाहिद कपूर से बेहतर कोई नहीं हो सकता था। 'जर्सी' के हिंदी संस्करण का निर्माण अलू अरविंद, अमन गिल, दिल राजू करेंगे। यह फिल्म अगले साल 28 अगस्त को रिलीज होगी।

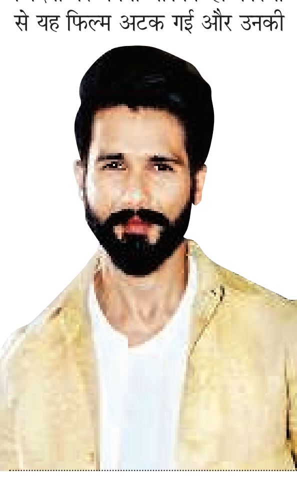

ऐश्वर्या ने तीन दिन में की एंजेलिना जोली की डबिंग

हॉलीवुड लगातार अपनी बड़ी बजट की फिल्मों को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में डब करके रिलीज कर रहा है। बीते दिनों रिलीज हुई 'द लॉयन किंग' फिल्म में शाह रुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने मुख्य किरदारों के लिए अपनी आवाज दी थी। अब पहली बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने हॉलीवुड फिल्म 'मैलिफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल' के हिंदी संस्करण में एंजेलिना जोली के किरदार को अपनी आवाज दी है। ऐश्वर्या के मुताबिक इसकी डबिंग करने में उन्हें तीन दिन लगे। हिंदी में फिल्म के डायलॉग मयूर पुरी ने लिखे हैं। ऐश्वर्या के मुताबिक, उन्होंने चंद दिन पहले ही इस फिल्म का पहला पार्ट अपनी बेटी आराध्या के साथ देखा था। उसके दो दिन बाद ही उन्हें इस फिल्म की सीक्वल के डबिंग का प्रस्ताव मिला गया। यह जानकर आराध्या काफी उत्साहित हो गई कि उनकी मां एंजेलिना के किरदार को आवाज देंगी। साथ ही ऐश्वर्या ने मणिरत्नम के साथ अगली फिल्म करने की बात भी स्वीकार की है। हालांकि फिल्म और उसकी कहानी के बारे में बताने से उन्होंने इन्कार कर दिया। ऐश्वर्या के मुताबिक, महान फिल्ममेकरों में शुमार मणिरत्नम के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई फिल्में की हैं, इसलिए उन्हें उनके साथ काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है।

रणवीर से शादी करना मेरा सही फैसला : दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी को नवंबर में एक साल हो जाएंगे। शादी से पहले दीपिका और रणबीर कपूर के अफेयर के चर्चे काफी आम रहे हैं। दीपिका ने रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद 'ये जवानी है दीवानी' और 'तमाशा' में साथ काम भी किया था। दोनों विज्ञापन में भी साथ नजर आते हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जब दर्शकों से पूछा गया कि वे पर्दे पर दीपिका को रणवीर सिंह के साथ ज्यादा देखना चाहते हैं या रणबीर कपूर के साथ? तो दर्शकों ने रणवीर सिंह का नाम लिया।

इस प्रतिक्रिया को देखकर दीपिका कह उठीं कि यानी मैंने सही इंसान से शादी की है। इस मौके पर दीपिका ने रणबीर और रणवीर के काम करने के तरीकों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, 'रणबीर कपूर होमवर्क करके नहीं आते हैं। वह स्पॉन्टेनियस अभिनेता हैं। जबकि रणवीर सिंह अपने किरदार की जमकर तैयारी करते हैं। रणवीर जब कोई किरदार निभाते हैं, तो वह उसी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उसी किरदार की तरह रहने लग जाते हैं। जब 'पद्मावत' फिल्म में वह अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभा रहे थे, तो वह सेट पर वह उसी के अंदाज में रहते और बातचीत किया करते थे।' दीपिका और रणवीर की अगली फिल्म '83 है। यह फिल्म 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम के विश्वकप जीतने पर आधारित है।

कृति नहीं चाहतीं कि उनके किसी सीन से गलत मैसेज जाए

अभिनेत्री कृति सैनन का कहना है कि वह कोई भी सीन करने के पहले जरूर सोचती हैं कि इससे कोई गलत संदेश तो नहीं जाएगा। कृति कहती हैं, 'मैं जिम्मेदार एक्टर हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी सीन या फिल्म से दर्शकों तक कोई गलत मैसेज पहुंचे।' कृति फिलहाल अपनी फिल्म 'हाउसफुल 4' को लेकर उत्साहित हैं। हालांकि इस फिल्म के गाने एक चुम्मा... को लेकर फिल्म की खिंचाई हो रही है। कृति कहती हैं, 'इस गाने में लड़के अपनी पार्टनर के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं न कि किसी अनजान के लिए। अगर चुम्मा शब्द औरतों का निरादर करता तो मैं जरूर प्रतिरोध करती।' उन्होंने कहा, 'यह अच्छी बात है कि जेंडर समानता की बात हो रही है, लेकिन इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। कहा गया कि 'लुका छुपी' के 'कोका कोला' गाने में लड़की को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन मेरा किरदार भी पार्टनर को वही कह रहा था।'

अध्ययन

ब्रिटेन की ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया शोध कहा- धीमी गति से चलने वाले लोगों के फेफड़े, दांत और इम्यून सिस्टम होता है कमजोर

धीमी चाल का संबंध हमारे मस्तिष्क से है

वाशिंगटन, प्रेट्र : अक्सर देखा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों पर भी असर दिखना शुरू हो जाता है। 45 वर्ष के लोगों के चलने की गति का अध्ययन कर शोधकर्ताओं ने इसके पीछे के कारणों का पता लगाने का दावा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि 45 साल की उम्र के बाद लोगों की अन्य शारीरिक गतिविधियों के साथ-साथ चलने की गति भी प्रभावित हो जाती है क्योंकि चलने की गति का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। यदि हमारी चाल प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे मस्तिष्क की उम्र बढ़ रही है।

इस अध्ययन के शोधकर्ताओं में अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधार्थी भी शामिल थे। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि धीमी गति से चलने वाले लोगों के फेफड़े, दांत और इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) भी तेज चलने वाले लोगों के मुकाबले कमजोर था। जामा नेटवर्क ओपन नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, बूढ़े रोगियों को आमतौर पर इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन कम उम्र में इस तरह की समस्याओं से घिरे रहना चिंताजनक है।

लगाया जा सकता है पूर्वानुमान : शोधकर्ताओं ने कहा कि न्यूरोकांग्निटिव परीक्षण के जरिये यह पता लगया जा सकता है कि भविष्य में किन लोगों की चलने की गति कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के आइक्यू स्तर, भाषा समझने व निराशा सहने की क्षमता, मोटर कौशल और भावनात्मक नियंत्रण का अध्ययन कर यह पता लगाया जा सकता है कि 45 वर्ष की उम्र में उनकी चलने की गति कैसी होगी।

समय से पूर्व मौत की आशंका : इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक और ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता टेरी ई. मोफिट ने कहा, 'डॉक्टरों जानते हैं कि धीमी गति से चलने वाले लोगों की तेजी से चलने वालों की तुलना में जल्दी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अध्ययन में दावा किया गया है कि पैदा होने से लेकर युवावस्था तक यदि व्यक्ति धीमी चाल से चलता है और यह यदि उनकी आदत में शुमार है तो ऐसी आशंका ज्यादा रहती है कि उनकी मौत समय से पूर्व हो जाए।

ऐसे पड़ता है चाल पर असर

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के डुनेडिन में एक वर्ष के दौरान पैदा हुए लगभग 1,000 लोगों के डेटा की जांच की और 904 प्रतिभागियों का परीक्षण किया जिनकी उम्र 45 वर्ष की थी। इस दौरान उनके जीवन में आए शारीरिक-मानसिक बदलावों का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन से पता चला है कि धीमी गति से चलने वाले लोगों के मस्तिष्क का द्रव्यमान कम होता है और मुख्य कॉर्टिकल की मोटाई भी औसतन कम होती है, जिसका असर उनके चलने की गति पर पड़ता है।

तेज चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। फाइल